Fourth Series, No.28

Wednesday, March 26, 1969
Chaitra 5, 1891 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

Seventh Session
(Fourth Lok Sabha)

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi

CONTENTS

No. 28, -Wednesday, March 26, 1969 / Chaitra 5, 1891 (Saka).

	COLUMNS
Oral Answers to Questions-	
*Starred Questions Nos. 723, 724 and 727	1-33
Short Notice Question No. 10	34-45
Written Answers to Questions-	
Starred Questions Nos. 721, 722, 725, 726 and 728 to 750	45-64
Unstarred Questions Nos. 4409 to 4431, 4434 to 4501 4503 to 4513, 4575 to 4521, 4523 to 4526, 4528 to 4538	64-159
Calling Attention to matter of Urgent Public Importance- Firing by Central Reserve Police Force on the Security Personnel of Durgapur Steel Plant. ...	159-72
Matter under Rule 377	173-75
Voting on Constitution (Twenty-second Amendment) Bill...	
Paper Laid on the Table ...	176-77
Message from Rajya Sabha	177
Committee on Private Members Bills-and Resolutions— Forty-sixth Report.	177
Estimates Committee— Seventy-eighth Report	177-78
Lok Pal and Lok Ayuktas Bill-	
Report of-Joint Committee; ...	178
Evidence; and ...	178
Memoranda ...	178
Demands for Grants- ...	178-333
Ministry of Home Affairs ...	178-333
Shri Lobo Prabhu	200-09
Dr. Govind Das ...	209-16
Shri S. Kandappan ...	216-25
Shri Rane ...	225-29
Shri Ram Gopal Shalwale ...	229-36

---

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

COLUMNS

Shri Ganga Reddy 236–54
Shri Nihal Singh 254–58
Shri Sitaram Kesri 258–65
Shri Abdul Gani Dar 265–83
Shri Kushok Bakula 283–91
Shri Tenneti Viswanatham 291–96
Shri Virbhadra Singh 296–303
Shri Kedar Paswan 303–07
Shri P. Mandal 307–10
Shri Prakash Vir Shastri 310–19
Shrimati Ila Palchoudhuri 319–24
Shrimati Lakshmikanthamma 324–30
Shri Randhir Singh ... 330–33

Half-An-Hour Discussion
Income-Tax-Appelate Tribunal
for Mysore ... 333–50
Shri Beni Shanker Sharma .. 333–39
Shri M. Yunus Saleem ... 339–50

LOK SABHA

Wednesday, March 26, 1969/Chaitra 5, 1891 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. SPEAKER : The House will now take take up Questions-Dr. Sushila Nayar–

AN HON. MEMBER :She is not present.

MR. SPEAKER : Shri A. Sreedharan -

AN HON. MEMBER : He is also not present.

MR. SPEAKER : Shri Lakkappa - not present. We will take the next Question-Shri Sudarsanam -

AN HON. MEMBER : Not present.

MR. SPEAKER : Next Question – Shri J. B. Singh - Shri Shri Chand Goyal - Shri Onkar Singh - Shri Sharda Nand -

SHRI SHARDA NAND : Question No. 723.

THE DEPUTY MINISTER (SHRIMATI NANDINI SATPATHY) : (a) It is true that some States are not quite satisfied . . . . .

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Where is the Prime Minister ?

SHRI S. K. TAPURIAH: The Deputy Minister can read the answer but the Prime Minister should be present. The Deputy Minister has been doing it all along but not in the absence of the Prime Minister.

श्री कंवर लाल गुप्त : रिशफलिंग के बाद यह पहला मौका है, प्रधान मंत्री को स्वयं आकर जवाब देना चाहिए था ।

SHRI PILOO MODY : We were wondering whether there had been a reshuffle overnight.

श्री मधु लिमये : उनका तो पार्लमेन्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है । कभी आती नहीं, कभी बोलती नहीं । कल इतना कुछ हो गया फिर भी उन का पता नहीं है । . . . अब आ रही है ।

MR. SPEAKER : The hon. Deputy Minister may repeat the answer.

PLAN CEILINGS FOR STATES

+

*723. SHRI SHARDA NAND :
SHRI J. B. SINGH :
SHRI SHRI CHAND GOYAL :
SHRI ONKAR SINGH :
SHRI BAL RAJ MADHOK :
SHRI HARDAYAL DEVGUN :
SHRI D. C. SHARMA :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some States

have shown their unhappiness with Plan ceiling and if so, their names;

(b) whether it is also a fact that some of these State Governments have written about it to the Centre ; and

(c) if so, the details thereof and the action taken by Government thereon ?

THE DEPUTY MINISTER (SHRIMATI NANDNI SATPATHY) : (a) It is true that some States are not quite satisfied with the size of their State Plans as suggested by the Planning Commission.

(b) and (c). There is correspondence between the Centre and the States on the subject and the Plan outlays will be finalised only after the meeting of the National Development Council.

श्री शारदा नन्द : मन्त्री महोदय बतायेंगे कि योजनाओं में राज्यों के खर्चे की सीमा निर्धारित करने के लिए सरकार ने क्या क्या आधार बनाये थे और किन किन राज्यों को क्या क्या निर्देश दिये गये थे ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : राज्य सरकारों ने जो अपने स्टेट प्लान बनाकर भेजे थे उनके सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये थे कि रेट आफ ग्रोथ इतना होना चाहिए, एग्रीकल्चर और दूसरी बातों पर इतना इतना जोर देना चाहिए । उसके आधार पर राज्य सरकारों ने अपने प्लान बनाये । उसमें केन्द्रीय सहायता कितनी दी जायेगी, यह उनको बताया गया और वे स्वयं अपने प्रदेश में कितने रिसोर्सेज़ बढ़ायेंगे इसका भी जिक्र था । इसी के आधार पर प्लान बनाने की बात हुई ।

श्री शारदा नन्द : अभी मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि कुछ राज्यों से पत्र-व्यवहार चल रहा है तथा इस प्रश्न में एक बात स्पष्ट रूप से पूछी गई थी कि किन किन राज्यों ने अपनी अप्रसन्नता प्रगट की है लेकिन मन्त्री महोदय ने उन राज्यों के नाम नहीं बताये हैं, अतः मैं जानना चाहता हूं कि किन किन राज्यों से पत्र-व्यवहार चल रहे हैं, किन किन राज्यों के उत्तर आ गए हैं तथा उनके नाम क्या हैं ?

श्री ब० रा० भगत : करीब करीब सभी राज्यों ने अपनी नाखुशी जाहिर की है कि वे इससे संतुष्ट नहीं है और खासकर दो राज्यों – उड़ीसा और वेस्ट बंगाल–ने लिखा भी है ।

श्री बलराज मधोक : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मुझे यह कहना है कि जो प्रश्न दिये जाते हैं पेपर पर उनका कम से कम पूरा उत्तर मिलना चाहिए ताकि फिर उसके ऊपर सप्लीमेन्टरी पूछे जा सकें, मूल प्रश्न ही सप्लीमेन्टरी के रूप में पूछना पड़े, यह बात मुनासिब नहीं है ।

मैं जानना चाहता हूं क्या यह सत्य है कि आपने प्लान पर विचार करते हुए कुछ प्रान्तों को विशेष स्थिति दी है कि वे अपने रिसोर्सेज़ को चाहे रेज करें या न करें जिसमें जम्मू कश्मीर, नागालैंड, उड़ीसा,राजस्थान भी शामिल हैं . . . (**व्यवधान**) . . . मैं पहले यही जानना चाहूँगा कि आप बताइये वे कौन कौन स्टेट है ? और क्या यह सत्य है कि दिल्ली पूरे देश की राजधानी है जहां की रेट आफ ग्रोथ इस समय दुनिया में हायस्ट है और उसके बारे में आपने जो प्लान बनाया है जबकि दिल्ली प्रदेश के अन्दर आबादी जो है उसकी ग्रोथ फोर हन्ड्रेड परसेन्ट है जोकि दुनिया में और कोई नहीं है और यहां पर मिनिमम सोशल सर्विसेज़ के लिए मिनिमम फंड्स को ध्यान में रखकर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने चार सौ करोड़ का प्लान बनाया था, दिल्ली मेट्रोपोलिटन कौंसिल ने 225 करोड़ का प्लान यूनानिमसली पास किया और उसको सभी पार्टीज़ के पास भेजा परन्तु प्लानिंग कमीशन के अन्दर जो वर्किंग ग्रुप है उसने 217 करोड़ का प्लान ही माना और फिर आपने जो प्लान बनाया है उसमें दिल्ली को

155 करोड़ ही दिए हैं और अगर पर-कैपिटा के हिसाब से या पिछले डेवलपमेन्ट के हिसाब से, उसी आधार पर चला गया तो दिल्ली के अन्दर जो आज एमिनिटीज हैं, सोशल सर्विसेज हैं वह भी मेनटेन नहीं हो पायेंगी और जब दिल्ली प्रशासन ने कहा कि अगर आप अधिक नहीं दे सकते हैं तो जो हम एकोनामी करें या जो और अधिक रिसोर्सेज रेज करें उसे दिल्ली के डेवलपमेन्ट में इस्तेमाल करने के लिए दिया जाये लेकिन उस बात को भी आप नहीं मानते हैं – इसकी वजह से आज दिल्ली के अन्दर बड़ी बेचैनी है और दिल्ली के कुछ मेम्बर्स ने फाइनेन्स मिनिस्टर के घर के सामने धरना भी दिया था तो मैं जानना चाहता हूँ कि चूंकि दिल्ली का केस जेनुइन है इसलिए इस केस में नागालैंड, आसाम, जम्मू कश्मीर, इन प्रान्तों के साथ, जबकि यह राजधानी भी है, इसके लिए स्पेशल कंसीड्रेशन करेंगे और जो उनकी मांगे हैं कि जो अधिक रिसोर्सेज हम पैदा करें वह दिल्ली के डेवलपमेन्ट पर खर्च करने के लिए दिया जाये, उसको पूरा करेंगे ?

श्री ब०रा० भगत: माननीय सदस्य ने ठीक कहा है, नेशनल डेवलपमेन्ट कौंसिल की जो कमेटी बनी उसमें सभी मुख्य मन्त्री थे उन्होंने, प्रदेशों के प्लान के लिए जो केन्द्रीय सहायता दी जाये, उसके सम्बन्ध में एक तजवीज रखी और उसमें उनकी सिफारिश यह भी थी कि कुछ प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर या नागालैंड वगैरह जो हैं, उनको एक खास तरह से सहायता दी जाये। यह उनकी सिफारिश थी और इसके अलावा और भी सिफारिशें थी जिनको केन्द्रीय सरकार ने मान लिया और उन्हीं सिफारिशों के आधार पर, राज्यों को जो सहायता दी जाती है वह दी जायेगी।

जहां तक दिल्ली का सवाल है, माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि दिल्ली यूनियन टेरीटरी है। यूनियन टेरिटरीज के लिए दूसरा ही तरीका है। इनके सम्बन्ध में जो प्लान बनेगा उसमें रिसोर्सेज के अलावा जितना डेफिसिट होगा वह केन्द्रीय सरकार देगी। अब दिल्ली चूंकि राजधानी है और यहां की आमदनी भी देश में सबसे ज्यादा है और साथ ही साथ खर्चा भी सबसे ज्यादा है, इन्वेस्टमेन्ट भी ज्यादा है – आज अगर उस हिसाब से देखेंगे, पर-कैपिटा इन्वेस्टमेन्ट देखेंगे या पर-कैपिटा इनकम देखेंगे तो दिल्ली में सबसे ज्यादा है-लेकिन इस बात का सवाल जरूर किया जायेगा कि दिल्ली की जो एमिनिटीज है उनका प्राविजन, जो प्लान बना है, उसमें हो सके।

श्री बलराज मधोक : वह अपने रिसोर्सेज रेज करें और एकोनामी करें तो उस पैसे को दिल्ली के डेवलपमेन्ट पर इस्तेमाल करने की इजाजत आप देंगे ?

श्री ब० रा० भगत : यह सिफारिश आई है कि वे अपने रिसोर्सेज बढ़ायें तो प्लान बढ़ाने की इजाजत दी जाये – उसपर विचार किया जा रहा है।

SHRI P. K. DEO : It is a fact that the Government of Orissa while expressing their dissatisfaction over the allotment for the Fourth Five Year Plan have suggested that the payment liability of Rs. 138 crores of Central dues, for which the extravagance of previous Government and bad workmanship are primarily responsible, be suspended for the time being and as Orissa contains 48 per cent of Scheduled Castes and Scheduled Tribes--my hon. friend Shri Chanda over there will bear me out -some special allotment should be made outside the ceiling of the Plan ?

SHRI B. R. BHAGAT : State dues or debt services are matters which are considered by the Finance Commission. As for extravagance, it is a matter of history that during that period the rate of growth in that State was high.

SHRI P. K. DEO:The Khanna Commission has given its own view about the performance of that State. Anyhow, the latter

part of my question has not been answered. What about special provision outside the ceiling of the plan for Scheduled Castes and Tribes.

SHRI B. R. BHAGAT : There is provision for Scheduled Castes and Tribes in the Plan. There cannot be anything outside the Plan ceiling for any particular State.

SHRI P. K. DEO : But in Orissa 48 per cent of the people belong to that category.

श्रीमती सुशीला रोहतगी: यह देखते हुए कि उत्तर प्रदेश को पहली पंचवर्षीय योजना में कोई सहायता नहीं मिली और दूसरी व तीसरी पंचवर्षीय योजना में पर कैपिटा इनवैस्टमेंन्ट सब प्रदेशों से कम है और यह बात देखते हुए कि डेंसिटी आफ पापूलेशन सबसे अधिक है और यह भी कि वहां की विशेष समस्याओं को देखते हुए पटेल आयोग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में अपनी कुछ सिफारिशें भी दी हैं और उस पहाड़ी इलाके में, उत्तर काशी में काफी गरीबी है तो इन बातों को देखते हुए क्या उत्तर प्रदेश को ज्यादा केन्द्रीय सहायता मिलेगी और यह जो फोर्थ फाइव इयर नया प्लान आ रहा है उस में विशेष कर कोई विशेष सहायता उत्तरप्रदेश के लिए भारत सरकार देने के बारे में सोचेगी ?

श्री ब० रा० भगत : जो सिफारिशें की गई थीं उन में यह भी था कि चूंकि इस प्रदेश की आमदनी नेशनल एवरेज से कम है इसलिए वहां उनको सैंट्रल पूल से 10 परसैंट ज्यादा देने के बारे में विचार किया जाय । यह भी कहा गया था कि जहां तक स्पेशल प्राबलम्स का ताल्लुक है तो उन के बारे में भी ख्याल किया जायेगा । यह बात उत्तरप्रदेश पर भी लागू होती है ।

SHRI P. GOPALAN : It is a sad commentary on the technique and strategy of planning in this country that even after 18 years of planning regional imbalances are still being perpetuated and the per capita income in many of the States is far below the all India average. This warrants a radical change in the policies and programmes of planning. In this connection, I would like to know from the hon. Minister whether the Kerala Chief Minister, who happens to be the Chairman of the State Planning Board, has submitted an alternative Fourth Plan to the Government. If so, what are the salient features of it ?

SHRI B. R. BHAGAT : The question of regional imbalance was taken up in the Third Plan. Then the Patel Committee was set up to consider the strategy of development for promoting and stimulating the rate of growth in areas which were submerged or which were not developed over the previous plan periods. This process has been taken care of in the present plan. The problem of regional imbalance is a very important one, concerning as it does all sides of the House irrespective of party affiliations. But it has to be tackled over a period of time; it cannot be tackled in a day. Every effort is being made to tackle it. As for the alternative plan suggested by the Kerala Chief Minister, it has been received and it will be considered by the National Development Council. As for the report of that Plan, I think the hon. Member must have seen that report.

SHRI ANANTRAO PATIL: May I know whether the Government of Maharashtra have expressed their willingness to raise Rs. 450 crores for plan expenditure besides the Central allotment ? If so, may I know whether it is not the largest amount that a State is going to raise ?

SHRI B. R. BHAGAT : The record of the Maharashtra Government for raising resources is very creditable.

SHRI S. KANDAPPAN : Thanks to the mismanagement of the financial affairs of this country by this government, now a stage has come where every State feels that it is not getting its due share. While making allocations, I would like to know from the government whether they will take into consideration the past performance of a State also - I am putting it in a general way and

not referring to any particular State-because we know from record of past performance that there are some States which are not able to make the maximum utilisation of the finances that are vested in them while there are other States which are able to give a good performance. In order to give incentive and create healthy competition among the States for the national growth of the economy in *toto*, may I know whether the government would take into consideration and give some kind of percentage for their past performance.

SHRI B. R. BHAGAT : I think, in this report in the allocation of resources this aspect is also taken into consideration.

श्री चन्द्रजीत यादव : अभी माननीय मंत्री ने अपने प्रश्न के उत्तर में बतलाया कि जो क्षेत्रीय असन्तुलन है उस बारे में पटेल कमिशन की स्थापना की गई थी। उस में इस बात पर विचार किया गया था। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि उत्तरप्रदेश का पूर्वी अंचल जिसमें बनारस, गोरखपुर और फैजाबाद के डिवीजन आते हैं और उस में लगभग पौने दो करोड़ की आबादी है। उस क्षेत्र की स्थिति यह है कि फी कस आमदनी 200 रुपये से भी कम है जबकि सारे देश की फी कस आमदनी का औसत 460 रुपये है। उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र सदा से उपेक्षित है हर तरह से पिछड़ा हुआ है हालांकि उत्तरप्रदेश की सरकार इन क्षेत्रों के विकास के लिए अपने तौर पर काफ़ी कर रही है। इस सदन में स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने दिये हुए आश्वासन के मुताबिक पटेल कमिशन की स्थापना की। पटेल कमिशन ने ऐसे पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार को सिफारिश व रिपोर्ट भी दी लेकिन पाकिस्तानी हमले के बाद केन्द्रीय सरकार को जो सहायता देनी थी वह बंद कर दी और फिर वह सिफारिशें अपनी जगह पर पड़ी हुई हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश के अन्दर क्षेत्रीय विकास की समस्याएं पैदा हो रही हैं और उस इलाके में कोई ऐसी गम्भीर स्थिति पैदा न हो कि दूसरे भागों की तरह मजबूर होकर अपने विकास के लिए उसे आन्दोलन करना पड़े और यह स्वीकार कर कि भारत सरकार और उत्तरप्रदेश की सरकार इन क्षेत्रों की निरन्तर उपेक्षा करती रही है क्या मैं जान सकता हूँ कि पटेल कमिशन की उन सिफारिशों को फिर लागू किया जायगा और उस के वास्ते कोई सरकार एक योजना बनायेगी और उसे कार्यान्वित करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : पटेल कमिशन ने जो रिपोर्ट बनाई उस में उस ने यह रिपोर्ट दी थी कि ऐसे अर्ध विकसित और पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास कैसे किया जाय। जब वह पंचवर्षीय योजना का पहला प्रारूप बना था तो उस में चूंकि बहुत सारे देश के भागों में इस स्ट्रैटिजी को लागू करना था उन को सैंटर से अलग अलग सहायता देकर सैंट्रल प्रोजेक्ट के रूप में रखना सम्भव नहीं हुआ होता। इसलिए प्लानिंग कमीशन ने उस समय यह सोचा अब चौथी पचवर्षीय योजना में इस स्ट्रैटिजी को जो उन्होंने बनाया जैसे कि खेती का या वहां सड़कों का अभाव है, सोशल इनफा स्ट्रक्चर या एग्रो इंडस्ट्रीज को बढ़ाना था तो उन बातों को प्लान में लाकर और सारे प्लान को स्ट्रैटिजी को ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए बना कर यह रूपरेखा बनाई गई है। यह पूर्वी यू पी में भी लागू होता है, उत्तरी बिहार में भी लागू होता है और दूसरे प्रदेशों के अर्धविकसित या कम विकसित क्षेत्रों में भी लागू होता है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं ने सप्लिमेंटरी सवाल एक खास ऐरिया के लिए पूछा था यह नहीं कि सारे देश के पिछड़े हुए इलाकों के पूरे चौखटे के अन्दर मैं ने जानना चाहा था जिसका कि मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। मेरा सप्लिमेंटरी सवाल यह था कि उस इलाके की बाबत विशेष रूप से पटेल कमिशन ने अपनी सिफारिशें दी हैं जिन्हें कि केन्द्रीय सरकार ने लागू

करना स्वीकार किया था। पाकिस्तानी हमले के बाद उसे अमल में लाना स्थगित कर दिया गया उन को क्या मंत्री महोदय द्वारा अमल में लाया जायगा ? यह ठीक है कि सारे देश के पिछड़े इलाकों के विकास की योजना है लेकिन जैसा मैं ने कहा यह स्पैसिफिक इलाका है जिस की कि बराबर उपेक्षा की जाती रही है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उस योजना को वहां पर लागू किया जायगा ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : माननीय सदस्य के इस कथन से हम सहमत हैं पूर्वी उत्तरप्रदेश के इस क्षेत्र में बहुत ही अधिक कठिनाई और गरीबी है। इस की बहुत आवश्यकता है कि वहां विशेष कार्यक्रम चालू हों और उस के लिए हमारी कोशिश भी है। लेकिन, इस समय मैं यह बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कह सकती हूं कि पटेल योजना वहां पर चल सकती है या नहीं। माननीय सदस्य को मालूम है कि हमारे साधन कितने सीमित हैं। अब उन को मद्देनजर रखते हुए हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इन क्षेत्रों की मदद हो जिससे कि वे ऊपर उठें और उन्नति करें।

The hon. Member has said something about giving special help to those States whose performance has been better. Naturally, one would like to help them to go ahead much faster but we must remember that there are historic reasons why certain areas developed faster and we have got the problem of disparity of backward regions. Therefore all these factors have to be balanced. Much as we would like to help a person who is making the best use of these facilities, we cannot really do so at the cost of those who have not had these facilities earlier and therefore, are not in a position today to make the best utilisation.

SHRI HEM BARUA : It is not a fact that the hon. Prime Minister wrote a letter to the National Development Council suggesting that population should not be the only basis for allocation of financial grants but economic needs must be the basis for allocattion of financial grants and that the N. D. C. rejected the suggestion of the Prime Minister and, secondly, is it not a fact that the Government of Assam whose budget this year showed a deficit of Rs. 50 crore has approached the Government for further allocation in the interest of the execution of the Fourth Plan because Assam is an underdeveloped State ?

SHRIMATI INDIRA GANDHI : I have expressed some views on this matter. But as the hon. Members know, the criteria for the allocations were decided by the Chief Ministers themselves taking all these points in view. Assam has asked for better allocation and so have all other States. All their problems are real ones and they have our fullest sympathy. The real question is one of limitation of resources. But all these matters will be discussed in the N. D. C.

SHRI HEM BARUA : She has not replied to the first part of my question as to whether she had written to the N. D. C. suggesting that not the population basis alone but also the economic needs of the States should be taken into consideration while making the financial allocations but the Chief Minister who were on the National Development Council rejected the proposal.

MR. SPEAKER : She has stated that.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि यूनियन टैरीटरी का प्लानिंग का खर्चा और उस के अपने साधन में जो फ़र्क होता है वह यूनियन टैरिटरी को दिया जाता है। तो क्या यह सच है कि हिमाचल को 66 करोड़ रु० तीसरी पंचवर्षीय योजना में मिला और उस के बाद 1966 में जितनी उस की आबादी थी उस से 110 प्रतिशत अधिक लोग और इतना ही क्षेत्र हिमाचल में शामिल हो गया है। अब जो सरकार ने प्लान भेजा है वह 150 करोड़ से ज्यादा का था लेकिन हमारी सरकार ने केवल 108 करोड़ रु० सैंक्शन किया

है। जब एक तरफ आप कहते हैं कि जो फर्क होता है वह हम अदा करेंगे, दूसरी ओर हमें स्टेट हुड नहीं दिया जाता है, और जब हम केन्द्र शासित प्रदेश हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो फर्क है इस फर्क को पूरा करने के लिये जितना हिमाचल सरकार ने पैसा मांगा है उतना देने के लिये आप विचार करेंगे ? अगर करेंगे तो उस का ब्यौरा कृपया दें ?

श्री ब० रा० भगत : प्लानिंग कमीशन इस पर भी विचार करेगा, दूसरे राज्यों की जो मांगें हैं उन सब को मिला जुला कर जितने हमारे रिसोर्सेज हैं उस के आधार पर जरूर विचार करेंगे।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। यूनियन टैरीटरी के बारे में बता दें। जो उन्होंने खुद कहा है उस के अनुसार हिमाचल के बारे में उन का क्या विचार है ?

श्री ब० रा० भगत : यूनियन टैरीटरी के बारे में जो सिफारिश है और जो मंजूर की गई है, उन का जो डेफिसिट होता है प्लान में उस को केन्द्रीय सरकार पूरा करदे। माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा था उन्होंने जो योजना बनायी है, उन की जो मांगे हैं, उन्होंने जो मांग की है, वह सब मन्जूर कर लेंगे कि नहीं ? मैंने कहा कि उन की मांगें जो हैं उन पर विचार होगा, और केन्द्र के पास जितने साधन हैं, और दूसरे राज्यों की जो मांगें हैं उन सब को सम्मिलित रूप से विचार कर के फैसला लिया जायगा।

श्री महाराज सिंह भारती : मैं जानना चाहता हूं कि जिन प्रदेशों में विषय तो प्रदेश का है और चीज वह ऐसी है जो पूरे देश के काम आ सकती है, जैसे बिजली है वह विषय प्रदेश का है वह पैदा करेगा, उत्तर प्रदेश में हिमाचल में बहुत बड़ी शक्ति है ढाई करोड़ किलोवाट बिजली वह दे सकता है, एक ग्रिड भी आप बनाने जा रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे प्रदेश में जहां से दूसरी जगह भी हम वह चीज दे सकते हैं, और विषय वह उसी प्रदेश का है, तो खासतौर से क्या हम उन को प्लान के अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने जा रहे हैं ?

श्री ब० रा० भगत : प्लान के अतिरिक्त देने का सवाल नहीं है। प्लान के अन्दर ही देने का सवाल है।

श्री महाराज सिंह भारती : प्लान की सीलिंग बढ़ाने का सवाल है, उस को बढ़ायेंगे कि नहीं ?

श्री ब० रा० भगत : साधन होंगे तो जरूर बढ़ायेंगे।

श्री शिव नारायण : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय बली राम भगत जी जवाब दे रहे हैं। (**व्यवधान**) "तमीजे न बाशद कमन्दे हवा, उलटने की रोटी उलट दी तवा"। मेरा सवाल यह है कि माननीय बली राम भगत जी मंत्री थे वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णामचारी के साथ और तब सरकार ने जो ऐश्योरेंस दिया था वह पूरा न करें, तो मैं जानना चाहता हूं कि पटेल कमीशन ने बलिया और बस्ती को ऐश्योरेंस दिया था, और टी० टी० कृष्णामचारी साहब ने मुझ से कहा कि डिबेट में इन्टरवीन न करो, तो मैं कहां दरख्वास्त करूंगा। हमारे पास छोटी लाइन है, और न ट्यूब वैल है, न बिजली है इसीलिये कोई व्यापारी पूर्वी यू० पी० में जाता नहीं है, सरकार के पास रिपोर्ट है कि भारत का सब से पिछड़ा हुआ वह पोरशन है, उस के लिये कोई विशेष प्रबन्ध करेंगे। और तीन प्लान में से एक प्लान का पैसा नहीं मिला। हर साल हमारे चीफ मिनिस्टर मांग करते है, तो मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस का डेफ़िनेट जवाब दे कि हम को क्या देगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्य यहां नहीं थे, यही प्रश्न उन के पीछे बैठने वाले माननीय सदस्य ने किया था ।

श्री शिव नारायण : इन्होंने ऐश्योरेंस दिया था इस हाउस के अन्दर, टी० टी० कृष्णामचारी फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उन्हों ने कोई व्यक्तिगत आश्वासन नहीं दिया था, सरकार की तरफ से दिया था । हमारे सामने कठिनाइयां आयीं, युद्ध हुआ, लेकिन हम पूरे तौर से सजग हैं कि उस जिले के लिये क्या करना चाहिये । मुझे मालूम है कि बलिया जिला एक देश भक्त जिला है, वहां से देश भक्त निकले हैं, देश सेवा करने वाले निकले हैं, और इस समय उस जिले के लोग बहुत दूर दूर जा कर देश का काम कर रहे हैं । इसलिये हम सब का कर्तव्य है कि हम उन की सहायता करें ।

Some Hon. Members *rose–*

MR. SPEAKER : There are still 20 or 30 members who want to ask questions. We have already spent half an hour on this. I do not know how I can satisfy everybody. After all, the demands pertaining to planning will be coming up and the hon. members can speak at that time.

Now I go to the next Question. Mr. Kanwar Lal Gupta.

राष्ट्रीय आय और औद्योगिक उत्पादन संबधी लक्ष्य

*724. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय और औद्योगिक उत्पादन के लिए नियत किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है तथा ये लक्ष्य कहां तक प्राप्त किए गए हैं; और

(ख) लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण क्या हैं ?

उप-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) और (ख). "चौथी पंचवर्षीय योजना-प्रारंभिक रूपरेखा 1966" में पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई है । इसके अलावा, दूसरी तथा तीसरी योजना दस्तावेज तथा समय समय पर जो विभिन्न समीक्षाएं प्रकाशित की गई हैं उनमें योजनाओं की प्रगति दर्शायी गई है । चौथी योजना के प्रारूप की रूपरेखा के अध्याय 1 और 14 की ओर विशेष रूप से और सभा पटल पर प्रस्तुत विवरण में अंकित अन्य प्रकाशनों की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

विवरण

"राष्ट्रीय आय और औद्योगिक उत्पादन संबंधी" श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा दिनांक 26 मार्च, 1969 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 724 के उत्तर में सभापटल पर रखा गया विवरण ।

1. **पहली पंचवर्षीय योजना**

1. पहली पंचवर्षीय योजना–प्रगति प्रतिवेदन 1951-52 और 1952-53 (1953)

2. पहली पंचवर्षीय योजना-प्रगति प्रतिवेदन 1953-54 (1954)

3. पहली पंचवर्षीय योजना-प्रगति प्रतिवेदन अप्रैल-सितम्बर, 1954 (1955)

4. पहली पंचवर्षीय योजना-प्रगति प्रतिवेदन 1954-555 (1956)

5. पहली पंचवर्षीय योजना की समीक्षा (1957)

2. दूसरी पंचवर्षीय योजना

1. दूसरी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज

2. दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन तथा संभावनाएं (1958)

3. दूसरी पंचवर्षीय योजना का पुन-र्मूल्यांकन : एक सार (1958)

4. दूसरी पंचवर्षीय योजना-प्रगति प्रतिवे-दन, 1958-59 (1960)

5. दूसरी पंचवर्षीय योजना-प्रगति प्रतिवे-दन 1959-60 (1962)

3. तीसरी पंचवर्षीय योजना

1. तीसरी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज

2. तीसरी पंचवर्षीय योजना--प्रगति प्रतिवे-दन 1961-62 (1963)

3. तीसरी पंचवर्षीय योजना--मध्यावधि मूल्यांकन (1963)

4. तीसरी योजना प्रगति प्रतिवेदन 1963-65

5. चौथी पंचवर्षीय योजना--प्रारंभिक रूपरेखा

4. तीन पंचवर्षीय योजनाएं एक साथ

1. चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभिक रूपरेखा ।

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, आप देखिये कि एक स्कूल का टीचर जिस प्रकार बच्चों को किताबें पढ़ाकर हुक्का पीने लगता है उसी तरह से 16 किताबों का रेफ़रेंस इस जवाब में दिया गया है। मैं ने सवाल पूछा था।

"the details of the targets fixed for the national income and industrial production."

दो बातों के बारे में मैं ने पूछा था कि क्या-क्या टारगेट थे और कितने कितने पूरे हुए। इतने लम्बे चौडे जवाब की जरूरत नहीं हैं। इन्हों ने तो किताबों को रेफ़रेंस दे दिया। तो जो मेरा सवाल था कि क्या क्या टार्गेट थे, क्या क्या पूरे हुए, क्यों नहीं पूरे हुए, इस का जवाब दें तो मैं आगे सवाल करूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किताबें अगर पढ़ना है तो जवाब देने की क्या जरूरत है।

श्री ब० रा० भगत : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा का यह नियम है कि जो पब्लिश्ड डाकु-मेंट्स हैं उन के बारे में ऐसा विवरण हम दे सकते हैं। यह कहते हैं कि टार्गेट क्या थे और वे कहां तक प्राप्त किये गये और अगर नहीं किये गये तो उस के क्या कारण हैं। इन सब की सूचना दीजिये। तो यह एक लम्बा विवरण देना होगा। इसलिये जनरल सवाल का जनरल जवाब दिया। माननीय सदस्य स्पेसिफिक सवाल पूछें तो उस का स्पेसिफिक जवाब दूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा सवाल यह था नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्शन का क्या टार्गेट था। साथ में यह भी था कि अगर पूरा नहीं हुआ तो क्यों पूरा नहीं हुआ।

श्री ब० रा० भगत : फर्स्ट प्लैन में नेशनल इनकम का टार्गेट था 12 प्रतिशत ग्रोथ का, ऐचीवमेंट हुआ 18.4 प्रतिशत, सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन में टार्गेट ग्रोथ का था 25 प्रतिशत और ऐचीवमेंट हुआ 21.5 प्रतिशत, थर्ड फाइव इअर प्लैन में ग्रोथ का टार्गेट था 30 प्रतिशत और ऐचीवमेंट हुआ 15.2 प्रतिशत।

श्री कंवर लाल गुप्त : प्रोडक्शन भी तो बतलाइये।

श्री ब० रा० भगत : 1966-67 में नेशनल इनकम की ग्रोथ हुई 2 प्रतिशत, 1967-68 में नेशनल इनकम की ग्रोथ हुई 8.9 प्रतिशत। फर्स्ट प्लैन में प्रोडक्शन....

SHRI R. D. BHANDARE : This is general information. This is avilable in the books.

MR. SPEAKER : If the information is available in the published books, you do not ask a question.

श्री ब० रा० भगत : फर्स्ट प्लैन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा 25.1 प्रतिशत, सेकेन्ड प्लैन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा 41.7 प्रतिशत, थर्ड प्लैन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा 44.2 प्रतिशत। Over 16 years industrial production has increased by 165.7%.

श्री कंवर लाल गुप्त : रीजन्स तो बतलाइये।

MR. SPEAKER : If you do not want to ask a question, I will go to the next question.

श्री कंवर लाल गुप्त : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि थर्ड प्लैन के एक्सपेन्सेज जो तय किये गये थे उन से ज्यादा खर्च किया गया और टार्गेट जो थे वह पूरे नहीं हुए। इसका कारण यह है कि उन की प्लैन फाल्टी थी, प्रायारिटी ठीक नहीं थीं, ओवर-ऐम्बिशस प्लैन थी, करप्ट मशीनरी थी और कोई क्लियर कट आब्जेक्टिव नहीं था। इस के अलावा आप को मालूम है कि जो आदमी रूरल एरियाज में रहते हैं उन में से 5 प्रतिशत केवल 6 रु० महीना खर्च करते हैं। आज 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन को रोटी नहीं मिलती। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह जो प्लैन आगे बनाने वाले हैं उस में वह किसी नैशनलमिनिमम इनकम की गारन्टी देंगे, और कोई फिजिकल टार्गेट होगा, जिस में हर एक आदमी को रोटी मिले या पीने का पानी मिले ?

श्री ब० रा० भगत : जो कुछ माननीय सदस्य ने बतलाया है वह मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इस बीच में हिन्दुस्तान आगे बढ़ा है। यह बात जरूर है कि दिक्कतें हमारे सामने आई हैं, हम जो प्रगति करना चाहते थे उस में बीच बीच में रुकावटें आई हैं, लेकिन आज देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत है और अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अगर आदमी आंख बन्द कर के न देखे तो मालूम हो सकता है, माननीय सदस्य भी देखेंगे तो पता चलेगा कि देश आगे बढ़ा है और हमारी योजना सफलीभूत हो रही है। हां, यह बात सही है कि बहुत से क्षेत्रों में गरीबी है, यह बात भी सही है कि जो सब से गरीब लोग हैं उन की आमदनी भी कम है और खर्च भी कम है, पीने का पानी गांवों में बहुत नहीं है। यह बात भी सही है कि जो लोगों की कम से कम जरूरतें हैं उन के लिये हम ऐसी योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन को नेशनल मिनिमम इनकम मिले, उन की गरीबी दूर हो सके और इन बातों को हम आगे बढ़ा सकें।

श्री कंवर लाल गुप्त : इस सरकार ने तीनो पंचवर्षीय योजनाओं में इस बात की कोशिश की कि मोनोपोलीज खत्म हो, लेकिन आज 63 प्रतिशत खेती पर काम करने वाले लोग ऐसे हैं जो 5 एकड़ या उस से नीचे के मालिक हैं और 11 प्रतिशत ऐसे हैं जो कि लैंडलार्ड हैं जिन के पास 70 प्रतिशत से ज्यादा भूमि है। सरकार ने पंच-वर्षीय योजना में जो खर्च किया है उस में 80 परसेंट तो इन 11 परसेंट लोगों पर किया है और 20 परसेंट 89 परसेंट लोगों पर किया है। इसी तरह से इंडस्ट्रीज के बारे में मोनोपोली कमिश्न की रिपोर्ट है कि 75 परिवार ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर के 45 परसेंट इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करते हैं। मंत्री महोदय ने प्लैन में जो कुछ तय किया था उस का नतीजा कुछ और निकला। मैं जानना चाहता हूं कि मोनोपोली खत्म हो और छोटे लोगों तक उस का लाभ पहुंचे, उस के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि मोनोपोली को खत्म करने के लिये हम को जोरदार कदम उठाना चाहिये। जो मोनोपोलीज बिल आया है वह इसी रास्ते पर एक कदम है जहां तक अरबन क्षेत्र का सवाल है इंडस्ट्रियल पालिसी और एकानमिक पालिसी इसी आधार पर है कि मोनोपोली बनने के बाद खत्म न हो साथ साथ कंसेंट्रेशन भी न बढ़े। इसी लिये हमारा डिस्पर्सल का प्रोग्राम है। जहां तक हमारी एकानमिक फोर्सेज का सवाल है हमारी सभी नीतियों का यही आजेक्टिव है। जब इंडस्ट्रीज बढ़ती है तब कंसेंट्रेशन भी बढ़ता है, इसलिए सोशल आजेक्टिव के कारण दूसरी चीजों को भी लाना पड़ता है और इस के लिये हम सजग हैं। जहां तक रूरल क्षेत्र का सवाल है, यह बात हम को मालूम है कि 5 एकड़ या उस से कम वाले किसान ज्यादा हैं।

श्री शिव नारायण : विकेन्द्रीकरण के बारे में आप का क्या कहना है ?

श्री ब० रा भगत : विकेन्द्रीकरण करने की हमारी नीति है और हम चाहते हैं कि विकेन्द्रीकरण हो।

खेती के बारे में समस्या कुछ ज्यादा उठ खड़ी हुई है क्योंकि अच्छे पैमाने पर पानी, खाद या बीज का इन्तजाम करना है। गांवों में जो अच्छे किसान हैं, बड़े किसान हैं उन को फायदा ज्यादा होता है, साथ साथ गांवों में सोशल और पोलिटिकल कांशमनेस ज्यादा बढ़ रही है इस लिये हमें चाहिये कि हम लोग अपनी योजनाओं में ड्राई फार्मिंग एरिया में छोटे किसानों के लिये और दूसरे लैंडलेस लोगों के लिये ऐसी नीति बनायें जिस से उन की आमदनी बढ़े और उनको मदद कर के हम आगे बढ़ा सकें।

श्री सीताराम केसरी : आर्थिक मोनोपोली और इंडस्ट्रियल मोनोपोली की जो बात है, उस के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने कहा कि छोटे छोटे उद्योग धन्धों और छोटे किसानों के लिये ऐसा होना चाहिये कि वह तरक्की करें। मैं जानना चाहता हूँ कि इस को मद्दे नजर रखते हुए कि कभी कभी व्यक्तियों की मोनोपोली ज्यादा हो जाती है, क्या मंत्री महोदय कोई ऐसी घोषणा करेंगे कि राष्ट्रीय आय का इस सीमा से ज्यादा अंश किसी के पास नहीं होना चाहिये ?

श्री ब० रा० भगत : यह एक सजेशन है और इस पर भी विचार होता रहता है।

SHRI LOBO PRABHU : As the Minister must be aware, while the financial targets of the three plans have been maintained the physical targets have not been maintained. The reason for this may be, first, there was an under-estimate of the cost of the projects. Secondly, there was inflation. Thirdly, there was bad implementation. I would like to ask a specific question. I want to know whether the Planning Commission, the Chairman of the Planning Commission is also present here, has compared these deficiencies. What conclusions have they arrived at so that in the fourth plan the same mistakes are not repeated ?

SHRI B. R. BHAGAT : Based on our experience we have to prepare the fourth plan. We will try to get over all the deficiencies that the hon. Member has mentioned.

श्री तुलशी दास जाधव : इस देश में जिन लोगों के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है उन को फर्स्ट प्लैन, सेकेन्ड प्लैन और थर्ड प्लैन में गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ है, जैसे कि देहात के लोग हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन्तजाम किया गया है जिस से सिक्योरिटी न होने पर भी वह अपना उत्पादन बढ़ा सकें, जैसे भैंस रखना है, गाय रखना है ?

श्री ब०रा० भगत: यह बात सही है कि अभी जो हमारा क्रेडिट सिस्टम है उस में कर्ज उन्हें ही मिलता है जिन की कोई सिक्योरिटी है, बैंक क्रेडिट है या कोआपरेटिव क्रेडिट है वह उन को ही मिलता है जो अच्छे किसान हैं। यह

कमी है हमारे कर्ज के सिस्टम में और हम इस विचार में लगे हुए हैं कि इस कमी को कैसे पूरा किया जाये ।

श्री मधु लिमये : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि राष्ट्रीय आमदनी और औद्योगिक पैदावार में जो इजाफा हुआ है उसके साथ साथ राष्ट्रीय आमदनी का जो बटवारा होता है, क्या उस में असमानता और गैर बराबरी बढ़ती नहीं जा रही है ? महलनोबीस कमेटी की रपट आपके सामने है, नैशनल सैम्पल की सर्वे की रिपोर्ट आपके सामने है । औद्योगिक पैदावार के बारे में भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमीरों के उपभोग की जो चीजें होती हैं जैसे एयर कंडीशनर वगैरह हैं उनकी पैदावार तो बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन साधारण जनता के उपभोग में जो चीजें आती है उनकी पैदावार उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है । मैं जानना चाहता हूँ कि चौथी योजना में सरकार कौन सी नीतियां अपनाने वाली है जिससे यह गैर बराबरी कम हो ?

श्री जार्ज फरनेंडीस : छोटी मोटर कार ।

श्री ब० रा० भगत : चौथी योजना में इन बातों का खयाल किया जाएगा कि जहां तक सम्भव हो यह कमी दूर हो...

श्री मधु लिमये : कौन सी नीति अपनाने जा रहे हैं....

श्री ब० रा० भगत : योजना आपके सामने आएगी और उस पर बहस भी होगा । तब इसका आपको पता चल जाएगा । आम तौर से यह सही है कि जो लग्जरी गुड्ज हैं उनका उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उन पर कर भी बढ़ रहा है । उन पर ज्यादा एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाती है ताकि जो उनका उपभोग करें उनकी बिक्री से सरकार को आमदनी भी हो । जो आम जनता की जरूरत की चीजें हैं जैसे अनाज है या कपड़ा है या और भी दूसरी चीजें है उनका उत्पादन बढ़ाने में ज्यादा नेशनल रिसोर्सिस लगें, इसकी कोशिश की जाएगी ।

श्री रणधीर सिंह : मुल्क की आमदनी तभी बढ़ी हुई मैं समझूंगा जब देहात वालों की आमदनी बढ़ेगी जहां पर कि अस्सी फी सदी लोग रहते हैं । जब इस अस्सी फी आबादी की आमदनी बढ़ेगी तभी मुल्क की आमदनी भी बढ़ी है, ऐसा मैं समझूंगा । आज देखने में आता है कि जितने बड़े बड़े कारखाने हैं, मनतें हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वे सब शहरों में लग रही हैं । जरूरत इस बात की है कि छोटे कारखाने, काटेज इंडस्ट्रीज, कल पुर्जों के रूप में देहातों में खोले जायें । मैं जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट की वाजं पालिसि क्या है । क्या वह शहरों के बजाय देहातों में छोटे छोटे कारखाने खोलना चाहती है ताकि गांव का जो हरिजन है, जो बैकवर्ड क्लासिस के लोग हैं या गरीब लोग हैं उनको काम मिले और आबादी का सारा बोझ खेत पर ही न पड़ जाए ? क्या इस तरह से वहां जो बेरोजगारी है, उसको दूर करने के लिए सरकार चौथी योजना में कुछ व्यवस्था करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : चौथी योजना में विकेन्द्रीयकरण हो, इंडस्ट्रीज का डिसपर्सल गावों की तरफ हो और वे बडे कसबों की तरफ जायें, इस पर ध्यान दिया जाएगा ।

SHRI S. KUNDU : The hon. Minister said that in the First Five Year Plan the target of national income which was fixed was exceeded. At thes ame he time also said that in the Third Five Year Plan the target that was fixed was reduced to half. May I know whether he has made any study of this and, if so, whether he can inform the House if it is not true that during the corresponding period some countries in Asia and like Japan had a steady rise of national income per year at 11 per cent in some years; and if that is so, why during this corresponding period our target fixed was reduced by half ?

SHRI B. R. BHAGAT : I discussed this matter with a leading, top economist in Japan and said that more than economic factors, the sub-conscious factors are responsible for this rise and the sub-conscious factors are discipline, patriotism, dedication and hard work. If we have these....*(interruptions)*.

श्री जार्ज फारनेंडीस : आप में से किसी में भी नहीं है । जहां शर्म लगनी चाहिये वहां आप हंस रहे हैं ।

SHRI BEDABRATA BARUA : In addition to the factors that have been mentioned by the Hon. Minister, is it not a fact that so far as targets of industrial production are concerned, they are bound to fall short if the plant and machinery are not utilised to their full capacity ? Yesterday, we were surprised to learn from the Industries Minister that the demand position or the order placed on the public enterprises is not very clear. Therefore, may I know from the Hon. Minister whether this has been provided for in the Fourth Plan that the capacity that has been created for heavy machinery will be utilised and if not whether he will make a categorical and definite provision for utilisation of the capacity for heavy machinery production ?

SHRI B. R. BHAGAT : The utilisation of the surplus or unutilised capacity in the industrial sector is the first charge on the national budget. This strategy has been accepted in the Fourth Plan.

श्री स०मो० बनर्जी : राष्ट्रीय आमदनी बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है यह ठीक है । लेकिन लोगों की हालत सुधरी नहीं है । इस वास्ते जो सवाल हमसे लोग किया करते हैं अकसर वही सवाल मैं आप से पूछना चाहता हूं । हम से यह सवाल वे करते हैं :

जिस देश में गंगा बहती है उस
देश का पौधा सूखा क्यों ?
जो देश है वीर जवानों का उस
देश का बचपन बूढ़ा क्यों ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा वितरण हम चाहते हैं वैसा नहीं हुआ है, यह हमें मालूम है ।

Working of Textile Mills taken over by the Textile Corporation of India

*727. SHRI GEORGE FERNANDES : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the number of cotton textile mills taken over by the Textile Corporation of India;

(b) the total number of workers working in these mills;

(c) the terms and conditions under which the mills have been taken over;

(d) whether there has been any improvement in the profitability of these mills since the Corporation took them over; and

(e) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI B. R. BHAGAT) : (a) to (c). The New Maneckchock Spinning and Weaving Mills Ltd., Ahmedabad was taken over by the Government in February, 1969. The Gujarat State Textile Corporation, which has been appointed as Authorised Controller, will be assisted by the National Textile Corporation in the running of the mill. The number of workers in the mill is about 1700.

(d) and (e). It is too early to make any assessment.

श्री जार्ज फरनेंडीस : इस वक्त अस्सी मिलें जिनमें करीब अस्सी हजार कर्मचारी काम करते हैं बन्द पड़ी हैं । पिछले पांच बरसों से ये मिलें बन्द हैं । चूंकि वे बन्द हुई इस वास्ते इस सदन में और इस सदन के बाहर भी आवाज उठी थी और उसी का यह नतीजा था कि टैक्सटाइल कारपोरेशन की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार को एक विधेयक लाना पड़ा । मन्त्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि सिर्फ

एक मिल को अब तक इन लोगों ने अपने हाथ में लिया है। मेरा प्रश्न यह है कि जहां अस्सी मिलें बन्द हैं, वहां इन मिलों को अपने हाथ में इस कारपोरेशन द्वारा क्यों नहीं लिया जाता है और उनको चलाने की क्यों व्यवस्था नहीं की जाती है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस बारे में सोच रहे हैं या कोई कदम उठा रहे हैं और अगर उठा रहे हैं, तो क्या उसका विवरण आप इस सदन में पेश करेंगे?

श्री ब० रा० भगत: विधेयक की मार्फत जो प्रोसीजर अपनाया गया था उस में यह है कि पहले तो उनका इनवैस्टीगेशन हो, उनकी हालत को देखा जाएगा कि वे कैसी हैं, उसके बाद अथोराइज्ड कंट्रोलर बहाल होंगे, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आएगी कि इनका रेनोवेशन हो या लिक्विडे न हो या करेंट रनिंग स्टेज पर इन को चलाया जाए। बारह मिलें हैं जिनके केसिस कारपोरेशन अभी एग्जेमिन कर रही है। तीन मिलों के केस में काफी प्रगति हो चुकी है

श्री जार्ज फरनेंडीस: नाम बताइये।

श्री स० मो० बनर्जी: कानपुर में कुछ नहीं हुआ है। क्वीन विक्टोरिया मिल को ले भी लिया है फिर भी कुछ नहीं हुआ है।

श्री ब०रा० भगत: तीन मिलों के नाम है, माडल मिल लिमिटेड, नागपुर, आर०एस०आर० जी मोटा स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल लिमिटेड अकोला और प्रताप वीविंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, आलमनार। उम्मीद की जाती है कि और भी मिलों के केसिस पर विचार करके तेजी से प्रगति होगी।

श्री जार्ज फरनेंडीस: अभी महाराष्ट्र सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिस का नाम कोगेकार कमेटी। इस कमेटी की रिपोर्ट में से एक वाक्य मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं:

> "Out of the 74 mills in Maharashtra accounting for 87 per cent of installed spindles and 86 per cent of installed looms in the State studied by the committee 43 mills have neglected maintenance and modernisation of their machinery.....

इसका मतलब यह है कि जो मिलें अभी भी निजी क्षेत्र में हैं वे बहुत तेजी से इसी रास्ते पर चल रही हैं। जो अस्सी मिलें बन्द हैं उसका मतलब होता है कि हिन्दुस्तान की कुल जो मिलें हैं उसका बारह प्रतिशत। एक तरफ तो जो मिलें बन्द पड़ी हुई हैं उनको लेने में आप असमर्थ है और दूसरी तरफ जो ये मिलें हैं और जो आज भी मिसमैनेजमेंट पड़ी हुई है ऐसा सरकारी कमेटी अलग अलग सूत्रों में कह रही हैं, तो यह जो हालत है यह और न बिगड़े, इसके लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं?

श्री ब० रा० भगत: माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उस पर हम विचार कर रहे है। बन्द मिलो को चलाने में काफी कठिनाइयां हो रही हैं, क्योंकि उन में बहुत सारी मिलें ऐसी हैं जो मोडर्नाइजेशन न होने के कारण या मैनेजमेंट की कमी के कारण बन्द है। कुछ मिलें फाइनेन्शल या दूसरी दिक्कतों के कारण बन्द हैं। इस लिये इस इण्डस्ट्री को प्रायोरिटी इंडस्ट्री बना कर यह कोशिश की गई है कि जिन मिलों के पास रूपया है और वे उसको लगायें तो उनको मोडर्नाइज करने की सुविधा दी जाय।

दूसरे—यह विचार किया जा रहा है कि भविष्य में मैनेजमेंट की कमी के कारण या मोडर्नाइजेशन की कमी के कारण मिलें बन्द न हों—इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जांय, यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्रीमती जयाबेन शाह: अध्यक्ष महोदय, हमारी टैक्सटाइल इण्डस्ट्री बहुत सालों से हमारी इण्डस्ट्री रही है, लेकिन मिल-ओनर्स ने उस में से ज्यादा से ज्यादा प्राफिट

लेकर उनको स्क्रैप करके छोड़ दिया है, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मिलें बन्द होती जा रही हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि आइन्दा जो स्थिति पैदा होने वाली है उस को दृष्टि में रखते हुए वह क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। जो कर्मचारी बेकार हो गये हैं और भविष्य में और ज्यादा होने वाले हैं, उन के लिये क्या इन्तजाम किया जायगा ? जिन मिलों को सरकार ने लेकर अथोराइज्ड कन्ट्रोलर नियुक्त किया है, वहां भी कार्यवाही तेजी से नहीं चल रही है। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि जो नई मिलें बन्द होने वाली हैं उनके लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : पहले सवाल का मैं जवाब दे चुका हूं– इस पर गौर किया जा रहा है।

श्रीमती जयाबेन शाह : कन्ट्रोलर के बारे में बतलाइये, नई मिलों के बारे में बतलाइये।

श्री ब० रा० भगत : अथोराइज्ड कन्ट्रोलर्स से रिपोर्ट मांगी जा रही हैं....

श्रीमती जयाबेन शाह : 6 महीने हो गये।

श्री ब० रा० भगत : जिन अथोराइज्ड कन्ट्रोलर्स की रिपोर्ट नहीं आई है, उन को ताकीद की गई है कि जल्द भेजें।

SHRI S. K. TAPURIAH : On various occasions, during discussions in this House and elsewhere many of us had voiced the feeling that the Textile Corporation of India would not turn out to be the magic wand which the then Commerce Minister Shri Dinesh Singh had dreamt it to be. As the hon. Minister has just now told us, they have taken over only one mill. This means that either they have themselves lost faith in this scheme and they feel that this corporation is not the panacea for this malady or they are working slowly deliberately in order to see that they do not have to commit themselves into this scheme which will be a failure. In view of the other provisions that the hon. Minister detailed a few minutes back, and in view of the fact that so many mills are closed, throwing out nearly 80,000 worker, may I know whether Government have specified any time-limit within which those reports must come ? This question of taking over of the Manekchock mills smells of some thing bad, because there are mills which have remained closed for a longer period, for four or five years and more, but this mill has been closed only recently. May I know the name of the mill which has remained closed for the longest period, the period for which this particular mill has remained closed, and the reason why they decided to take this recently closed mill first ?

SHRI B. R. BHAGAT : Nobody should imagine that this corporation will be a magic wand which will end all problems.

SHRI S. K. TAPURIAH : The hon. Minister had imagined, and we tried to disillusion him.

SHRI B. R. BHAGAT : During the coming years, of the 13 mills that are under consideration, the Textile Corporation may be able to take only a part of them, perhaps only 7 or 8 or few more. This aspect of modernisation of the textile industry is not only long overdue but it is a clossal problem involving a lot of finances and other problems, and this matter has to be seriously considered, and our attention is engaged on this question.

As for the name of the mill which has been under closure the longest, I require notice as I do not have the information with me at the moment.

SHRI S. K. TAPURIAH : Has any time limit been set for the surveys?

SHRI B. R. BHAGAT : We are trying to do it. These 13 mills are on hand now.

श्री सु०कु० तापड़िया : कोई टाइम-लिमिट दिया है–साल, 6 महीने, 3 महीने–क्या कोई स्पेसिफाइड पीरियड दिया है ?

SHRI B. R. BHAGAT : We will decide about it during the next few months.

श्री अचल सिंह : पिछले 10 वर्षों से मैं निरन्तर कामर्स मिनिस्टर साहब से कह रहा हूँ- आगरा में तीन सूत की मिलें बन्द पड़ी हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन को चलाया जायगा या वैसी ही बन्द पड़ी रहेंगी?

श्री ब० रा० भगत उन मिलों के लिये भी वही तरीका अपनाया जायगा जो दूसरी मिलों के लिये है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी जब टेक्सटाइल कारपोरेशन कायम करने के लिये सदन में चर्चा हो रही थी, तब श्री कुरेशी महोदय ने कहा था कि कारपोरेशन सभी बीमार मिलों को लेने के लिये नहीं बनाया जा रहा है। क्या यह बात सही है या सरकार इस के बारे में पुनर्विचार कर रही है? अगर मिलों को सरकार नहीं लेगी तो इन मिलों को कौन चलायेगा ?

श्री ब० रा० भगत बहुत सारी ऐसी मिलें हैं जो चलाई नहीं जा सकती है, इतनी आउट-डेटेड हो चुकी हैं कि उन के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिये। जो कभी चल ही नहीं सकतीं, इकानामिक नहीं हो सकतीं, उन मिलों को यह कारपोरेशन ले ले-- यह उचित नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसी मिलें हैं जिनकी लिक्वीडेशन एक्ट के अण्डर प्रोसीडिंग्ज चल रही हैं, उनको चलाने के लिये अगर कोई खरीदने को तैयार होगा, तब तो ठीक है, वरना उस दाम पर सरकार खरीद लेगी। कुछ मिलें हैं जिनका मोडर्नाइजेशन किया जा सकता है ऐसी और जो रूपया उनमें लगेगा, उससे रिटर्न आयेगा, उन मिलों को ले लिया जायगा। इसके लिये एक तरीका बनाया गया है, उस के अन्तर्गत जिनको लिया जा सकता है उन को लिया जायगा।

SHRI TENNETI VISWANATHAM : The Minister has stated that many mills are outdated. The fact is that even dress is becoming outdated a little and our textile industry is losing because of competiton in the whole of Asia. Therefore, instead of trying to take over sick mills, will he get the capital structure reorganised completely and machinery revalued and hand over whatever is exiting to the workers to be run on a co-operative basis? Will he do that instead of indulging in this futile exercise of the Textile Corporation trying to take them over and running them ?

SHRI B. R. BHAGAT : Does he mean that the mills should be handed over to the workers to be run?

SHRI TENNETI VISWANATHAM : As far as possible.

SHRI B. R. BHAGAT : If there is any such scheme, we will consider it.

SHRI MANUBHAI PATEL : In the last session, one definite suggestion was made regarding the Baroda Mills which the owners were trying to send under liquidation. Government were requested to appoint an authorised controller. The Deputy Minister assured us that the process was being gone through. One year has already passed. I would like to know whether the authorised controller has been appointed for these mills, whether the Corporation has taken it over or is allowing it to go into liquidation ?

SHRI B. R. BHAGAT : I will look into it; I do not have the information with me now.

SHRI RANGA : During the last two or three years, there have been many occasions when the Coimbatore textile mills were in great trouble. They had to approach the Madras Government and we were told that Government was in touch with the Government of India asking the latter to strengthen their efforts to help the Coimbatore textile industry. Has anything been done in that direction ? Have Government any proposal to help the Coimbatore textile industry ?

SHRI B.R. BHAGAT: This Corporation is entrusted at the moment with mils which

are closed, known as sick mills. As for the other, I do not have information at the moment. I will look into it.

श्री एस० एम० जोशी :अध्यक्ष महोदय, जब कभी कोई बड़ी मिल बन्द हो जाती है और उस को लेने के लिये मजदूरों की तरफ़ से दरख्वास्त आती है और अगर कोई क्रेडिटर कोर्ट में जाकर लिक्वीडेशन प्रोसीडिंग्ज शुरू कर देता है तो हम को कहा जाता है कि जब तक प्रोसीडिंग्ज खत्म नहीं हो जाती, तब तक मिल को नहीं ले सकते हैं। जैसे बम्बई की एडवर्ड मिल बहुत दिनों से बन्द थी, उस का मामला कोर्ट में पड़ा है, इस लिये हम उस को ले नहीं सकते हैं। क्या सरकार इस के बारे में सोचने की कोशिश करेगी कि क्योंकि जब आप लेने की कोशिश करेंगे तभी कोई आदमी, क्रेडिटर, कोर्ट में जा सकता है और फिर जो हमारी नीति है उसको हम अमल में नहीं ला सकते हैं-इसलिए क्या सरकार कोई कानून लाने या अन्य प्रबन्ध करने की बात सोच रही है ?

श्री ब० रा० भगत : अभी भी जो प्रोसीजर है उसकी मातहत किसी मिल को लेने के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ता है। अगर कोई क्रेडिटर इस तरह से रुकावट डालने की बात करता है, कोर्ट में जाता है तो फिर स्टेट गवर्नमेन्ट या केन्द्रीय सरकार की ओर से अगर कोई कार्यवाही होगी भी तो वह कानूनी कार्यवाही ही होगी, उसके लिए कोर्ट में ही जाना पड़ेगा।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : आप कानपुर की न्यू विक्टोरिया मिल के बारे में भी बताइये जिसको कि आपने पहले लेने के लिए तय किया था लेकिन अभी तक नहीं लिया है।

श्री ब० रा० भगत : उसको हम देखेंगे।

SHORT NOTICE QUESTION

Gherao of General Manager of South Eastern Railway

\+

SNQ. 10. SHRI KANWAR LAL GUPTA :
SHRI NARAIN SWARUP SHARMA :
SHRI SHRI CHAND GOYAL :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the General Manager of the South Eastern Railway was gheraoed by some railway employees along with a Member of Parliament; and

(b) the steps Government propose to take to check such incidents ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI R. L. CHATURVEDI) : (a) Yes, Sir.

(b) Since this is a law and order matter, we brought it to the notice of the concerned State Government

श्री कंवर लाल गुप्त: अध्यक्ष महोदय, सरकार को एक माडल एम्प्लायर बनना चाहिए, उसके अन्तर्गत जो कर्मचारी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधायें देनी चाहिए। इसके सम्बन्ध में वे हड़ताल भी कर सकते हैं, यह उनका हक है लेकिन जहांतक घेराव की बात है, हम उसको ऐन्टीनेशनल समझते हैं और उसको पूरी तरह से कन्डेम करना चाहते हैं क्योंकि इससे देश में एनाकी और लालेसनेस पैदा होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कोर्ट ने जब फैसला कर दिया कि घेराव कानून के खिलाफ है तो पुलिस को इस घेराव के सम्बन्ध में कब खबर की गई और पुलिस ने अभीतक क्या कार्यवाही की है ? और आपने डिपार्टमेन्टल क्या कार्यवाही की है ? क्या पिछले दो तीन महीनों में इस प्रकार के घेराव और भी हुए हैं ? यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): पुलिस को 18 मार्च को खबर की गई। अभी कोई कार्यवाही शायद नहीं हुई है लेकिन इसकी इत्तला मुख्य मन्त्री और उप मुख्य मन्त्री को 17 मार्च को ही मैंने दी थी और उन्होंने इस घेराव को दूर कराने का कदम उठाया जोकि स्वागत योग्य है।

श्री कंवर लाल गुप्त: आपने डिपार्टमेन्टल कार्यवाही की और क्या ऐसे घेराव हुए और है?

डा. राम सुभग सिंह : एक घेराव हुआ अदरा में 24 फरवरी को, यह हुआ 17 मार्च को और एक हुआ 19 मार्च को मोजपुर स्टेशन, साउथ ईस्टर्न रेलवे में।

श्री कंवर लाल गुप्त: अगर रेलवे में या सरकार के जो और कारखाने है वहां पर कल को पुलिस को बुलाया जाता है घेराव के समय, और अगर पुलिस नहीं आती है, कोई मदद नहीं करती है तो फिर उस समय सरकार के वे आफिसर्स डिमारलाइज न हों और उनकी रक्षा की जाये-क्योंकि वे आपके कहने के अनुसार काम कर रहे हैं– इस सम्बन्ध में आप क्या कदम उठाना चाहते हैं ? क्या आपने इस समस्या को हल करने के सम्बन्ध में बंगाल गवर्नमेन्ट से कोई बात-चीत की है ? यदि हां, तो क्या ?

डा० राम सुभग सिंह: मैं ने पहले ही बताया कि मुख्य मन्त्री और उप-मुख्य मन्त्री को जब मैं ने इत्तला दी तो दोनों ने कहा कि हम इसको हटाने का प्रयास कर रहे है और उन्होंने श्री विश्वनाथ मुकर्जी को वहां पर भेजा जिन्होंने वहां पर जाकर काफी प्रयास किया और मुख्य मंत्री और उप–मुख्य मन्त्री दोनों ने स्वयं जनरल मैनेजर को टेलीफोन किया। उन लोगों के प्रयासों के फलस्वरूप घेराव हटा।

जहांतक डिमारलाइज होने की बात है, हम किसी भी रेल कर्मचारी को डिमारलाइज नहीं होने देंगे।

श्री कंवर लाल गुप्त: क्या कदम उठाया, यह तो बताया ही नहीं ? अगर पुलिस नहीं आई तो आप क्या करेंगे ?

डा० राम सुभग सिंह: इस सिलसिले में मिनिस्टर को भेजा, वह गये, स्पीच दी और लोगों को हटाया।

श्री नारायण स्वरूप शर्मा: अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारी घेराव के लिए मजबूर होते हैं, यह एक ऐसी स्थिति है जिसको टाला नहीं जा सकता है···(**व्यवधान**)···कोई न कोई असंतोष उनके मन में होता है जिसकी वजह से यह बात समय समय पर होती रहती है। सरकारी कर्मचारियों के प्रति सरकार की जो नीति चल रही है वह पूर्णतया संतोषजनक नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जितने टेम्पोरेरी कर्मचारी निकाले गए थे उनमें से कितने वापिस लिए गए हैं और बाकी कब तक वापिस लिए जायेंगे ? अगर उनको वापिस लेने का आपका प्लान नहीं है, और वे कर्मचारी अपना असंतोष व्यक्त करते हैं तो फिर इस प्रकार से उनके घेरावों को कन्डेम करके हम सफल नहीं हो सकते हैं।

डा० राम सुभग सिंह: जहां जहां घेराव हुए वहां वहां पर घेराव को उत्तेजना देनेवाले गैर-सरकारी थे, कुछ सरकारी कर्मचारी भी उसमें हो सकते हैं....

श्री नारायण स्वरूप शर्मा: इसका मूल-कारण क्या है ?

डा० राम सुभग सिंह : मूल कारण के बारे में गृह मन्त्री जी ने गवर्नमेन्ट की राय को यहां पर घोषित किया है और उसी के अनुकूल हम कार्यवाही भी कर रहे हैं। हमारी सारी कार्यवाही उसी के अनुकूल होगी।

श्री नारायण स्वरूप शर्मा : टेम्पोरेरी कर्मचारी जो निकाले गए थे उनमें से कितने वापिस लिए गए और बाकी कबतक वापिस लिए जायेंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : 17 तारीख को आदेश मिला, हम इमीडिएटली कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री श्रीचन्द गोयल: मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने यह घेराव किया है उनकी संख्या कितनी थी ? और क्या ये वही सरकारी कर्मचारी नहीं हैं जिनके विरूद्ध यहां भारत सरकार ने निर्णय किया है, गृह मंत्रालय ने, कि उनके विरूद्ध आगे केसेज नहीं चलेंगे लेकिन अभी तक वहां उसके ऊपर अमल नहीं हुआ और इसी कारण उनको कदम उठाना पड़ा ? इसके अतिरिक्त कितनी देर उन्होंने जनरल मैनेजर को हिरासत में रखा, इसके बारे में भी जानकारी दें ?

डा० राम सुभग सिंह : लोगों ने जनरल मैनेजर को गार्डन रीच में 6 घंटे 12 मिनट तक हिरासत में रखा। जैसा कि मैंने पहले बताया उत्तेजित करने वाले गैर-सरकारी थे और यही नहीं कि गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत जो आते हों वही हों क्योंकि गृह मन्त्रालय का आदेश रेल मन्त्रालय को 17 मार्च को मिला और 17 मार्च को ही यह घेराव हुआ, दूसरा घेराव 24 फरवरी को हो चुका था। तीसरा घेराव 19 मार्च को हुआ। इस लिए माननीय सदस्य जो कहते हैं वह पूरी तरह से सही नहीं है। इस घेराव को हम गलत मानते हैं और इसको प्रश्रय कभी भी नहीं देंगे।

श्री बूटा सिंह : ऐसा मालूम हुआ है कि यह घेराव हुआ उसमें, जिस संसद सदस्य का नाम आया है वे जनरल मैनेजर की कुर्सी पर जाकर बैठ गए थे। तो ये जो घेराव हो रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के इनमें वह मुलाजिम नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वही हैं ···(**व्यवधान**).... मैं यह जानना चाहता हूं कि इन घेरावों को रोकने के लिए, यदि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारें पूरा कोआपरेशन नहीं देती हैं, तो केन्द्रीय सरकार क्या करना चाहती है ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि सदन को विदित है गार्डेन रीच में साउथ ईस्टर्न रेलवे के दफ्तर में 6 हजार कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर कोई एक माननीय सदस्य सवा सौ आदमियों के साथ जनरल मैनेजर के कमरे में घुसे जो कि एक बिल्कुल निन्दनीय कार्यवाही थी जिसकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती है। —···(**व्यवधान**)..... उन 6 हजार कर्मचारियों में से करीब करीब सारे के सारे दफ्तर में रहे और उनकी उत्तेजना में नहीं फंसे।

एक माननीय सदस्य: माननीय सदस्य का नाम तो बताइये।

डा० राम सुभग सिंह: नाम तो छप चुका है श्री जे० एम० विस्वास।

SHRI S. M. BANERJEE: Sir, generally the railway workers or any worker used to demonstrate for the ventilation of their grievances before the new form of demonstration, that is, gherao, came in. So, I would like to know whether it is a fact that the General Manager, South-eastern Railway, did not assure the deputationists who met him repeatedly- the delegation headed by the President of the South-eastern Railway Union and others, that he would sympathetically consider the cases of victimisation arising out of the strike of the 19th September, 1968 or otherwise, including the case of the casual workers who had served there for years together, who were declared as surplus and discharged ? They were casual workers and they were discharged straightaway. Even after the issue of the Home Ministry's orders in October, 1968, 7th January 1969 and the recent one, they were not taken back. May I know whether this demonstration was a manifestation of their hunger and anger and if so, what steps

are being taken to see that the orders are implenemted without any delay ?

DR. RAM SUBHAG SINGH: Sir, you were yourself present when during the reply to the general discussion on the railway budget, I categorically stated that there would not be any victimisation of any railway employee. I am prepared to review it, each and every case, if there is any victimisation. But in the face of that declaration, if any body wants to gherao the General Manager, that can never be allowed to happen on the railways. I repeat, if there is any victimisation, I am prepared to examine it.

SHRI KARTIK ORAON: There appears to be a mass hysteria for gheraos and it is a very serious situation that this tendency should be encouraged. I would like to know the name of that dignified Member of Parliament by whose, actions commissions, omimissions and initiative- the General Manager was gheraoed and the reasons thereof, for which the Government should be held responsible.

DR. RAM SUBHAG SINGH: I quite sympathise with the hon. member.

MR. SPEAKER: He never gheraoed any body.

DR. RAM SUBHAG SINGH: Our officers on three occasions were put to great difficulty and I hope this type of gheraos would not occur in future, because this is objectionable.

SHRI SAMAR GUHA: Gherao is a general phenomenon linked with certain vital interests of labour. (*Interruption*).

MR. SPEAKER : What a pity, members behave like this.

SHRI SAMAR GUHA: Gheroa is a general pheonomemon of a deeper malady relating to the vital interests of workers and also the relation between employers and employees. In view of this, the West Bengal Government has takeen a very bold step in evolving a new system in Durgapur industrial complex, particularly in concerns run by the West Bengal Government, whereby the representatives of trade unions have been taken in the Board of Directors. This is a very bold step. In view of this, would the Government consider whether it is possible to set up a board of managment in all the railways, where the representatives of of the trade unions there would also be invited not only as participants but as members of the board, so that they may have an understanding of the problems, have a sobering effect and deal with the fundamental problems like ghereo fundamentally ?

DR. RAM SUBHAG SINGH: As the House knows, the Government of India, long time back, not recently, enunciated its policy of worker's participation in management. The Goverment of India has got its own policy. We do not want to imitate others.

SHRI NARARENDERA KUMAR SLAVE: In the reply given by the minister is implicit a clear indication that the 125 men who participated in the gerao were instigated by political parties with political motives It is necessary some-how or other to draw a line beyond with indiscipline and lawlessness, from our own employees must not be tolerated. He has himself condemned gheraos in no uncertain terms. May I know whether he will take bold step and suspend all those 125 workers ?

DR. RAM SUBHAG SINGH: I have already replied how we propose to function under the directions issued by the Home Ministry. But anybody who wants willfully to contravene the rules will have to be firmly dealt with.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: मैं यह जानना चाहता हूं, जैसा अभी रेलवे मंत्री महोदय ने कहा कि जिन कर्मचारियों का या अधिकारियों का इस प्रकार घेराव होगा उन को सरकार की ओर से समुचित संरक्षण प्राप्त होगा । परन्तु यदि उन राज्यों की राज्य सरकारें शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने में असमर्थ हों और अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन कर रही हों तो ऐसी स्थिति में कैसे आप उन को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, उन के सम्बन्ध

क्या आप के मस्तिष्क में कोई स्पष्ट नीति है ? है तो, वह क्या है ?

डा० राम सुभग सिंह : अगर किसी रेल कर्मचारी पर ज्यादती होगी तो उस को मैं अपने ऊपर ज्यादती समझूंगा । चाहे वह कर्मचारी जनरल मैनेजर हो या कोई छोटा कर्मचारी हो, उस की रक्षा करने का प्रयत्न करूंगा ।

जहां तक वेस्ट बंगाल के मुख्य मंत्री, उप-मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री का सवाल है उन लोगों ने हमारी बड़ी मदद की है, उन के लिये मैं शुक्रिया अदा करता हूं ।

SHRI K. P. SINGH DEO: Sir I, have had occasion to attend the South-Eastern Zonal Railway Users' Consultative Committee meetings where my hon. friends Shri Kartik Oraon is a member and Shri Biswas is also a member. In some of the meetings they pointed out that whenever we members say something the authorities are impatient to give us a patient hearing. So I am not surprised that some of the workers of the South-Eastern Railway had to resort to intimidating these officers. I want to know for how long these grievances have been brought to the notice of the Manager, South-Eastern Railway and why was it necessary for them to go in a body and meet him ? May I also know what is the definition of 'gherao', whether he was gheraoed and whether he was allowed to go into the room ?

DR. RAM SUBHAG SINGH: That is an argument which, I think, if the hon. Member knew the reality he would not have advanced, because here there is no difficulty for any Member to tell me what he likes me to do. Even the persons who are involved have written to me. I am not a person who takes unduly long time to deal with letters. If someboby wants to indulge in any wrong action and even then you want to plead his case, that is not going to find any sympathetic attention.

श्री सु० अ० खां: मुल्क में घेराव की बढ़ती हुई कार्यवाहियों की वजह से जो मुल्क की प्रोपर्टी को नुकसान पहुंच रहा है, इस की रोशनी में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो लोग कानून के खिलाफ इस किस्म की कार्यवाही करते हैं, उनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल कार्यवाही करेंगे ?

इस के अलावा जैसा मंत्री जी ने बताया कि घेराव के वक्त से अब तक कोई कानूनी कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ नहीं की गई है जिन्हों ने घेराव किया है । तो क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायगी ?

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन्होंने घेराव को लीड किया उन संसद सदस्य का नाम क्या है और वह किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ?

डा० राम सुभग सिंह: श्रीमन्, मैं नाम बता चुका हूं । उन का नाम जे० एम० बिस्वास है । और सारे रेल कर्मचारियों के प्रति हमारी इतनी सहानुभूति है कि मैं सब के घरों की, कोई भी गरीब आदमी है कितनी तकलीफ है, उस तकलीफ से हम लोगों को पूरी वाकफियत है । लेकिन उस वाकफियत के चलते उस चीज को मैं बढ़ाना नहीं चाहता कि जिस की जब तबियत चाही तभी गैर कानूनी कार्यवाही कर दे । यह मेरी अंतिम चेतावनी है और अगर इस के बाद कोई रेल कर्मचारी कहीं भी गलत कार्यवाही करेंगे तो उन को कानून के अनुसार सजा मिलेगी ।

श्री मधु लिमये: रेलवे के बड़े अफसरान को भी मिलेगी ?

DR. RAM SUBHAG SINGH: They are also government servants and they will be dealt with under the law.

SHRI J. M. BISWAS: I am that member of Parliament who had to do this thing. I do not know how far it can be called gher-

ao because the officer at Adra never prevented from moving about. At the very outset we had told him "we shall be at your door; you can have your food; your movement is not restricted". On the 25th February the new United Front Government was going to take their oath of office. On the 24th of February, on the plea that the casual labour did not cast their votes for the Congress, 1, 300 people were removed by the Divisional Superintdent. At that time I was on my way to Delhi. I can prove it from the reservation chart. But people forced me to get down. And I did not do it in my capacity as a member of a political party. I am the Vice-Chairman of the All India Railwaymen's Federation and the Vice-President of the South Eastern Railwayman's union. I am a born Railwayman and I have worked for the railway men for the last 22 years ..... *(interruptions)*

SHRI KARTIK ORAON: He is misrepresenting facts..... *(interruptions)*

MR. SPEAKER : Order, order.

SHRI J. M. BISWAS : Sir, the House should know the position.

MR. SPEAKER : It knows it already... *(Interruptions)*.

SHRI J. M. BISWAS : Sir, I want your protection. I should be givin the facillty to speak before this house ..... *(Interruptions)*.

SHRI S. M. BANERJEE: I was all along thinking that insanity is a disqualification for membership of this House. But, after seeing the behaviour of Shri Oraon I am convinced that insanity is not a disqualification for membership of this House.

SHRI J. M. BISWAS : Because my name has been mentioned, I have to explain my position. On the plea that they did not vote for the Congress, these 1,300 men of Adra Division who were casual labourers were removed. He was also saying : last month was the voting month; so I did not remove them; this month I have removed the n..... *(Interruptions)* Even then, the Divisional Superintendent was allowed to take his food and go anywhere he liked; people were waiting outside the chamber and they were shouting slogans. Does it mean gherao ?

MR. SPEAKER : We will now take up the Calling Attention Notice.

DR. RAM SUBHAG SINGH : Before that, shall I clarify one thing ? Two points have been raised; by Shri Biswas in his speech. One is that they had voted against the Congress and, therefore, the casual workers were dismissed. That is absolutely incorrect. They had participated in the 19th September strike and, therefore, the law had taken its own course Secondly, he referred to being office-bearer of an organisation which he has named. Since they are unrecognised organisations under the rules the General Manager has nothing to do with those office-bearers.

SHRI J. M. BISWAS : The Minister is completely incorrect. Not a single casual labour at Adra was removed in connection with the 19th September strike. Not a single casual labour at Adra was removed for taking part in strike. He does not know what he is talking. He is missinformed.

DR. RAM SUBHAG SINGH : This is not the general manager that you want to *gherao*, Hold your tongue ... *(Interruption)*. It is not the Divisional Superintendent's office. You will have to be dealt with ..... *(Interruption)*. From now onwards you will not be allowed to see anybody .....*(Interruption)*.

MR. SPEAKAR : Order, order.

श्री शिव नारायण : बनर्जी उस मैम्बर को मुक्का दिखाते हैं यह क्या बात है ?

श्री प्रेमचन्द वर्मा : यह बेहूदा हरकतें बन्द करवाई जायं

श्री रणधीर सिंह : हम ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे ।

MR. SPEAKER : Order, order. Will you kindly sit down now, all of you ? I know, Shri Biswas was a bit exited but Shri Oraon is always excited. Both of them are excited. What to do now ? I know that Shri Biswas was little excited. But did you not hear the noise this side ? Doing this, showing a mailed fist that side is a great sin but from this side it is not a sin ! If I could not control Shri Biswas, could I control Shri Oraon ? Both of them were shouting and if anybody could control Shri Oraon. I could also tell Shri Biswas that he was wrong. But I was a silent spectator; I was a helpless witness. Unfortunate things are happening here. Every minute he is getting up and shouting. What can I do ? To whom could I look on this side who will control the hon. Member ? Absolutely none. I am a helpless spectator.

SHRI H. N. MUKERJEE : Ministers are expected to behave with some restraint..... (*Interruption*).

SHRI RANDHIR SINGH : That hon. Member must behave.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Official Team's visit to U. S. A. for Purchase of Fertilzers

*721. DR. SUSHILA NAYAR :
SHRI A. SREEDHARAN :
SHRI K. LAKKAPPA :

Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1490 on the 29th July, 1968 and state :

(a) whether the report submitted by the official team which visited U. S. A. and other countries for the purchase of fertilizers has since been considered; and

(b) if so, the decision taken thereon ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI B. R. BHAGAT) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement showing the decisions taken on the important recommendations made by the official team is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-503/69].

Export of Castor Oil

*722. SHRI M. SUDARSANAM : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the price at which Castor Oil is being exported;

(b) whether Brazil and China are offering severe competition; and

(c) if so, the price at which these two countries are underquoting *vis-a vis* Indian castor oil ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) The average F. O. B. value of Castor Oil exported during April-December, 1968 works out to Rs. 2,760 per tonne.

(b) Yes, Sir.

(c) The latest available prices of Castor Oil in London Market have been :

Indian Origin (Commercial)	£ 141 per Ton
Brazilian Origin (No. 1)	£ 120 per Ton
Chinese Origin	£ 119 per Ton

Aid to Nepal

*725. SHRI R. K. SINHA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total amount of aid India has given to Nepal since 1966-67; and

(b) the projects that are completed or are under progress in Nepal which are financed by India ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) the total amount of aid allocated for Nepal since 1966-67 is approximately Rs. 29 crores.

(b) A list of projects completed or

in progress in Nepal and financed by India is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT–504/69].

State Trading Corporation

*726. SHRI GADILINGANA GOWD : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether the State Trading Corporation have adopted new schemes to increase exports;

(b) if so, the details thereof;

(c) the details of goods exported to various countries during the period from the 1st April, 1968 to the 31st December, 1968; and

(d) the names of new countries to which goods have been exported or are proposed to be exported through the State Trading Corporation during the year 1968-69 ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI B. R. BHAGAT) : (a) to (d) . A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT–505/69].

Meeting of International Coffee Council

*728. SHRI SITARAM KESRI : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of the International Coffee Council was held in London in December, 1968;

(b) whether India also participated in that meeting; and

(c) if so, the outcome of the meeting ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) and (b) . Yes, Sir.

(c) Decisions on three important matters relating to the working of the International Coffee Agreement were taken. These were (i) inststitution of stricter control measures on exports to Annexure 'B' countries (non-quota countries), (ii) finalisation of the statutes of the Diversification Fund and (iii) removal of certain countries from Annexure 'B' (non-quota countries) with effect from 1st April, 1969.

भारतीय पटसन के निर्यात में कमी

* 729. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967-68 के दौरान विभिन्न देशों को भारतीय पटसन के निर्यात में कमी हो गई है जबकि पाकिस्तान पटसन के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में पाकिस्तान की स्पर्धा का सामान करने और भारतीय पटसन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक): (क) संभवत: माननीय सदस्य का अभिप्राय पटसन के माल निर्यात से है । वर्ष 1966–67 के निर्यात की अपेक्षा, वर्ष 1967–1968 में भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों से पटसन के माल के निर्यात में वृद्धि हुई ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें पटसन के माल के निर्यात संवर्धन के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का उल्लेख है ।

विवरण

पटसन के माल का निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये है :—

आवश्यक किस्म के पटसन का आवश्यक मात्रा में अपने देश में ही उत्पादन करने और उसकी उपज बढ़ाने के लिए सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं;

1 मार्च, 1969 से पटसन के माल पर लगे निर्यात शुल्क को कम अथवा समाप्त कर दिया गया है, जैसा नीचे दिखाया गया है :

हेसियन (कालीन अस्तर को छोड़कर)	500 रु० से घटा कर 200 रु० प्रति मी० टन।
बोरे का टाट	250 रु० से घटा कर 150 रु० प्रति मी० टन।
ऊन भरने के बोरे	250 रु० प्रति मी० टन को समाप्त कर दिया गया है।
कपास भरने के बोरे	200 रु० प्रति मी० टन को समाप्त कर दिया गया है।
बटे हुए धागे (स्पेश्यलीटिज को छोड़ कर) के रस्से, ट्वाईन तथा अन्य विविध माल।	250 रु० से घटा कर 150 रु० प्रति मी० टन।

(ग) आधुनिकीकरण की गति को तेज करने के उद्देश्य से अपेक्षाकृत अधिक विकास छूट देने के प्रयोजन से, पटसन उद्योग को आयकर अधिनियम की अनुसूची 5 में शामिल करने का निश्चय किया गया है।

(घ) पटसन उद्योग के उत्पादन के विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए मिलों को औद्योगिक वित्त निगम के माध्यम से ऋण सहायता दी जा रही है।

Indian Industrial Delegation to Malaysia

*730. SHRI CHENGALRAYA NAIDU : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4881 on the 17th December, 1968 and state :

(a) whether the Indian delegation which visited Malaysia during November, 1968 for exploring possibilities of collaboration in commercial technological and Industrial fields has since submitted its report to Government;

(b) if so, the main points of the recommendations;

(c) the steps taken by Government to implement them; and

(d) how far the trade between the two countries is likely to increase thereby ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) and (b). Yes, Sir. A copy of the Report of the Delegation has also been placed in the parliament Library. The suggestions and recommendations have been summarised in Chapter V of the Report.

(c) The suggestions/recommendations made in the Report concern a number of authorities to whom these have been referred for consideration. Necessary action has also been initiated in so far as they related to this Ministry.

(d) It is not possible to assess the effects of the visit of the Delegation on the volume of trade between the two countries.

Violation of Regulations of Import Export Licences

731 SHRI YAJNA DATT SHARMA : Will the Minister of FOREIGN TRADE

AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the names of the 49 firms against whom prosecutions for violations of import/export regulations are going on;

(b) the amount involved in each case and the dates when the prosecutions were started in each case; and

(c) the total amount realised during the last five years on account of such prosecutions ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI B. R. BHAGAT) : (a) and (b). Out of the 49 cases registered by the Central Bureau of Investigation during the period 1-1 1967 to 31-10-1968, 10 were prosecuted for violation of Import and Export Regulations and a statement giving the names of these firms is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No.* LT-506/69]. Of the remaining 39 cases, 3 were closed for want of proof, 2 were black-listed 1 is pending departmental action and 33 are under investigation.

(c) The total amout of fine imposed by courts in cases which ended in conviction during the years 1964 to 1968 amounts to Rs. 4,47,650/-. The amount actually realised is not available.

Export of Jute Goods

*732. SHRI M. L. SONDHI :
SHRI HIMATSINGKA :
SHRI S. K. TAPURIAH :

Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the export of jute goods which has been occupying the first place in our exports in the previous years, has suffered a fall during the first nine months of the current financial year;

(b) if so, the extent thereof as compared with the figures of the corresponding period of the last year and the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government to revitalise the export of jute goods ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI B. R. BHAGAT: (a) Yes, Sir. Exports of jute carpet backing cloth have however been steadily increasing.

(b) 78,700 tonnes. The decline in export of jute manufactures (other than carpet backing) has been due to :

(i) the exceptionally low jute and mesta crop this season and the consequent abnormal rise in prices of jute and jute goods; and

(ii) competition from Pakistan and synthetic substitutes.

(c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The following steps have been taken to increase exports of jute manufactures :

(i) All possible steps are being taken to increase the production and yield of the required quality and quantity of jute within the country;

(ii) With effect from the 1st March, 1969 export duties of jute goods have been reduced or abolished as follows :

Hessian (Other than carpet backing)	from Rs. 500/- to Rs. 200/- per tonne.
Sacking	from Rs. 250/- to Rs. 150/- per tonne.
Wool-packs	from Rs. 250/- per tonne to Nil.
Cotton Bagging	from Rs. 200/- per tonne to Nil.
Twist, yarn (other than specialities) rope, twine and other miscellaneous goods.	from Rs. 250/- to Rs. 150/- per tonne.

(iii) In order to speed up the pace of modernisation, it has been decided to include the jute industry in the Schedule V to the Income-tax Act

for purposes of higher development rebate.

(iv) With a view to encouraging diversification of production in the jute industry, loan assistance is being given to the mills through the Industrial Finance Corporation.

भारतीय माल के लिये विदेशों में प्रदर्शन कक्ष

*733 **श्री यशपाल सिंह :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय माल के लिये किन-किन देशों में प्रदर्शन कक्ष खोले गये हैं और विदेशों में भारत में बनी वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने तथा उनकी बिक्री बढ़ाने के लिये अस्थायी या स्थायी प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है और इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये प्रयत्न किये गये हैं;

(ख) वर्ष 1969-70 में किन-किन अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भारत का भाग लेने का विचार है; और

(ग) क्या भारतीय निर्माता भी प्रदर्शनियों और प्रचार कार्य में रूचि लेते हैं और यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक): (क) और (ख) . दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं । [**पुस्तकालय में रख दिये गये । देखिए संख्या** LT-507/69]

(ग) जी, हां । भारतीय निर्माता तथा निर्यातक विदेशों में होने वाली प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों में हमारे द्वारा भाग लेने के सम्बन्ध में गहरी दिलचस्पी दिखाते हैं । उन्हें इन प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है क्योंकि सरकार मेलों में भाग लेने की तथा प्रदर्शित वस्तुओं के परिवहन की अधिकांश लागत वहन करती है तथा उनके प्रबन्ध, प्रदर्शन तथा व्यापारिक पूछताछ के सम्बन्ध में उन्हें सुविधाएं प्रदान करती है । उन्हें अपनी बिक्रियों के बढ़ाने तथा व्यापार सम्बन्धी बातचीत करने के लिए, मेलों में जाने के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा दी जाती है ।

Modi Fabrics, Modinagar

*734. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) Whether the Modi Fabrics, Modinagar have recently been given any industrial licence or import licence for tyres and tyre cord in the last two years; and

(b) If so, the details of the physical quantities and value in terms of foreign exchange and rupees involved ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI B. R. BHAGAT) : (a) No, Sir, however a letter of intent to M/s. Modi Industries Ltd., Modinagar has been issued for the manufacture of automobile tyres and tubes.

(b) Does not arise.

Help to Freedom-Fighters of Angola and other African Countries

*735. SHRI YOGENDRA SHARMA :
SHRI BHOGENDRA JHA :
SHRI LATAFAT ALI KHAN :
SHRI VASUDEVAN NAIR :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) Whether the question of giving effective material support to the freedom-fighters in the Portuguese Angola and other African countries has been considered by Government; and

(b) if so, what steps are being taken in this direction ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): (a) and (b). The Government of India have rendered, and shall continue to render, to the extent possible, assistance to the liberation movements in Africa. The Government are giving scholarships and training facilities to students from these territories to enable them to pursue higher studies in India. In addition, the Government have made contributions to the U.N. Trust Fund for assisting refugees from South Africa and to the Defence Aid Fund for victims of apartheid.

From time to time Government have also sent medicines and cloth to the liberation organizations.

Nuclear Arms For Pakistan

*736. SHRI SRADHAKAR SUPAKAR: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether there is any truth in the report of some newspapers that Pakistan likely to get nuclear arms from some friendly countries; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) Government have no such information.

(b) Does not arise.

Reasons for chinese Invasion in 1962

* 737. SHRI RANJIT SINGH: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether any analysis has been made for the reasons for the 1962 Chinese invasion; and

(b) if so, the outcome thereof and conclusions drawn therefrom ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH): (a) and (b). The Chinese aggression of 1962 must have been motivated by a variety of reasons. It is difficult to go into all of them but on the political side it can be said that China might have wanted to establish the superiority of its method of bringing about changes by violent method over our policy of changes by peaceful means. The main conclusion is that we must continue to emphasize our approach and at the same time remain prepared and able to defend our sovereignty and territorial integrity with the efforts of our people.

Irregularities Committed in Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling

*738. SHRI BABURAO PATEL : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the names and designations of the ex-Principal and ex-Registrar of the Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, who are reported to have committed grave irregularities and the amount of fraud involved in each case;

(b) whether criminal proceedings have been instituted against them and if not, the reasons therefor;

(c) the other steps taken against them and the manner in which the loss would be recovered; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) They are :

(i) Lt. Colonel. (Retd) B. S. Jaswal, and

(ii) Shri B. K. Mukherjee, SAS Officer, Office of the Accountant General West Bengal.

The amounts assessed as overdrawn are Rs. 7,199/-and Rs. 2,553/- respectively.

(b) On the evidence available it was decided in consultation with the Govt. of West Bengal not to institute criminal

proceedings against these officers. Disciplinary action initiated against Lt. Col. Jaswal by the Ministry of Defence has been completed and his pension is being reduced by Rs. 75/- p. m. A. G., West Bengal has instituted disciplinary action against Shri Mukherjee. The case is expected to be finalised soon.

(c) and (d). No other step is contemplated against Lt. Col. Jaswal Reduction of pension in his case implies indirect recovery of the loss. A final decision regarding Shri Mukherjee has yet to be taken.

Soviet peace proposals on West Asia

*739. SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI :
SHRI R. BARUA :
SHRI ONKAR LAL BERWA :
SHRI N. R. LASKAR :
SHRI K. M. KAUSHIK :
SHRI R. K. AMIN :
SHRI D. N. DEB :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1386 on the 20th November, 1968 and state :

(a) whether the Soviet plan on the West Asia problems has since been received by the Government of India from the Government of the U. S. S. R.;

(b) if so, the nature of the proposals; and

(c) Government of India's reaction thereto ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The document is confidential and the reaction of the Government of India cannot, therefore, be made public. We are in general agreement with them in as much as they support the implementation of the Security Council Resolution of 22 November, 1967.

Repair of a Pak. Railway line for Passage to Nepal through India

*740. SHRI P. VISWAMBHARAN :
SHRI SHRI GOPAL SABOO :
SHRI BANSH NARAIN SINGH :
SHRI SURENDRA NATH DWIVEDY :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the old Railway line at Radhikapur in East Pakistan connecting India is being repaired by Pakistan for connecting her with Nepal through India; and

(b) if so, the reaction of Government on this proposed connection of Pakistan railway line to Nepal through India ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) The Government are not aware of any such proposal.

(b) Does not arise.

Shipment of Iron ore from Haldia Port

*741. SHRI K. P. SINGH DEO :
SHRI MEETHA LAL MEENA :
SHRI J. MOHAMED IMAM :

Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether the Minerals and Metals Trading Corporation has recently postponed its iron ore shipment programme from the Haldia port;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the attention of Government has been invited to a report which appeared in the "Economic Times" of January 10, 1969, in this regard; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). Yes, Sir. The vessel s. s. ORPHEUS, that sailed from Haldia on 11-1-1969, as scheduled, was loaded with initial cargo at Calcutta and uptopped at Haldia. The second vessel s. s. JAGDEV named in the report was not offered for loading at Haldia.

The Japanese Steel Mills have nominated another vessel for uptopping at Haldia and it is shortly expected.

Indian Officials in Commonwealth Secretariat

*742. SHRI MANGALATHUMADAM : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Indian officials in the Commonwealth Secretariat;

(b) the terms and conditions of their appointment;

(c) whether it is a fact that there is a general feeling in the Secretariat quarters that the representation of India and Pakistan is more in the Secretariat as compared to other Commonwealth countries; and

(d) if so, the reaction of Government in the matter ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Sixteen.

(b) Most of the diplomatic staff are on deputation from member Governments. Junior staff are recruited locally on local terms applicable to British Civil Service in U. K., irrespective of their nationality.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Manufacture of T. V. Sets

*743. SHRI B. K. DASCHOWDHURY : SHRI RAM AVTAR SHRMA :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government have sanctioned the formation of two consortia of small industries for the manufacture of T. V., sets ;

(b) if so, the total number of T. V. sets likely to be manufactured by them during a year; and

(c) the total amount of imported contents that will be ruquired ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) and (b) Two consortia of small scale firms have been allowed to set up manufacture of 5,000 TV sets each per annum.

(c) The import content per TV set is about Rs. 250/- at present. For 10,000 sets the total foreign exchange required will be about Rs. 25 lakhs per annum. The foreign exchange content is expected to come down to about Rs. 30/- per set in about two years during which indigenous manufacture of a number of TV compenents including picture tubes would be set up.

Bogus Exports

*744. SHRI SRINIBAS MISRA : SHRI S.M. KRISHNA :

Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of exporting firms in Surat and Bombay are indulging in bogus exports;

(b) whether Government have investigated into the matter; and

(c) if so, the result thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND

SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) to (c) . No, Sir; only one case has come to the notice of Government and the same is under investigation by the Central Bureau of Investigation.

U. N. Charter

*745 SHRI S. KUNDU : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether any change is contemplated in the United Nations Charter: and

(b) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHI DINESH SINGH) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Supply of U.S. Planes to Pakistan

*746. SHRI K.M. MADHUKAR : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the press reports that U. S. A. is likely to supply Phantom fighter planes to Pakistan either through Saudi Arabia or Iran;

(b) whether any enquiry has been made to find out the actual position in this respect; and

(c) if so, what is Government's information in this regard ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). According to information received by Government, on such agreement has been concluded for the supply of Phantom fighters to Pakistan.

Trade Agreement between India and East Germany

*747. SHRI K. ANIRUDHAN :
SHRI GANESH GHOSH ;
SHRI A.K. GOPALAN ;
SHRI UMANATH :

Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2713 on the 12th March, 1969 and state :

(a) whether the West German Government have objected to the recent trade agreement between India and East Germany; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI B. R. BHAGAT) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Sale of Raw Jute by S. T. C.

*748. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Trading Corporation has made a profit of Rs. two crores by selling jute to the industry at a price which is 100 per cent more than its own cost price;

(b) whether Government's policy to sell jute to the industry at such a high price pushes up the cost of jute products and makes it uncompetitive in the world market where Indian jute products are already facing a very stiff competition;

(c) if so, the justification for charging such a high price by the Corporation; and

(d) whether the Government have laid down any norm for the maximum profit that the Corporation should make for the supply of raw material to the industry which it imports from foreign countries for being supplied to the industry ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI B. R. BHAGAT) : (a) No, Sir. The nett profit of the S.T.C. was only Rs. 49 lakhs.

(b) and (c) . No. Sir. Sale price of the Corporation was based on the prevailing market price.

(d) No, Sir. The sale price is determined with reference to circumstances of each case.

Compensation to Claimants of Properties Confiscated by Pakistan

*749. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2733 on the 12th March, 1969 and state :

(a) whether Government have received claims from the Indian citizens regarding the goods, properties and assets confiscated by the Pakistan Government after Indo-Pak conflict in 1965; and

(b) if so, the arrangemeuts made to pay for their losses to Indian citizens who have been illegally deprived of their properties by Pakistan ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Yes Sir.

(b) The Government have been requesting Pakistan through a series of Notes to discuss the return of properties and assets seized by Pakistan and India in connection with the 1965 conflict, as provided for in the Tashkent Declaration. Unfortunately, there has been no constructive response from the Government of Pakistan so far. The Government are, however, continuing efforts in this regard.

India's Participation in Leipzig Fair

*750. SHRI INDRAJIT GUPTA : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether India participated in the recent Leipzig Fair on a smaller scale than previously;

(b) if so, whether there were any political considerations for this; and

(c) whether it is a fact that no Indian trade delegtion was present at the Leipzig Fair and if so, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) No, Sir. The participation was on the same scale as last year.

(b) Does not arise.

(c) As in the previous years, no official trade delegation was sent from India to Leipzig at the time of the Fair. However, as has been the practice in the past, representatives of the participants in the Exhibition were given the necessary facilities by way of release of foreign exchange to be present at the Fair for business negotiations with buyers coming to the Fair.

Rehabilitation of Ex-servicemen in Gujarat

4409. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether there is any scheme for rehabiltating ex-servicemen in Gujarat by allotting agricultural land to them, and if so, the progress made so far tn this regard;

(b) the number of applications received by the State Government from ex-servicemen for the allotment of land;

(c) the number of applicants among them as have retired from service before the 15th August, 1947;

(d) the number of applications received from military personnel injured during the attacks by China and Pakistan and from dependents of these soldiers who were killed during these attacks separtely;

(e) the number of applicants who have since been allotted land and the number of those who have not been allotted land and the time by which land would be allotted to such applicants; and

(f) the class-wise priority fixed in these cases and the proportion in which land is distributed amongst them ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) to (f). The information required has been called for from the State Covernment and will be placed on the Table of the House when received.

Killing of Army Officers by Underground Nagas

4410. SHRI BABURAO PATEL : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the names and designations of the Army Officers who were waylaid and shot dead by underground Nagas in Rungazumi area, near Kohima on the 8th September, 1968; and

(b) whether it is a fact that these brave officers were persuaded by local priests of the Baptist Church to go into the interior to capture some Chinese trained guerillas while a trap was laid for shooting these officers ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) The details of the incident were given on the floor of the House on the 20th November, 1968 in response to the Lok Sabha Starred Question No. 213. The officers who lost their lives were:---

Capt B. Subramanian,

Naib Subedar Chhabi Lal Limbu, and
Naib Subedar Balkrishan Mohan.

(b) No, Sir. The officers were on duty in that area.

United Provinces Commercial Corporation

4411. SHRI BABURAO PATEL : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state:

(a) the nature and amount of fraud committed by the United Provinces commercial Corporation with names and designations of the directors and employees against whom action has been taken with the number of suits with particulars of such suits;

(b) the names of those who were arrested and bailed out and if so, section under which they have been charged;

(c) the name of the director who tried to jump bail by flying out of Calcutta and with what result;

(d) the amount which Government owe to the United Provinces Commercial Corporation and in what respect and whether these dues have frozen; and

(e) the stage at which the criminal cases are likely to be decided ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT-508/69*]

(c) The name of the Director in respect of whom information had been received by the Central Bureau of Investigation that he might cross over to Pakistan from Agartala is Shri S. M. Wahi. A message was flashed to the Security Control, Calcutta, Gauhati and other places to prevent Shri S. M. Wahi from crossing over to the Pakistan border. The plane carrying him was recalled on 27.10.1968 by the Security Control, Calcutta Police and Shri S. M. Wahi was arrested and produced before the Special Judge who released him on the condition that he should obtain the permission from the Court before he goes out of its jurisdiction.

(d) Rs. 26,97,000 approximately in respect of various DGS&D contracts are being withheld.

(e) In three cases, where charge-sheets have been filed by the Central Bureau of Investigation, the trial is at the initial stages and it is not possible at this stage to indicate when the cases are likely to be decided by the Court.

Smuggling of Coconut Oil from Ceylon

4412. SHRI BENI SHANKER SHARMA :
SHRI RANJIT SINCH :
SHRI D. C. SHARMA :
SHRI HARDAYAL DEVGUN :

Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the large scale smuggling of Coconut oil from Ceylon to India ;

(b) whether the Coconut Oil is cheaper in Ceylon than in India ; and

(c) whether any effort has been made to increase the production of Coconut in India and extend its area of cultivation ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) No, Sir. During 1967 and 1968, only 31 kgs. of Ceylonese coconut oil were seized by Customs authorities.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir.

Re-Export of Cotton Textiles exported by S. T. C.

4413. SHRI BABURAO PATEL : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the names of the countries to which the State Trading Corporation exports cotton textiles at a loss to promote our exports and the amount of loss suffered annually in this regard during the last five years ;

(b) whether it is a fact that Hungary buys our textiles at low prices causing us a loss and sells the same to countries in Western Europe and earns a substantial middle man's profit ;

(c) the reasons due to which we continue this losing transaction to help Hungarg's economy and not sell diretly to the countries in Western Europe and make the profit which Hungary makes on our textiles ;

(d) whether it is an export achievement to undersell goods and earn a loss there by ; and

(e) if not, the reasons for which this trade practice is preserved in ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) there have been losses in the exports of cotton textiles and allied items to Hungary, U. S. S. R. Lebanon, Iraq, Jordan and Canada. A statement indicating the amount of loss suffered annually during the last 5 years on exports of these items to these countries is laid on the table of the House. [*Placed in Libray. See No.* LT-509/69].

(b) Government's attention has been drawn to some reports of re-sale of Western Europe but no concrete evidence has been available so far. It may, however, be mentioned that sales to Hungary have been made at prices higher than the prices obtainable in Western Europe.

(c) to (e). In the interest of retaining in East European and other countries the position gained by Indian textiles after years of sustained promotional activities, the S. T. C. undertook to export this commodity at prices which in some cases resulted in losses. It was part of the S.T.C.'s endeavour to promote the country's exports, to find new markets for the country's products and to maintian difficult but potential markets.

Floating Exhibitions to Popularise Indian Goods

4414. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether Government have considered the possibility of holding floating exhibitions on Indian ships in other countries to display the Indian goods and to encourage the export thereof ;

(b) if so, the decision taken in this regard;

(c) whether any such exhibition has been held in the recent past; and

(d) if so, in which countries and with what result ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE & SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) and (b). The proposal to organise a Floating Exhibition on an Indian ship for displaying Indian export products abroad was considered sometime back but was dropped because of the financial implications which were very high compared to other means of publicity such as participation in organised Exhibitions abroad.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Compensation for Acquisition of Homestead Land in Darjeeling

4415. SHRI C. K. BHATTACHARYYA : Will the MINISTER OF DEFENCE be pleased to refer to the statement laid on the Table on the 19th February, 1968 in fulfilment of the assurance given in reply to Unstarred Question No. 1085 on the 20th November, 1967 and state :

(a) whether the compensation for the acquisition of homestead land due to the second group of 92 families has been disbursed by civil authorities; and

(b) whether the compensation due to the third group of families (58) has been finally determined and paid ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) Yes, Sir. The requisition compensation has been disbursed.

(b) Yes, Sir. The requisition compensation has been determined and disbursed.

Working Conditions of Lecturers in the School of Foreign Languages

4416. SHRI SIDDAYYA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the working conditions of the lecturers in the school of Foreign Languages under his Ministry;

(b) whether there are any rules laid down regarding the working conditions;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) to (d). The Lecturers in the School of Foreign Languages are Class I Gazetted officers; all service benefits extended to Central Government servants (like General Provident Fund, Gratuity, Pension, etc.) are applicable to them. Regarding their leave, this School is a vacation Department and the lecturers avail themselves of 2 months' summer vacation (from the middle of May to middle of July) every year, in addition to casual leave and commuted leave, as admissible to such Central Government employees. If a Lecturer is prevented from taking his full vacation, he is granted earned leave in lieu, as prescribed under the rules. A Lecturer employed on contract for a specified period is not entitled to pensionary benefits.

The Lecturers teach Preliminary and Advanced (Part-time) as well as Interpretership (Full-time) classes. Those lecturers, who come in the evening, in addition to their morning duty for taking classes, are provided free Government transport both ways. The work load of a lecturer does not normally exceed 5 hours per day.

The Lecturers are allowed to accept part-time teaching jobs in institutions like the Indian School of International Studies, to work as casual Artistes with All India Radio, to undertake translation work from foreign languages into English and *vice versa*, to act as interpreters and examiners, provided the work undertaken does not interfere with their normal duties.

No separate rules regarding working conditions of lecturers have been framed, as

they are generally governed by the conditions applicable to other Central Government Class-I (Gazetted) employees.

Library in the Schools of Foreign Languages

4417. SHRI SIDDAYYA : Will the MINISTER OF DEFENCE be pleased to state :

(a) whether there is any library in the School of Foreign Languages under his Ministry; and

(b) if so, the total number of books in each of the languages and the annual grant sanctioned for the purchase of books ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) Yes, Sir.

(b) 6,067 books in various foreign languages are held in the Library as under :-

Arabic	769
Burmese	125
Chinese	626
French	915
German	683
Japanese	477
Malay & Bhasa	
Indonesia	10
Persian	471
Russian	778
Spanish	215
Tibetan	121
Italian	95
English	782
Total :	6067

There is no separate grant for purchase of books as such. The School is authorised a consolidated annual grant of Rs. 4,000/- for purchase of books, journals, instructional equipment and accessories.

Lecturers in the School of Foreign Languages

4418. SHRI SIDDAYYA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether orders have been passed to upgrade the posts of Lecturers in the School of Foreign Languages under his Ministry;

(b) if so, the date of the orders and whether they have been implemented; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) 16.11.1964.

The orders have been implemented.

(c) Does not arise.

Mao Literature in India

4419. SHRI MADHU LIMAYE :
SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chinese Embassy has been distributing Mao literature in India;

(b) what are the different ways adopted by the Chinese Embassy for the distribution of Mao literature;

(c) to what extent the Government of India have been able to stop this practice; and

(d) what are the new proposals to deal with the new *modus operaudi* adopted by the Chinese Embassy, which includes posting of literature in plain envelopes from places outside Delhi and through 'contact' men ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) to (b). According to international practice dissemination of information and publicity material relating to their respective countries by diplomatic Missions is permitted so long as the contents are not in contravention of

the internal laws of the host country. The Chinese Embassy's attention has been drawn on a number of occasions when they have circulated objectionable propaganda literature.

Payment for Export of Ores to North Korea

4470. SHRI R. K. SINHA : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that North Korea has been failed to make payments for the ores supplied by the Indian firms during the year 1968; and

(b) if so, the steps taken to recover the amount ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) No, Sir. The DPRK buyer according to the terms of the contract was to make only provisional payment 95% on presentation of certain documents and balance 5% later. Consequently during 1968, the provisional payment of the contract has been received.

(b) Does not arise.

Trade Agreement with Syria

4521. SHRI CHENGALRAYYA NAIDU : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India and Syria have concluded a trade agreement; and

(b) if so, the main items to be exported to and imported from Syria under this agreement ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAM) : (a) and (b) . No Trade Agreement has been signed between India and Syria so far. However, in December last the representatives of the two Governments held discussions with a view to taking measures for expanding the trade between the two countries; and initialled the Text of an Agreed Draft of a Trade Agreement, which, it is hoped, will be formally signed by the two Ministers of Foreign Trade, in the near future.

रूस और अमरीका द्वारा जासूसी के काम के लिए अन्तरिक्ष का प्रयोग

4422. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि रूस और अमरीका की सरकारें अन्तरिक्ष का जासूसी के काम के लिए प्रयोग कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) . (क) जी हां ।

(ख) अन्य देशों द्वारा किसी भी तरीके से किये जाने वाली जासूसी कार्रवाई की कितनी भी निन्दा क्यों न करें, ऐसी कार्रवाई जारी रहती ही है । तथापि हमें आशा है कि जहां तक बाह्य अन्तरिक्ष का सम्बन्ध है इसका उपयोग पूर्णतः शान्तिमय कार्यों के लिए किया जायेगा । इस उद्देश्य से ही भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में होने वाली उस सन्धि का समर्थन किया जो अक्टूबर सन् 1967 में लागू हुई ।

Allotment of Agricultural Land to Ex-servicemen

4423. SHRI K LAKKAPPA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 511 on the 4th December, 1968 regarding

allotment of agricultural land to Ex-Servicemen and state :

(a) whether the information has since been collected from the State Government; and

(b) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) and (b) . Information has been received from the Governments of Maharashtra, Nagaland, Gujarat, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal, Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Delhi Administration, Andaman and Nicobar Islands, Pondicherry, Tripura, Manipur, Chandigarh and Goa, Daman and Diu, as given in the statement laid on the Table of the house. [*Placed in Library. See* No. LT-510/69]. Information regarding the other States will be laid on the Table of the House in due course.

Indian Rare Earths Limited

4424. SHRI PREM CHAND VERMA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) when the Indian Rare Earths Ltd. was floated, who were the members on its Board of Directors at that time and how long the same Board continued; and

(b) who are the members of the Board of Directors at present and who is the Chairman of Managing Director of the Company and when they were appointed and what is their tenure and terms of employment ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) and (b) . A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-511/69].

आयुध कारखानो आदि में नियुक्त महाप्रबन्धक तथा अन्य उच्च अधिकारी

4425. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
कुमारी कमला कुमारी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कारखानों, आयुध डिपुओं, तोप तथा गोला निर्माण कारखानों और प्रतिरक्षा उत्पादन में लगे ऐसे अन्य कारखानों के नाम क्या है जहां पर गैर-तकनीकी, गैर-वैज्ञानिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी और अन्य असैनिक अधिकारी महाप्रबन्धक और अन्य उच्च पदों पर नियुक्त किये जाते है और ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन अधिकारियों के स्थान पर वैज्ञानिकों और तकनीकी व्यक्तियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षणिक तथा तकनीकी अर्हतायें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) कोई भी गैर-तकनीकी आई० ए० एस० या आई० सी० एस० अफसर किसी आर्डनेन्स फैक्टरी के जनरल मैनेजर या ई०एम०ई० वर्कशाप के मुख्य के तौर पर नियुक्त नहीं किया गया । तदपि, आर्डनेन्स फैक्टरियों के जनरल मैनेजर असैनिक हैं, जब कि ई०एम० ई० वर्कशापों में उच्च स्थान असैनिकों द्वारा धारण नहीं किये जाते ।

आर्डनेन्स डिपु रक्षा उत्पादन में प्रवृत्त नहीं है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

प्रतिरक्षा सेना में काम करने वाले अधिकारियों के लिए पहचान-पत्र

4426. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
कुमारी कमला कुमारी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सेनाओं में काम कर रहे अधिकारियों को पहचानपत्र जारी किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या एक अधिकारी का पहचानपत्र खो जाने अथवा चोरी हो जाने पर उसे दूसरा पहचानपत्र दे दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो दूसरी प्रति दिये जाने की शर्तें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) शनाख्ती कार्ड अफसरों की शनाख्त के लिए जारी किए जाते हैं ।

(ग) तथा (घ) . जब किसी शनाख्ती कार्ड के गुम या चोरी हो जाने की रिपोर्ट प्राप्त होती है कोर्ट आंफ इन्क्वायरी की मामले की जांच के पश्चात् उसे दुबारा जारी कर दिया जाता है । अगर जांच से पता चले कि वह अफसर की असावधानी से गुम हुआ था, तो मामले के मेरिट के अनुसार उसके विरुद्ध उचित अनुशासनिक-प्रशासनिक कार्यवाही की जाती है ।

सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों के लिए पहचानपत्र

4427. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
कुमारी कमला कुमारी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना की सेवा से निवृत्त होने वाले अधिकारियों को पहचानपत्र जारी किये जाते हैं;

(ख) क्या पहला पहचानपत्र खो जाने अथवा चोरी हो जाने की स्थिति में दूसरा पहचानपत्र दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे पहचानपत्र किन शर्तों पर जारी किये जाते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पेन्शनी लाभों के साथ रिटायर होने वाले सभी अफसरों को अपने शनाख्ती कार्ड अपने पास रहने दिये जाते हैं ।

(ख) से (घ) . रिटायर हो चुके अफसरों को दुबारा शनाख्ती कार्ड जारी नहीं किए जाते । ऐसा मुख्यतः सुरक्षा कारणोंवश किया जाता है, और शनाख्ती कार्ड गुम होने को प्रोत्साहन न देने के लिए ।

नौसेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार

4428. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री बलराज मधोक :
कुमारी कमला कुमारी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री 20 नवम्बर, 1968

के अतारांकित प्रश्न संख्या 1373 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना मुख्यालय से भर्ती के बारे में जानकारी मांगने वाले पत्रों के उत्तर उसी भाषा में देने सम्बन्धी स्थिति पर इस बीच विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) सम्बन्धित भाषाओं में सभी पत्रों के उत्तर देने के लिए कुल कितने कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). जी हां। हिन्दी में प्राप्त होने वाले सभी पत्रों का अब हिन्दी में उत्तर दिया जा रहा है। हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में प्राप्त होने वाले पत्रों की संख्या उपेक्ष्य है। उन पत्रों का भी जहां सम्भव हो उसी भाषा में उत्तर देने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस समय कोई विशेष कर्मचारीगण भर्ती करने का विचार नहीं है।

Soviet Presence in Indian Ocean

4429. SHRI YAJNA DATT SHARMA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the attention of the Government of India has been drawn to the article appearing in the Swiss Daily 'Neve Zurcher Zeitung' regarding "increasing Soviet presence in the Indian Ocean"; and

(b) if so, the reaction of the Indian Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Government has seen the Press Report.

(b) The Report published in the paper is totally unfounded.

लार्ड माउंटबेटन द्वारा दिये गये "नेहरू भाषण-माला" के भाषण

4430. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री 18 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4945 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लार्ड माउंटबेटन द्वारा दिये गये "नेहरू स्मारक भाषण-माला" के सभी भाषण सभा पटल पर रखे जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). सरकार को लार्ड माउंटबेटन द्वारा दिये गये केवल एक ही सार्वजनिक भाषण की जानकारी है। इस भाषण को समाचार पत्रों द्वारा व्यापक रूप से विस्तार किया गया था, और इसकी प्रतियां सुलभ हैं।

भारतीय दूतावासों के अध्यक्षों की नियुक्ति

4431. **श्री मोलहू प्रसाद** :
श्री एस० आर० दामानी :
श्री बलराज मधोक :

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** 18 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4950 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय दूतावासों के अध्यक्ष नियुक्त किये गये 11 व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ख) उनकी योग्यताओं, राजनैतिक अनुभव तथा दलों से सम्बन्ध के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनमें से कितने पिछले सामान्य चुनाव में पराजित हुए थे अथवा कांग्रेस के टिकट पर चुने गये थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह. (क) नाम नीचे दिए गए हैं:-

1. श्री टी० स्वामीनाथन
2. श्री वाई०बी० गन्डेविया
3. श्री के० एल० मेहता
4. श्री ए०एम० टॉमस
5. श्री राज बहादुर
6. श्री एस०एस०धवन
7. नवाब अली यावर जंग
8. श्री ओ०वी० अल्गेसन
9. डा० के०एस० शेलवंकर
10. श्री पी०एस० नस्कर
11. श्री डी०पी०धर

(ख) उनकी शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पत्र में दी गई हैं जो सभा पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** LT--512/69] इनमें से चार सर्व श्री राजबहादुर, ए०एम० टामस, ओ०वी० अल्गेसन और पी० एस० नस्कर कांग्रेस दल के सदस्य थे। श्री डी० पी० धर जम्मू और काश्मीर में राष्ट्रीय सम्मेलन के सदस्य थे। अन्य व्यक्तियों का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं था।

(ग) आम चुनाव में चार हार गए और एक विजयी हुए।

नौसेना मुख्यालय में प्राप्त गुजराती और मराठी भाषा में आवेदन

4434. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
श्री बलराज मधोक :
कुमारी कमला कुमारी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री 20 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1374 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौसेना मुख्यालय में जुलाई, 1968 से दिसम्बर, 1968 तक भर्ती के लिये गुजराती और मराठी भाषाओं में कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) जिन आवेदनों के उत्तर दिये गये उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है जिन पर पता न होने के कारण उत्तर नहीं दिया गया ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क)
गुजराती 2
मराठी 4

(ख) पांच

(ग) एक।

तारापुर परमाणु बिजली केन्द्र

4435. **श्री महाराज सिंह भारती :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र के लिये ईंधन के उत्पादन की योजना पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). संयंत्र का विस्तृत डिजायन तथा ले-आउट अभी तैयार किये जा रहे हैं।

Conference of Indian Ambassadors of West Asia

4436. **SHRI R. K. SINHA :**
SHRI SHRI CHAND GOYAL :
SHRI HARDAYAL DEVGUN :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS

be pleased to state :

(a) whether a Conference of the Indian Ambassadors in West Asian countries is being convened;

(b) if so, the probable date;

(c) the major issues to be discussed; and

(d) whether Conference of Ambassadors in the other regions is also being convened ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) and (b). A Conference of the Indian Ambassadors in West Asia and North Africa will be held from May 20-23, 1969.

(c) The West Asian situation and other matters including development of trade, economic and cultural relations in which India is interested are expected to be discussed.

(d) Conferences of Heads of Missions in various regions are held from time to time.

Manufacture of Transmitters

4437. SHRI GADILINGANA GOWD : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a factory for the manufacture of transmitters in collaboration with some foreign countries;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the place where it is likely to be located and the time by which their manufacture will start ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) No, Sir. There is no proposal to set up a new unit for the manufacture of Transmitters.

(b) and (c). Do not arise.

Haj Pilgrims

4438. SHRI GADILINGANA GOWD : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Haj pilgrims authorized by Government for Haj during the last three years;

(b) the amount of foreign exchange given, year-wise;

(c) the number of Haj pilgrims who did not come back; and

(d) the reasons therefor and the action taken by Government in such cases ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) :

(a) 1967 15,200
1968 15,000
1969 15,000

(b) 1967 Rs.2,38,84,205/-
1968 Rs.2,34,13,315/-
1969 Rs.2,36,25,000/-was authorised. The exact amount released to the pilgrims is being ascertained.

(c) Except for the pilgrims who die on board the ships or in Saudi Arabia due to old age or sickness, all other pilgrims do com back--some may return late by a few months or by a different route after visiting other holy places. There is, however, no definite means of ascertaining the number of pilgrims who do not return to India after Haj as the Pilgrim Pass on which they travel is valid for one year and they can always retun to India during that period. Any pilgrim over-staying in Saudi Arabia, if and when apprehended by the Saudi Authorities, in given Consular assistance by our Embassy in Jeddah to repatriate him to India.

(d) In view of the position stated in (c) the question does not arise.

Anti-Indian Propaganda by Radio Peking

4439. SHRI GADILINGANA GOWD :
SHRI RANJIT SINGH :
SHRI BAL RAJ MADHOK :
SHRI HAR DAYAL DEVGUN :
SHRI D. C. SHARMA :
SHRI BENI SHANKER SHARMA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there has been an increase in the anti-Indian propaganda by Radio Peking recently;

(b) if so, Government's reaction thereto;

(c) the number of Protest Notes sent to the Chinese Government during the second half of 1968; and

(d) the steps taken to counteract the anti-Indian propaganda ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a). While the actual intensity of the anti-Indian propaganda by Radio Peking varies slightly from time to time, on the whole it has been at a sustained high level in the recent past.

(b) Government of India have deplored such propaganda and have asked the Chinese Government in the past to stop it and return to the path of normal international behaviour.

(c) No written protest note was given to the Chinese Government in the second half of 1968 on this subject.

(d) Government of India and their Missions abroad are using every available opportunity to counteract the false and hostile propaganda put by Chinese Press, Radio and other mass media.

Development of Nuclear Weapons by Israel

4440. SHRI M.L. SONDHI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Israel has developed Nuclear Weapons; and

(b) if so, the reaction of the Government of India in the matter ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Certain Press reports appeared early in January this year to the effect that Israel either has the nuclear bomb or will have it shortly, but Israeli sources have denied the reports. The Government have no information on this matter.

(b) Does not arise.

Deceased Army Personnel belonging to Gujarat in Kutch and Indo-Pak Conflict

4441. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether the Army personnel belonging to Gujarat also laid down their lives in 1964-65 in Kutch and Indo-Pak conflict; and

(b) if so, the details in regard to the pension being given to their families ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) Yes, Sir. Four Army personnel belonging to Gujarat (2 Officers, 1 JCO and 1 OR) were killed in action in Indo-Pak conflict. No one from Gujarat was killed in the Kutch conflict.

(b) Details regarding pensionary benefits given to their families is being collected from the pension paying authorities and will be laid on the table of the House in due course.

ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्च आयोग में लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा अनियमितताओं का पता लगाना

4442. श्री मधु लिमये : क्या वैदेशिक-

कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग के वाणिज्य दौत्य विभाग में लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा विभाग द्वारा हजारों पौंड की अनियमितताओं का पता लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि गत तीन वर्षों से उक्त विभाग के लेखों की लेखा-परीक्षा नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :) (क) एक अनियमितता हुई थी किंतु कोंसली विभाग में नहीं, अपितु डाक शाखा में, और उसका पता भारत के हाई कमीशन को नवम्बर, 1966 में चल गया था और उन्होंने लेखा-परीक्षा निदेशक, लन्दन, को इसकी रिपोर्ट दे दी थी। यह 5,240 पौंड की रकम का मामला था।

(ख) इसमें स्थानीय भर्ती के सर्वश्री जुगर सिंह और एन.सी. बोस नामक जिन दो कर्मचारियों का हाथ था उन्हें आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद मार्च, 1968 में बिना पैंशन और उपदान के बर्खास्त कर दिया गया था।

(ग) और (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है।

Release of Shri Trilok Chandra Gupta

4443 SHRI M.L. SONDHI : Will the the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to to hold a high level inquiry into the circumstances in which inordinate delay occurred in his Ministry in taking up the case of Shri Trilok Chandra Gupta, 17 years old detenue in Pakistan;

(b) whether Government have considered offering compensation to the family of Shri Trilok Chandra Gupta; and

(c) the steps Government are taking to provide prompt help in such cases in future ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): (a) No, Sir. There has been no delay in the Ministry taking up the case of Trilok Chandra Gupta.

(b) There is no standing scheme of the Government of India under which compensation can be granted in such cases. However, Government are considering how Trilok Chandra can be helped in his rehabilitation.

(c) Government are already providing prompt help in all cases of detention of Indian nationals in Pakistan brought to their notice.

Pakistani Invasion in 1965

4444. SHRI RANJIT SINGH :
SHRI BAL RAJ MADHOK :
SHRI HARDAYAL DEVGUN :
SHRI D.C. SHARMA :
SHRI BENI SHANKER SHARMA :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether any analysis has been made of the Pakistani invasion of India in 1965;

(b) if so, the outcome thereof; and

(c) the steps taken in the matter so far ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) to (c). It is one

of the functions of the Chiefs of Staff to analyse and study the various military operations in which the defence forces were called upon to participate and advise the Government in the light of conclusions derived therefrom. The military operations during August-September 1965 were no exception to this. As already indicated in the Annual Reports of the Ministry of Defence for 1966-67, 1967-68 circulated to to the honourable Members, some internal re-organisations and streamlining of units have been made with a view to improving the "teeth to tail" ratio and to making the army a more effective striking force without increasing the existing manpower. The task of providing the armed forces with more modern and effective weapons and equipments has been kept in view and substantial progress has been made in this direction, both quantitively and qualitatively. Improvements have also been made in strategic communications.

The experience of 1965 also demonstrated that our dependence on foreign countries for defence equipment should be reduced and efforts have therefore been continued along the twin courses of modernisation of arms and progressive self-reliance by setting up new capacities and generally gearing up the industrial apparatus in the country for the manufacture of defence equipment and stores.

आयुध कारखाने

4445. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखानों में सरकार ने कितनी पूंजी लगा रखी है और गत तीन वर्षों में उनका वार्षिक उत्पादन कितना-कितना रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि उन कारखानों में असैनिक उपयोग की वस्तुएं भी बनाई जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में आयुध कारखानों में सैनिक उपयोग की कितने मूल्य की वस्तुएं बनाई गई ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल०ना०मिश्र) : (क) से (ग) . सूचना इकट्ठी की जा रही है । और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को पुनः वेतन देना

4446. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 27 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2331 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को अब तक भूतपूर्व भारतीय सैनिकों से जो आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गये थे; वेतन तथा भत्ते पुनः प्राप्त करने के लिए कितने आवेदन पत्र मिले हैं, जो सरकार द्वारा जब्त कर लिए गये थे और कब तक इस राशि का भुगतान कर दिया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : भूतपूर्व आजाद आई० एन० ए० सेविवर्ग की संख्या कि जिन्होंने अपने जब्तशुदा वेतन और भत्तों की बहाली के लिए 31 जनवरी, 1969 तक प्रार्थना पत्र भेजे हैं, 13825 है । इन में से 8644 सेविवर्ग को वास्तविक तौर पर अदायगी कर दी गई है । इस के अतिरिक्त आडिट द्वारा 3307 दावे पारित कर दिए गए हैं और शीघ्र ही अदा कर दिए जाएंगे । शेष दावे जांच अधीन हैं, और आशा है कि वह शीघ्र ही निपटा दिए जाएंगे ।

Trade Agreement with North Korea

4447. SHRI BABURAO PATEL : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether a North Korean trade delegation came to Delhi on the 25th November, 1968, headed by Mr. Kim Suk Jin, and

if so, the names of the members of the Indian team including officials who participated in the trade talks;

(b) whether India has agreed to export 10,000 tons of high grade manganese ore to North Korea and if so, the guarantee secured by Government to prevent the possibility of the manganese ore finding its way into China as happened with other goods in the past:

(c) the type and quantity of goods offered in return for our ore and the nature of payment agreed upon: and

(d) whether Government realise that by such hush-hush deals we are arming our enemy and sabotaging the defence of the country ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) Yes, Sir. A list of the members of the Indian Delegation who participated in the trade talks with the DPRK Delegation is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT*-513-/69].

(b) Manganese ore is one of the exportable items from India to the Democratic People's Republic of Korea under the trade and payments agreement concluded by the exchange of letters on 9th December, 1968. The quantity of Manganese ore to be exported to DPRK would depend upon contracts to be concluded between the concerned enterprises in the two countries. The Agreement specifically stipulates that commodities exchanged between the two countries shall be for consumption in their respective countries and shall not be re-exported.

(c) Lists of exportable and importable items agreed to be exchanged between the two countries are attached to the above mentioned Trade Agreement copies of which are available in the Parliament Library.

(d) The Trade Agreement with the DPRK follows the estabilshed pattern of Trade and Payments Agreements with all those countries with whom India has entered into bilateral rupee payment arrangements. Government do not see in this Agreement any danger to the defence of the country.

Silver Jubilee Celebrations of the Azad Hind Government

4448. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 372 on the 7th August, 1968 and state :

(a) whether Government have since considered the suggestions made in the representation regarding observance of Silver Jubilee Celebrations of the foundation day of the Azad Hind Government;

(b) if so, which suggestions Government have accepted or have not accepted;

(c) the reasons for acceptance of some or rejection of other suggestions: and

(d) the steps taken by Government to implement the suggestions accepted by Government ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). A statement indicating the action taken on the various suggestions is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT*-514/69].

बर्मा में घिरे हुए विद्रोही नागाओं को सहायता के लिये चीन-बर्मा सीमा के समीप चीन की सप्लाई चौकियां

4449. श्री रघुवीर सिंह :
श्री वाल्मीकि चौधरी ।
श्री प्रविचन :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि चीन-बर्मा सीमा

के निकट उन विद्रोही नागाओं की सहायता करने के लिए जो भारत लौटते हुए बर्मा में भटक गये हैं कुछ सप्लाई चौकियां स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में बर्मा सरकार की सहायता तथा सहयोग प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उस पर बर्मा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) बर्मा सीमा के निकट, चीन के यून्नान प्रान्त में स्थापित केंद्रों से, छिपे नागा सामान और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) और (ग). लोक-सभा में 27 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 877 के उत्तर और राज्य सभा में 1 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 580 के उत्तर की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित किया जाता है। भारत और बर्मा सरकार, आपसी हितों के सभी मामलों पर, एक दूसरे से परामर्श लेती हैं। इस प्रकार के परामर्श निरन्तर लिए जाते रहे हैं और वे सन्तोषजनक सिद्ध हुए हैं।

Indian Air Force Planes Used by Ministers During Mid-Term Elections

4450. SHRI GOERGE FERNANDES : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether any Army or Air Force Planes were used by the Prime Minister or any other Minister during the campaign in the mid-term elections in Bihar, U. P., Punjab and Bengal;

(b) if so, the number of occasions those Planes were used and the terms and conditions under which they were used;

(c) whether Government would consider allowing leaders of all political parties to use these Planes for electioneering purposes;

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) and (b) . I, A. F. aircraft were used by the Prime Minister during the campaign in the mid-term elections on 25 occasions. The Prime Minister as the Head of the Government is entitled to use these aircraft even for purposes other than official. For such flights, fares are calculated at commercial rates if the destination is linked by a regular commercial air service or at the rate of Rs. 0.33 per statute miles for each passenger. In addition, detention charges are levied at the rate of Rs. 150/- per hour or part thereof for halts in excess of the first 48 hours.

(c) and (d) . No, Sir. Only the Prime Minister as the Head of the Government is allowed this facility.

Export of Iron Ore

4451. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the total quantity of Iron ore exported from India in the year 1968-69 so for; and

(b) the port-wise shipment of Iron ore during this period ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) The exports of iron ore from India during 1968-69 (from 1-4-1968 to 31-12-1968) were 11·026 million tonnes.

(b) A statement showing port-wise exports of Iron ore from India during the above period is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No . LT-515-/69*]

Supply of Textile Machinery to Burma

4452. SHRI HARDAYAL DEVGUN : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether the Government of India had submitted a tender for the supply of taxtile machinery and accessories to Burma;

(b) if so, the estimated requirement of Burma for these articles;

(c) whether the tender has been accepted; and

(d) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) The State Trading Corporation has submitted a tender to the Government of Burma for setting up a cotton spinning and weaving unit.

(b) The requirement is for a complete cotton spinning and weaving plant of 40,000 spindles and 600 looms on turnkey basis.

(c) and (d) . The tender is under consideration of the Government of Burma.

Welfare workers for Ex-servicemen and Servicemen's Families

4453. SHRI HEM RAJ : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the number of welfare workers for ex-servicemen and servicemen's families which have been sanctioned for different States and Union Territories;

(b) the principles on which they are allocated to different states and union territories; and

(c) the number which have been to different District Soldiers, Sailors and Airmen's Boards. State and Union Territority-wise ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) The number of welfare workers sanctioned for different States and Union Territories is as follows :

Assam	5
Bihar	20
Haryana	20
Himachal Pradesh	6
Kerala	6
Jammu & Kashmir	9
Tamil Nadu	12
Maharashtra	8
Mysore	7
Orissa	2
Punjab	25
Rajasthan	8
West Bengal	7
Delhi	1

(b) The appointment of Welfare Workers is made on a request from the State Government. Their number depends on the number of ex-servicemen in the district concerned, its area and terrain.

(c) Welfare workers sanctioned for different States are allocated to the district Boards by the State Soldiers and sailors, and Airmen's Board considered necessary.

तेजी से काम करने वाले संगणकों का निर्माण

4454. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में वाणिज्यिक पैमाने पर शीघ्रकारी संगणकों का निर्माण कब तक आरम्भ करने का प्रस्ताव है और इस बारे में क्या ब्यौरा है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मद्रास में एक फर्म पहले से अनालाग कम्प्यूटरों का निर्माण कर रही है। ऐसे 50 कम्प्यूटर प्रतिवर्ष के लिए उनके पास लाईसेंस शुदा क्षमता है। प्रत्येक किस्म के 10 कम्प्यूटर प्रतिवर्ष की क्षमता सहित अनालाग तथा तेजगति के डिजिटल कम्प्यूटरों का उत्पादन हैदराबाद में राजकीय क्षेत्र के एक उपकरण द्वारा स्थापित किया जा रहा है। यह 2 वर्षों में विकसित होंगे। बंगलोर में राजकीय क्षेत्र के

एक उपकरण के साथ सहयोग से एक और फार्म इन्टेग्रेटिड सर्कटों का प्रयोग करते हुए कम्प्यूटरों का निर्माण स्थापित कर रही है। वह 1969-70 से शुरू कर के आगामी 4 वर्षों में ऐसे 56 कम्प्यूटरों का निर्माण करेंगे। एक चौथी फर्म में आधुनिक कम्प्यूटरों का निर्माण हस्तगत करने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा है।

Indian Military Contingent in South Vietnam

4455. SHRI RANJIT SINGH : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) Whether our military contingent in South Vietnam has been drastically reduced; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) As a result of the obligations arising out of our membership of the International Commission for Supervison and Control in Indo-China, Indian Army personnel have been deputed to Indo-China since 1954. As certain countries, which had initially agreed to contribute funds for financing the Commission, defaulted in making their contribution, the Commission was forced to curtail its activities during the last few years with a view to reducing expenditure. Further, the conditions pervailing now in Vietnam have reduced the range of effective functioning of the Commission.

पाकिस्तान के सैनिक विमानों की भारत से होकर उड़ान

4456. **श्री रणजीत सिंह** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत जुलाई से लेकर अब तक पाकिस्तान के कितने सैनिक विमानों ने भारत के ऊपर से होकर उड़ान की हैं;

(ख) उनमें से कितने विमानों ने भारत पर उड़ान की थी; और

(ग) क्या यह सच है कि जब से ये उड़ानें शुरू हुई हैं तब से एक भी भारतीय सैनिक विमान ने पाकिस्तान पर उड़ान नहीं की जबकि पाकिस्तान के अनेक सैनिक विमानों ने उपयुक्त अनुमति लेकर हमारे क्षेत्र पर उड़ान की हैं?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) 24

(ख) एक भी नहीं।

(ग) जी नहीं। इस अवधि में 23 आई० ए०एफ० विमान पाकिस्तान से हो कर गए हैं।

Tarapore Atomic Plant

4457. SHRI D. N. PATODIA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Tarapore Atomic Energy Plant would be able to supply nuclear power from April 1969;

(b) if so, what would be the supply line;

(c) whether the schemes for the distribution of the power between Maharashtra and Gujarat both for industrial and non-industrial needs have been drawn up; and

(d) if so, the details thereof ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) and (b) Power is expected to be available from the Tarapur Atomic Power Station on an 'as available when available' basis from May 1969 and at full rated capacity from July 1969.

(c) and (d). Power from this Station will be made available to both Maharashtra and Gjuarat. Its actual distribution is the responsibility of the two States.

Retired Defence Services Officers Employed in Private or Public Sector Undertakings

4458. SHRI JYOTIRMOY BASU : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the names and designations of Officers retired form defence services who have found employment either in the private sector or in the public sector and other Government departments except Defence Ministry during the last three years; and

(b) the salary and other emoluments of each of those officers ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) According to the information available, the retired Service Officers in the appended lists [*Placed in Library See. No.* LT-516/69] have found employment in the private sector or the public sector or in other Government departments except the Ministry of Defence during the years 1966 to 1968.

(b) The information is not readily available.

International Control Commission in Vietnam

4459. SHRI S. KUNDU :
SHRI S. M. KRISHNA :
SHRI P. VISHWAMBHARAN :
SHRI K. LAKKAPPA :
SHRI SURENDRA NATH DWIVEDY :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the present composition of the International Control Commission in Vietnam (I. C. C.) is proposed to be changed; and

(b) if so, what is the nature of the change proposed to be made and Government's reaction thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) The Government of India have no information in this regard.

(b) Does not arise.

American Tanks Reaching Pakistan Through other Countries

4460. SHRI INDRAJIT GUPTA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether West Germany is shortly selling over 1000 Amrican built M-47 and M-74 tanks to Italy;

(b) whether similar tanks sold by West Germany last year found their way to Pakistan thus circumvetning a West German promise that no such weapons would be sold to areas of tension;

(c) whether there is any possibility of Italy selling some of those new tanks to Pakistan; and

(a) if so, the action Government propose to take in regard thereto ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) Government have seen Press reports to the effect that the Federal Republic of Germany may sell about 800 M-47 and 300 M-74 tanks, which are no longer in service to an Italian company. Government have, however, no authentic information relating to this.

(b) According to our information this did not happen.

(c) and (d) . Government's view on the question of arms supplies to Pakistan have been made known to all friendly countries, including Italy. Government hope that these countries will agree with our assessment

Relations with Indonesia

4461. SHRI GEORGE FERNANDES : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether any positive steps have

been taken to improve India's relations with Indonesia;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is proposed to improve India's trade and cultural relations with Indonesia; and

(d) if so, in what way ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) to (d) . A statement is placed on the Table of the House.

Statement

The Joint Communique issued after the recent visit of the Indonesian Foreign Minister, outlined steps to be taken, in the future, to increase cooperation between India and Indonesia:

(i) The two Foreign Ministers reaffirmed their desire to take concerted action to enlarge and strengthen relations in the political, economic, technical and cultural fields.

(ii) Both countries recognised the need for formulating and adopting practical measures to enhance technical and economic cooperation and to promote increased trade to mutual advantage.

(iii) The Foreign Minister of Indonesia welcomed Indian investment in the Five-Year Development Plan of Indonesia as also Indian collaboration through joint industrial ventures and technical assistance.

(iv) It was decided that bilateral discussions at the official level between the two Governments would take place in Djakarata next year.

(v) The two Foreign Ministers agreed that exchanges of visits between the leaders of the two countries would further develop and strengthen mutual relations.

(vi) Both countries agreed that further discussions should take place to indentify areas of economic co-operation including commodity arrangements and to undertake studies in specific aspects of trade promotion.

(vii) It was also decided to reactivate the cultural agreement between the two countries

Export of Jute

4462 SHRI B.K. DASCHOUDHURY : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether the Food and Agricultural Orgnisation has indicated that India may be out of world market for jute during the year 1969-70;

(b) if so, the steps Government propose to take to improve the jute crop pattern; and

(c) the total quantity of jute exported during the year 1966-67 and 1957-68 ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) While reviewing the outlook for 1969-70 in the light of India's crop expectations, the Consultative Committee of the F. O A. Study Group on Jute, Kenaf and Allied Fibres had, at its meeting held in January, 1969, indicated that India was hoping to reach self-sufficiency in raw jute both 1959-70 and beyond.

(b) It is proposed to increase the production of jute and mesta by raising the yield of fibre through application of all inputs and adoption of improved agriculturals practices, double cropping in extensive areas, introduction of high-yielding strains, distribution of improved jute seeds, aerial spraying and fertilisers. A minimum support price will also be assured to the grower.

(c) 1966-67 32,777 tonnes
1967-68 12,449 tonnes

Indo-G.D.R. Economic Cooperation

4463. SHRI INDRAJIT GUPTA : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether any proposal was received from the German Democratic Republic for an economic co-operation treaty with India covering technical co-operation, financial credit and industrial collaboration, besides commercial trade;

(b) whether the G.D.R. authorities do not insist on diplomatic recognition as a pre-condition for such an agreement; and

(c) if so, the reasons for India's reported rejection of the offer ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) No, Sir.

(b) and (c) . Do not arise.

Exports from Nepal

4464. SHRI SITARAM KESRI :
SHRI HARDAYAL DEVGUN :
SHRI BENI SHANKER SHARMA :
SHRI D.C. SHARMA :
SHRI RANJIT SINGH :

Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether Government have asked Nepal to ensure that the export of certain items to India does not exceed the 1967-68 level;

(b) if so, the names of such items; and

(c) the reasons for not increasing the import of these items from Nepal ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) to (c) . As a result of the discussion between the representatives of India and Nepal held in Kathmandu in November, 1968, the Government of Nepal have agreed to limit the export of synthetic yarn fabrics and stainless steel manufactures to India to the level of 1967-68. The step had to be taken, as owing the difference in the import and fiscal policies of the two countries, unrestricted movement of these items manufactured in Nepal out of imported raw materials, had been causing difficulties.

Ceylon Economic Liberation Movements' Effect on Indian Nationals

4465. SHRI SITARAM KESRI :
SHRI D. N. PATODIA :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news items regarding the formation of a new organisation in Ceylon called the Economic Liberation Movement with the main objective of driving out Indians from Ceylon;

(b) whether the activities of the organisation have in any way prejudicially effected the Indian nationals there and the implementation of Indo-Ceylonse agreement in this regard; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) to (c) . Government have seen press report to that effect but have no information about the activities of the movement as such. Government are, however, confident that so far as Indo-Ceylon relations are concerned they will be guided and governed by the goodwill and close understanding existing between the two countries and the Agreement concluded between them.

Loss suffered by M. M. T. C.

4466. SHRI B.K. DASCHOWDHARY: Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the total amount of loss suffered

by the Minerals and Metals Trading Corporation during the year 1967-68; and

(b) the steps Government propose to take to economise the cost of exports ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) During the year 1967-68, the Minerals and Metals Trading Corporation suffered no loss.

(b) Government have embarked on several developmental scheme in the field of mining, transport and ports. These schemes include integrated projects for providing mechanical loading facilities at the ports of Visakhapatnam, Paradeep, Madras, Marmagoa and Haldia. With the completion of these Projects, considerable economies are likely to be effected in the cost exports of mineral ores.

Second Unit of Bharat Electronics Limited

4467. SHRI M. N. NAGHNOOR: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to start a Second Unit of the Bharat Electronics; and

(b) if so, whether Government are examining the feasibility and advisibility of having the same in Bangalore in the interest of economy and of low cost of production ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) Yes, Sir.

(b) All relevant aspects will be given due consideration before deciding on a suitable location.

Trade Delegation to Japan

4468. SHRI D. N. PATODIA :
SHRI CHENGALRAYA NAIDU:
SHRI N. R. LASKAR :

Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an official trade delegation was sent to Japan to assess the possibilities of increased trade with that country; and

(b) if so, the findings of the team ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) No, Sir, no trade delegation was sent recenty.

(b) Does not arise.

Loss due to Floods and Landslides in Darjeeling Tea Estates

4469. SHRI S. K. TAPURIAH :
SHRI HIMATSINGKA :

Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as a result of the unprecedented floods and landslides in the first week of October, 1968 in Darjeeling, tea estates in Darjeeling suffered heavy loss and some of them have lost as much as 25 per cent of their tea bearing land;

(b) whether the Tea Board had deputed some of its representatives to make on-the-spot study to assess the damage caused to the tea estates in that area;

(c) whether any central aid had been given provisionally to the tea estates for revitalising and whether the life Insurance Corporation of India also gave such aid;

(d) if so, the extent of such aid given by each agency and the form in which such aid has been given; and

(e) whether the on-the-spot study by the Tea Board has been completed and if so, the findings thereof and the further aid proposed to be given to these estates in the light thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND

SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) and (b) . Yes, Sir.

(c) and (d) . The Tea Replantation subsidy Scheme has been extended to cover replacement areas lost. Crant of loans to estates affected towards cost of repairs/ reconstruction of factory buildings, plant and machinery damaged is contemplated. Financial assistance to the tune of Rs. 16 lakhs in the form of loans and subsidy for the reconstruction of labour houses in the area during the current financial year has been agreed to. Out of this, an amount of Rs. 4 lakhs is expected to be disbursed by the West Bengal Government by 31-3-1969 The West Bengal Government also propose to utilise the latest Life Insurance Corporation of India loan allocation of Rs 10 lakhs for the grant of housing loans to the affected estates, subject to the terms and conditions laid down in this behalf.

(e) On-the-spot study by the Tea Board's officer to ascertain the loss/damage caused to the estates is still in progress.

Export of Products of Commercial Crops

4470. SHRI S. K. TAPURIAH :
SHRI HIMATSINGKA :
SHRI SITARAM KESRI :

Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state the present yearly exports of products of commercial crops and to what extent their exports are likely to be increased during the year 1970-71 ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : The annual exports of India's commercial crops and products thereof during the years 1966-67 and 1967-68 were of the order of Rs 732.46 crores and Rs 740.94 crores respectively. The level of exports of these products is expected to increase during the coming years, depending on favourable climatic conditions and other factors. It is therefore not possible to specify the exact extent of the likely increase.

Export of Marine Products

4471. SHRI R. K. SINHA : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the total quantity of Marine products exported during the years 1967-68 and 1968-69;

(b) the amount of foreign exchange earned by these products for the same pereiod; and

(c) the steps being taken to step up the export?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) and (b). The total quantity of Marine products exported and the amount of foreign exchange earned during the years 1967-68 and 1968-69 (upto January, 1969) are as follows :-

Year	Quantity (Tonnes)	Value (Rs. crores)
1967-68	21907	19.72
1968-69 (upto Janury 1969)	20330	18.19

(c) (i) With a view to increase the export of canned/frozen shrimps a Seafood delegation was sent recently to U. S A., Mexico, Canada, U. K., France and Belgium to study the market in these countries.

(ii) Under the import policy for Registered Exrporters of Fish and fish products, Import Licence to the extent of 10% of the F.O.B. value of exports are issued to cover the ineport requirements of the industry.

(iii) In order to improve the quality of the products exported, compulsory quality control and preshipment inspection has been introduced for most of items of marine products.

Formation of an Asian Economic Community

4472 SHRI R. K. SINHA : Will the Minister of FOREIGN AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether India and Ceylon have explored the possibilities of forming an Asian Economic Community during the talks between the representatives of the two countries on economic cooperation held in January, 1969; and

(b) if so, the reaction of the Asian Countries to the proposal ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) No, Sir. A copy of the Communique issued after the talks, has already been placed on the Table of the Housein reply to parts (d) and (e) of Starred Question No. 450 answered on March 12,1969.

(b) Does not arise.

Market for Industrial Goods Manufactured by Ceylon

4473. SHRI BENI SHANKER SHARMA :
SHRI D C SHARMA :

Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether the desirability of providing a limited market to industrial goods which Ceylon is in a position to manufacture because of her natural endowisments like rubber etc. as a first step towards Asian Corporation has been examined;

(b) if so, with what result; and

(c) the steps proposed to be taken in the matter ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) to (c). The matter was, *inter-alia* generally considered by the Indo-Ceylon Joint Committee on Eocnomic Cooperation at its first meeting in Colombo in January, 1969. The Committee identified certain commodities where a potential existed for expansion of mutual trade, and it was decided to set up a small Woking Group consisting of representatives of the two Governments to recommend arrangements, where approriate, for expansion of trade beween the two countries in these commodities.

All India Drugs and Pharmaceuticals Manufacturers Association

4474. SHRI TENNETI VISHAWANATHAN : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the All India Drugs and Pharmaceutical Manufacturers Association have represented to Government that compulsory export imposed on them should be kept in abeyance for five years; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) Yes, Sir.

(b) Suggestions made are being examined.

Indo-Nepal Trade Treaty

4475 SHRI D. N PATODIA :
SHRI CHENGALRRAYA NAIDU:
SHRI N R. LASKAR :
SHRI ONKAR LAL BERWA :
SHRI R. K. SINHA :

Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India has pointed out to the Government of Nepal that since the signing of the *aide-memmoire* between the two countries, the trade between

the two countries has not proceeded on the lines as was desired; and

(b) if so, the reaction of the Government of Nepal in the matter and whether the trade treaty between the two countries is likely to be amended suitably ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK): (a) and (b). No *Aide-Memoire* has been signed as such between India and Nepal. Presumably the Hon'ble Members have in mind the agreements reached at the trade talks held in Kathmandu in November, 1968, between the representatives of the two Governments. A copy of the Joint press Report issued on the conclusion of the talks has already been placed on the Table of the House on November 19, 1968. The Treaty of Trade and Transit between the Govrenment of India and H. M G. of Nepal is valid up to October 31, 1970. No amendment in the provision of the Treaty is contemplated at present.

जापान को लौह-युक्त मेंगनीज का निर्यात

4476. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जापान को लौह-युक्त मेंगनीज का निर्यात करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी है, और इस बारे में हुए करार का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). भारत से निर्यातित मेंगनीज अयस्क में लौहा भिन्न-भिन्न अनुपात में होता है जो अयस्क के ग्रेड पर निर्भर करता है। वर्ष 1969 में सुपुर्दगी के लिए निम्नलिखित परिमाण में मेंगनीज अयस्क जापान को बेचा गया :-

(1) फेरूजिनस मेंगनीज अयस्क (30 प्र० श० मेंग० 16-18 प्र० श० लौह सहित) जिसमें स्युर 'मी' (30/32 प्र० श० मेंग० 20-22 प्र० श० लौहा सहित) —4 लाख टन

(2) मेंगनीज फेरम अयस्क (27/28 प्र० श० मेंगनीज 23-25 प्र० श० लौह सहित) –2 लाख टन (अनुमानतः)

(2) काला लौह अयस्क (5-8 प्र० श० मेंग० 48-52 प्र० श० लौह सहित) —1 लाख टन (अनुमानतः)

Second Fleet at Visakhapatnam

4477. SHRI LOBO PRABHU :
SHRI D. N. PATODIA :

Will the MINISTER OF DEFENCE be pleased to state :

(a) whether new vessels and institutions will be added to the second fleet to be constituted at Visakhapatnam; and if so, the estimated cost;

(b) the number of new posts to be created and the additional cost involved thereby;

(c) the advantages that will arise which are not possessed by the existing base at Visakhapatnam; and

(d) which country is assisting in its construction ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) to (d). A Russian team of experts assisted in preparing a project report for setting up naval facilities at Vishakhapatnam. The work of construction is entrusted to Indian engineers. The development of these naval facilities is a part of the programme for strengthening the

Indian Navy and will particularly help the deployment of the Navy along our eastern coast.

Profit Earned by S. T. C.

4478. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the norms followed by the State Trading Corporation in determining the cost of the goods it imports for sell to the trade or to the industry;

(b) the margin that it keeps for service charge or as 'profit' ; and

(c) how often that is changed and has been changed and has been changed with particulars thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) and (b). The selling price of goods imported by S. T. C. is fixed by the Corporation adding a suitable margin to the landed cost, the margin takes into account expenses on clearings, storage, interest on investment and in certain cases, the gap between landed cost of imported material and internal price of material available within the country.

The quantum of the margin varies from item to item having regard to the above factors.

(c) There is no rigidity about the margin and the periodicity of change in prices. The release prices of such commodities change as and when considered necessary depending upon the actual operation of the various factors enumerated above.

Inclusion of West Germany in Development Decade Committee

4479. SHRI R. BARUA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether West Germany is proposed to be included in the preparatory Committee for the Second Development Decade of United Nations; and

(b) if so whether this move is resisted by any of the big powers and the reaction of India thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): (a) The Federal Republic of Germany was nominated to the Preparatory Committee for the Second Development Decade by the President of the United Nations General Assembly.

(b) USSR, Poland, Bulgaria, Rumania and Byelorussia, which were also nominated to this Committee, are opposed to the inclusion of the Federal Republic of Germany and are not therefore attending its meetings.

India is a member of this Committee and is participating in its work. The Government have expressed the hope that having regard to the importance of the Second Development Decade, the Socialist Bloc countries will find it possible to cooperate in the formulation and implementation of an international development strategy for the next decade.

Indian Consultancy Services

4480. SHRI HARDAYAL DEVGUN :
SHRI BENI SHANKER SHARMA :
SHRI D. C. SHARMA :
SHRI RANJIT SINGH :

Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether the Indian Engineering Association has suggested that facilities of the Export Credit and Guarantee Corporation be extended to Indian Consultancy Services to facilitate the export of Indian technical know-how;

(b) whether it is a fact that the Consultancy organisations in this country are

not thriving because of the general lack of of appreciation of the quality and range of services that they can provide; and

(c) if so, the reaction of Government thereto and the steps proposed to be taken in the matter ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) Yes, Sir.

(b) Consultancy services have been built up in the country recently and even during the short period of their functioning consultancy organisations have started handling a sizeable volume of business. These services are also being utilised in overseas countries as part of turn-key projects executed by Indian exporters.

(c) Government have already taken a number of steps to encourage consultancy services :

(i) Utilisation of indigenous technical consultancy services is steadily on the increase.

(ii) the employment of foreign technicians and foreign technical know-how is permitted unless equivalent technical personnel and know-how is not available in the country.

(iii) the suggestion to grant insurance and guarantee facilities in respect of export of services is being considered by the Export Credit and Guarantee Corporation.

(iv) Income consisting of dividends, royalties and fees derived through export of technical know-how and technical services, is wholly exempt from income tax.

Indefinite Hunger Strike Decision by All-India Defence Employees Federation

4481. SHRI UMANATH :
SHRI MOHAMMAD ISMAIL :
SHRI A. K. GOPALAN :
SHRI K. M. ABRAHAM :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the decision taken by the executive Committee of the All-India Defence Employee's Federation that the members of the executive would start indefinite hunger strike in front of Parliament House from March 24, 1969;

(b) if so, the main demands of the employees; and

(c) the steps taken by Government to avoid such a situation ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) and (b) . Yes, Sir. According to press reports, the main demands of the AIDEF related to the reinstatement of employees whose services had been terminated for participation in the strike of September 1968, withdrawal of court cases and cancellation of show cause notices for derecognition of Unions.

(c) Two policy decisions regarding persons who had participated in illegal strike of 19th September, were announced in October, 1968 and January, 1969 respectively. All cases brought to the notice of Government regarding alleged non-implementation of these two policy decisions, have been duly reviewed and Government are satisfied that all action required to be taken in persuance of the Government decisions, has been taken in these cases. Government announced a further relaxation in March 1969, instructions regarding which have been duly conveyed to all concerned establishments for early implementation.

Reinstatement of Employees who Participated in the Sept. 1968 Strike

4482. SHRI MOHAMMAD ISMAIL :
SHRI NAMBIAR :
SHRI K. ANIRUDHAN :
SHRI A. K. GOPALAN :

Will the Minister of DEFENCE be

pleased to state :

(a) the total number of Defence employees whose services have been terminated for participation in the September, 1968 strike; and

(b) the number of employees taken back in view of the declaration of leniency by Government ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) and (b). Information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as possible.

Import of Natural Rubber

4483. SHRI VASUDEVAN NAIR : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the total quantity of natural rubber proposed to be imported in the year 1969-70 .

(b) whether any quantity licensed for the year 1968-69 is yet to be imported; and

(c) if so, the quantity that remains to be imported against the licences already issued ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) No decision has so far been taken in regard to the import of natural rubber during 1969-70.

(b) Yes, Sir.

(c) Against the licences issued for the import of 15,500 tonnes of natural rubber, import to the extent of about 10,500 tonnes would have arrived by the end of March, 1969. The balance quantity of about 5,000 tonnes is expected to be imported after March, 1969.

उर्वरकों का आयात

4484. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री लखन लाल गुप्ता :

क्या **वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उर्वरक के आयात की व्यवस्था करने के हेतु विदेशों में अपने प्रतिनिधि भेजने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उर्वरकों की खरीद किस तरह की जायेगी ?

वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) . यह निर्णय किया गया है कि जहां प्राप्त होने वाले उधार की शर्तों में बातचीत की पद्धति का निराकरण न किया गया हो, जैसे कि यू० के०, पश्चिमी यूरोप और जापान के सम्बन्ध में है, वहां उन से उर्वरकों की खरीद के लिए की जाने वाली बातचीत साधारणतया भारत में ही की जानी चाहिये । परन्तु खरीद के प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को देखते हुए छूट दी जा सकेगी । अमेरीका और केनेडा से उधार पर की जाने वाली खरीद के लिए टेन्डर मंगवाने की पद्धति ही जारी रहेगी, क्योंकि उन देशों के ए० आई० डी० विनियमों के अधीन बातचीत की पद्धति की अनुमति नहीं है । निर्बाध विदेशी मुद्रा पर उर्वरकों की खरीद विश्व-टेन्डरों द्वारा की जाएगी ।

मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र

4485. **श्री ग० च० दीक्षित** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968-69 में मध्य प्रदेश में

कुछ नये क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों का विकास करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कुछ नई योजनाएं शामिल किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) वर्ष 1968–69 के दौरान राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश का कोई भी नया क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

मध्य प्रदेश में शक्तिचालित करघे

4486. **श्री गं० च० दीक्षित** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार ने मध्य प्रदेश में कितने शक्तिचालित करघे स्थापित करने की मन्जूरी दी तथा राज्य सरकार द्वारा किये गए उनके नियतन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने अन्य राज्यों को भी ऐसे करघों की मन्जूरी दी है ;

(ग) यदि हां, तो कितने राज्यों को और प्रत्येक राज्य के लिए कितने शक्तिचालित करघे नियत किए गये हैं;

(घ) क्या शक्तिचालित करघे मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों को भी दिए गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन सहकारी समितियों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक समिति को कितने कितने करघे आवंटित किए गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) मध्य प्रदेश को 4,700 शक्तिचालित करघों का आवंटन किया गया है । राज्य सरकार द्वारा किये गए आवंटन के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जायेंगे ।

(ख) जी हां ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या LT-517/69]

(घ) जी हां ।

(ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Trade with Thailand

4487. SHRI MAYAVAN : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether any agreement for the expansion of trade with Thailand was entered into; and

(b) if so, the main items for exports to Thailand ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) The Trade Agreement was concluded between India and Thailand on December 3, 1969. Trade talks were also held on February 21st and 22nd between the Indian Delegation and a visiting Thai Delegation in which commodities and items where a potential existed for expansion of mutual trade exchanges between India and Thailand were identified.

(b) In 1967-68, India's main export to Thailand consisted of iron and steel items and petroleum products.

Pension Benefits to Master Craftsmen

4488. SHRI BAL RAJ MADHOK :
SHRI D. C. SHARMA :

Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether a scheme to provide pension benefits to master craftsmen was under the consideration of Government;

(b) if so, the decision taken in the matter; and

(c) the steps proposed to be taken to implement the same ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK): (a) to (c). The scheme is to grant financial assistance to master craftsmen who are in indigent circumstances. This is under consideration of the Government.

Historical Section in the Ministry of Defence

4489. SHRI BAL RAJ MADHOK :
SHRI RANJIT SINGH :
SHRI BENI SHANKER SHARMA :
SHRI D. C. SHARMA :
SHRI HARDAYAL DAVGUN :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether a historical section is functioning in the Ministry of Defence;

(b) the date when the historical section came into being;

(c) the documents that the historical section has produced so far (i) for public consumption and (ii) for distribution within the Armed forces; and

(d) whether any history of the Kashmir compaign has been written by this section ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) In July 1945 a Combined Inter-Services Historical Section under General Headquarters was established. Subsequently, it was reorganised and in April, 1948 was placed directly under the Ministry of Defence.

(c) 24 volumes of Official History of India Armed Forces in World War II have been produced and published and have been on sale. Three more books *viz.* History of the Corps of Engineers, Police Action in Hyderabad and Libration of Goa, have been completed by the Historical Section and arrangements for their printing are in hand. These books will also be available to the general public. In addition, a book "Military Evacuation Organisation" and 28 Monographs on various subjects have been published as restricted documents for officicals use only.

(d) Yes, Sir. The draft on J & K Operations (1947-48) has been completed and it is presently under scrutiny.

Performance of Commanders in Indo-Pak War

4490. SHRI BAL RAJ MADHOK :
SHRI RANJIT SINGH :
SHRI BENI SHANKER SHARMA :
SHRI D. C. SHARMA :
SHRI HARDAYAL DEVGUN :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether a number of Commanders from the Company level to the Divisional level were alleged to have performed badly in the Indo-Pak War of 1965;

(b) how many of such officers were removed from service or punished;

(c) whether there have been subsequent representations against these summary actions; and

(d) whether an inquiry in the whole matter is proposed to be held ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) and (b) . As a result of disciplinary action taken, 11 officers were either dismissed or made to resign/retire and 24 officers of the acting ranks of Lt.Col. and above were reverted to their substantive ranks Information regarding officers of lesser acting ranks reverted is not readily available.

(c) and (d) . Representations and appeals were put in by some of the officers and these have been dealt with in accordance with normal procedure. No further enquiry is proposed to be held in the matter.

Soames-de-Gaulle Talk on new Free Trade Area in Europe

4491. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the Soames-De-Gaulle talk on the proposal for a new free trade area in Europe with a inner political council consisting of Britain, France, West Germany and Italy;

(b) whether Government have studied the implications of this proposal for Indian's exports; and

(c) what steps Government have taken to stimulate India's exports to the Common Market countries on the one hand and European Free-Trade Area on the other ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) Government have seen the press reports regarding the talk mentioned by the Hon'ble Member but are not aware of any formal proposal regarding a new free trade area in Europe.

(b) Does not arise.

(c) The steps taken by the Government of India to stimulate her exports to the European Common Market and the European Free Trade Area (EFTA) countries are two-fold :

(i) As a result of our diplomatic approaches to the Commission and the council of Ministers and the member countries of the European Economic Community (EEC) and to the governments of EFTA COUNTRIES,AS WELL AS OUR EFFORTS IN GATT UNCTAD and other international forums, valuable concessions for India's trade in items such as tea, Cashew Kernels, tropical spices, East India Kips, Handloom textiles. Mill-made cotton textiles etc. have been secured.

(ii) Following trade promotional measures have been taken to promote our exports to the EEC as well as EFTA :

(1) Participation in trade fairs and exhibitions held in these countries and organisation of India Weeks to show the range and quality of Indian products.

(2) Sending of trade delegations and sales teams to study the marketability of India's products and to conclude business contracts.

(3) Inviting trade delegations/purchase teams from these countries to visit India.

(4) Publicity for India's products through various publicity media.

(5) Opening of overseas offices by Export promotion Councils/Com-

modity Boards as well as private and public sector undertakings.

(6) Training of personnel from export oriented sectors in India in the field of trade promotion.

Activities of I. C. C. Delegates in Laos

4492. SHRI E. K. NAYANAR : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Government of India are aware that the Laotian Patriotic Front has protested against the illegal use of the Power of the International Commission in Laos by the Indian and Canadian delegates for an investigation trip to Thateng Village in Lower Laos at the request of Vientins in February, 1969; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) and (b). The International Control Commission in Laos visited Thateng in January, 1969 to study the developing tension in the area which had been reported to it by the Royal Lao Government. The Neo Lao Haksat took the view that this activity of the Commission was in contravention of Article 19 of the Geneva Protocol to the declaration of neutrality of Laos. However, the majority view in the Commission was that the decision taken by the Commission was in accordance with the Geneva Protocol of 1962 concerning Laos. The Government of India accepts this view.

Manufacture of Commercial and Passenger Aeroplanes

4493. SHRI K. LAKKAPPA :
SHRI A SHREEDHARAN :
SHRI JUGAL MONDAL :
DR. SUSHILA NAYAR :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the target in regard to the manufacture of commercial and passenger aeroplanes in the country is behind the schedule;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the annual demand of commercial and passenger aeroplanes in the country; and

(d) the time by which the country will become self-sufficient in this field ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). These aspects are being examined by the Aeronautics Committee appointed by Government in 1968. A decision regarding the policy to be followed in future for indigenous manufacture of aircraft will be taken after consideration of the report of the Aeronautics Committee.

Complaints Against the Indian Chairman of International Control Commission

4494 SHRI INDRAJIT GUPTA :
SHRI GEORGE FERNANDES:
SHRI SAMAR GUHA :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether serious complaints have been received regarding the behaviour and attitude of the Indian Chairman of the International Control Commission in Vietnam;

(b) whether any inquiry has been hed into the complaints; and if so, by whom; and

(c) the findings of the inquiry and action, if any, taken thereon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) to

(c). The Government of India had received some complaints regarding living conditions of the Indians serving in the I. C. S. C., Vietnam, arising out of the large influx of refugees and the difficulties of better accommodation and because of the poor financial condition of the Commission consequent on non-payment of contributions by some of the contributory powers. In order, therefore, to study the finances of the Commission and essential reductions in the personnel, an Inter-Ministerial Team visited Vietnam in July 1968. The main recommendations of this Team have since been implemented.

Report of Borooah Committee on Indian Tea Industry

4495. SHRI S. K TAPURIAH : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 163 on the 25th February, 1969 and state :

(a) whether the report of the Borooah Committee on Indian Tea Industry dominated the proceedings of the Conference of tea producing countries held under the auspices of the Food and Agricultural Organisation at Kampala; and

(b) if so, the main observations and recommendations made by it in the light of that report and the decision/action taken by Government in view of these recommendations and observations ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) The conference dealt with many of the matters dealt with in the Borooah Committee Report.

(b) Does not arise.

Transfer of Actual Users' Licences for Import of Synthetic Yarn

4496. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Miniser of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether Goverment's attention has been drawn to the observations made by the Public Accounts Commitee in its Fiftieth Report (Third Lok Sabha) on the illegal amendment and transfer of actual users'licences for the import of synthetic yarn.

(b) whether Government have snbmitted any action taken Report to the Public Accounts Committee;

(c) whether any action has been taken against the officials and the firms involved in this transaction; and

(d) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) and (b) . Yes, Sir.

(c) and (d) . Prosecutions under Section 5 of the Improts and Exports Control Act, 1947 against 27 licensee mills as well as partners/directors of Messrs. Madhusudan Gordhandas and Company and Messrs. Dhanraj Mills Private Limited are pending in the courts at Bombay. In addition, the partners/directors of Messrs. Madhusudan Gordhandas and Company and Messrs. Dhanraj Mills Private Limited respectively are also being charged under Section 120-B read with 420 IPC. As regards the complicity of the Govt. officers the matter is under investigation.

Imported Machines remaining Idle in Praga Tools Ltd.

4497. SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : Will the Minister of DEFENCE be pleaced to state :

(a) the percentage of machines imported by Praga Tools Ltd., during the period from the 1st January, 1964 to 31st December, 1968 that remained idle for over one year;

(b) whether these machines remained idle as purches were not planned properly ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) The total number of machines imported by Praga Tools during the period from 1st January, 1964 to 31st December, 1968 was 49 out of which 8 *i.e.* 17% remained idle for over one year.

(b) and (c) . In case of three machines the purchase was not planned properly. These were procured by Praga Tools for an Expansion Project under Polish Credit which was ultimately not implemented. Out of the remaining, two machines were purchased for jobs which were later off loaded to Praga's ancillary Units. These machines have since been commissioned and used on alternate Jobs. Three machines received in 1967 for the Pratt Lathe Chuck Project remained idle because of delay in the commissioning of this Project.

Manufacture of Spare Parts of Aircrafts

4498. SHRI JUGAL MONDAL : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether any steps have been taken to manufacture spare parts of aircrafts in the country which are at present imported from abroad; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) and (b) . Consistent with economics of production, spare parts of aircraft are being manufactured to the extent possible A proposal for the setting up of Accessories Division by Hindustan Aeronautics Ltd., for the manufacture of Flight and general Instruments, wheels and brakes, hydraulic equipment and other general accessories is under consideration.

Total Area of India

4499. SHRI JUGAL MONDAL : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total area of India as in 1934, as on 1st November, 1947 and to-day;

(b) if there is a difference in these three figures what is the extent of the difference and the reasons therefor in detail; and

(c) how much area of India is in the hands of China and Pakistan ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) and (b) The total area of India as in 1934, according to the then programme of survey was 48,81,339.3 rq. kms. Following the partition of India, new area figures had to be worked out. The area figures have not been computed as on 1st November, 1947. The present area of India is given as 32,68,090 sq kms. The difference is due to changes in the territory of India since 1934, and improved techniques of survey.

(c) Approximately 4,500 sq. miles are under the illegal occupation of China and approximately 32,500 sq. miles under the illegal occupation of Pakistan.

Self-sufficiency in Production of Rubber Jute and Tea

4500. SHRI JUGAL MONDAL : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state the steps taken by Government to attain self-sufficiency in the matter of production of Rubber, Jute and Tea ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : It is proposed to increase the production of Jute and mesta by double cropping in extensive areas, introduction of high yielding strains and adoption of intensive cultivation methods.

The increase in production of tea is to be achieved by intensive cultivation, use of high yielding planting material and higher application of fertilisers. The Replantation

subsidy Scheme announced recently for helping the industry in carrying out replantation of old tree areas is also expected to give a fillip to the tea production

As regards, rubber, steps are being taken to increase its production, but self-sufficiency is not expected to be achieved by the end of the Fourth Five Year Plan. A statement indicating the steps that are being taken to increase the production of rubber is given below.

Statement

The following Schemes are being implemented by the Rubber Board in order to increase the production of natural rubber :

(1) Payment of a replanting subsidy at the rate of Rs. 1,000/-per acre to all rubber growers.

(2) Grant of loans to small growers to increase their acreage so as to increase production and turn their holding into economic units.

(3) Maintenance Loans are sanctioned to small growers for proper maintenance of immature areas planted with high yielding plants.

(4) High-yielding planting materials are given to the small growers at subsidised costs.

(5) The Board is maintaining regional nurseries and is supplying to the growers high-yielding materials from its own nurseries or collected from approved resources.

(6) The Board arranges to supply fertilisers, fungicides and sprayers to small growers through Cooperative Societies and also arranges for aereal spraying. Free technical advice is given to the growers by the Board. Fertilisers are given to small growers at subsidised rates.

(7) The Board has started a Rubber Pilot Project in the Andaman and Nicobar Islands, which is designed to be an experiment-*cum*-demonstration plantation and will establish the technical feasibility of rubber cultivation and also serve as model for other enterpreneures.

(8) The Board is exploring the possibilities of utilisation of new areas for rubber cultivation. The Board has advised the Government of the States where certain areas are considered suitable for rubber cultivation, to release such areas for planting rubber.

2. Besides the above Schemes, Government of Kerala have set up the Kerala Plantation Corporation Ltd., with a view to undertake rubber cultivation. Government of India have accepted this as a centrally sponsored scheme and are giving 100% loans assistance to the State Government for investment in the share captital of the Corporation. The corporation has already planted about 15,000 acres under rubber and plans to bring in additional acreage under rubber during the IV Plan period.

Issue of Import/Export Licences

4501. SHRI JUGAL MONDAL : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the names and addresses of the Companies which were granted export licences during the last three years together with the items for which licences were given;

(b) the names of firms which applied for export licences; and

(c) the names of the firms which are being given licences continuously for the last three years ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) and (c). Details of export licences issued are published in the 'Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences', copies of which are available in the parliament Library.

(b) The number of applicants is over a lakh and the time and labour involved in compiling the information will not be commensurate with the advantage to be derived therefrom.

Diplomatic Relations with Israel

4503. SHRI JUGAL MONDAL : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the question of establishing diplomatic relations with Israel has been considered afresh by Government; and

(b) if so, the decision taken thereon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Implementation of Tashkent Declaration

4504. SHRI K. P. SINGH DEO :
SHRI D. N. PATODIA :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the views expressed by the Chairman of the Supreme Soviet, USSR during his recent Press Conference as reported in "Patriot", dated the 21st February, 1969 regarding slow implementation of the Tashkent Declaration; and

(b) if so, the reaction of Government in regard thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) The House is aware that Government have made a number of proposals for implementation of the Tashkent Declaration, to Pakistan. The lack of progress in this matter is due to the Government of Pakistan's unconstructive attitude to our proposals.

Lac Board

4505. DR. SUSHILA NAYAR :
SHRI A. SREEDHARAN :
SHRI VALMIKI CHOUDHARY:

Will the Minister of FOREIGN TRDE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to set up a Lac Board in the country;

(b) if so, the main objectives for setting up the Board;

(c) the financial implications thereof; and

(d) the time by which it is likely to be set up ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) No, Sir.

(b) to (d) . Do not arise.

Trade Negotiations with USSR, Italy, France and Japan

4506. SHRI R. K. BIRLA : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India is having trade negotiations with USSR, Italy, Japan and France;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government propose to consult trade and industry before finalising and deal with these countries ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) and (b). No trade negotiations are taking place with USSR, Japan and Italy at present. Trade negotiations were held with France from 7th March to 11th March, 1969, the details of which are given in the statement given below.

(c) Export Promotion Councils and Commodity Boards are usually consulted before the negotiations are finalised.

Statement

Indo-French Trade Agreement originally concluded in 1959 and renewed from time to time has been renewed for a further period of one year from 1st January, 1969.

It provides for increased quotas for Indian Products which are subject to quantitative restrictions in France as under :-

Item	Increase in Quotas (In Million French Francs) From 1968	To 1969
Dried Mushrooms	1.500	2.000
Woollen Hosiery	0.200	0.220
Clothing other than cotton	0.650	0.720
Tennis and basket-ball shoes	0.660	0.800
Fairs and Exhibitions	0.750	0.800
Miscellaneous products	0.600	0.650

All quantitative restrictions on the Import of onions into France from India have been abolished for the period 1st March, 1969 to 15th May, 1969.

In has also been agreed that licences for the import of articles made of Coir from India into France will henceforth be visaed by the Indian Embassy in Paris.

Production of Jute

4507. SHRI BENI SHANKER SHARMA: Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the quantity of jute expected to be produced in India during the current year;

(b) the approximate quantity of consumption by the jute mills in India;

(c) how the gap between consumption and production is proposed to be filled ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) to (c). The jute industry is faced with shortage of raw material in view of an exceptionally short crop this year. The estimated jute and mesta production in 1968-69 is unlikely to exceed 48.50 lakh bales. Even with the carryover stock of last season and the imports of raw jute, there will be a sizeable gap between the availability and normal requirements of fibre. The normal consumption requirements are of the order of about 72 lakh bales. In view however, of the shortage, consumption is being regulated in a planned manner in accordance with the availablity of fibre, since November, 1968.

Centaur Rocket Launched at Thumba Rocket Centre

4508. SHRI BENI SHANKER SHARMA :
SHRI D. C SHARMA :
SHRI HARDAYAL DEVGUN :
SHRI RANJIT SINGH :
SHRI BAL RAJ MADHOK :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether a Centaur rocket made in India was launched from the Thumba rocket centre on the 26th Februray, 1969;

(b) if so, the salient features of the rocket fired; and

(c) the advance made so far by India in rocketary ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) Yes Sir.

(b) The Centaur rocket manufactured in India is a two-stage sounding rocket. The rocket launched from Thumba carried a payload weighing 32 kgs. and reached an altitude of 150 kgs. The rocket vehicle was manufactured at the Central workshops of the Bhabha Atomic Research Centre. The charging of the vehicle and payload integration was done at Thumba.

(c) Facilities have been established for the regular production of Centaur rocket vehicles and propellant required for fuelling them. Work on import substitution of materials used in the manufacture of Centaur rockets is in progress. A Rocket Fabrication Facility is being established at Thumba. This facility which is scheduled to be completed by April, 1970, will undertake fabrication of Centaure and other rockets indigenously designed and developed at the Space Science and Technology Centre and the Thumba Equatorial Rocket Launching Station.

Resignations by Elected members of Cantonment Boards

4509. SHRI S M JOSHI :
SHRI RANJIT SINGH :
SHRI JAGANNATH RAO JOSHI :
SHRI RAM GOPAL SHALWALE :
SHRI BRIJ BHUSHAN LAL :
SHRI ATAL BIHARI VAJPAEE :
SHRI SURAJ BHAN :
SHRI NITRAJ SINGH CHAUDHARI :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the elected members of the Poona, Kirkee, Dehu, Aurangabad, Ahmednagar and Jabalpur Cantonment Boards have resigned from the Boards against indifferent attitude of the Central Government;

(b) whether it is a fact that their demand is for the withdrawal of certain Government of India letters by which the power of the elected members are curtailed;

(c) whether the non-withdrawal of these letters have hampered building activity in the civil areas;

(d) whether it is a fact that Government have not acknowledged even the resolutions of the All India Cantonment Boards' Elected Members Conference held in January last, sent to them; and

(e) whether some members had asked for an interview but the Defence Ministry has failed to grant it and if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) and (b). Communications tendering resignation have been received by Government from most of the elected members of the Cantonment Boards Poona, Kirkee, Dehu Road, Aurangabad, Ahmednagar and Jabalpur. The main reasons mentioned in these communications are firstly that the Cantonments Act should be revised and in particular, the term of the elected members increased from 3 to 5 years and secondly that the instructions contained in the Government letter of 23rd March, 1969 requiring 'Old Grant' holders to obtain leases before making new construction, reconstruction, change of purpose, sub-division etc. in civil area be withdrawn.

(c) No, Sir.

(d) and (e). In response to a request received from the General Secretary of the All India Cantonment Elected Members Conference, an interview has been arranged with the Defence Minister on 1st April, 1969.

Cantonment Board Act, 1924

4510. SHRI S. M. JOSHI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the present Cantonment Board Act, 1924 is outmoded; and

(b) if so, when Government propose to amend it suitably to meet the requirements of the present situation ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) and (b) . The Cantonments Act, 1924, requires certain amendments. A Bill incorporating the requisite amendments is proposed to be introduced in Parliament.

Eligibility for Appearing in I. M. A. Examination

4511. SHRI VALMIKI CHOUDHARY: SHRI NIHAL SINGH :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the students who pass the firsty year of Jamia Rural Institute Delhi are eligible to appear in the Indian Military Academy entrance examination; and

(b) if so, the reasons for not accepting the candidates for the said examination who pass the first year of Delhi polytechnics when there is no difference in the courses and duration of both the institutions ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) Yes, Sir, so far as diploma course in rural services is concerned.

(b) It so happens that, amongst the qualifications prescribed so far, this qualifications does not feature. The whole question, however, is due for a review which Government propose to undertake following the expected recommedations of a Committee set up to make recommendations regarding qualifications for admission to the National Defence Academy and related matters.

विदेशी भाषाओं के स्कूल में शिक्षा का माध्यम

4512. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**
श्री ना० रा० पाटिल :
श्री जगेश्वर यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे विदेशी भाषाओं के स्कूल में शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी है : और

(ख) यदि हां, तो विदेशी भाषाओं को पढ़ाने के लिए हिन्दी को शिक्षा का माध्यम न बनाने के क्या कारण हैं जबकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन के लिए हिन्दी को शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू किया गया है और इस बारे में प्रशिक्षक और पुस्तकें उपलब्ध हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) जी हां ।

(ख) स्कूल में हिन्दी को विदेशी भाषाएं सिखाने के लिए शिक्षा के माध्यम के तौर पर, अभी निम्न कारणोंवश पुरस्थापित कर पाना सम्भव नहीं हो पाया है ..

(1) विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण पा रहे छात्रों की एक संख्या को हिन्दी में काफी ज्ञान प्राप्त करना है, और

(2) प्राध्यापकों की कुछ श्रेणियों उपयुक्त योग्यता प्राप्त, भारतीयों की अप्राप्यता के कारण विदेशियों द्वारा पूरी की जाती है ।

आयुध कारखानों में निर्मित बन्दूकें

4513. **श्री शशि भूषण** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या आयुध कारखानों में बनाई जा रही 315 और 12 बोर की बन्दूकें जनता के लिये उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका मूल्य क्रमश: क्या क्या है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि . 315 बोर की बन्दूकें निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर बेची जा रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) 12 बोर की आर्डनेन्स फैक्टरियों में बनाई गई डबल बैरल ब्रीच लोडिंग शाटगन आयुधों और गोली बारूद के रजिस्टर शुदा विक्रेताओं के माध्यम से जनता को विक्रय के लिए प्राप्य है ।

.315 राईफल का निर्माण 1962 की आपात स्थिति के दौरान स्थगित कर दिया गया था, परन्तु हाल ही में पुन: आर्डनेन्स फैक्टरियों में हस्तगत कर लिया गया है और आशा है कि यह राईफलें निकट भविष्य में बाजार में बिकने लगेगी ।

(ख) बाजार में 12 बोर की बी० बी० एल० गन की कीमतें इस प्रकार नियत की गई हैं:—

1. नान ईजेक्टर पैटर्न 2¾" चैम्बर (नान एन्ग्रेव्ड) 950 रुपये प्रतिगन

2. नान ईजेक्टर पैटर्न 2¾" चैम्बर (एन्ग्रेव्ड) 1150 रुपये प्रतिगन

3. ईजेक्टर पैटर्न 2¾" चैम्बर (नान-एन्ग्रेव्ड) 1150 रुपये प्रति गन

4. ईजेक्टर पैटर्न 2¾" चैम्बर (एन्ग्रेव्ड) 1350 रुपये प्रति गन

जहां तक .315 राईफलों का सम्बन्ध है उनकी कीमतें यथासमय नियत की जायेंगी, जब वह विक्रय के लिए तैयार हुई ।

(ग) तथा (घ) . प्रश्न नहीं उठते ।

Military Agricultural Farms

4515. SHRI P. R. THAKUR : Will the MINISTER OF DEFENCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 546 on the 13th November, 1968 regarding Military Agricultural Farms and state :

(a) whether the information has since been collected :

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, when it is likely to be made available ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) The requisite information is gievn in the statement laid on the table of the House. [*Placed in library. See* **No.** LT-518/69].

(c) Does not arise.

Technical-hands in Ordnance Factories

4516. SHRI P. R. THAKUR : Will the Minister of DEFENCE be pleased to refer

to the reply given to Unstarred Question No. 4773 on the 21 st August, 1968 regarding technical hands in Ordnance Factories and state :

(a) whether the requisite information has since been collected :

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N MISHRA) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A statement is laid on the Table of the House [*Placed in Library. See No.* LT-519/69]

S.C. and S T. Civilian Apprentices in Defence Establishments

4517. SHRI P. R. THAKUR : Will the Minister of DEFENCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4775 on the 21st August, 1968 regarding recruitment of apprentices in Defence Establishments and state :

(a) whether the requisite information has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) Yes Sir

(b) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-520/69].

(c) Does not arise.

Constitution of Central Services

4518. SHRI P. R THAKUR : Will the Minister of DEFENCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4774 on the 21st August, 1968 regarding Central Services under his Ministry and state :

(a) whether the required information has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) A Statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-521/69].

(c) Does not arise.

Holding of Commonwe lth Prime Ministers' Conference in India

4519. SHRI KIKAR SINGH :
SHRI DEVEN SEN :
SHRI P N. SOLANKI :
SHRI D R. PARMAR :
SHRI ONKAR LAL BERWA :
SHRI GEORGE FERNANDES :
SHRI JYOTIRMOY BASU :
SHRI D N. PATODIA :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there is any move for a Commonwealth Prime Ministers' Conference to be held in the near future at a place other than United Kingdom;

(b) the names of the countries which have urged for such a meeting;

(c) what is India's attitude in the matter; and

(d) whether Government have considered the advisibility of holding such a conference in India ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

Selection of Indian Representatives For U.N.O. Sessions

4520. SHRI KIKAR SINGH :
SHRI DEVEN SEN :
SHRI P.N. SOLANKI :
SHRI D.R. PARMAR :
SHRI ONKAR LAL BERWA :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the various factors which are kept in view while selecting representatives for participating in the sessions of the General Assembly of the U.N.O.;

(b) the number and names of Members selected for these delegations showing their party affiliation during the last three years; and

(c) whether all of them belonged to the Congress party only and if so, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) (a) The Indian Delegation to the General Assembly sessions of the U.N. represents the Government of India, and consequently only those persons are selected as representatives who are in agreement with the Government's policies. Additional factors include the ability of the persons concerned to project the Government's policies properly and support them fully in the General Assembly.

(b) The name of Members of parliament who attended the General Assembly sessions during the last three years are set out below. They were all members of the Congress Party.

1966	1967	1968
Shri D.P. Karmarkar	Shri D.N. Tiwari	Shri Shantilal Kothari
Shri Brahm Prakash	Shri Ram Niwas Mirdha	Kumari Mary Naidu
Shri Bhagwat Jha Azad	Smt. Lalitha Rajagopalan	Shri K.R. Ganesh
Dr. Anup Singh	Smt. Devaki Gopi Das	Shri M.N. Naghnoor
Shri R.P. Sinha	Shri Sant Baksh Singh	Shri T.N. Sonavane
	Shri R.D. Bhandare	

(c) Yes Sir, because they were in agreement with the Government's policies.

Foreign Trade Undertaken by Public Sector

4521. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3943 on the 10th December, 1968 and state :

(a) whether the information regarding foreign trade undertaken by the Public Sector has since been collected by Government ; and

(b) if so, the areas where the said trade is likely to be developed ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) No, Sir.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Sale of Imported Cars to Individuals in Madhya Pradesh

4523. SHRI K. N. PANDEY: Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleasedto refer to the reply given

to Unstarred Question No. 4933 on the 17th December, 1968 and state :

(a) whether the required information regarding the sale of imported cars to individuals in Madhya Pradesh has since been were collected ; and

(b) if so, whether any attempt was made to know whether the said cars were being used for the purpose for which they were purchased ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) Yes, Sir. A Statement containing the details of cars sold by the State Trading Corporation to parties in Madhya Pradesh is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No.* LT-522/69].

(b) No, Sir.

Sale of Diamonds, Precious Stones, etc.

4524. SHRI K. N. PANDEY : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 3074 on the 3rd December, 1968 and state :

(a) whether the information relating to the steps being taken to promote the sales of diamonds, precious stones and jewellery to the tourists and foreign visitors against foreign exchange within India has since been collected; and

(b) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) and (b) . The information required was duly furnished in answer to part (d) of Lok Sabha Unstarred Question No. 3074 answered on 3-12-1968. The same is repeated below together with an additional step since taken as in item (4) of the answer.

(1) Replenishment scheme of sales to Foreign Tourists of Gem and Jewellery items has been introduced with effect from 1-4-1968. The scheme provides for import of non-indigenous materials used in the manufacture of products exported.

(2) Replenishment in (1) above has been extended to all sales of Jewellery to foreign tourists against all foreign currency bank transactions, *e. g.* foreign currency travellers cheques, crossed foreign banks drafts and personal cheques drawn on foreign banks instead of only against traveller cheques.

(3) Apart from (1) and (2) above, facilities for sending abroad of sales/study teams and delegations, participation in exhibitions in foreign countries etc. are provided through the Gem and Jewellery export Promotion Council.

(4) It has been decided to allow foreign tourists to take Indian Jewellery out of India without any value limit. (Formerly a limit of Rs. 10,000/- was prescribed in the scheme of sales to foreign tourists of Gem and Jewellery items).

(5) The assurance for collection of information extended through Lok Sabha Unstarred Question No. 3074 was regarding foreign exchange earned through sale of jewellery to foreign tourists. This involves collection of information from numerous individual sources and is still being compiled.

Compensation given for Land Acquired near Kandrori Railway Station, Kangra Distt.

4525. SHRI HEM RAJ : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the extent of lands that have been acquired near about Kandrori Railway Sta-

tion in the Andaura Block of Tehsil Nurpore District Kangra of Himachal Pradesh;

(b) how many small formers are affected by it and the quantum of compensation given to them; and

(c) the extent of land that have been taken and the extent of land left for their subsistance ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) to (c) . No land has been acquired near Kandrori Railway Station in the Andaura Block of Tehsil Nurpore Distt. Kangra of Himachal Pradesh. An area of 39 585 acres affecting approximately 53 landholders has been requisitioned during the years 1966 and 1967 at Kandrori for Defence purposes.

In respect of 19.345 acres requisitioned in 1966, recurring compensation amounting to Rs. 1,754.71 per annum has been paid upto Rabi 1968.

In respect of an area of 20.24 acres requisitioned in 1967, recurring compensation has been assessed by the competent authority in March 1969 at Rs. 2,779 per annum and financial sanction has been issued for payment of the amount. The local revenue authorities have been expedited to disburse the rental compensation.

It is not known how much area is left in the possession of the landholders affected.

Idle capacity of Land, Labour and Plant

4526. SHRI LOBO PRABHU : Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the reply given to Unstarred Questions Nos. 348 and 1267 on the 29th and 26th February, 1969 respectively and state :

(a) whether the Planning Commission have assembled figures of the idle capacity of land, labour and plant;

(b) whether any attempt has been made to specially relate these figures to measures and projects to meet unemployment in specific or in all areas; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) and (b). On the basis of available estimates, fuller utilisation of human and material resources is sought through the formulation of appropriate development programmes.

(c) Does not arise.

Trade-Agreement with Malaysia And Singapore

4528. SHRI MAYAVAN : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India has entered into bilateral agreements with the Eastern countries *viz.*, Malaysia, Singapore etc., for trade purposes; and

(b) if so, whether the import of betelnuts or wecanuts in one of the items included in the trade agreement ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) We have not so far entered into any Trade Agreement either with Malaysia or with Singapore.

(b) Does not arise.

Export Incentives

4529. SHRI MAYAVAN : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that export incentives are offered by Government just to promote exports to bring in foreign exchange, badly required by our country; and

(b) if so, apart from established importers, whether Government propose to encou-

rage the new-comers in the fieled at least on an *ad hoc* basis ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPLLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK): (a) Yes, Sir.

(b) Established importers do not come into the picture so far as export promotion is concerned. Measures of assistance like import replenishment and cash assistance on exports are extended to exporters registered with Export Promotion Councils and Commodity Boards concerned. Registration is open not only to firms with experience in exports, but also to new entrants in the field who have resources to undertake exports.

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार प्रतिव्यक्ति आय

4530. **श्री देवराव पाटिल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार देश की कुल जनसंख्या के एक तिहाई लोग प्रतिदिन एक रुपये पर गुजर करते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त सर्वेक्षण के अनुसार गांवों में जनसंख्या के 70 प्रतिशत लोग प्रतिमास 15 रुपये कमाते हैं और शहरों में जनसंख्या के 70 प्रतिशत लोग प्रतिमास 20 रुपये कमाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो देश में गरीबी तथा कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर उपाय किये जा रहे हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1963-64 के सम्बन्ध में जो कतिपय आंकड़े इकट्ठे किये गये, वे उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों से अनुमान लगाया गया था कि भारत की 78 प्रतिशत जनसंख्या एक रुपया या इससे कम प्रतिदिन खर्च करती है। इसके बाद के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के मध्य प्रतिव्यक्ति आमदनी के ब्योरे के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में समाहित विकास कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शनैः शनैः इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा रही है। असली अर्थों में 1950-51 के बाद प्रति व्यक्ति आय में लगभग तीस प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। एक समन्वित पोषाहार कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसमें स्कूल-पूर्व बच्चों के आहार, स्कूल भोजन, माताओं और बच्चों की पोषाहार की कमी से होने वाले अनीमियां के खिलाफ निरोधक चिकित्सा, विटामिन 'ए' की कमी से बच्चों में होने वाले अन्धेपन को रोकना इत्यादि कार्यक्रम है और उसे चौथी योजना में शामिल किया जायेगा। इसके अलावा हमारी योजनाओं में सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा सुविधाओं के विस्तार पर जो बल दिया गया है उसे भी जनसंख्या के गरीब वर्ग की कार्य कुशलताओं में सुधार कर उत्तरोत्तर गरीबी के उन्मूलन में योगदान देना चाहिए।

Re-Export of Indian Mica by Nepal

4531. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the quantity of mica exported to Nepal during the years 1967-68 and 1968-69;

(b) whether the mica imported by Nepal is meant for their internal consumption or re-export to foreign countries; and

(c) if so, the names of the countries to which Indian Mica is re-exported by Nepal ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) to (c). According to the available published statistics, no mica was exported to Nepal during 1967-68 and 1968-69. There were, however, unconfirmed reports about export of mica of Indian origin from Nepal to third countries in order to gain foreign exchange bonus vouchers in Nepal. Besides tightening vigilance along the border efforts are being made to enlist the co-opration of the Government of Nepal to stop these activities which are contrary to the letter and spirit of the Indo-Nepal Treaty of Trade and Transit.

नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति-आय

4532. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के निष्कर्ष के अनुसार इस समय ऐसे कितने लोग हैं जो प्रतिदिन एक रुपये से भी कम खर्च करते हैं ;

(ख) देश में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति मास आय क्या-क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में एक रुपये से भी कम खर्च करने वालों की प्रतिशतता कितनी कितनी है ?

प्रधान मन्त्री, श्रम शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा संगृहीत 1963-64 के लिए सम्बन्ध आंकड़े उपलब्ध हैं, पिछले अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। संगृहीत जानकारी के अनुसार एक रुपये से कम प्रतिदिन व्यय करने वाले व्यक्तियों की संख्या 1963-64 में अनुमानित मध्य-वार्षिक 46.5 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 36.3 करोड़ हैं।

(ख) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति मासिक आय के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या LT-523/69]

रूई का मूल्य

4533. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के लिए रूई का क्या मूल्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने मूल्य निर्धारित करने से पूर्व इस सम्बन्ध में रूई उत्पादकों के विचारों का भी पता लगाया है ;

(ग) क्या यह सच है कि उत्पादकों ने मूल्य में वृद्धि करने के लिये कहा था ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). रूई पर लगे कानूनी मूल्य नियंत्रण को रूई वर्ष 1967-68 से हटा दिया गया था। तब से रूई के नियंत्रित मूल्य नियत नहीं किये गये हैं परन्तु न्यूनतम समर्थक मूल्यों की प्रति वर्ष घोषणा की जाती रही है। रूई वर्ष 1968-69 के लिए भी न्यूनतम समर्थक मूल्य घोषित किये गये हैं। उनकी घोषणा करने से पूर्व रूई सलाहकार बोर्ड, जिसमें उत्पादकों के प्रतिनिधि हैं, से परामर्श किया गया था। तब से न्यूनतम समर्थक मूल्य बढ़ाने के लिये कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

Mobilisation of Chinese Army along Indo-Tibetan Border

4534. SHRI SHIVACHANDRA JHA : SHRI PRAKASH VIR SHASTRI: SHRI SHIV KUMAR SHASTRI: SHRI K. M. MADHUKAR:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that because of the recent Soviet-Chinese confrontation, Chinese forces are being further mobilized on the Indo-Tibetan border; and

(b) if so, the steps taken by the Indian Government to defend the Indian territory ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) and (b) . Chinese troops continue to remain in strength across our Northern border. There is however no indication that these troops have been recently augmented. A close watch is kept across our borders in the interests of safeguarding our territorial integrity.

Employment of local people Mig Factory at Sunabeda in Koraput District (Orissa)

4535. SHRI SURENDRANATH DWIVEDI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Minister of Defence (Defence Production) delivered a speech in January last at MIG Factory, Sunabeda in Koraput District of Orissa against the employment of the local people in the MIG Factory;

(b) if so, whether this statement is according to the Government's policy laid down in respect of employment of local people in the public undertaking;

(c) whether it is a fact that the Personnel Officer and the Security Officer in the MIG Factory at Sunabeda belong to the Orissa cadre; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) In his speech on the occasion of delivery of the first engine on 2. 1. 69 the Minister of Defence (Defence Production) made no statement against the employment of local people in the Hindustan Aeronautics Limited MIG Factory, Koraput.

(b) Does not arise. The recruitment at HAL Koraput is made in accordance with the prescribed rules of the Company and in accordance with the provisions of the Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act.

(c) No Sir.

(d) The posts are filled in accordance with the rules of the Company. It is not necessary that the Personnel and Security Officers should be from the State in which the HAL Factories are located.

Re-Export of Indian Textiles by Nepal

4536. SHRI YAJNA DATT SHARMA : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the quantity and value of export of grey textiles to Nepal in the years 1967 and 1968 saparately;

(b) whether in the view of the extraordinary rise in the exports, Government have undertaken any study to know the loopholes in the Trade and the Transit Treaty with Nepal; and

(c) the steps taken by Government to stop the export of Indian textiles to Nepal as they are being re-exported to other countries ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) During the years 1967 and 1968, our exports of grey cloth to Nepal were of the order of 109.5 lakhs Sq. Metres valued at Rs. 142 lakhs and 268.5 lakhs Sq.

Metres valued at Rs. 389 lakhs, respectively.

(b) and (c). Indo-Nepal trade is governed under the provisions of the Treaty of Trade and Transit (1960), which is valid upto Octobers, 31, 1970. Under provisions of Article II of the Treaty, goods originating in either country and intended for consumption in the territory of the other are exempted *inter alia* from quantitative restrictions. The customs authorities have, however, reported that no grey cloth has been exported by Nepal through the Calcutta port. The matter of deflection of trade is kept under review, and was discussed with the H. M. G. of Nepal during the talks held in Kathmandu in November, 1968. Both the Governments agreed to continue to take preventive measures against any deflection of trade.

Trade Delegations to Nepal and Other Countries

4537. SHRI YAJNA DUTT SHARMA : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the number of officials and Ministerial delegations gone abroad to explore the possibilities of trade with Nepal and other countries of the world and the total amount of money spent giving the figures regarding foreign exchange spent on such visits separately during the year 1967 and 1968;

(b) whether any study of the trends in our exports, taking into consideration the money spent on popularising them in these two years, has been undertaken by his Ministry; and

(c) if so, with what results ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) A statement is attached.

(b) and (c). Our export trends are kept constantly under review and various export promotion measures are taken as a result of these studies. It is, however, not possible to quantitify the results achieved by the Trade Delegations sent abroad or by any single export promotion measure in isolation.

Statement

Official/Ministerial Trade Delegations sent abroad during 1967 and 1968 and expenditure incurred thereon.

	1967	1968
(i) No. of Trade Delegations sent abroad.	13	15
(ii) Total Expenditure incurred	Rs. 1,24,000	Rs. 2,47,600
(iii) Expenditure in foreign exchang incurred	Rs. 37,160	Rs. 78,500

Proposal to Introduce Military Studies in Schools

4538. SHRI BRIJ RAJ SINGH : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce military studies as a compulsory or an optional subject in all schools, particularly in view of the continuing threat to national security from China and Pakistan; and

(b) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) and (b). The curriculum at the school stage is a matter with which State Governments are concerned. So far as the Central Government is aware, there is no proposal to introduce military studies as such in schools either on a compulsory or on an optional basis. Under the NCC scheme, however, some military training is given to students in schools and colleges and at the end of 1968 there were nearly 13 lakhs students in the

NCC. In all Sainik Schools NCC is compulsory and in 9 of the Universities it continues to be compulsory.

12.29 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Firing by Central Reserve Police on the Security Personnel of Durgapur Steel Plant

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :-

> The firing by Central Reserve Police force on the security personnel of Durgapur Steel Plant resulting in death of three persons and serious injuries to many.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAWAN) : Mr. Speaker, Sir, According to the State Government, the Police version of the incident at Durgapur is as follows :

On 24.3.1969, at about 1100 hours, 150 members of the Durgapur Steel Plant security staff went to the Administrative Building of the Plant with a view to placing a memorandum regarding their grievances before the Director in-charge. They were prevented from going to the Director's office by a section of UP PAC force stationed at the plant. That resulted in a clash between the security staff and the UP PAC who were attacked by steel chairs, steel chips etc. A lathi charge followed for the dispersal of the security staff. The news of this brought workers of the Steel Plant to the Administrative Building. A mob of 3000 strong assembled before the building and started ransacking office room, smashing window panes, etc. 5 cars, 2 jeeps and 2 scooters were set on fire. The UP PAC personnel opened fire in self defence. Four or five rounds were fired. Subsequently the mob swelled and attacked the UP PAC force again. Crackers were used in the attack. A jawan of one of the pickets fired two rounds in the air in self-defence.

The report received by Government from the management of the Steel Plant is broadly similar to the version of the incident given by the State police. The management which had prior information of the demonstration had requested the local police at 10.00 AM to make adequate arrangement for maintaining law and order. The local Officer in-charge, however, expressed his difficulties due to prior commitments. The Director in-charge, Maj. General Wadhera had also contacted the Additional District Magistrate at 11.30 AM and the District Magistrate at 12 00 Noon.

The State Government have also received allegations that the UP PAC opened fire without any provocation. They have further stated that the Additional District Magistrate and the Additional Superintendent of Police, Asansol, reached the scene with a view to bringing the situation under control. The Chief Security Officer and some other officers were placed under arrest as there were allegations of the commission of cognizable offences including an offence under Section 307 IPC against them. 35 members of the UP PAC and 24 members of the Plant staff were injured. Among the latter, there were three who had sustained bullet injuries. They have been admitted to hospital. Five or six members of the UP PAC, whose injuries are also reported to be serious, have been admitted to hospital.

According to the State Govt., the full facts are not yet available and they have asked a senior officer of the Home Department to conduct an inquiry.

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, some time ago, in this House, the questions were raised about Kerala when the Chief Minister of Kerala refused entry of the C. R. P. at the time of the 19th September strike. If my memory is not failing, either in this House or outside, when he replied, in a latter to the Chief Minister, Mr. Namboodripad, the hon. Minister assured the Chief Minister of Kerala that, in future, orders

have been issued that the C. R. P. which is stationed in Kerala or even anywhere else, will be used only when the State Government wants it and that they will take directive from the State Government. I want to know that. Secondly, in the newspapers, it has come out clearly-I quote :

> "...that the security personnel went in a procession to the administrative building to place their demands before the authorities. When they reached there, they found the way blocked by the C. R. P. and the U. P. police.
>
> Arguments followed and the processionists were lathi-charged without provocation and without warning.
>
> As the crowd was dispersing, the policemen fired upon the retreating demonstrators."

It has come in many newspapers, including a Bengali daily and *Patriot*-I can produce many newspapers if you permit me to speak for an hour...

SHRI PILOO MODY (Godhra) : Being a patriot, he has produced only *Patriot*.

SHRI S. M. BANERJEE : Then, Mr. Jyoti Basu, the Deputy Chief Minister, when he was asked by the press, said :

> "I ordered a week ago the removal of the C. R. P... Why were the C. R. P. and the U. P. Armed Force stationed there ? What were they doing there ?
>
> "The local police were not informed of any threat to law and order. And, after all, law and order is our problem. There cannot be any parallel agency for maintaining law and order."

Again, in today's newspaper, you will find...

MR. SPEAKER : We have all read it; you need not read out everything.

SHRI S. M. BANERJEE : It says, "Bengal demands withdrawal of Central Police".

I would like to know from the hon. Minister, after the new Government came into existence, duly elected, defeating the Congress completely, after they came in power, when they made the request that it should be removed, why was the C. R. P. not removed ? I would like to know whether the Centre had issued necessary instructions for the withdrawal of the C. R. P. and, if not, the reasons for the same. If they have not issued instructions, it is quite clear that they want to take a clash with the State Government by stationing the C. R. P. there, like at Durgapur or any other Plant, and by subversive activities of the Indian National Trade Union Congress headed by Mr. Atulya Ghosh. I would like to know that.

SHRI Y. B. CHAVAN : As far as this particular incident is concerned, the C.R.P is not involved.

SHRI S. M. BANERJEE : The C.R.P is stationed there...

SHRI Y. B. CHAVAN : For that you can ask me a separate question. I am prepared to discuss the matter.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) : He may tell us whether the C.R P is there or not. He is avoiding that question.

SHRI Y. B. CHAVAN : There is nothing wrong. The C.R.P is there and will continue to be there.

SHRI S M. BANERJEE : I want to know whether he has received any request from the State Government that the C.R.P should be removed from Durgapur and if so, what is the reaction of the Government.

SHRI Y. B. CHAVAN : The position is that the C.R.P battalions or companies were sent to West Bengal when the I.G.P., West Bengal, requisitioned certain forces from us. The C.R.P forces were also sent,

[Y. B. Chavan]

as also the U.P.P.A.C companies. Immediately after that, the Deputy Chief Minister suggested that the C.R.P be withdrawn. That amounted to saying that the State Government did not want the C R.P for their work. Immediately we informed them that the C.R.P forces would not be available to them. So, the request made by the Deputy Chief Minister of West Bengal has been accepted. But the C.R.P., in the normal course, is located in different parts of the country. As such, it is located in West Bengal and that will continue to be there. The C.R.P. will not be imposed on the West Bengal Government against their will.

SHRI S. M. BANERJEE : That is used against the West Bengal Government (*Interruptions*).

MR. SPEAKER : Order, order.

Dr. Karni Singh.

SHRI S. M. BANERJEE : What about U.P.P.A.C ? He has not answered the other part of my question. What about U.P.P.A.C ? That is a very important matter.

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : जयपुर में उन्हीं लोगों ने गोलियां चलाई थी ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : राजस्थान में उन्हीं ने गोलियां चलाई हैं ।

SHRI Y.B CHAVAN : About U.P.P.A.C, as I said, U.P.P.A.C, if I remember right, was also called for sometime in 1967 and it continued to be their except for some period when it went to Bihar...(*Interruptions*).

SHRI S. M. BANERJEE : In the time of Mr. P. C. Ghosh.

SHRI Y. B. CHAVAN : Whose State Government it was is not material point here. Whether it was in the time of Mr. P. C. Ghosh or during the President's rule, it was the State Government; Their police authorities who asked for them. Even in the month of January the West Bengal police were aware of the existence of U.P.P.A.C, battalions there and they wanted them for election purposes, and also for deployment to Asansol and Durgapur. So far the West Bengal Government have not informed that they do not want them so that we could have removed them. If they want us to remove them, we shall certainly remove them.

DR. KARNI SINGH (Bikaner) : The firing that has taken place in Durgapur is indeed a very serious matter. It is not a question whether we are sitting in the Opposition or on the treasury benches. It shows the type of pattern that is developing in this country as a result of the deteriorating Centre-State relations. We have had more than our share of firings in the last ten years that no free country can be proud of. Whether they are justified or not, I cannot say. But in Rajasthan State we had three firings in two years and the Beri Commission report has not justified one. In Hanumangarh, in my area, only two days ago there was a firing and I have tabled a call-attention. The question that I want to ask today is, firstly, as to the type of ammunition that was used for the firing. I do not know whether the members here are aware of the new type of ammunition that has been developed for us in such firings. In Bikaner, during the strike of Central Government servants, firing took place in September. I know this because I visited the hospitals and saw the injured and I brought the matter to the attention of the hon. Minister here. I believe, about 20 people were injured by the bullets fired by the police alone, because I saw the bullet wound with my own eyes. I was told by the people who were hit by the new type of ammunition that has been introduced that it make so little noise that the crowd does not even know that a bullet has been fired or in fact firing has been resorted to. Several injured boys told me that they were playing around nearby during the trouble and apparently one of the boys pointed out to other that his leg was bleeding and the other fellow said that his hand was bleeding; they did not know that they were both hit by bullets. I brought the matter to the attention of the hon. Minister. If, God forbid, firing is to be resorted to, the police should

use the proper ammunition, so that even if one shot is fired it will dispel the crowd instead of putting 20 people in hospital with bullet wounds. The reports are not very clear as to how many people were actually injured by bullets.

I would like to know from the hon. Minister if in spite of the Members of Parliament bringing this matter to his attention, the same unfortunate type of ammunition has been used in the firing in Durgapur ?

The other point is that the Centre-State relations are deteriorating now. I have always been making an observation that the time has come, if we want to save this country, that we should have an all-party Government in the States and a national Government at the Centre. We shall sooner or later have to do that. As I said, this Centre-State strained relations is following a dangerous pattern and the Durgapur situation is one indication. The point is that in the interests of protection of the lives and property of people, not only the Central Government but the State Government will also have to sit round a table and take a very definite decision on this matter. In view of this, may I know from the hon. Home Minister whether he has any proposals to call a round table conference of all party Members and Chief Ministers of all the States and the Central Government to try and evolve some way whereby Centre-State relations can be more smoothly worked out, and whether Government have any proposals to define the functions of the Central police forces as situated in the States ? I make this request on the grounds namely that some of the public sector industries are defence-oriented industries, and if this sort of trouble goes on, our defence production will be affected and hence this question.

SHRI S. K. TAPURIAH (Pali) : Let him join my party first and then suggest it.

SHRI Y. B. CHAVAN : As far as police firing is concerned, nobody likes it. I do not like it. It is always a very sad affair that police firing takes place and some people are injured and some people are killed; it leaves a very sad feeling. The point is whether the firings had to be resorted to for justifiable reasons or not. That is one thing. In many cases, these questions have been examined by the commissions, and certain views have been given. I with the concerned State Governments act accordingly.

As far as the suggestion about the ammunition is concerned, I think my hon. friend Dr.Karni Singh mentioned this on the floor of the House .....

DR. KARNI SINGH : I had written to him.

SHRI Y. B. CHAVAN : I think I had replied to him also.

Dr. KARNI SINGH : Did they use the same type of ammunition ?

SHRI Y. B. CHAVAN : Since it is a question regarding the type of ammunition, it had to be examined by the experts concerned, and I have asked some committee to go into this matter.

DR. KARNI SINGH : Is he to experiment on poor Indian people or will he listen to the eye-witnesses in regard to what happened in Bikaner ?

SHRI Y. B. CHAVAN : Merely because he gives me some suggestion, does he expect me immediately to accept it. (Interruptions).

DR. KARNI SINGH : I had made this suggestion five months ago.

SHRI Y. B. CHAVAN : The purpose for which he uses the gun is absolutely different.

DR. KARNI SINGH : I had made this suggestion five months ago.

SHRI Y. B. CHAVAN : I am prepared to accept his authority on the use of arms and ammunitions .. .

DR. KARNI SINGH : I am no authority.

SHRI Y. B. CHAVAN : I am prepared to accept.....

DR. KARNI SINGH : I am no authority. I had seen those poor boys in the hospital, about 19 or 20 of them with bullet injuries.

SHRI Y. B. CHAVAN : I am prepared to accept his authority.....

MR. SPEAKER : I would like hon. Members to address the Chair. Let there be no dialogue across.

SHRI Y. B. CHAVAN : I am prepared to accept him as authority because he knows more about arms and ammunition than I do. That is why I am prepared to accept him as authority.

As far as Centre-State relations are concerned, Government are aware of certain situations. This matter was very recently discussed in the standing committee of the National Integration Council and it has been decided that we should meet again and discuss this matter in all its aspects. Certain talks and certain dialogues are necessary.

As far as national government is concerned, I think it is not for my hon friend to talk about it, but at all he has meant it, then I would suggest to him or make a recommendation that he may try coalition with the Communist Marxists if he can.

DR. KARNI SINGH : He has not answerd the second part of my question. What is he going to do to define the functions of the Central Reserve Police in the States? He has not answered my question. What is he going to do to define the functions of the Central Reserve Police force in the State as a result of this dialogue ?

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : The deployment of the Central Reserve Police force as also the police force from different States in the different States of India has assumed the proportions of, and posed a very serious, problem to the country today and under altered circumstances now the relations between the Centre and the States have come up for discussion and should be discussed and finalised.

The Central Reserve Police force is posted in Assam also. And what did they do ? Very recently they shot dead a boy at the Gauhati Sports Stadium. At the same time, the Central Reserve Police people are wonderful people and they go about asking anybody they meet on the street. 'What are you ?', and if he says that he is an Assamese, then he gets a few beatings.

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : It is not fair that he should say like this.

SHRI HEM BARUA : He gets a beating. Because my hon.friends have not got the beatings, therefore, they say 'No'. They may not get beatings, but I know that the people get such beatings. Whatever that might be, may I know whether Government propose to see that the authority of the Central Government is preserved and at the same time the autonomy of the State Government is not eroded ? May I know whether Government propose to evolve a formula to the effect that the Central Reserve Police or the UP police force which is the worst not only from the point of view of the committing of atrocities...

SHRI SHEO NARAIN : I object to this. Such a learned professor should not make such remarks. The UP police is the best police in the country. I would request the Home Minister to withdraw the police force of UP from Bihar, Bengal and other States. Let them not be sent to other States. I is a very shameful thing that such a learned professor should say like this. We are not going to tolerate this. I would request the Home Minister to withdraw the UP police from other States.

SHRI HEM BARUA : Shri Sheo Narain is getting excited over this...

SHRI SHEO NARAIN : It is not a question of excitement. He cannot make such remarks. We have the best of jawans there. We have the ablest police in UP.

SHRI HEM BARUA : Mr. Mulla has made a comment on the UP police force, and on the strength of that, I have said that the UP police force is the worst in India. Therefore, may I know whether Government have evolved any formula in the matter of deployment of the Central Reserve Police or the police force from any other State in the different States of India and whether they have finally decided not to deploy the police force from the Centre unless a request is made directly by the State Government to the Central Government ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I would certainly like to make the position very clear again.

SHRI HEM BARUA : May I tell him that the Central Reserve Police in Assam is known as 'Chavan sena' ?

SHRI Y. P. CHAVAN : I do not need any *senas*. I think this is just by the way as a sort of humour.

I would like to make the policy of the Government of India very clear about the Central Reserve Police force. The Central Reserve Police force is a Central armed force, and it will be given to the State Governments only if they want it. There is no question of compromising the autonomy of States, because we respect it and we would like to strengthen it. As far as the autonomy of the States is concerned, there is no question of ...

SHRI PILOO MODY : Does he want them to stew in their own juice ?

SHRI Y. B. CHAVAN : This is another interpretation of what I am saying.

But I would like to make it clear that the Central Reserve police force, being a national armed force, will have to be located in different places in the country, and it is within the function of the Central Reserve Police Force to protect the Central Government property and the Central Government projects.

SHRI SHEO NARAIN *rose*—

MR. SPEAKER: I am not going to allow him. His name is not there. Some other Congress Member's name is there and I shall call him now.

SHRI SHEO NARAIN : May I just say.....

MR. SPEAKER : The hon.Member should resume his seat. Somebody in the Congress Party must help me from this menace.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : It is the job of the State police force to protect the Central Government property.

SHRI PILOO MODY : Never.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : The Industrial Security Force has been created to look after the interests of the Central undertakings but they have failed to protect the property of the industrial undertakings. In view of this, will Government take some steps to modify the Industrial Security Force and frame some rules to properly manage them ?

Secondly, just now the hon. Minister said that UP Reserve Police will be withdrawn if the State Government of West Bengal wanted them to go away. It is all right. He has also said another thing that they will also consider that the Central Reserve Police which is stationed in West Bengal will not be available for the security of the people there In view of the explosive situation in West Bengal and also in view of the fact that responsible people in the Government are instigating people to 'gherao' and other things, is it not good to use the Central Reserve Police not only to safeguard the central industries but also, when times come, to give security to the public from this unlawful Government. (*Interruptions*)

SHRI S. M. BANERJEE : I want to raise a point of order.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं चल सकता है– आप एक राज्य सर-

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

कार को अनलाफुल गवर्नमेन्ट कैसे कह सकते हैं।

SHRI S. M. BANERJEE : He first of all said that this Government cannot protect people from illegal 'gheraos'. Then, having encouraged by his own voice, he went on saying that the Government is unlawful. He should withdraw those words. Sir, it is an elected Government. The Congress has been defeated and they are only 55 people.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : I have never asked the question from Shri Banerjee.

SHRI S. M. BANERJEE : I have great regard for Shri Naidu. I have supported his groundnut resolution. Let him withdraw those words. It is in the larger interest.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : I will explain it.

MR. SPEAKER : There is no question. The whole House will agree that the Government of West Bengal is not an unlawful Government. It is elected by the people and it is there.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : I will explain, Sir. When a Government refuses to be a lawful Government and encourages people to 'gherao', it becomes an unlawful Government at that moment. There is no reply from the Minister.

MR. SPEAKER : I have replied it anyway.

SHRI C. K. CHAKRAPANI (Ponnani): Mr. Speaker, Sir, as usual the Home Minister is a bit adamant and arrogant. First of all I would like to make it clear that the Central Government has no business to station C.R.P or other forces in the State without the consent of the State Government. Now the fact is that they have stationed C.R.P and other forces in Kerala and other places. You have sent C.R.P to Kerala to suppress the 19th September strike of the Central Government employees. The Chief Minister of Kerala has expressed his dissatisfaction over this issue and he has vehemently protested against this. I can understand the political background. After the General Elections and after the mid term poll there are non-Congress Governments in West Bengal and Kerala. The attitude of the Central Government towards these Governments is not helpful and you say that harmonious relationship will be established between the State and the Centre. How can you establish cordial relations with this attitude? The question is that in Durgapur the C.R.P and the UP Police have opened fire. Thank God, he has not denied the firing. The Minister has just now said that the steel plant authorities have not approached the State police for protection. This is wrong. He is distorting the fact. According to me, the State Police was not informed of it. The Steel plant authorities did not even inform the Police about the so-called threat to law and order. I understand that the steel plant authorities instigated this thing with political motives by the Centre who created a situation like this. I want to know this from the Government. Is the Government going to enquire into these aspects, as to why the steel plant authorities did not approach the State Police? Secondly, I want to know this, from the Government. Will the Government take immediate steps to withdraw the C.R.P forces of these States ?

SHRI Y. B. CHAVAN : As far as the C.R.P's role is concerned, I have made Government's position absolutely clear. As far as his claim that the Durgapur plant authorities did not inform the local police is concerned, it does not appear to be true from the reports that I got. I have to depend upon two sources of information. One is naturally the State Government on whose report I will have to work; and the other one is the one from the Director of the Durgapur steel plant itself. The information that I have received from the Manager of the Durgapur Plant says that they did inform the local police authorities once at 10 O'clock; then again, the Additional District Magistrate was approached at 11-30 and the District Magistrate was approached at 12 O' clock.

12.56 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

Voting on Constitution (Twenty second Amendment) Bill

SHRI NATH PAI (Rajapur) : Sir, I have sought your permission to raise one matter concerning what happend Yesterday.

MR. SPEAKER : It is with me.

SHRI NATH PAI : I have sought your permission, Sir, and I am glad that you are kind enough to give the permission. What happened yesterday raises some very issues of procedure in the House and we have to calmly reflect over it. I would try not to frame all of them because we think that you will give us the lead as to what should be done when a situation like that arises. But Sir, many vital issues regarding the Business in the House and Procedure arises as a result of what transpired in the House yesterday. Sir, I am at a loss to know where exactly the House stands with regard to the fate of this Bill which was voted upon. May I Sir, draw your attention.....

MR. SPEAKER : The hon. Member wrote to me about the resignation of the Minister. But he is raising something else now.

SHRI NATH PAI : This is directly connected. *(Interruptions)*.

MR. SPEAKER : I wanted myself to explain that point. The point is, the Home Minister is giving notice. He announced yesterday on the Floor of the House that he was withdrawing the Motion ...

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : आप पहले मेरी बात सुनिये । प्रक्रिया की समस्या पर आपको सुनना चाहिये । हम ने आपकी मदद करने के लिये नोटिस दिया है ।

MR. SPEAKER : I am not allowing that discussion. I am myself aware of one hing. I am aware that he is going to give notice, about withdrawal of this thing. And therefore, there is no further discussion which I can allow. You wanted to know about the Parliamentary Affairs Minister. I myself do not know.

श्री मधु लिमये : उस के लिए रास्ता क्या है? मैंने 377 में बाकायदा नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । I do not allow that also. You wrote to me that you wanted to raise it. If you want to raise such things you need not write to me also from tomorrow. The moment I got your notice I enquired and he told me that he promised on the Floor of the House. It is not a secret information to me. On the Floor of the House he said that he is withdrawing. He is giving notice and on that you want discussion now. I cannot help it.

SHRI NATH PAI : I think I wrote to you about the reported resignation of the Minister.....

MR. SPEAKER : I myself wanted to know. I have not been able to know myself.

SHRI NATH PAI : I am confining myself absolutely to that only. I think it is a very healthy precedent that the Minister of Parliamentary Affairs is trying to secure, if the report of his resignation is true and if the resignation is accepted. Because, Sir, nobody in this country is responsible for whatever happens anywhere. For Plan failures nobody is responsible. If we suffer military reverses nobody is responsible. For upholding healthy traditions of parliamentary democracy, he has done the right thing in tendering his resignation. I congratulate him. We want to make one thing perfectly clear. I don't think it is he who was basically responsible. Yesterday, you said, you have gone to the next item. May I be permitted to say just two sentences ? Basically the responsibility for this was not only of the Minister of Parliamentary Affairs but of the gentlemen who occupy the front treasury benches and the responsibility is also a joint responsibility. I am saying, with all

[Shri Nath Pai]

that is required of propriety, that one fails to be convinced...that they are bothered to study the elementary rules of procedure. The fact is, after you pointed out that the first motion was carried by the narrowest majority required under our Constitutional rules-by two-they did not hesitate to leave the Chamber.....

MR. SPEAKER : Please confine yourself to the resignation of the Minister.

SHRI NATH PAI : When do we get a statement on the resignation ?

MR. SPEAKER: I do not think there is anybody here to give that information. The Minister is not here and the Prime Minister is not here ..... *(Interruptions)*. Your point of view will be conveyed.

SHRI NATH PAI : Who is responsible for the conduct of the Minister?

MR. SPEAKER : Only the Prime Minister can say.

SHRI NATH PAI : Summon her..... *(Interruptions)*.

श्री मधु लिमये : यहां पर ऐसे मन्त्री भी थे जिन्होंने पहले विभाजन में वोट दिया लेकिन बाद में चले गये । दिनेश सिंह जैसे मन्त्री पहले डिविजन में यहां पर मौजूद थे लेकिन बाद में उठक र चले गये । .....(व्यवधान).....

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : आप इस तरह से प्रधान मन्त्री का बचाव न करिए । यह कैसे हो सकता है? मदन के कुछ अधिकार है?.....(व्यवधान).....

13 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Merchandise Marks (Judicial Proceedings, Madras) Rules

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRAIL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATHA REDDY): I beg to lay on the Table a copy of the Trade and Merchandise Marks (Judicial Proceedings, Madras) Rules, 1968, published in Notification No. S.O. 4327 in Gazette of India dated the 7th December, 1968, under section 134 of the Trade and Merchandise Marks Act, 1958. [*Placed in Library. See* No. LT-499/69].

Indian Telegraph (Fifth Amendment Rules)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH) : I beg to lay on the Table a copy of the Indian Telegraph (Fifth Amendment) Rules, 1969, published in Notification No. G.S.R. 417 (English version) and G.S.R. 418 (Hindi version) in Gazette of India dated the 22nd February, 1969, under sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885. [*Placed in Library. See* No. LT-500/69].

Notifications under Rubber Act

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI RAM SEWAK CHOWDHARY) :I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi version) under sub-section (3) of section 25 of theRubber Act, 1947 :

(1) The Rubber (Third Amendment) Rules, 1968, published in Notification No. G.S.R. 546 in Gazette of India dated the 8th March, 1969.

(2) The Rubber (Second Amendment) Rules, 1968, published in Notification No. G.S.R. 547 in Gazette of India dated the 8th March, 1969. [*Placed in Library See* No. LT-501/69]

Passports (Amendment) Rules

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : I beg to lay on the Table a copy of the Passports (Amendment) Rules, 1969, Published in Notification No. G.S.R. 212 in Gazette of India dated the 28th January, 1969, under sub-section (3) of section 24 of the Passports Act, 1967. [*Placed in Library, See* No. LT-502/69].

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha:

> "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Delhi Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 1969, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 22nd March, 1969, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Forty-sixth Report

SHRI KHADILKAR (Khed) : I beg to present the Forty-sixth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

ESTIMATES COMMITTEE

Seventy-eighth Report

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : I beg to present the Seventy-eighth Report of the Estimates Committee on the Ministry of Home Affairs-Central Bureau of Investigation.

LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL

(i) Report of Joint Committee

SHRI M. B. RANA (Broach) : I beg to present the Report of the Joint Committee on the Bill to make provision for the appointment and functions of certain authorities for the investigation of administrative action taken by or on behalf of the Government or certain public authorities in certain cases and for matters connected therewith.

(ii) Evidence

SHRI M. B. RANA : I beg to lay on the Table a copy of the evidence given before the Joint Committee on the Bill to make provision for the appointment and functions of certain authorities for the investigation of administrative action taken by or on behalf of the Government or certain public authorities in certain cases and for matters connected therewith, along with a copy of the statement containing a gist of main points made by witnesses in their Evidence before the Joint Committee.

(iii) Memoranda/Representations

SHRI M. B. RANA : I beg to lay on the Table copies of Memoranda/Representations received by the Joint Committee on the Bill to make provision for the appointment and functions of certain authorities for the investigation of administrative action taken by or on behalf of the Government or certain public authorities in certain cases and for matters connected therewith.

13.03 hrs.

* DEMANDS FOR GRANTS

Ministry of Home Affairs

MR. SPEAKER : The House will now take up discussion and voting on Demand

---

* *Moved with the recommendation of the President.*

[Mr. Speaker]

Nos. 43 to 57, 119 and 120 relating to the Ministry of Home Affairs for which 8 hours have been allotted.

Hon. Members present in the House who are desirous of moving their cut motions may send slips to the Table before 14.15 hours indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. They will be treated as moved if they are otherwise admissible.

The Demands are before the House.

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

Demand No.43--Ministry of Home Affairs

"That a sum not exceeding Rs.1,45,96,000 be granted to the President to complete the sum necessary....to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1970 in respect of 'Ministry of Home Affairs'."

Demand No.44--Cabinet

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs. 55,57,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Cabinet'."

Demand No.45--Administration of Justice

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs.2,04,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Administration of Justice'."

Demand No.46 -Police

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs.48,30,12000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Police'."

Demand No.47 -Census

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs.1,31,53,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Census'."

Demand No.48 -Statistics

MR SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum exceeding Rs.3,10,15,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Statistics'."

Demand No.49--Privy Purses and Allowances of Indian Rulers

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs 1,36,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Privy Purses and Allowances of Indian Rulers'."

Demand No.50--Territorial and Political Pensions

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs. 15,77,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Territorial and Political Pensions'."

Demand No. 51--Delhi

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs.36,08,25,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Delhi'."

Demand No.52--Chandigarh

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs.4,90,67000 be granted to the President to complete the sum necessary to defrary the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Chandigarh'."

Demand No. 53--Andaman and Nicobar Islands

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs.6,53,55,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Andaman and Nicobar Islands'."

Demand No. 54--Tribal Areas

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs.21,20,38,000 be granted to the President to Complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Tribal Areas'."

Demand No. 55--Dadra and Nagar Haveli Area

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs.53,54,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Dadra and Nagar Haveli Area'."

Demand No 56-Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs 1,00,82,000, be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands.

Demand No. 57. other Revenue Expenditure of the Ministry of Home Affairs.

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs.9,33,65,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Other Revenue Expenditure of the Ministry of Home Affairs'."

Demand No. 119. Capital Outlay in Union Territories and Tribal Areas.

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceediug Rs.20,71,83,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Capital Outlay in Union Territories and Tribal Areas'."

Demand No. 120 Other Capital Outlay of the Ministry of Home Affairs.

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs. 40,00,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Other Capital Outlay of the Ministry of Home Affairs'."

13.05 hrs.

Lok Sabha adjourned for Lunch till fourteen of the Clock.

———

Lok Sabha reassembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER: *in the chair.*]

DEMAND FOR GRANTS-*Contd.*

Ministry of Home Affains-contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Hon. Member may now move the cut motions.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs.100."

[Growing atmosphere of violence in the country and failure of the Government to devise effective measures to meet the situation in the law and order front as also the sociological front (5)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Growing tension in Andhra Pradesh symptomatic of an undesirable trend of divisive policy in the country and the failure of the Government to create cohesion in the country by removing the causes of grievance and discontent (6)]

SHRI ERASMO DE SEQUEIRA (Marmagao) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Rs.1."

[Failure to ensure prompt payment pensions. (67)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re.1."

[Failure to complete absorption of employees in the Union Territory of Goa, Daman and Diu (68)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1".

[Failure to enquire into the approval of land for fertilizer project in Goa (69)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1".

[Failure to ensure a judicial enquiry into the death of union leader D. I. Cruz in Goa while under police custody. (70)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to allocate necessary administrative and financial powers to Union Territories. (71)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to enquire into financial mismangement in the Union Territory of Goa, Daman and Diu. (72)]

"That the Demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to check the use of official administrative machinery in Goa, for attempts to create ill feeling between communities. (73)]

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi-Sadar) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to provide authoritative clarification about the powers of the Governors in different circumstances. (74)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1".

[Failure to check the foreign money and material for the help of foreign Chiristian missionaries in India. (75)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to provide more powers to Delhi Administration to run the Government efficiently. (76)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to improve the law and order situation in Delhi. (77)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to check anti-national and disruptive activities in the country. (78)]

SHRI ERASMO DE SEQUEIRA : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs 100".

[Need to constitute a Parliamentary Committee to enquire into executive action taken with reference to problems of transition with reference to Goa, Daman and Diu. (79)]

SHRI SRINIBAS MISHRA (Cuttack) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to provide a uniform administration in all the Himalayan border. (126)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to check Pakistani infiltration into Assam. (127)]

"That the damand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1".

[Failure to curb anti-national activities of foreign agents in the country. (128)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to stop foreign interference in elections in India. (129)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to liquidate the para-military senas from the country. (130)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to deal effcetively with the anti-national utterances of Sheikh Abdulla. (131)]

"That the demand under the head Police be reduced to Re. 1."

[Failure to check communal riots. (149)]

"That the demand under the head Police be reduced to Re. 1."

[Failure to check the activities of the Mizo National Front. (150)].

"That the demand under the head Territorial and Political Pensions be reduced to Re. 1".

[Failure to reduce and abolish pensions granted by the British Government. (154)]

"That the demand under the head Delhi be reduced by Rs. 100."

[Failure to teach in primary and secondary schools through Oriya medium. (155)]

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced by Rs. 100."

[Failure in developing the tribal areas. (156)]

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced by Rs. 100 "

[Failure to Provide communications in in tribal areas. (157)]

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced by Rs. 100."

[Lack of medical facilities in tribal areas. (158)]

[Shri Erasmo De Sequeira]

"That the demand under the head Other Revenue Expenditure of the Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Systematic Suppression of the Oriya speaking minority in Bihar and Andhra Pradesh. (159)]

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to change the anti-people policies of the Ministry. (160)]

"That the demand under the head Ministry of Home affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to end the repressive policies. (161)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Need to stop framing repressive laws and to scrap existing such laws. (162)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to check increasing communalism and its instigator the R.S.S. (163)].

"That the demand under the head Cabinet be reduced by Rs. 100."

[Failure to reduce the number of Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers. (164)].

"That the demand the head Cabinet be reduced by Rs. 100."

[Failure to reduce the salaries and allowances of Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers. (165)].

"That the demand under the head Cabinet be reduced by Rs.100."

[Need to reduce the expenditure on other itmes of the Cabinet. (166)]

"That the demand under the head Cabinet be reduced by Rs.100."

[Failure to avoid all expenditure being incurred on the Security of Ministers. (167)].

"That the demand under head Cabinet be reduced by Rs.100."

[Need to allot smaller residence to Ministers. (168)].

"That the demand under the head Cabinet be reduced by Rs.100."

[Need to reduce expenditure being incurred on Ministers residences. (169)].

"That the demand under the head Cabinet be reduced by Rs.100."

[Need to reduce the expenditure on Prime Minister's Secretariat. (170)]

"That the demand under the head Cabinet be reduced by Rs.100."

[Need to stop the payment of salary from Government to Deputy Chief Whip of Congress Parliamentary Party. (171)]

"That the demand under the head Administration of Justice be reduced by Rs 100."

[Failure to make legal administration easily accessible for the public. (172)]

"That the demand under the head Administration of Justice be reduced by Rs.100."

[Failure to reduce expenditure on legal administration. (173)]

"That the demand under the head Administration of Justice be reduced by Rs.100."

[Failure to make justice cheap and accessible for the poor. (174)]

"That the demand under the head Administration of Justice be reduced by Rs. 100."

[Need to provide free justice to the poor and to make it easily available to them. (175)]

"That the demand under the head Administration of Justice be reduced by Rs.100."

[Need to make available free legal advice by Government to defend the cases of the poor. (176)]

"That the demand under the head Administration of Justice be reduced by Rs. 100."

[Need to fix a time limit for disposal legal cases. (177)]

"That the demand under the head Administration of Justice be reduced by Rs. 100."

[Failure to do away with policy of keeping the culprits in jails for year together pending a decision on their cases. (178)]

"That the demand under the head Administration of Justice be reduced by Rs. 100."

[Need to improve the working of Indian Penal Code. (179)]

SHRI S M. BANERJEE (Kanpur) : I beg to move :

"That the demad under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure of the Government to reinstate the Central Government Empolyees discharged on account of Participation in 19th September, 1968 strike. (197)]

"That the demand under the head Ministry Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Restoration of recognition of All Unions and Federations withdrawn after 19th September, 1968 strike. (198)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Non-inclusion of some of the members of J.C.M. in meeting held on 27th December, 1968. (199)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure of the Government to treat the political Party workers political prisoners.(200)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100 "

[Danger to country by Shiva Sena. (201)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Communal riots in the country. (202)].

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Copper clad cables worth about rupees 36 22 lakhs, imported in 1964, which have not been put to any use so far. (240)]

SHRI S. M. BANERJEE : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[To discuss the Firing by the Central Reserve Police on people in Durgapur even against the directive of the State Deputy Chief Minister and Home Minister

[S. M. Banerjee]

that they do not interfere in State affairs and that they should confine themselves to their barracks. (241)]

SHRI LOBO PRABHU : I beg to move :

"That the demand under the head Police be reduced by Rs.100."

[Taking possession of land from five owners in 1963 and negotiating with fifth owner with the result that after paying rent of Rs. 1.03 lakhs, construction has still not started of buildings for the Central Reserve Police. (255)]

"That the demand under the head Andaman and Nicobar Islands be reduced by Rs.100."

[Abandnoment of training-cum-development Centre in Andaman on which Rs.1.56 lakhs had been spent. (258)]

"That the demand under the head Tribal areas be reduced by Rs.100."

[Overpayment of Rs. 0.63 lakhs by the NEFA administration by buying sugar through an agent. (259)]

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced by Rs. 100."

[Avoidable expenditure reported in the Audit of Rs. 131 lakhs on vegetable ghee, Rs. 30,000 on parachutes andRs 0.89 lakhs on dry rations. (260)]

SHRI S. M. KRISHNA (Mandya) : I beg to move.

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to ensure safety to people who live outside their home State (261)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to reinstate all the Central Government employees victimised for participation in one day token strike on 19th September, 1968 (262)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to check the activities of pro-Chinese and pro-Pakistani elements. (263)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to maintian law and order in the State during President's Rule. (264)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to implement the Mahajan Commission Report on Maharastra-Mysore border dispute. (265)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to check the growing lawlessness in certain part of the country. (266)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to resolve the dispute between the Nagas and Government through peaceful negotiations (267)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to resolve amicably the Maharashtra-Mysore border dispute. (268)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need for uniform policy in the matter of promotions to section officers grade (281)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need for a set policy for promotions to the section officers grade of the Central Secretariat Services. (282)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to remove the inequality in the matter of promotions to the grade of section officers. (283)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Re. 100."

[Failure to issue a list for promotion to the grade of section officers in the Central Secretariat services. (284)]

"That the demand under the head Cabinet be reduced to Re. 1."

[Failure to reduce the size of the Cabinet as suggested by Administrative reforms Commission. (285)]

"That the demand under the head Administrative of Justice be reduced to Re. 1."

[Failure to create machinery for cordial relations between Centre and State administration. (289)]

"That the demand under the head Administration of justice be reduced by Rs. 100."

[Failure to check crimes in Delhi (290)].

"That the demand under the head Administration of Justice be reduced by Rs. 100."

[Need for a legistalure for Delhi. (291)]

SHRI RAM SINGH AYARWAL (Sagar) : I beg to move.

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to provide free justice to those whose income is less than Rs. 300/- p.m. (320)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to stop tyranny and exploitation of the public. (321)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to post more police force in dacoit infested areas. (322)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to find basic solution to solve dacoit problem. (323)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to send abroad prescribed number of Harijan Adivasis. (324)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to provide cheap and speady justice. (325)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Inaction and failure of Government to eradicate untouchability. (326)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to ban use of caste indicative surnames legally. (327)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to ensure the appointment of of Harijans Adivasis on percentage

[Ram Singh Ayarwal]

basis in Government, Semi Government and grant receiving non-Government concerns. (328)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to bring such backward States as Madhya Pradesh at par withthe rest of the country. (329)]

SHRI GEORGE FERNANDES (Bombay-South) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to bring about national integration. (332)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to safeguard the lives, property and religious places of minorities, especially of the Muslims. (333)]

"That the demand under the head Cabinet be reduced to Re. 1."

[Failure to reduce the size of the Cabinet. (334)]

"That the demand under the head Cabinet be reduced to Re. 1."

[Failure to reduce the foreign tours of the Ministers, especially of the Prime Minister. (335)]

"That the demand under the head Cabinet be reduced to Re. 1."

[Use of Government machinery by the Ministers, especially by the Prime Minister, during the midterm elections. (336)]

"That the demand under the head Cabinet be reduced by Rs. 5,00,000."

[Reduction in the tours of Ministers. (337)]

"That the demand under the head Police be reduced to Re. 1."

[Failure to improve the salaries and working conditions of the Police. (338)]

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced to Re. 1."

[Failure to improve the standard of living of the Tribal people. (339)]

SHRI RAM SINGH AYARWAL : I beg to move :

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced by Rs. 100 "

[Failure to properly implement Community Development Schemes in Tribal Areas. (344)]

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced by Rs. 100."

[Indifference shown towards social and development works and failure to allot more funds therefor. (345)]

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced by Rs. 100."

[Failure to spend more on multi-purpose river-vally projects in Tribal Areas. (346)]

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced by Rs. 100."

[Failure to construct more roads under Public Works in Tribal Areas. (347)]

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced by Rs. 100."

[Need for economy in the expenditure on malaria eradication programme in Tribal Areas. (348)]

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced by Rs. 100."

[Failure to check misuse of funds on Public Works in Tribal Areas. (349)]

SHRI GEORGE FERNANDES : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to restore the recognition to the unions whose recognition was withdrawn after the strike of 19th September, 1968. (350)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to reinstate the employees victimised during the 19th September, 1968 strike. (351)]

"That the demand under the head Cabinet be reduced by Rs. 100."

[Misuse of Government machinery by the Prime Minister during the mid-term elections. (354)]

"That the demand under the head Administration of justice be reduced by Rs. 100.

[Need to increase the number of High Court and Supreme Court Judges. (355)]

"That the demand under the head Police be reduced by Rs. 100."

[Need to improve the salary and working conditions of the Police. (356)]

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced by Rs. 100."

[Need to improve the conditions of life of the Tribal people. (357)]

MR. DEPUTY-SPEAKER : The cut motions are also before the House.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : Before we begin, may I say this ? This morning the Speaker was saying when questions arose here, 'To whom shall I look that side ? There is no leader'. Is there no deputy floor leader for the ruling Party ?

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : We are controlling the house. What is this ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : We meet now after the lunch recess. The other day some questions were raised. Sometimes I feel I should give some latitude for at least mentioning some important events.

Shri Shastri observed that I was rather too generous. I do not want to be generous now. That question is closed. Let us begin our work.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, प्रोसीजर से संबंधित है। जब सुबह अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि लीडर नहीं है, मैं किस से कहूं तो कम से कम प्रोसीजर के बारे में कोइ सफाई हो कि कोई लीडर है या नहीं ? और अगर है तो कौन है ?

SHRI SHEO NARAIN : May I say that the Home Minister is here and he is in charge of that department. This should be placed before the Speaker. Is is not you, Mr. Deputy Speaker, who said that, स्पीकर के वाडिक्ट प्रर कुछ नहीं होना चाहिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : When the question was raised in the House, I was present in the House. The Speaker made certain observations and I do not think that we should now carry on this debate about procedure.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : On a point of order....(*Interruptions.*) I shall be relevant.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can make your point later on.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : इस की रेलीवेंस सुनिये।

SHRI S. M. BANERJEE : Rule 376 (2) says that a point of order may be raised in

[Shri S. M. Banerjee]

relation to the business before the House at the moment. The Demands of the Home Ministry are before the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : And the Home Minister is present.

SHRI S. M. BANERJEE : That is why I am raising this issue. If the Labour Minister had been present, I would not have raised it. On 13s3-1969 a statement was made by Shri V. C. Shukla regarding lenient action to be taken by the Central Government. Shri George Fernandes, Shri Madhu Limaye and I pointed out to him what he said should also apply to temporary employees and he said that orders on that matter would be issued later on....(*Interruptions.*)

AN HON. MEMBER : It is a point of disorder.

SHRI S. M. P NERJEE : The letter had been issued by the Home Ministry on 15 March 1969 : Strike of Central Government employees, September 1968-follow-up action regarding. This differs from that statement in that this says that the temporary employees .... (*Interruptions.*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : You want clarification from the Minister; in his reply he will do that.

SHRI S. M. BANERJEE : I did not doubt their intention; they are fighting hard against their own bureaucracy. If you permit me I shall read out this letter or I shall lay it on the Table of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : When his party spokesman speaks, he can refer to it.

SHRI S. M. BANERJEE : I am above parties.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You are above parties but then so nebody else will get an opportunity to read it out and if necessary Government will come with their clarification.

SHRI S. M. BANERJEE : I request the Home Minister to clarify it. Shall I lay it on the Table ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : No permission is given. There is no point of order.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : आप ने अभी मेरे नाम का उल्लेख किया था इसलिये व्यक्तिगत स्पष्टीकरण मैं आप को देना चाहता हूँ । उस दिन भी और दूसरे दिन भी जो मैं ने यह कहा था कि आप अधिक उदार हैं तो उस के साथ मैं ने आप की उदारता की सराहना की थी, निन्दा नहीं की थी ।

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : Two thousand years ago Pliny laid down that home is where the heart is.

We are proud today that we have a Home Minister who has a big heart. It is with the heart that you can deal with the affairs of the home ...(*Interruptions.*)

SHRI SHEO NARAIN : Speak of the heart, not the head.

SHRI LOBO PRABHU : You have no head. The Home Ministry stands for two of the thee rights enshrined in the American Constitution- ight to liberty and right to life. The third right, namely, the pursuit of happiness is elaborated by the other Ministries. I had been Home Secretary to the Government of Madras and I have been interested in the Home Ministry for other reasons also. The Home Ministry was very much in the public eye during the last year and I think no other Ministry had been in the focus and under fire as the Home Ministry.

For that reason, I feel very privileged when I open this debate against the Home Ministry, against the Home Ministry not in the sense that I have to find any fault with any person but against the Home Ministry because there are certain matters in which improvement is possible.

I begin with a thing very near to my heart. I belong to minority communities. There are others also here who belong to a minority community. The responsibility for

minorities is a matter of importance not only to the minorities themselves but to the Government and to this country. We have to remember that this country is linked with one-fifth of the population of the world by Buddhism which it has given to the world. This country is linked with one-fourth of the world which follows Islam, because we are a country which at one time had the largest Muslim population in the world and today we are the second country with the largest Muslim population. Thirdly, this country is linked with nearly the rest of the world through Christians who came here two thousand years ago. St. Thomas came directly after Christ and was treated with great hospitality. We have existed all this time in the friendliest of terms living with the other members of this country, living in complete friendship and co-operation. Anything that you do, therefore, to the minorities affects your relations with the rest of the world. Threfore, it is a matter of great importance that certain doubts should be cleared.

I am very grateful that last year when I raised the question, the Minister of State affirmed that article 25 gives all reglions, not only christians, but to all religians including the Hindu religion the right to practise, profess and propagate their faith. I am glad that the Ministry has observed this dictum time and again when there were some unwarranted attacks on the different religions.

There is one point here which however remains to be clarified I used the word 'clarified' because I think it is due to some misapprehension that it continues to exist so far on the book of instructions of the Home Ministry.

By a Cabinet decision it has been decided that foreign missionaries should not be encouraged in this country and that the priesthood of the Christians should be Indianised. I beg to point out that the choice of the priest is an internal matter and that article 25 should protect us if we chose those persons who serve us best. The Home Minister himself was kind enough on a previous occasion to point out that the Indian clergy was not able or not willing to perform certain disagreeable tasks like attending to lepers and the sick. But beyond that, there is the fact that Catholic church, for instance, is universal. It makes no difference between one colour and another, one country and another. To us, it is a principle that they are the same. If these people bring to us some foreign know-how, why should there be be objection ? There are 58, 272 foreigners in this country. Does it matter that there are 5000 missionaries ? Does it matter that they should be reduced in number ? Last year about 300 of them have left. They have left because they are under the disagreeable necessity of every year renewing their stay here; every year, they have to get their visa renewed, Is this necessary in respect of priests who have been here for 30 or 35 years ? Does the Home Ministry allow the rule of law when they refuse a visa to some of these priests ? The rule of law is that every man should have a right and an opportunity to defend himself. Even if they do not do it, do they give some notice of what the charge against him is ? And then he leaves this country with apparently something on his character that he has been found to be a *persona non grata* with the Government. I would, therefore, suggest one thing. We have no sympathies for any foreigner who interferes in the security of this country. We are with the Home Ministry a hundred times if they turn out such persons, but please let them give chance; let these persons not be made the victims of some kind of intrigues by people who have their own motives.

I need not say to this House that it is not at all fair to doubt the loyalty of minorities in this country. I would like to point out that there is not one instance where a member of a minority community has been found to be a spy. I would like to remind my hon. friends that in the Indo-Pakistan conflict, the first to lay down their lives were Christians and Muslims. I would like to assure this House that if it comes to it's defence, we shall never be behind anyone. In these circumstances, do not let us be in the agony of Shylock and say.

> "we are warmed by the same summer,
> Chilled by the same winter,
>
> If you prick us, do we not bleed ?"

Therefore, I would beg of the Home Ministry that in their broadly secular pol-

[Shri Lobo Prabhu]

icy, let them avoid these slight pin-pricks of getting rid of a priest or two because that places us very wrong with the rest of the world and it makes us feel that you do not accept us.

Secondly, I come to the subject of the other disturbances which the Home Ministry is faced with. I come to the subject of the police. The police are getting a larger and larger part of the budget of the Home Ministry. This year, there is an increase of nearly Rs. 11 crores for the Central police. We had a discussion this morning about that. But first and foremost, let us take the State police, the police who are concerned with the administration of law and order. It is very fortunate that the Calcutta High Court has clearly enunciated that the police have to act according to the law and according to the Criminal Procedure Code, irrespective of any directions from the Government. That is a very important principle, and it is the duty of the Home Ministry and this Parliament to encourage the police to do their duties by making it clear to them that they will be supported when they do their duties irrespective of what the passing Government of the country may say or tell them. Of course, there are difficulties; when that same government which gives instructions also controls their postings/promotions, it is very difficult for the police to ignore the instructions they may receive. May I suggest that there are two ways in which the police can be assured of independence ? First, we may adopt Rajaji's suggestion made recently that the police and the administration should be a reserved responsibility of the Governor. No doubt, it is a fundamental suggestion, but in due course, the Home Minister will be driven to accepting this that the police as technicians should not be contaminated by politics. If he does not wish to go so far, would he at least place the promotions and postings of the police in the hands of an independent authority like the Public Service Commission. This is happening in Ceylon. This has happened in New Zealand. It is not a new departure. If they were to depend on the Public Service Commission they would be free to act according to the law and in the interests of the police. Secondly, law and order is suffering because the police do not take action under the preventive sections of the Criminal Procedure Code. The hon. Minister was flattering to me when I had raised the question and he had informed me that the State Governments had been informed that after a riot took place, the officers concerned would be asked to report if they had taken the necessary preventive action.

Sir, it is necessary to emphasise this, because if preventive action is taken there will be no riots, and in the 30 years I was in service, there was not a single occasion where I had to face a riot and I was in some of the most inflammable areas of this country. And that I did because I took the simple precaution of demanding bonds under section 107 from whomsoever was likely to break the peace, from whosoever announced a programme which may imperil peace. I would like this to be emphasised: that these bonds should be taken not only from those who declare the political programmes but also from those who declare the labour programmes. No man has a right in the name of labour to destroy the peace of the people. The peace of the people is a fundamental right which, in the interests of the country, no section can imperil.

The third point about the police is, you are spending a lot, but are you getting the best use for your money, particularly on modern equipment for the police ? Are you doing it ? I know from my own experience that after an accident, the two vehicles have to remain on the road for... 24 hours or even more, because the police officer cannot get there.

SHRI RANGA (Srikakulam) : The people are also injured.

SHRI LOBO PRABHU : Yes; they are not allowed to be removed. Can you not, when you are spending so much, provide a motor-cycle for your Station House Officers ? Can you not provide jeeps especially in the bigger cities, and can you not have a control room ?

SHRI RANGA : Not even telephones.

SHRI LOBO PRABHU : Sir, these are two very vital things, and I do not think the country will grudge an extra crore or two if you are going to provide them with this equipment to make the police a modern force.

The third important subject which has been before this House in connection with the Home Ministry is about the Centre-State relationship We have had the spectacle of four Governments collapsing this year.. in the wake of Haryana collapsing before. These four Governments have gone through a mid-term election, and the prospect arising is no better than what it was before. You have had a Committee on Defections. The question is, will you believe in this Committee and implement the recommendations of this Committee ? Even today, you are forming a Government in Madhya Pradesh in the same way with defectors. (*Interruption*) I would not make an exception of my own party or any other party. We all rely on defectors. Our politics is bound up with defectors. Of course, we are not in power everywhere. (*Interruption*) What I would like to say is, you cannot do this by a change of law or convention. There is a simple thing to which I would like to draw your attention in this matter. There is comparative stability in the office of the President of municipalities. Has anyone found out why it is so ? It is because while the President or the Chairman is elected by a simple majority vote, he cannot be removed except by two-thirds majority. Why do we not introduce this simple change Chief Ministers ?

Then comes the question of the Governors. What are you going to do with our Governors ? One Governor in West Bengal refused to read the address against himself presented by the Ministry, and another one in Punjab does it with a great deal of flourish. Who is right ? Have you made up your mind what the Governor should do ? And in the meanwhile what have you done ? You are destroying the independence of the Governor by practically asking Mr. Dharma Vira to go away. No doubt he has put in an application for leave, but he understood where he was. The application would not have been pressed if you had the Congress there. The Governors do not know where their loyalties lie. If you are going to send a Governor whom the West Bengal Government wants, to whom will be the loyalty of the Governor ? To you or to the West Bengal Government ?

In this connection, I again refer to Rajaji who is the prophet not only for my party but is the prophet of this country. He said, make the office of the Governor a functional one. Give him reserve powers to look after the police and administration, and thereafter you will possibly have a situation where the Governor will be better than he has been so far.

The fourth point which I would like to bring forward is concerned with the administration. The administration of this country is largely concentrated in your office. You have the Public Service Commission. Even though 21 years have passed, you have not yet finalised the rules about the appointment and powers of the members. I do not want to go very deep into it, because my time is running out. I would only say this that don't appoint to the Public Service Commission people who remain obliged. If you want members to be independent, let them be serving officers or High Court Judges. Let them not remain at least in the eyes of the public the mere servants of the will of the Home Ministry. You must make this change as soon as opportunities arise If you appoint serving men, you will get the confidence of the people and of the unemployed, because the unemployed are a very serious problem.

It is a staggering fact that there are at present not less than 333,000 and odd cases-more than a third of a million-pending before the High Courts The Law Commission has warned you that there would be a breakdown if law was so dilatory and civil cases took more than 10 years to be decided. I would like the Home Ministry to consider seriously the question of delay, arising from adjournment, convenience of lawyers or of judges or corruption of officials who want

[Shri Lobo Prabhu]

to make money from delay. This is a problem you cannot allow to linger long. You must ask the High Courts to suggest a way out to reduce delays.

Coming to the Vigilance Commissioner and Grievance Commissioner, the Grievance Commissioner has gone and the Vigilance Commissioner will also probably go in the near future, because the Lokpal is coming in. Your own report discloses that when the Vigilance Commissioner started functioing in 1963, the number of complaints received were nearly 6,000. This year, the number was only 1,000. It does not mean that corruption has decreased. It only means the public have lost confidence in that office, and they feel that the Vigilance Commissioner is of no vital use. Though much is expected, I do not think the Lokpal is going to be very much better. You are giving him probably the same powers. He will be under the Parliament instead of being under you. But what is Parliament with your brute majority ? It will make no difference except that we will have a Vigilance Commissioner more glorified and with a bigger staff.

You have to find out why corruption exists and why you do not attempt to remove it. In this connection, I do not like to outrage my own modesty, but in 1962 you complimented me by adopting a system of spotlighting delays I suggested. That is, whenever an officer failed to write his note within a week of the receipt of the paper, he had to write it in red ink. There was thus a visual demonstration of the delay which the higher officers would take note of and take action. I do not know how far it continues. From my own enquiries, it appears that the higher officers have not taken care to implement it. That will remove one of the very important causes of corruption, because the Grievance Commissioner's figures show that 80 per cent of the complaints relate to delay.

The second reason why the Lokpal may fail is, you are not going to remove the causes of corruption and reduce the opportunities for it through your controls, enterprises and other acts of interference with the life of the private individual. You are presenting opportunities to corruption and there is no wonder that it exists. You have to make up your mind from your end that it should stop.

I am glad the Minister of State is here. There is no use having a Lokpal or Grievance Commissioner, because as long as the minister is not a public servant, he cannot be touched even if he is exposed in Parliament. Ministers have been exposed many times and I do not think having a Lokpal will make any difference Ministers will only feel the necessity of being honest if like any other citizens, they are exposed to the law of corruption, by being public servants. The hon. minister gave me an assurance in June, 1968 that Government was going to bring a Bill in respect of making ministers public servants. He has not done it nor has the Assurances Committee done anything in this matter. This Bill must come by which ministers should be declared public servants.

Now I shall speak as one who was a public servant to those who are now public servants. I had occasion, when the Bill came for essential services, to differ with the Government on this point that they failed to give these government servants the provision of arbitration of the Joint Consultative Committee and the Industrial Disputes Act. You would not have had a strike if you had followed that Act. It is quite clear. The same thing I repeated when the Act was being passed, that the Act would be infructuous unless you included arbitration and gave them a chance to be heard. Do not delay that. The mement you enforce that provision a strike becomes illegal, the same thing you were trying to get by the Ordinance.

To government servants among whom I once was I would like to say this that their privilege to influence the life of the people is more than of anyone else. They have the power to do so much. They did not show discipline in this matter. They thought too much of their own interest and then they lost the chance. They have to serve the people. I would like, on this occasion, to address them as Lord Curzon addressed the

government servants of his day, because what he said then is true today as it was then. It is a statement which should be hung up in every office. It is a statement worthy for them to note and for this country to benefit from. This was what he addressed them :

> "To feel that somewhere among those millions you have left a little justice or happiness or prosperity, a sense of manliness or moral dignity, a spring of patriotism, a dawn of intellectual enlightenment or a stirring of duty where it did not exist before, that is enough reward. It is good enough as a watchword while in service and an epitaph thereafter".

Curzon added :

> "I worked for no other aim. Let India be my judge".

I would like to add this. I said to myself the same thing when I left service, and I would like to say when I conclude my term of Parliament that I had no other aim than to serve the people and let the people of India be my judge.

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : उपाध्यक्ष जी, गृह मन्त्रालय ऐसा मन्त्रालय है जिस में वैदेशिक बातों को छोड़ कर, सुरक्षा को छोड़ कर और रेलवे को छोड़ कर शासन के प्रायः सभी प्रमुख विभाग आ जाते हैं। मैं श्री चव्हाण जी की और अपने भाई श्री विद्या चरण शुक्ल जी को इस बात पर बधाई देना चाहता हूं कि..

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : शुक्ल जी को डबल ।

डा० गोविन्द दास : उन्होंने अपने विभाग के काम को बहुत अच्छी तरह से सम्भाला है बहुत अच्छी तरह से किया है । जो रिपोर्ट 1968-69 की मेरे सामने है और जिस के 127 पृष्ठ हैं, उस रिपोर्ट को भी यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो राजनीतिक पकड़ की बात तो अलग है लेकिन मैंने जो कुछ कहा है, निष्पक्षता से यदि विचार किया जाएगा तो सब ओर से उसका समर्थन होगा ।

इतने पर भी मैं एक बात कहे बिना नहीं रह सकता और वह यह है कि यदि इस सारे काम को अंग्रेजी के एक शब्द के अन्तर्गत ले जाए तो वह शब्द है 'रूटीन' । इतिहास में इसी शब्द से इस समस्त कार्य का विवेचन और विवरण होगा । इसका कारण यह है कि देश के निर्माण के सम्बन्ध में हमारे सामने कोई आदर्श, कोई ध्येय, कोई उद्देश्य नहीं रह गया है । महात्मा गांधी ने स्वराज्य के बाद के भारत का जो एक चित्र खींचा था वह एक दम धूमिल हो गया है । उस तरफ हमारा कोई भी ध्यान नहीं है और इसका कारण है हमारी सारी दृष्टि उस रूटीन के साथ एक दूसरे हिन्दी शब्द के अन्तर्गत आ जाती है, वह शब्द है भौतिक । हमने केवल भौतिक चीज को अपनी योजनाओं में, अपने आदर्श में, अपने ध्येय में और अपने उद्देश्यों में रख छोड़ा है । उसके आगे हम नहीं जाते । आज जो भ्रष्टाचार चल रहा है और इस प्रकार की दूसरी चीजें चल रही है, उसकी जड़ में क्या है । आप ऊपर ऊपर इलाज करना चाहते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर इलाज से काम चलने वाला नहीं है । उसकी जड़ में वही भौतिकवाद है, केवल भौतिक उन्नति है, पैसे को ईश्वर से भी बड़ा समझना, यह हमारा आदर्श हो गया है ।

मैं एक दृष्टान्त देता हूं । नैतिकता का कहां तक पतन हो गया है, इसका वह दृष्टान्त है । दल बदलने वालों की ओर आप जरा दृष्टि डालिये । वे आज एक दल में होते हैं और कल दूसरे दल में । मैं अनेक बार कह चुका हूं कि इस प्रकार का कानून बनना चाहिए या हमारे संविधान में संशोधन होना चाहिये कि यदि व्यक्ति, कोई सदस्य किसी दल को प्रतिज्ञापत्र दे कर आता है और अगर वह अपने प्रतिज्ञापत्र को तोड़ता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जाए । कांग्रेस दल भी इस सम्बन्ध में दूध का

[डा० गोविन्द दास]

धुला हुआ नहीं है। कांग्रेस दल और जितने विरोधी दल हैं उनका एक समझौता सा हो गया है कि दल बदलने वालों के लिए कोई कानून न बनाया जाए। सब का उद्देश्य किसी न किसी तरह से मिनिस्ट्री को, पदों को हथियाना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

कामराज योजना को आप लें। उपाध्यक्ष जी, मैं एक छोटा सा नाटककार हूँ। कोई भी नाटककार नाटककार नहीं हो सकता अगर उसका मनोविज्ञान का थोड़ा सा अध्ययन न हो। मन में जो कुछ होता है वह चेहरे पर आ जाता है। मैंने कामराज योजना में देखा था कि उस योजना के अनुसार जिन मन्त्रियों को अलग किया गया था, उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ती थीं और जब तक उनको फिर से पद प्राप्त नहीं हो गए तब तक उनको चैन नहीं पड़ा। फिर हमारे अध्यक्ष श्री संजीव रेड्डी ने जब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे उस समय कहा था कि मिनिस्टरों के लिए दस वर्ष का समय नियत होना चाहिये, कोई दस वर्ष से अधिक मिनिस्टर न रहे और संसद सदस्यों के लिए और विधान सभाओं के सदस्यों के लिए भी दस वर्ष का समय नियत होना चाहिये। लेकिन उस तरफ भी कोई ध्यान नहीं। इस सब का भी वही कारण है जो अभी मैंने आप से कहा। भौतिक दृष्टि से हमारे देश के प्रश्नों और संसार के प्रश्नों का हल होने वाला नहीं है। मैं भौतिक उन्नति के विरुद्ध नहीं हूँ। भौतिक उन्नति भी होनी चाहिये लेकिन भौतिकता के साथ यह देश जिस बात के लिए सदियों से ही नहीं बल्कि हजारों वर्षों से प्रसिद्ध रहा है और आज भी प्रसिद्ध है, और जिस को हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था आध्यात्मिकता, उस तरफ भी इसे ध्यान देना होगा। जब तक हम आध्यात्मिकता अपनी योजनाओं में नहीं लाएंगे, शिक्षा में नहीं लाएंगे, दूसरी जगहों पर नहीं लाएंगे, तब तक अनैतिकता की समाप्ति नहीं होगी।

अब मैं फिर उस विषय पर आता हूँ, जिस विषय को मैं स्वराज्य के बाद सब से महत्वपूर्ण मानता हूँ– भाषा का विषय। मानव सृष्टि में सब से श्रेष्ठ प्राणी क्यों है? मैंने कई बार कहा है और कहता जाऊंगा– वह इस लिये सर्वश्रेष्ठ है कि निसर्ग ने उसे जो ज्ञान शक्ति दी है, वह किसी अन्य प्राणी को नहीं दी और उस का आधार है– भाषा। इस भाषा के सम्बन्ध में सब से पहले मैं हिन्दी के संविधान के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। संविधान सभा के अब कितने सदस्य लोक सभा और राज्य सभा में हैं, मुझे नहीं मालूम– लेकिन श्री गोविन्द मैनन हैं मैं हूं, शायद और भी कुछ सदस्य हों। जहां तक हिन्दी के संविधान का रूप है, उस के सम्बन्ध में संविधान सभा के अन्तिम दिन क्या हुआ था? डा० राजेन्द्र प्रसाद जी जो संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने कहा था—

> "Now there are two things more which remain to be done. One is the authentication or rather the certification of the Hindi Translation of the Constitution. Hon. Members will recollect that this House authorised me by a resolution to get the Hindi Translation prepared, and printed and published before the 26th of January. That has been done. The House also authorised me to get translations in other languages prepared, printed and published. This work has not yet been completed; it has been taken up.
>
> I will ask Shri Ghanshyam Singh Gupta to let me have the Hindi Translation so that I may formally place it before the House and certify it."

14.42 hrs.

[श्री गादिलिंगन गौड पीठासीन हुए]

उस के बाद वह संविधान सभा के सामने रखा गया, राजेन्द्र बाबू ने उस पर हस्ताक्षर किये, हम लोगों ने, सब ने, उस पर हस्ताक्षर किये। अब आप देखें कि यह जो विवाद उठा है

कि हमारा हिन्दी संविधान प्रामाणिक नहीं है, इसका एक कारण यह कहा जाता है कि उसकी धारायें प्रथक रूप से संविधान सभा में स्वीकृत नहीं की गई थीं। इसकी आवश्यकता नहीं थी। संविधान सभा की नियमावली में यह बात कही गई है कि—

> "it shall be in discretion of the President when a motion that the Constitution or a Bill taken into consideration has been made to submit the Constitution or any part of the Constitution to the Assembly clause by clause."

यह संविधान सभा के अध्यक्ष के ऊपर निर्भर था। संविधान सभा का काम किसी विधेयक के द्वारा नहीं चलता था, संकल्पों के द्वारा, रेजोल्यूशन के द्वारा चलता था और यह स्पष्ट प्रस्ताव था कि संविधान की प्रत्येक धारा अलग अलग ली जाये, इसकी आवश्यकता नहीं थी। यदि हमारे अध्यक्ष चाहते तो पूरे संविधान को रख कर, उस को प्रामाणिक मान कर उस को स्वीकृत करा सकते थे। यही हम ने किया भी। लेकिन इस सम्बन्ध में अगर कोई सन्देह है तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सन्देह की निवृत्ति तुरन्त होनी चाहिये। कारण यह है कि कम से कम पांच राज्यों में उन राज्यों की सरकारों ने और वहां की विधान सभाओं ने निश्चय कर लिया है कि उन का कुल काम हिन्दी में चलेगा, वे राज्य हैं– उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा ...

श्री प्रकाशवीर शास्त्री हिमाचल प्रदेश भी है।

डा० गोविन्द दास : जब तक संविधान का हिन्दी स्वरूप प्रामाणिक नहीं माना जायेगा, तब तक इन राज्यों का और आगे चल कर इन राज्यों की हाईकोर्टों का भी काम हिन्दी में नहीं चल सकेगा। इस लिये मैं तो यह मानता हूं कि हमारा संविधान प्रामाणिक है, लेकिन इस सम्बन्ध में यदि कोई सन्देह हो तो इस सन्देह की निवृत्ति तुरन्त होनी चाहिये।

अब मैं कुछ और बातें हिन्दी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में भी कहा गया है– संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिन्दी 26 जनवरी, 1965 से संघ की राजभाषा हो गई। तथापि उस तारीख के पश्चात् भी राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अनुसार हिन्दी के साथ साथ संघ के उन सभी सरकारी कार्यों के लिए जिनके लिए उस तारीख से पूर्व इस का प्रयोग किया जा रहा था और संसद् में काम काज चलाने के लिए अंग्रेजी के प्रयोग की व्यवस्था है। मैं इस में शब्द "हिन्दी के साथ साथ" पर जोर देना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं– चव्हाण जी इस समय नहीं हैं, श्री विद्या चरण शुक्ल से पूछना चाहता हूं जिस संविधान के प्रति वफादार रहने की हम प्रतिज्ञा करते हैं, उस संविधान के अनुसार क्या केन्द्रीय सरकार का समूचा काम इस समय पहले हिन्दी में चलता है और उस के साथ अंग्रेजी में चल रहा है? मैं कहता हूं– नहीं चल रहा है। हम हर पल संविधान को तोड़ रहे हैं, जिसके प्रति हम वफादार रहने की शपथ लेते हैं। उस की हम परवाह नहीं करते और सब काम धड़ल्ले से अंग्रेजी में चल रहा है।

आप यह भी देखें–इसी रिपोर्ट में कहा गया है· 2 लाख 19 हजार कर्मचारियों ने हिन्दी की एक या अधिक निर्धारित परीक्षायें पास कर ली हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन 2 लाख 19 हजार में से कितने ऐसे राज्य कर्मचारी है जो हिन्दी में कार्य करते हैं और उन में से कितने भूल गये हैं। बड़े अफसर हिन्दी में काम नहीं चाहते, जब बड़े अफ़सर काम नहीं करना चाहते तो छोटे अफ़सर इसलिये काम नहीं करते कि बड़े अफसर नाराज़ हो जायेंगे। इस सम्बन्ध में जब तक सख्ती से कदम नहीं उठाये जाते, तब तक नहीं चलने वाला है।

[डा० गोविन्द दास]

संघ लोक सेवा आयोग के सम्बन्ध में मैं श्री विद्याचरण जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने दो विषयों में हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं में परीक्षा लेना स्वीकार कर लिया है। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के शायद पांच या छः विषय हैं, अभी केवल दो विषयों के लिये यह किया गया है। हम ने अपने संविधान में यह बात निश्चित की थी कि 15 वर्षों के भीतर अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी चलने लगेगी, मैं जानना चाहता हूँ कि बाकी विषयों को हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं में चलाने के लिये कितना समय लगेगा। 15 वर्षों में हिन्दी नहीं चली, अभी केवल दो विषयों के लिये व्यवस्था की गई है और मुझे इस बात का डर है कि यदि आपने कोई समय निश्चित नहीं किया तो लोक संघ सेवा आयोग की पूरी परीक्षाओं को हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं में चलाने के लिये 50 वर्ष लगेंगे। इस लिये मेरी आप से प्रार्थना है कि आप इस के लिये कोई समय निश्चित कीजिये कि कितने दिनों में आप इसे करना चाहते हैं।

गृह मन्त्री जी प्रत्येक मन्त्रालय को हिन्दी में काम करने के लिये प्रोत्साहन दें। हिन्दी भाषी राज्यों से हिन्दी में पत्र व्यवहार करें। ससद् में विधेयक और संकल्प आदि हिन्दी में उपस्थित करें। सब से अच्छा तो यह होगा कि हिन्दी का मन्त्रालय ही अलग स्थापित हो। यदि हम अपने देश में प्रजातन्त्र चलाना चाहते हैं तो प्रजातन्त्र विदेशी भाषा से नहीं चल सकता। आज सरकारी कामों में यहां की जनता की जो रूचि कम हो गई है, उस का मुख्य कारण यह है कि यहां का अधिकांश काम आज भी अंग्रेजी में चलता है। मैंने कहा था कि स्वराज्य के बाद में सब से महत्वपूर्ण काम भाषा को मानता हूं और मैं तो सरकार के काम की जांच इस तरह से करूंगा कि वह कहां तक हिन्दी को चला सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं फिर से चव्हाण जी और विद्या चरण जी को बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस रुटीन से बाहर निकलिये, अध्यात्मिकता को स्थान दीजिये, भौतिकता से ऊपर उठ कर। हिन्दी और भारतीय भाषाओं को उन का स्थान दें, तभी इतिहास में उन का स्थान रहने वाला है, नहीं तो केवल रुटीन के एक शब्द में दोनों के नाम लिखे जाने वाले है।

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : In the very 'introduction' of the Report, I find the following observations:—

> "One of the important functions of the Ministry has been to identify and remove causes of friction---communal, linguistic or regional."

I am sorry to say that, on all these three counts, the Home Minister has failed. It is not to be blamed entirely, the reason being that there is something radically topsy-turvied in the whole approach to problems that this Government as a whole is making. But what I would like to concentrate more is on the question of language, but before entering into that, I would like to say a few words about Centre-State relations.

I am glad that Government are at least giving an indication that they are trying to appreciate the difficulties of the States. Even today the hon. Home Minister, while answering during Question Hour, has stated that Government is taking up the matter in the Integration Council and they will be pursuing it. I remember, in the recent meeting of the Council, the Prime Minister, referring to this particular aspect of Centre-State relations, has said that we should pay very careful attention to the various demands of different States, but at the same time we should not lose sight of the fact that while various States are pulling in different directions, the unity and the strength of the Centre should not be undermined. This is what she said. I do not know where the question of the Centre's strength being attenuated or affected comes into this because even if you decentralise the whole thing, so long as this power of superseding a State and installing your

own Government is there when there is some threat to the unity or a challenge to the sovereignty and Integrity of the nation, when you have got the power to supersede a State, you need not give this reason that the Centre will be undermined. It will never be undermined. The Governor will be there. The various powers vested under the Constitution are there. So, there is no use going on suspecting the *bona fides* of the various State Governments to whichever political party they may belong. It is high time that they were entrusted with more powers to carry on the responsibilities that are already vested in them under the Constitution. I do not want to dilate or elaborate much on this point because we have already spoken during the General Debate on the Budget and the hon. Finance Minister also has a little bit dilated on that; also, my State Government, along with, I think, Kerala and West Bengal, are presently working out some proposals to be placed before the Government expressing their views as to how best the financial devalution and other things could be adjusted to give a satisfactory position to the State Governments concerned. So, since this matter will be pursued at Government's level, I do not want to elaborate further on that, but I only appeal that the Home Minister should also play his constructive and vital role at this juncture and see to it that we evolve a healthy set-up instead of allowing things to drag on like this which will ultimately lead to our facing a lot of difficulties all over the country.

Dr. Seth Govind Das was referring to certain discussions that took place in the Constituent Assembly. Of course, he picked up some of the points which were very convenient to him and he expressed his views on them. He was very sore and angry that Government have not been able to fully replace English by Hindi in all walks of life in India. When I was going through the debates of the Constituent Assembly, what struck me most was an expression used by one Mr. M. V. Dhulekar. He affirmed that people who did not know Hindustani had no right to stay in India or in the Constituent Assembly.

AN HON. MEMBER : Who is he ?

SHRI S. KANDAPPAN : I do not know who he is.

AN HON. MEMBER : Where is he ?

SHRI S. KANDAPPAN : He is one of the fathers of our constitution because I found this expression in the debates of the Constituent Assembly.

I am sure things are not so bad as they were at that time. Still I am not able to appreciate what the Home Ministry or the various Ministries at the Centre are driving at when they take measures to vigorously implement this policy of Hindi. Without going into the basic issue—I will come to that later because rather our problem is that we are totally against the provisions with regard to the official language that are there in the Constitution. That is the basic issue. The Home Minister will simply answer my point that they strick to the Constitution. Even with regard to the constitutional provisions, what is the day-to-day practice ? I may point out one thing. There is a provision in the Constitution with regard to linguistic minorities. There is a Commissioner for linguistic minorities. Whenever there is some trouble or some difficulties for the minorities living in any State, for that matter whichever be the ruling Party, the Central Government takes upon itself the responsibility to see that they get education in their mother tongue at the primary level and at other levels. On the basis of the recommendation of the Commissioner, they instruct the State Governments to provide them with educational facilities in their mother tongue. It is working well so far in some of the States. But, here, under the very nose of the Central Government in Delhi as well as particularly in Andaman and Nicobar islands which are the direct responsibility of the Centre, nothing has been done to provide facility even to have primary education in their mother tongue for the children of non-Hindi people who are residents of that area. I had been to those islands in 1963. Soon after that I took up this matter with the Home Minister. Every time when I wrote to them, I received an acknowledgment and nothing more If I talk to them, they say that they will look into the matter.

[Shri Kandappan]

When the matter was further pursued very seriously, by that time they lose sight of my earlier representation I am sorry to say that the letter I wrote and the representation I made to the present Home Minister received an acknowledgment but nothing happened afterwards. Probably, Sir, I am too small a man to get a reply from too big a man like the Home Minister. The latest information is that things are still as bad as they were 7 years ago. Why should it be so ? There are fine schools. It is a fine location. The islands are so beautiful. In fact when I was there I did not want to leave those islands at all. But I cannot it help.

The Government there has also provided free education upto middle or secondary school stage. Unfortunately in all these schools in that Union Territory I find Hindi medium excepting in some areas where Bengalis were rehabilitated, some facility for primary education was provided in their mother tongue. But with regard to other areas I found not a single primary school provided for education in their mother tongue either for the Tamil children or for the Malayalee children or for the Telugu children. If the Minister has got the figure, let him contradict me. There are 500 Tamil school-going children in Port Blair, the capital of Andaman. We are forced to have recourse to Hindi because they do not have facility in their own language and the Tamil Sangham by collecting money have built a building and they are now trying to teach them at least primary education in Tamil. Even when I was in that island, I took it up with the Chief Commissioner there. In fact I was not against Hindi being taught there. I advocated and pleaded with the Tamilians there to continue Hindi. I found that many of them in their homes were speaking Hindustani. So I do not want to make it a point of dispute at all. What I was pleading as to why the Tamil children should be deprived of their mother tongue ? What is the harm if it is provided ? The only answer so far I have been able to get was that they were not able to get enough teachers. That is no excuse at all. In fact I gave my word to the Chief Commissioner and also I wrote a letter to the Home Minister that if they have any difficulty with regard to teachers, I am prepared to take it up with my Government at the State level and see that as many teachers as needed are supplied to that island.

15 hrs.

But they have not done anything. What I am driving at is that they pretend to do, but in fact do nothing for the other linguistic groups and their intention seems to be to see by fair or foul means that everyone in this country learns Hindi and Hindi alone. That is not going to help Hindi or even this country in the long run. They should remember this while making provisions for education in the various Union Territories and also in other States where there are linguistic minorities which I do not want to elaborate as others will speak on that. Even a cursory perusal of the Constituent Assembly debates on the question of language goes to prove that there were deep differences. The debate on language started as soon as the Constituent Assembly was formed and it ended only after it was dissolved after the Constitution was adopted. No lasting compromise could be worked out; only a workable formula could be agreed upon; even so there were a lot of differences and some strong views were expressed. I came across an interesting proposal made on 12 September 1949 by one Mr Naziruddin Ahmed from Bengal who pleaded for the postponement of the whole issue He said that the language question should be postponed till primary education is made compulsory and about sixty percent of the population became literate and a commission was appointed and its recommendations were considered by provincial and central legislatures and also by the Press and the public for a long time. Then only, he felt, we could come to an agreeable settlement. The Hindi bloc did not agree to that suggestion as they feared that if they lost that opportunity they would get no other.

The impression I gathered on going through those debates was that the Non-Hindi bloc was somewhat susceptible

because of their patriotic and national sentiments. Probably they felt that they should put up a big show before the British imperialists who left our country but expressed their apprehensions that this country would never remain united or pull together. Possibly, they wanted to prove to the outside world that they could pull together, come what may. All of them reluctantly agreed to some kind of a compromise formula. If you read the debates you will find that no Member from the Non-Hindi areas willingly and spontaneously gave his support to this formula on language in the Constitution. In the beginning there was some talk of Hindustani but probably after the death of Gandhiji and after Pakistan came into being, it was given a decent burial and Hindi seems to have come up. Whether it should be in Devanagiri or Persian or Arabic script, even that was not properly thrashed out. So, all this rather goes to prove that we should not shut our eyes to the realities. After all, when people were not able to agree to the compromise resolution even at the time when we were in the first flush of freedom, how could you expect them, simply because it is there in the constitution, to be loyal or to agree to the language resolution when they know full well that it is making them second class citizens ? But till now, repeatedly, even the Home Minister and responsible people in this Cabinet and other leaders of some parties have been telling us : "After all, your language, or for that matter, any other language, is not inferior to Hindi. It is on a par with that language and that has been recognised." If it is so, if it is really true that all the languages of this country are put on a par with Hindi,-I would like to ask one question. Three or four years back my colleague Shri Sezhiyan brought a Constitution (Amendment) Bill on the floor of the House. He wanted to amend Article 15. Sir, this relates to discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. The word 'language' is conspicuous by its absence. In this country, everybody knows that there are differences on the basis of language. Religion, race, all these are mentioned. I do not find much difference with regard to race but still it is mentioned there. Religion is mentioned there So, everything finds a place here. But they are not prepared to include 'language' in this category. This Article reads as follows, namely--

> "The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them."

I would like to know from the hon. Minister, Shri Shukla, whether they are prepared to include language in this category. If they are prepared to include language in this category, I am prepared to concede their claim that all the languages are treated on a par with Hindi. But so long as they are not prepared to put language in this category, it is obvious, there is some disability with regard to the other languages. Everything seems to be going on very smoothly in my part of the country and the Government here do not realise what is the actual difficulty with regard to the Tamilians and also with regard to the Government that is there, whichever might be the party that is ruling. I Challenge the Home Minister that if today the DMK were to resign in Madras, in Tamil Nadu, and if the Congress were to take over power I tell you, they have to come before the public openly and say 'We are not for Hindi'. Because, Sir, it is not a political issue. Many people do not appreciate the origin of this anti-feeling. As far as the language of my part of the country is concerned, it is as old as 2500 years, I should say. We had our ancient Tamil history and there were ancient Tamil poems before the Pallava age, say before 2nd or 3rd century A. D. In all the poems that they had written there is a clear note against the Sanskrit culture. I do not know the reason. But there is that note. It is very much there. The literature is very popular and people read it widely. And, after that ancient period during the Pallava age, there was royal patronage to Sanskrit. Along with other languages, in Tamil also there was lot of admixture of Sanskrit and Tamil. Even at that time side by side with this mixed language there were assertions by poets and essayists and other people to retain the puritanism of the old language also It went on for quite some time. In Tamil it is known as the *manipravaala* style, or mixed style. We find that mixed style in some of

[Shri Kandappan]

the inscriptions of the middle ages, which are quite similar to Telugu, quite similar to Kannada and quite similar to Malayalam in some places. In fact, the first book in Malayalam, namely Ezuthachan's Ramayana, if it could be written in Tamil script, could be understood by us also. That was the position at that time. But fortunately or unfortunately, at the end of the 19th century and at the beginning of the 20th century, a lot of the ancient manuscripts were found out and printed. It synchronised with the modern reniassance all over the world with regard to literature and their outlook. That literature being so medern in its outlook, the people were very much enamoured of that. Then, there started a movement, long before the political movement in Tamil Nadu. Among the Tamil scholars, there was a right royal battle going on whether we should use the pure form of Tamil or we should use the mixed form of Tamil. Later development went in favour of the Pure Tamil movement leaders; among them were Marumalaiadigal, Naralam, Somasundaram and T.V. Kalyanasundaran, who happened to be the founder of some of the labour unions in my part of the country. All those people popularised that movement among the intelligentia and at the academic level. What happened afterwards was this. There was the political movement and the Dravidian movement, and the DMK made it a popular movement. But even before that, the origin was there and the seeds were sown.

Today, the position is this. Unless you totally do away with the literature in Tamil which was there before the 2nd century AD you cannot change the attitude that they are having with regard to language and the scare that they have got against Hindi. This is the historical reason behind it. If the mixed Tamil had been allowed probably to continue, things would not have been so hard for the Tamilians as far as their acceptance of Hindi is concerned, but some how historically it has not come to stay. So, now you cannot do anything about it, unless it be that you are going to ask us to throw into the Arabian Sea all that ancient Tamil literature?...

SHRI TENNETI VISWANATHAM : Why not Bay of Bengal ?

SHRI S KANDAPPAN : Anywhere you like. But that is not going to happen. This being the case, Government should appreciate the realities. So, they should approach the problem in such a way that people are not provoked there. But unfortunately, what has happened is this.

I would like Shri Y. B. Chavan as well as the House to appreciate what happened with regard to language in Tamil Nadu after we came to power. The three-language formula was there with regard to education. We did not do anything. It continued. After we assumed power, the three--languagre formula continued in my State for one year. After the Home Minister brought forwad a Bill with regard to the Language Act for further amending it, even at the introduction stage, we supported it. After that, it was further diluted, and we had some fear; at the final stage only we opposed it. Then, the trouble started. People started burning buses, railway wagons, trucks and things like that; the law and order situation became very grave. Then, we were forced to call the Assembly. Then, we suspended the three-language formula, and we adopted the two-language formula. And it is important to remember here that the two-language formula was adopted unanimously. With regard to the NCC also, we did not suspend them After we came to power, the NCC commands were in Hindi for a year. Nobody objected to them. It is only because of provocation from the Centre that the students' attitude stiffened and they forced us to drop those commands also. So, we had to drop it. After that, some time elapsed, and before everything subsided and before time was given for things to cool off, the radio business came. So, you are not helping us to see how far we can adjust. Rather, you are unnecessarily provoking and putting the DMK Government there into trouble. Today, the propaganda there in Tamil Nadu ..

MR. CHAIRMAN : The hon. Member should try to conclude now.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : Practically he is representing the entire South India, and so, let him continue.

SHRI S. KANDAPPAN : The whole propaganda there is this. Even from the Congress platform, people are approaching the masseses and telling them that the DMK Government has led the Tamilians very badly on the language issue. That is the impression that is sought to be created. Fortunately, the people still have faith in us. If we are going to lose the faith of the people on this issue, I am sure that nobody is going to solve the language problem, and what may happen in Tamil Nadu may be something which we may not like. Either you have to live with the Tamil language, giving more importance to it, or they may tolerate English, if you accede to that demand, or you will be forcing them to secede. There are not other alternatives, as far as I could see.

So, I would appeal to the hon. Home Minister as well as to the Members to see that their guardian angels who want to see that Hindi is propagated in this country and who by their attitude sometimes unwittingly damage the cause of Hindi should place confidence in the DMK Government in Tamil Nadu. Then, you can really hope to settle this matter amicably. I am not in a position to indicate the manner in which it would be possible. In fact, our leaders are very hopeful that it would be possible to come to some kind of settlement. So, I appeal to the hon. Minister to see that this very irritating and one of the grave issues that are facing us in this country is settled in the proper way and in a democratic way and in a way where persuasion will prevail and not force or burte majority.

SHRI RANE (Buldana) : I rise to support the Demands of the Home Ministry which is one of the most important Ministries of ours. If you look at the number of cut motions tabled, you will see that they number more than 360. That itself shows the importance that this Ministry has got

I congratulate the Home Minister and his colleagues Shri Vidya Charan Shukla and Shri K. S. Ramaswamy for the excellent job that they have done during the year under review. Last year was an year of stress and strain for the Home Minister. Perhaps it was unprecedented year in India. After the Constitution came into force in 1950, till 1967, there was not a single year in which there was President's rule in four or five or six States. Then, there were mid-term elections on such a large scale in five States and one Union Territory. Besides, in September last, there was the token strike by the Government employees. I believe that the Home Minister has successfully done his job. The speeches made by Shri Lobo Prabhu and Shri S. Kandappan themselves show that they had no criticism to offer. All the suggestions were of a constructive nature. That itself shows that the Home Minister has done his job very successfully.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : 14 लोगों को मारना क्या यह सक्सैसफुली काम करना कहलायेगा ?

SHRI RANE : Let him look at what the non-Congress Governments have done. They have so taken also many lives. A part from that, this is my view.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : और चीजों में भले ही तारीफ कीजिये लेकिन यह 19 सितम्बर के बारे में मत करिये ।

SHRI RANE : Had it not been for the present Home Minister perhaps Shri George Fernanades and Shri Madhu Limaye would not have got that leniency towards the strikers, I am quite sure. They must thank him for showing that leniency towards the strikers. I would like to convey to the Home Minister that his action of firmly dealing with the strikers was appreciated by the public. But now the public say that the Home Minister and the Governmant have surrendered to the threats of Shri George Fernanades and others.

Before I go to other points, I would like to make a few submissions to the Home Minister on three or four main points. My first submission is that nothing should be done to weaken the Centre. Now, attempts are being made by States to see that the Centre is weakened and it has been attacked on almost all fronts. So, I would sugg-

[Shri Rane]

est that the Centre should not be weakened. Then, I would submit that there is a growing tendency to challenge the Centre's authority and to flout the Centre. This must also be firmly checked and dealt with sternly. Then, I would submit that the convention of appointing Governors in consultation with the States should be discontinued, because this has created new problems which we have to face every day. That is my third submission. My fourth submission is that the Union employees or the Central Government employees should be warned that in case they go on strike in future, they will not be shown the same leniency as was shown to them recently. These are my four suggestions.

I said that same State Governments are trying to weaken the Centre. You yourself have seen that the office of Governor is being attacked during the whole year on different grounds. Of course, they have double standards. If we read the same speeches of the same members, we will see different theories. The second attack is now on the services. I am reading from the *Times of India*, Bombay Dak Edition of the 24th March, 1969. The caption is "All India Services meeting a new challenge" and the article is by Mr. Karad. From that article, I shall quote a few lines. Here it relates to the West Bengal Government :

> "In its 32-point common programme, the United Front Government has declared that it will take steps to change the rules governing ICS, IAS and IPS."

The article goes on to say :

> "What the United Front has in mind is to have the service conditions which will put the Central Services as members of the State Services."

Again it says :

> "Significantly the West Bengal Government is not alone. Shri Namboodiripad, the Chief Minister of Kerala is also thinking on the same lines and Shri Karunanidhi, Chief Minister of DMK, has gone a step further."

This is the quotation from this article. I want to bring to the notice of the Home Minister that it is not only the office of the Governor that they have attacked, but now there is a cry that the rules of the Central Services should be changed and they should be according to their wishes. The Home Minister should be very cautious in relaxing the rules. My submission is that the Central Servicesis one of the factors that we are having an integrated India. Now these State Governments want to nominate Governors, not that the President should do it. They want to take over the powers of nominating Governors from the President. The State Cabinets want that power. Shri Sundarayya, the Marxist leader, said that 'we do not want nominated Governors by the President, we want to elect the Governors'. The provision to elect the Governor was there when the draft Constitution was being considered. But our Constitution-makers wisely gave it up and they put down that the Governors should be appointed by the President. This was a very wise decision and it should be continued. Even if some State Cabinets press for this, the Home Minister should not yield to their demand.

As regards the language question, Seth Govind Das spoke of it at great length. Mr. Kandappan gave very nice arguments for Tamil and other languages. This is not the first time that I am speaking on the subject, even when I spoke in 1967 and last year I said that Hindi alone can be the official language. It is the only integrating force that can unite India. There cannot be any other language.

As regards the other arguments of Shri Kandappan, I am not conversant with Telugu or Tamil language, but I only say that at least in the interest of the unity of the country, we should return to the three-language formula. I would appeal to him and through him to the Tamil Nadu Government to recognise this and return to three-language formula.

As regards Shri Lobo Prabhu, I appreciate one of his suggestions. After the fourth general elections, we find that stability of State Governments has been disturbed. He has made a suggestion that instead of a simple majority, a vote of no-confidence

against the cabinet should be carried only by a two-thirds majority. I agree with him on this.

I have experience in this matter in respect of municipal bodies in Maharashtra state. The Maharashtra Government has an enactment by which the President of a Municipality can be removed by a majority. During this one year, since the Act came into force—they are now amending it—in the Manmad Municipality, the President was changed about eight times. Speaking of my own Municipality of Jalgaon, the present President is the fourth or fifth we have had during one year.

Of course, there is nothing in the Constitution specifying that the vote of no-confidence against the Cabinet should be by a simple majority or a two-thirds majority. But it is time we evolved some such convention so that we do not allow a few defectors to change a Government and introduce instability of Government.

This is all I have to say.

श्री राम गोपाल शालवाले (चांदनी चौक): सभापति महोदय, मैं श्री कण्डप्पन के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि हिन्दी के समर्थक यह चाहते हैं कि केवल हिन्दी ही भारतवर्ष में पढ़ाई जाय, और किसी दूसरी भाषा को न पढ़ाया जाये। जहां तक मेरा विचार है, उन के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि किसी भी हिन्दी समर्थक ने यह दावा किया हो या यह मांग की हो। मैं मूलभूत-रूप से कहना चाहता हूं कि हम भारत की सभी भाषाओं को फलते और फूलते देखना चाहते हैं। यदि हमारा झगड़ा है तो वह विदेशी भाषा अंग्रेजी के साथ है, और मेरे ख्याल में श्री कण्डप्पन और दूसरे सज्जन जो इस देश में रह कर देश की आजादी और सुरक्षा चाहते हैं, किसी विदेशी भाषा का समर्थन नहीं कर सकते। आज वह हिन्दी का विरोध करते हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि जब अंग्रेज यहां पर राज्य करते थे, और वह विदेशी थे, तब उन्होंने अंग्रेजी का विरोध क्यों नहीं किया। मैं उन के सामने यह सवाल रख रहा हूं और उन से इस का जवाब चाहता हूं।

मैं डा० गोविन्द दास के उन विचारों का, जो उन्होंने भाषा के सम्बन्ध में रक्खे हैं, हार्दिक समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि उन्होंने महात्मा गांधी जी के विचारों को और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के विचारों को यहां रख कर एक बहुत बड़ा काम किया है।

एक माननीय सदस्य : यह विचार कांग्रेस के कहां हैं ?

श्री राम गोपाल शालवाले : कांग्रेस के प्रस्ताव हैं, उन के संविधान में है।

सब से पहले मैं दिल्ली प्रशासन के सम्बन्ध अपने विचार आप के सामने रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि गृह-कार्य मंत्री जी उन पर विचार करेंगे। पिछले पचास वर्षों में दिल्ली व आस पास के क्षेत्रों में भारी पैमाने पर परिवर्तन हुए हैं। सन् 1911 में दिल्ली शहर की जनसंख्या 2 लाख 38 हजार थी और 1967 में वह 37 लाख हो गई, और आज विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि सन 1981 में वह बढ़ कर 67 लाख तक पहुंच जायेगी। दिल्ली की बढ़ती हुई जन-संख्या के कारण राजधानी में 11 नगरपालिकायें-नोटिफाइड एरिया कमेटी बना दी गई हैं और बिजली, यातायात जल प्रदाय के दिल्ली राज्य के अन्तर्गत 3 बोर्ड बना दिये गये हैं। यह स्थानीय संस्थायें 1956 तक कार्य करती रहीं, उस समय दिल्ली के जन-जीवन की गति धीमी थी। जन-संख्या की वृद्धि तथा औद्योगीकरण तथा सरकार की बढ़ती हुई गतिविधियों के कारण यह जरूरी था कि दिल्ली की नागरिक सुविधाओं के लिये बड़े स्तर पर प्रबन्ध किया जाय।

1967 में राजधानी की जनता ने केन्द्रीय सत्ता की ठीक नाक के नीचे कांग्रेस के 18 वर्ष पुराने मोह को त्याग कर एक दल को

[श्री राम गोपाल शालवाले]

सत्तारूढ़ करके उस पर जिम्मेदारी डाली कि दोहरे प्रशासन वाले प्रदेश में मिली जुली राजनीतिक व्यवस्था को सफल बना कर स्वस्थ लोकतन्त्र की स्थापना करें। इस परिवर्तन से पहले केन्द्रीय सरकार ने रेड्डी आयोग की स्थापना की थी। नगर निगम की कांग्रेस के पुराने और लम्बे शासनकाल में वित्तीय स्थिति कितनी शोचनीय हो गई थी इस पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने 1966 में रेड्डी आयोग नियुक्त किया था। उस आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1967 के फरवरी माम में दिया जबकि आम चुनाव हो रहे थे। आयोग की मुख्य सिफारिशें ये थी कि केन्द्र निगम की आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए पांच करोड़ का ऋण दे और साथ ही निगम को दो करोड़ रुपये का अनुदान भी दे। किन्तु बीस फरवरी सन् 1967 को चुनाव का परिणाम प्रतिकूल निकलने से केन्द्रीय सरकार ने रेड्डी आयोग की सिफारिशों को वापिस ले लिया।

इसके पश्चात राजधानी के नागरिकों के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा जन हित कार्यों में ठोस कदम उठाने पर रोक लगाने के लिए रेड्डी आयोग की सिफारिशों को ताक पर रख दिया और लोक सभा के कांग्रेसी सदस्य श्री आर. आर. मुरारका की अध्यक्षता में एक नया आयोग बिठाया। इसका मुख्य उद्देश्य जनता पर बड़े बड़े करों का बोझ डाल कर दिल्ली के सत्तारूढ़ दल को बदनाम करना था। इसी प्रकार के सुझाव मुरारका आयोग ने दिये हैं। किन्तु दिल्ली प्रशासन ने उलटा छोटे मकानों पर हाउस टैक्स घटा कर 11 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर दिया। आयोग चाहता था कि गृह कर कम से कम 15 प्रतिशत कर दिया जाए और उसको 24 प्रतिशत तक ले जाया जाए। इस वर्ष निगमायुक्त ने कर बढ़ाने और नए कर लगाने की घोषणा अपने बजट में की थी। मुरारका आयोग ने पानी कर को कम से कम चार प्रतिशत, सफाई कर को ढाई प्रतिशत, गृह कर में पचास प्रतिशत की वृद्धि, चुंगी कर, साइकल कर, विज्ञापन कर, आय कर आदि कर बढ़ाने तथा कुछ नए कर जैसे शिक्षा कर, व्यवसाय कर, नौकरी कर, व्यापार कर लगाने की भी सिफारिशें की थीं। लेकिन नगर निगम तथा महानगर परिषद ने उन सिफारिशों को मानने से इन्कार कर दिया और अगर ऐसा न किया गया होता तो दिल्ली की जनता को दस गुना करों का शिकार होना पड़ता

केन्द्रीय सरकार ने निगम और प्रशासन की सहायता करने के बजाय, उनकी योजनाओं को स्वीकृति देने में भी आनाकानी की जिससे निगम को लाखों रुपये का नुकसान सहना पड़ा। प्रतिवर्ष ग्राम विकास के लिए आयोग ने कहा था कि 15 लाख रुपये निगम को देने चाहियें किन्तु केन्द्र इस पर खामोश है। आयोग की इस सिफारिश पर भी आचरण नहीं किया गया कि निगम क्षेत्र में केन्द्रीय सम्पत्ति की देखरेख का सम्पूर्ण खर्चा केन्द्र उठाये। इससे निगम को 35 लाख रुपये और मिलेंगे। भारत सरकार ने निगम के नौ करोड़ रुपये बकाया देने हैं और केन्द्र द्वारा संचालित नई दिल्ली नगरपालिका से निगम ने तीन करोड़ रुपये लेने हैं। यह बकाया धन यदि मिल जाए तो दिल्ली नगर निगम को कर बढ़ाने के बजाय जनता को राहत देने का अवसर मिल सकता है। इतना ही नहीं जो धन राशि पहले निगम को मिला करती थी वह भी काट ली गई है। बसों के लिए अस्सी लाख और पीने के पानी के लिए ढाई करोड़ रुपया देने के आश्वासन पूरे नहीं किये गये।

दिल्ली प्रशासन ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिल्ली जोकि भारत की राजधानी है, उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल, इसको बनाने के लिए चार सौ करोड़ रुपये की मांग की है और विकास की योजनायें केन्द्र को भेजी हैं। किन्तु योजना आयोग ने 155 करोड़ रुपये ही

स्वीकृत किये हैं । अब इसके अनुसार भी दिल्ली को इस वर्ष 31 करोड़ रुपये मिलने चाहियें । किन्तु दिये जा रहे हैं केवल 23 करोड़ 40 लाख रुपये । चालू वर्ष में बचत के 1 करोड़ रुपये की राशि भी प्रशासन को मिलनी चाहिये थी । यह एक करोड़ और अगले वर्ष के तीन करोड़ मिला कर 35 करोड़ मिलने चाहिये थें । किन्तु बारह करोड़ कम दिये जा रहे हैं । अब विचारणीय प्रश्न है कि राजधानी जहां संसार भर के राजनीतिज्ञ आते रहते हैं उसका विकास कैसे हो । अत मेरा निवेदन है कि गृह मन्त्रालय दलगत विचारों से ऊपर उठ कर वस्तु स्थिति पर विचार करे और दिल्ली प्रशासन की उचित मांगों को स्वीकार करके स्वस्थ परम्परा का संचालन करे ।

भूतपूर्व गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा ने गोहत्या बन्दी आन्दोलन के समय जो आश्वासन दिये थे, उन आश्वासनों को मैं चाहता हूँ कि पूरा किया जाए । उन्होंने कहा था कि जिन राज्यों में गोहत्या के सम्बन्ध में कानून नहीं बने है, केन्द्रीय सरकार अपने प्रभाव से काम ले कर सभी प्रान्तों में उत्तर प्रदेश जैसे कानून बनवा देगी । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है । उलटे गो हत्या बन्द करने के लिए जो सरकारी कमेटी बनाई गई थी उस में भी गतिरोध उत्पन्न हो गया है और तीन गैर सरकारी सदस्यों ने कमेटी के गलत कार्यक्रम के कारण त्यागपत्र दे दिये हैं । साथ ही 29 प्रतिष्ठित गवाहों ने गवाही देने से इन्कार कर दिया है । ऐसी अवस्था में उस कमेटी को तोड़ कर मेरी यह मांग है कि जो आश्वासन उस समय गृह मंत्री जी ने दिये थे गोरक्षा महाभियान समिति को, उनको पूरा करके सम्पूर्ण देश में गोहत्या को बन्द किया जाए ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जिस पर आपको चाहिये कि आप मानवता के आधार पर विचार करें । स्वामी रामेश्वरानन्द जी को जो इसी सदन के सदस्य थे 85 अन्य व्यक्तियो के साथ तब गिरफ्तार किया गया था । यह निश्चित बात है कि उस समय पुलिस रिपोर्ट के अनुसार यह प्रकाश में आया था कि गोहत्या बन्दी आन्दोलन में प्रदर्शनकारियों ने कोई तोड़ फोड़ का काम नहीं किया था । लेकिन फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया । आप देखें कि किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ? उन बेचारों को किया गया जो दफ्तर जा रहे थे या कोई बाहर से आए थे । स्वामी रामेश्वरानन्द जी का कसूर यही था कि उन्होंने इतना ही कहा कि संसद में आ कर मंत्रियों को घेर लो, तब वे तुम्हारी बात मानेंगे । कृपा करके गृह मंत्री जी बतायें कि इस में कौनसी हिंसा की बात है जिस के कारण उनको गिरफ्तार किया गया था और तब से ले कर आज तीस महीने से उन पर मुकदमा चल रहा है और उनको बार बार अदालत में घसीटा जा रहा है । मैं कहना चाहता हूँ कि जिन पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं वे जरूर छूट जायेंगे और उसी प्रकार से छूट जायेंगे जिस प्रकार कामराज की कोठी पर प्रदर्शन करने वालों पर मुकदमे चलाये गये थे और वे अदालतों से साफ छूट गए थे । यह आपको शोभा नहीं देता है कि बार बार आप उनको अदालतों में घसीटें । तीस महीने उनको घसीटते हुए हो गए है । उन गरीब लोगों पर भी मुकदमे चलाये जा रहे हैं जो बाहर के हैं और जो बाहर से आने में असमर्थ हैं और किराया खर्च करके नहीं आ सकते है । मैं निवेदन करता हूँ कि इन मुकदमों को वापिस ले कर आप उदारता का परिचय दें और जनता की बात को मानें ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि धर्म निरपेक्ष राज्य मे सब को धर्म प्रचार करने का अधिकार है और मैं इसका विरोध नहीं करता । किन्तु गरीब वनवासियों और हरिजनों का जिस ढग से बीमारी और गरीबी का लाभ उठा कर धर्म परिवर्तन किया जाता

[श्री राम गोपाल शालवाले]

है उस खतरनाक स्थिति के सम्बन्ध में खाद्य मंत्री श्री जगजीवन राम ने कहा था कि हरिजनों के धर्म परिवर्तन का यदि यह दौर चलता रहा तो पंद्रह बीस वर्ष में विदेशी दासता के पुनः दुर्दिन हमें देखने पड़ेंगे। उन्होंने इस पर चिन्ता व्यक्त की थी और कहा था कि देश का नक्शा बदलने के पूरे प्रयत्न धर्म परिवर्तन के माध्यम से किये जा रहे हैं। निओगी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। रेगे कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कानून पास कर दिया है। इन आयोगों ने विदेशी पादरियों की गतिविधियों को देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया है। मैं निवेदन करता हूं कि इंडियन नैशनल चर्च के प्रधान फादर विलियम्ज ने भारत सरकार से विदेशी पादरियों के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी और सरकार को प्रतिवेदन दिया था कि धर्म प्रचार का अधिकार विदेशी मिशनरियों से ले कर इंडियन नैशनल चर्च के पादरियों को दिया जाए। किन्तु सरकार इस पर भी मौन है।

आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि आज पादरी फेरर भारत में आ गए हैं। वह जब बम्बई में थे तब महाराष्ट्र सरकार ने उनका बम्बई में टिकना, वहां रहना बन्द कर दिया था। बम्बई में किसी गाड़ी पर चढ़ने की भी इजाजत उनको नहीं थी। बम्बई में किसी को उनके साथ मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी थी। मैं हैरान हूं कि जिस पादरी फेरर को महाराष्ट्र की सरकार खतरनाक समझती थी, उसको केन्द्रीय सरकार ने आंध्र में बसने की और वहां प्रचार करने की सुविधा क्यों दी ?

अब मैं केवल एक बात कह कर अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा और वह काश्मीर के सम्बन्ध में। जब परमेश्वरी हाण्डू का प्रश्न उठा था, उस समय गृह मंत्री चव्हाण वहां गये थे और मैं भी उन की सेवा में उपस्थित हुआ था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि परमेश्वरी हाण्डू को किसी तीसरे पक्ष के पास रखा जायगा, हम न्याय करेंगे। लेकिन आज दुखी हृदय से कहता हूँ-आप अल्पसंख्यकों के हितों का नारा लगाते हैं, लेकिन काश्मीर में हिन्दू अल्पसंख्यकों पर कितना अत्याचार हुआ है, उस का यह नमूना है। परमेश्वरी हाण्डू की 42 पेशियां होने के बावजूद भी उस को अदालत में पेश नहीं किया गया है। आपने कोहली कमीशन को बैठाया था, मैं जानना चाहता हूँ कि उस पर कितना रुपया खर्च हुआ, क्या उस का प्रतिवेदन आपको प्राप्त हो गया है। यदि प्राप्त हो गया है तो उसकी सिफारिशें क्या है, आप उसे सदन के टेबिल पर रखिये और यदि उस कमीशन ने सादिक सरकार की साम्प्रदायिक मनोवृत्तियों को खोला है तो आपका कर्तव्य है कि आप काश्मीर के अल्पसंख्यकों के साथ भी वही व्यवहार करें जो दूसरों के साथ करना चाहते हैं।

श्री गंगा रेड्डी (आदिलाबाद) : सभापति जी, मैं आपका तहेदिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे यह मौका इनायत फरमाया कि मैं खास कर मुल्क में बढ़ते हुए ला-लेसनेस के बारे में अपने विचार प्रकट कर सकूं। जो हालात बम्बई और आन्ध्र में पैदा हुए—हिन्दुस्तान की तकसीमे जदीद के सिलसिले में—उसकी तवारीख 1905 से शुरू होती है। 1905 में जब बंगाल के दो हिस्से हुए, तब कांग्रेस ने यह आवाज बुलन्द की थी कि एक जुबान बोलने वाले एक ही प्रदेश में रखे जायं और उसके टुकड़े न किये जायं। उसके बाद 1917 में, 1920 में, 1927 में और 1928 में इस किस्म के रेजोल्यूशन्ज एडाप्ट किये गये। 1938 में वर्धा कांग्रेस में यह निर्णय लिया गया कि आजादी के बाद अगर कांग्रेस इक्तदार में आई तो

हिन्दुस्तान की तकसीमे जदीद इन्सानी बुनियादों पर करेगी। 1945-46 के इलैक्शन में कांग्रेस ने अपने मेनीफैस्टो में इस बात को लेकर इलेक्शन-कोन्टेस्ट किया, लेकिन उस के एक साल बाद जब आजादी मिली तो पं० जवाहर लाल नेहरू ने 27 नवम्बर, 1947 को इसी सदन में कहा था कि बदले हुए हालात के मद्देनजर हम को यह चीज सोचनी चाहिये। इस के बाद धर कमीशन और जे. वी. पी. कमीशन बैठाये गये। उन्होंने यह कहा कि महज लोगों के विचार और लोगों की रजामन्दी से ही ऐसी चीजें अमल में लानी चाहियें। उस के बाद 1952 में नेहरू जी ने इस सदन में यह कहा कि ऐसी चीजों से हिन्दुस्तानी इस्तेहकाम और यकसानियत को नुकसान पहुंचेगा, लिहाजा इस चीज को नहीं सोचना चाहिये। इस के बारे में राजाजी ने भी कहा है-कि यह एक ट्राइबल अफेयर है। सरदार पटेल के विचार थे कि जिस हिन्दुस्तान को एक करने के लिये खून बहाया है, इस को डिसइन्टीग्रेट नहीं करना चाहिये। लेकिन इस के बर खिलाफ 1953 में आन्ध्र अमल में आया। उस के बाद विशाल आन्ध्र का मुतालबा चलता रहा और आन्ध्र प्रदेश के फोर्म होने के पहले हैदराबाद के मुताल्लिक एस०आर०सी० रिपोर्ट में जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है-मैं उन को आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं—

"Hyderabad was an integrated unit with common geo-political features and it presented a miniature real culture of India and be preserved as a model of other States."

काश कि यह बात मानी जाती, तो आज मुल्क के जो हालात हैं, वह न होते। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और विशाल आन्ध्र के बारे में सोचा गया। हैदराबाद का यह मुतालबा था-हमारी स्टेट हर लिहाज से एक मौजूं स्टेट है, यहां भिन्न भिन्न जुबानों के बोलने वाले, भिन्न जगहों पर रहते हैं यहां इण्डिया का कल्चर है, इस लिये इस को न तोड़ा जाय। उनकी इकानामिक कन्सीडेशन्ज भी थीं, वायाबिल्टी भी थी, आबादी के लिहाज से और मालिये के लिहाज से भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि आन्ध्र में अगर हम को डम्प कर दिया जायगा तो जो एन्टरप्राइजिज एरियाज हैं, व हम को कालोनी में तबदील कर देंगे। मैं उन अलफाज को भी आपको सुनाना चाहता हूं-

"The real fear of Telengana is that if they join Andhra they will be unequally placed in relation to the people of Andhra and in this partnership the major partner will deprive all the advantages immediately while Telengana itself may be converted into a colony by the enterprising coastal Andhra."

इस के बाद फजलअली कमीशन ने कई दूसरी बातों पर गौर करते हुए कहा कि गो आन्ध्र का कायम होना डिजायरेबिल है, मगर उस में कुछ तबानियत हो और किसी को कुछ शुब्हा न हो। इस के बाद तेलंगाना लीडर्स से गुफ्तगु हुई और नतीजे के तौर पर एक जैन्टिलमैन एग्रीमेन्ट हुआ इस जैन्टिलमैन एग्रीमेन्ट की इस चीज की मैं वजाहत करना चाहता हूं कि उस में यह एक प्रीकन्डीशन थी कि जिसकी बिना पर आन्ध्रप्रदेश का कयाम अमल में आया-जिस तरह से यू०एन०ओ० में व्हीटो पावर न होती तो आज यू०एन०ओ० न होता, उसी तरह से अगर यह प्रीकन्डीशन न होती तो आन्ध्र प्रदेश फार्म न होता। फजलअली कमीशन ने उस वक्त जो कुछ कहा था वह आज लफ्ज-ब-लफ्ज सही साबित हुआ है। आज हमको यह मानना पड़ेगा कि हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ है, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। अब अगर यह कहा जाय कि वहां के पब्लिक के नुमाइन्दे क्या करते थे, उन्होंने सामने आकर इस चीज को क्यों नहीं उठाया। उन्होंने उठाया, लेकिन जब वह कामयाब नहीं हुए, तो आम तौर पर यह इन्सानी फितरत होती है कि वह खुद-बखुद

[श्री गंगा रेड्डी]

उभर कर सामने आ जाती है। अब लोग मुतालवा करते हैं, एजीटेशन करते हैं और आजकल एक ऐसा दौर चल रहा है कि जब तक लोग एजीटेशन न करें, तोड़फोड़ न करें, उस चीज की तरफ निगाह नहीं जाती। यही आन्ध्र में भी हुआ।

लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि आन्ध्र में कोई ऐसा वायलैंस नहीं हुआ, जिसको शिव सेना से कम्पेअर किया जाय। आन्ध्र का एजीटेशन कम्पेरेटिवली बिलकुल पीसफुल था। आज भी लावी में या बाहर प्रेस के लोग हम से पूछते हैं कि आप पब्लिक के नुमाइन्दे हैं, आपकी रिजनल कमेटी क्या करती रही, आपके एम०पीज० और एम०एल० एज० क्या करते रहे। मैं बड़ी नम्रता से मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ–

नाहक यह तोहमत है हम मजबूरों पर
जो चाहें आप करें, अल्म हमें बदनाम किया।

जब आप पावर में हैं तो जो चाहते है, हम से मनवा लेते है। जब जिम्मेदारी की बात आती है तो कहते हैं कि तुम जिम्मेदार हो, तुमने क्या किया। और अगर रिजनल कमेटी की रिपोर्ट पर नजर डालें तो आपको वाजा होगा कि हर वक्त बिना किसी हिचकिचाहट के हम उन तमाम चीजों को उनकी नजर में लाते रहे, यह चीज गलत है, यह इस तरह से होनी चाहिये, मगर उन पर कभी अमल नहीं हुआ और आप जानते हैं एक मसल मशहूर है कि हमेशा मजबूत आदमी कमजोर आदमी को दबा देता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वही चीज हमारे साथ हुई। अगर हम कोई दिल की आवाज निकालते तो हमें कहा जाता कि तुम गलत कह रहे हो। मैं यह कहता हूं कि हमें ऐसा सोचने का मौका ही क्यों दिया गया, क्यों हमारे साथ नाइन्साफी की गई। हमारे 6 हजार मुलाजमीन के साथ अन्याय हुआ है, उन का बहुत नुकसान हुआ है, जो मस्ल उस वक्त नौकरी की उम्र में थे, आज वे एज-बार हो गये हैं–इस की तलाफी कैसे होगी ? ललित कुमार की रिपोर्ट आई है, उस पर चर्चा हो रही है कि वह सही नहीं है। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यह अर्ज जरूर करना चाहता हूँ कि अगर वरवक्त खर्च होता तो आज तेलंगाना वैकवर्ड न होता। वहां पर जितने वसायल हैं उन को अगर प्रापरली डवेलप किया जाता तो आज आन्ध्र की बद-किस्मती ऐसी न होती। आन्ध्र जिसको अन्न-दाता कहते है, अगर आप उस में घूम कर देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां कितने जिले ऐसे है जहां वसायल रहते हुए भी ध्यान नहीं दिया गया और उसकी यह दुर्दशा हुई।

मैं अपने कुलीग्स को बताना चाहता हूं कि आन्ध्र बनने के पहले हैदराबाद एक ऐसी स्टेट थी कि जहां औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थीं, घरों में पर्दा करती थी, लेकिन आज वे औरतें घर से बाहर निकल कर भूख-हड़ताल कर रही हैं। क्या कोई बाप पसन्द करेगा कि अपनी बेटी को बाहर बेपर्दा होने दे–आप को देखना चाहिये कि क्या तकलीफें हैं, जिनकी वजह से वह बाहर निकलने को मजबूर हुई और उन को एजीटेशन करना पड़ा। मेरे किसी दोस्त ने कहा कि वहां पुलिसमैन पर अण्डे फेंके गये, टमाटर फेंके गये–मैं आप से अर्ज करूंगा कि आप उन की मजबूरी का पता लगाइये कि ऐसा क्यों हुआ, उनकी बीमारी का पता लगाइये और उस के बाद दवा दीजिये। ऐसा न कहिये कि वह क्यों शोर मचाते हैं, यह बीमारी तक एप्रोच करने का गलत तरीका है।

मैं एक चीज पूछना चाहता हूं–जब 9 जिलों की आबादी डेढ़ करोड़ है और इतना बड़ा एजीटेशन चल रहा है, क्या गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि वहां पर कितने कत्ल हुए, कितनी औरतों की असमत लूटी गई, कितने गोली के निशान बनाये गये, कितने लोगों की जानें

गई । महज़ लोगों की अटेन्शन को डायवर्ट करने के लिये ऐसी बातें कही जाती हैं । मैं यकीन के साथ कहता हूं कि कोई भी ऐसी बदइखलाकी या ऐसी चीज़ नहीं हुई है । मैं यह मानता हूँ कि जब इतना बड़ा कोई आन्दोलन होता है तो थोड़े एन्टीसोशल एलीमेन्ट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे मौकों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और ऐसी हरकतें कर बैठते हैं ।

बहुत से लोगों ने हमारे चीफ मिनिस्टर को दोष दिया है और कहते हैं कि वह इस्तीफा दें । मैं तो यह कहूंगा कि हमारे प्रदेश में कोई और आदमी ऐसा हिम्मतवाला नहीं है जो कहे कि चलिये, ब्रह्मानन्द रेड्डी साहब, आप हट जाइये, मुझे मौका दीजिये, मैं हालात को सुधार सकता हूँ-ऐसा कोई नहीं कह सकता । अगर वह यह कहेगा तो दूसरे आदमी नाराज़ होंगे । यह बात सही है कि सभी को खुश करना बड़ा मुश्किल होता है । लेकिन मैं यह कहूंगा कि जिस खूबी के साथ इस सिचुएशन को सम्हाल रहे थे उससे अच्छा हो नहीं सकता । पर बदकिस्मती की बात यह है कि जो मतालिबात सन् 56 में दिए गए थे वही मांग रहे थे और आन्ध्र के भाई यह समझ बैठे कि हमको लूटना चाहते हैं । उन्होंने काउन्टर एजिटेशन शुरू किया बजाये इसके कि वे चीफ मिनिस्टर के हाथ और मजबूत करते और तेलंगाना वालों के दिलों में यह उम्मीद पैदा करते कि हम आपके साथ हैं, आप चाहते हैं तो थोड़ा और ले लें । जब बड़ा भाई माना तब फिर इतना जेनरस होना ही चाहिये था । वे थोड़ा दिलदार होते और कहते कि जो नुकसान हुआ उसके लिए और ज्यादा ले लो । लेकिन बजाय इसके उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्टर्ब करने के लिए कदम उठाये ।

एक बात और है । हमारे दोस्तों ने यहां तक किया कि रेफ्यूजी कैम्प्स लगा दिए और उनको इस तरह से आर्गेनाइज़ किया जैसे कि पहले पाकिस्तान से आये हुए रेफ्यूजीज़ को हिन्दुस्तान में कैम्पस में रखा गया था । उसी पैमाने पर उन कैम्प्स को अरेंज किया गया विजयवाड़ा वगैरह में ताकि उनकी गम्भीरता मालूम हो सके । मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् 56 का जो मुआहिदा था उसी को वे चाहते थे, कोई नयी चीज नहीं चाहते थे, फिर क्या जरूरत थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने की । मैं समझता हूँ कि हरएक का यह फर्ज है कि उनकी जो तकलीफ है उसको हल करने का काम करे । लेकिन इस मामले में जितने हमारे लीडरान हैं या जो दूसरे लोग हैं, सभी कन्फ्यूज्ड हैं कि इसका हल कैसे होगा । लीडर्स और पब्लिक के नुमाइन्दों की राय के बारे में आपने पढ़ा होगा, एम० एल० एज़० और एम० पीज० भी अपने नये नये विचार दे रहे हैं, एक विचार के कोई भी नहीं हैं । मैं आपके जरिए बताना चाहता हूँ कि ऐसी स्टेज आयेगी जिसमें ऐसी लालेसनेस होगी जिसको आप बन्दूक की गोलियों और पुलिस की लाठियों से सम्हाल नहीं सकेंगे । एक ह्यूमन प्राब्लम समझकर ही इसे आपको टैकिल करना होगा । जिस एरिया को आप बैकवर्ड समझते हैं उसकी तरक्की करने का रास्ता आपको निकालना चाहिये । इस मामले में मैं सेन्टर को भी दोष देता हूं । रीजनल इम्बैलेसेज़ को दूर करने के लिए सेन्टर को इमदाद करनी चाहिए । आज आन्ध्र प्रदेश की इतनी आमदनी नहीं है कि जो सरप्लस खर्च किया गया उसको वह पूरा कर सके और बैकवर्ड एरियाज़ को डेवलप करने के लिए उतना पैसा खर्च कर सके । इसलिए सेन्टर को चाहिये माली तौर पर, इन्तजामी तौर पर जितनी सहायता की जरूरत है उसको पूरा करे ।

मुझे थोड़ा सा मौका और दें क्योंकि यह मेरी रियासत का मामला है और मैं इसको अच्छी तरह से लोगों के सामने रख सकता हूँ । तो मैं यह कह रहा था कि इसके बारे में नये नये विचार आ रहे हैं, किसी के दिमाग में

[श्री गंगा रेड्डी]

क्लियर थिंकिंग नहीं हैं, कोई भी मसले को सुलझाने वाला नहीं है। इसकी वजह से अवाम और लीडर्स के बीच गल्फ और बढ़ गया है। इस समस्या को कोई समझना ही नहीं चाहता है और न कोई इस स्थिति में है कि इसको कन्ट्रोल कर सके। मैं चाहूँगा कि इस समस्या के भड़कने से पहले ही इसका इन्तजाम किया जाये वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। ऐसी गम्भीर स्थिति पैदा हो जायेगी जिसको फिर सम्हालना मुश्किल हो जायेगा। इसलिए मेरी अर्ज है कि जहांतक सरप्लस की बात है या मुलाजिमत की बात है जितना भी पैसा देने की बात है, उसके लिए कागज पर लिखने से या प्रेस स्टेटमेन्ट देने से कोई हल निकलने वाला नहीं है बल्कि अमली तौर पर यह बताना होगा कि यह हम करेंगे। काफी अरसा गुजर चुका है, गवर्नर एड्रेस में बताया गया, असेम्बली में वोट आन एकाउन्ट के वक्त बताया गया और पार्टी मीटिंग में भी हुआ, अब तो इसके लिए शाक ट्रीटमेन्ट की जरूरत है। पैसा फौरन रिलीज किया जाना चाहिये क्योंकि बरसात आने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 9 करोड़ दिया गया है वह भी खर्च नहीं हो पायेगा, उसका बेश्तर हिस्सा लैप्स हो जायेगा। फिर यह बात कही जायेगी कि हमने पैसा दिया लेकिन आप खर्च नहीं कर पाये। मुझे इस बात का तजुर्बा है कि अगर 9 करोड़ खर्च करना है तो 25 करोड़ का काम लेना होगा। और अगर वक्त पर पैसा रिलीज होगा तभी वह काम हो पायेगा। आजकल वह रिलीज नहीं हुआ है और न कोई काम ही देखा गया है, न खर्चे के लिए कोई आर्डर्स ही दिए गए हैं। अगर बरसात में रिलीज होगा तो उसके बाद मार्च में माली साल खत्म हो जायेगा और वह पैसा भी लैप्स हो जायेगा। लोगों में जो डिसकन्टेन्टमेन्ट है वह उसी तरह से बरकरार रहेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का फर्ज है और साथ ही साथ अपोजीशन के लीडर्स का और हर भाई का फर्ज है कि वे बैठ कर इस मसले पर गौर करें इसमें एक दूसरे पर तोहमत लगाने या जिम्मेदारी आयद करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर इसका हल वह नहीं सोचते हैं तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा :

न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिन्दोस्तां वालो
तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में।

[شری گنگا ریڈی (عادل آباد) سبھاپتی جی میں آپ کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں خاصکر ملک میں بڑھتی ہوئی Lawlessness افراتفری کے بارے میں اپنے وچار بیان کر سکوں جو بہار اور اندھرا میں پیدا ہوئے ہندوستان کی تقسیم جدید لسانی بنیادوں کی تاریخ ۱۹۰۵ سے شروع ہوتی ہے جبکہ بنگال کی تقسیم ہوئی تب کانگریس نے یہ آواز بلند کی تھی کہ ایک زبان کے بولنے والے ایک ہی پر دیش میں رکھے جائیں اور اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں—

اس کے بعد ۱۹۱۷ میں—۱۹۲۰ میں ۱۹۲۷ اور ۱۹۲۸ میں اس قسم Resolution adopt کیئے گئے—۱۹۳۸ میں کانگریس ورکنگ کمیٹی نے وردھا میں یہ طے لیا کہ آزادی کے بعد اگر کانگریس برسراقتدار آئے—تو ہندوستان کی تقسیم جدید لسانی بنیادوں پر کریگی—۱۹۴۵-۴۶ کے الیکشن میں کانگریس نے اپنے Election Menefesto میں اسی بات کو لیکر الیکشن لڑا لیکن اسکے ایک ہی سال بعد جب آزادی ملی تو پنڈت نہرو نے

۲۷-۱۱-۴۷ کو اسی سدن میں کہا تھا کہ بدلے ہوے حالات کے مدنظر ہم کو یہ چیزیں پوچھنی چاہئے-اس کے بعد دھار کمیٹی-.J.V.P کمیٹی کی تقریر ہوئی- انہوں نے یہ کہا کہ محض لوگوں کے وچار اور رضامندی سے یہ چیزیں عمل میں لانی چاہیے-اس کے بعد ۱۹۵۲ میں پنڈت نہرو نے اسی سدن میں یہ بھی کہا تھا کہ ایسی چیزوں کے عمل آوری سے ہندوستان کے انتظام اور یکسالمیت کو نقصان پہنچے گا- لہاذا ایسی چیزوں کو ابھی سوچا نہیں جائے اس کے بارے میں راجگوپال آچاریہ نے کہا تھا کہ ہندوستان کی تقسیم انسانی بنیادوں پر سوچنا ہی ایک Tribal affair ہے-سردار ولبھ بھائی پٹیل کے وچار تھے کہ جس ہندوستان کو ایک کرنے میں چو لاکھوں کا نقصان بھایا گیا اس کو Disintegrate نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے برخلاف اندھرا کا خیال ۱۹۵۳ میں عمل آیا اس کے بعد وشال اندھرا کا مطالبہ جاری رہا اور آندھرا پردیش کے قیام سے پہلے حیدرآباد کے متعلق .S. R. C رپورٹ میں جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے میں ان کو پڑھکر سنانا چاہتا ہوں-

"Hyderabad was an integrated unit with common geopolitical features and it preserved a miniature real culture of India and be preserved as a model for other states"

کاش کہ یہ بات مانی جاتی تو آج ملک کے جو حالات ہیں وہ نہ ہوتے لیکن اس پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا-اور قیام وشال آندھرا کے بارے میں سوچا گیا- حیدرآباد کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ ریاست ہر لحاظ سے ایک موزوں ریاست ہے یہاں ہر بھن بھن جاتی اور زبان کے بولنے والے بستے ہیں-یہاں کا culture صحیح طور پر ہندستان کا culture ہے اس سے اسکے ٹکرے نہ کئے جائیں اس کی آبادی-مالیتی اور ہر لحاظ سے یہ ایک Voible unit ہے-

حیدرآباد والوں نے یہ Protest (اعتراز) کیا کہ اگر ہم کو آندھرا میں ضم کر دیا جائے تو جو enterprising Andhra والے ہیں وہ ہم کو Colony (کالونی) میں تبدیل کردینگے میں .S. R. C کے یہ الفاظ بھی سنانا چاہتا ہوں-

"The real fear of Telengana is that if they Join Andhra, they will be unequally placed in relation to the people of Andhra and in this partnership the major partner wil deprive all the advantages immediately while Telengana itself may be converted into a colony by the enterprising coastal Andhra".

اس کے بعد فضل علی کمیشن .S.R.C نے کئی دوسری باتوں پر غور کرتے ہوے کہا کہ گو آندھرا پردیش کا قیام Desirable ہے مگر اس کے لئے کچھ تحفظات Guarantee ہونا کہ تلنگانا والوں کو شبہ نہ ہو اس کے بعد تلنگانا اور آندھرا لیڈرس کی گفتگو ہوئی اور نتیجہ کے طور پر ایک معاہدہ ہوا جسکو Gentlmen's agreement کہتے ہیں میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاہدہ آندھرا پردیش کے قیام کے لئے ایک Precondition (شرط) تھی جنکی بنا پر آندھرا پردیش کا قیام عمل میں

[شری گنگا ریڈی]

آیا-جس طرح سے کہ U. N. O. میں Veto-power نہ مانی جاتی تو U. N. O. کا قیام نہ ہوتا اس طرح سے یہ Precondition نہ ہوتی تو آندھرا پردیش قایم نہ ہوتا-

فضل علی کمیشن نے اس وقت جو کچھ کہا تھا آج وہ لفظ بہ لفظ صحیح ثابت ہوا اور ہم کو آج یہ ماننا پڑیگا کہ ہمارے ساتھ بھاری انیائے (ناانصافی) ہوا اور ہمارا بھاری نقصان ہوا-اب یہ کہا جائے تو تلنگانا کے عوامی نمائندے اب تک کیا کرتے رہے- انھوں نے ہر وقت سامنے آکر اس مسلہ کو کیوں نہیں اٹھایا اس مسلہ کو انھوں نے کئی بار اٹھایا مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے عام طور پر ایسا ہوتا ہی ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب ناانصافی ہوتی ہے تو جذبات خود بہ خود ابھرکر سامنے آجاتے ہیں۔ اور لوگ agitation کرتے ہیں۔ آجکل ایک ایسا دور چل رہا ہے کہ جبتک کہ لوگ agitation نہ کریں توڑ پھوڑ نہ کریں نہ اس چیزوں کی طرف ہماری نگاہ ہی نہیں جاتی ایسا ہی آندھرا میں ہوا۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آندھرا میں کوئی ایسا Voilence نہیں ہوا جس کو بمبئی کے شیو سینا سے مقابلہ کیا جائے آندھرا کا agitation مقابلتن Peaceful تھا آج بھی lobby میں اور دوسرے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہاں کے پبلک کے نمایندے اور آپکی Regional Committee کیا کرتے رہی آپ کے M-Ps اور M.L.As کیا کرتے رہیں میں بڑی امرتا (ادب) سے آپ کو ایک شعر سناتا ہوں-

”ناحق یہ تہمت ہے ہم عبوروں پر
جو چاہے سو آپ کریں عبث ہمیں بدنام کیا“

جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں ہم سے منوالیتے ہیں اور جب ذمہ داری کی بات آتی ہے تو کہتے ہو کہ تم ذمہ دار ہو تم نے کیا کیا-آپ اگر Regional Committee کے رپورٹس پر نظر ڈالیں تو آپ پر یہ واضح ہو جائیگا کہ ہروقت بنا ہچکچاہٹ کے ہم نے ان تمام چیزوں کو ان کے توجہ میں لائے کہ یہ غلطیاں ہو رہی ہیں اور وہ اس طرح سے ہونی چاہئے مگر ان پر کبھی عمل نہیں ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مثل مشہور ہے کہ ہمیشہ مضبوط آدمی کمزور آدمی کو دبا دیتا ہے بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے وہی ہمارے ساتھ ہوا-جب ہم کبھی دل کی آواز نکالتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے تو میں کہوں گا کہ ہمیں ایسا سوچنے اور کہنے کا موقع ہی کیوں دیا گیا-کیوں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہمارے تقریبا ۶۰۰۰ ملازمین employees کے ساتھ انیائے (ناانصافی) ہوئی ان کا وہ نقصان ہوا ہے جسکی تلافی نہیں ہو سکتی-جو شخص اسوقت نوکری کے اہل تھا مگر وہ agebar ہوگیا۔

کمار للت (Kumar Lalit) کی رپورٹ آئی ہے اس پر چرچا ہورہی ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے میں اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا مگر یہ عرض کر

دینا چاہتا ہوں کہ اگر بروقت یہ رقم تلنگانا میں خرچ ہوتی تو آج تلنگانا Backward نہیں ہوتا اور وہاں پر جتنے وسائل ہیں اگر انکو Properly develop کیا جاتا تو اس علاقہ کی ایسی درگتی نہیں ہوتی۔ آندھرا جس کو ان داتا کہتے ہیں اگر اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں کتنے ضلع ایسے ہیں کہ جہاں ہر وسائل کے رہتے ہوئے بھی ان کے Development کا خیال نہیں کیا گیا اور اس کی یہ درگتی ہوئی۔

میں اپنے ساتھیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد ایک ایسی ریاست تھی جہاں عورتیں پردا کرتی اور گھر سے باہر نہیں آتیں۔ لیکن آج وہی عورتیں گھر سے باہر آکر بھوک ہڑتال کررہی ہیں کیا کوئی باپ یہ پسند کریگا کہ اس کی بچیوں کو بے پردہ ہوکر ایسی ہڑتال کرانے دیں۔ مگر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کو کیا تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ باہر نکلنے کے لئے مجبور ہوئیں اور ان کو استعمال agitation کرنا پڑ رہا ہے میرے کسی دوست نے یہ کہا کہ وہاں پر سینٹر کے وزرا پر انڈے اور ٹماٹر پھینکے گئے میں آپ سے یہ عرض کرونگا کہ آپ ان کی تکلیف اور مجبوریوں کا پتہ لگائیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ان کی بیماری کا پتا لگا کر اس بیماری کی دوا دینا ہے ایسا نہ کہیئے کہ وہ کیوں شور مچاتا ہے اور تڑپتا ہے ورنہ یہ بیماری کے علاج کا غلط طریقہ ہوگا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ۹ ضلع کی آبادی 1½ کروڑ کی ہو جہاں پر اتنا بڑا agitation چل رہا ہوگیا گرہ منتری جی Home Minister یہ بتائینگے کہ وہاں پر کتنے قتل ہوئے کتنی عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئیں کتنے لوگ گولی کے نشانے بنے اور کتنے لوگوں کی جانیں گئیں۔ میں یقین کے ساتھ کہونگا کوئی ایسی خطرناک حالت نہیں ہوئی محض لوگوں کو متاثر کرنیکے لئے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں۔ جہاں کہ ایسا بڑا آندولن ہوتا ہے تو تھوڑے بہت Unsocial element ایسے موقع سے فائدہ اٹھاکر کچھ غلط حرکتیں کر بیٹھتے ہیں۔

بہت سے لوگوں نے ہمارے چیف منسٹر کو دوش دیا اور کہتے ہیں کہ وہ فوری مکتی ہوجائیں میں یہ کہونگا کہ اب وہاں پر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ چلئے برہمانند ریڈی صاحب آپ مکتی ہو میں حالات کو بالکل درست کردونگا آج کے حالات میں کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا اگر ایسا کریگا تو دوسرے حصوں سے اسکی مخالفت ہوگی یہ سچ ہے کہ ایک شخص ہر ایک کو خوش نہیں کرسکتا۔

میں یہ کہونگا کہ چیف منسٹر نے شروع میں جس خوبی کے ساتھ situation کو سنبھال رکھے تھے اس سے اچھا ممکن نہیں تھا مگر بدقسمتی کی بات جبکہ ہم سے وہی نشان Guarntees مانگ رہے تھے جو ۱۹۵٦ میں دیئے گئے تھے مگر ہمارے آندھرا کے بھائی یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم ان کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے غیر ضروری Counter agitation شروع کیا بجائے چیف منسٹر کے ہاتھ مضبوط کرنے اور

والی ھے جس کو آپ بندوق کی گولیون اور پولس کی لاٹھیون سے اسکو نہیں سنبھال سکین گے-میں اس معاملے مین سنٹرل گورنمینٹ کو دوش دینا ھون- دیش مین Regional Imbalances کو دور کرنیکے لئے سنٹرل گونمینٹ کو امداد دینی چاھیے-

آج آندھرا کی اتنی آمدنی نہین ھے کہ جو تلنگانا کے Surpluses آندھرا مین خرچ کرسکے وہ واپس کرسکے اس لئے شسٹر کو چاھئے کہ آندھرا کو مالی طور پر انتظامی طور پر جتنی امداد ھو فوری دین-سنبھالتی ہی مجھے کچھ اور وقت دیجیے چونکہ یہ میری ریاست کا مسلہ ھے مین وھان کے حالات اس سدن کے سامنے رکھنا چاھتا ھون-

تلنگانا کے بارے مین لئے لئے وچار آرھے ھین کسی کے دماغ مین اس بارے مین Clear thinking نہیں ھے کوئی ٹھوس اقدام لیکر اسکو حل کرنا ھی چاھئے- اس کی وجہ سے آج اندھرا پردیش مین عوامی نمائندون مین اور عوام بھی ایک (Gulf)خلا پیدا ھو گیا ھے اور ربط باقی نہین ھے اس مسلہ کو سنجیدگی سے کوئی سلجھانا نہین چاھتا اور اگر اس ماملے کو فوری حل نہ جائے تو یہ مسلہ بڑھکے گا اور اس سے قبل ھی اس کا موزون انتظام ھوجانا چاھئے ورنہ ھمین پچھتانا پڑے گا کہ ایسی گمبھیر استتی (حالات) پیدا ھوجائیگی کہ جس کو سنبھالنا بالکل مشکل ھوجائیگا- اس لئے میری عرض ھے کہ جھان تک کہ Safeguards کی عملآوری ھے-ملازمین

(شری گنگاریڈی)

تلنگانا والون کے دلون مین یہ یقین پیدا کرنے کہ ھم سب تمھارے ساتھ ھین آپ اپنا حصہ ھی میں اگر چاھین تو تھوڑا بھت زیادہ بھی لے لو تو ایسا نہین ھوتا-جب ھم نے انکو اپنا بڑا بھائی مانا تو انکو Generous ھونا تھا اگر وہ تھوڑے بھت دلدار ھوتے اور کھتے کہ جو نقصان ھوا اس کی تلافی ھی نہین بلکہ زیادہ لے لو ایسا کرلینے کے بجائے انھون نے معاملہ کو سنگین بنا دیا اور انھون نے یھان تک کیا کہ انھون نے Refugee Camps وغیرہ کھولے اور ان کو ایسے Organise کیا جیسے حکومت ھند نے پاکستان کے Refugees کے لئے کیا تھا-ویسے وارڈ وغیرہ ھین ایسا ھونا کہ مسلہ کی گمبھیرتا معلوم ھو-میں آپ کو یہ بتانا چاھتا ھون کہ ۱۹۵۶ کا معاھدہ تھا ھم اس کی عمل آزادی چاھتے تھے اور کوئی نئی بات نہیں چاھتے تھے پھر آندھرا والوں کو کیا ضرورت تھی کہ وہ Supreme Court, High court کے دروازے کھٹکھٹاتے-

میں سمجھتا ھون کہ یہ ھر ایک کا فرض ھے کہ تلنگانا والون کی جو تکلیف ھے اس کے حل کا طریقہ سوچے لیکن اس مسلہ مین جتنے ھمارے لیڈر ھیں وہ سب کے سب Confused ھین کہ اس کا حل کیسے ھو-لیڈر MLAs-MPs کی رائے مین لئے لئے وچار ھیں میں آپ کو بتانا چاھتا ھون کہ اگر اس کا حل فوری نہ نکالا جائے تو ایسی حالت ھونے

کا مسلہ ہو کہ Surpluses کا کاغذ پر لکھیے سے یا Press statements دینے سے اس کا کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے بلکہ عملی طور پر اقدامات کئے جائیں اب تک کافی عرصہ گذرچکا گورنرایڈریس میں اس بارے میں بتایا گیا اسمبلی میں اس بارے میں اعلان کیا گیا اور کانگریس پارٹی میں اسکا ذکر کے باہر آیا مگر ایسے عملیات سے کچھ ہونے والا نہیں اس کے لئے اب تو Shock treatment کی ضرورت ہے Supluses فوری Release کیئے جائیں چونکہ برسات آنے والی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ۹ کروڑ دئیے گئے ہیں وہ خرچ ہو نہیں پائگا اس کا بیشتر حصہ lapse ہو جائیگا پھر یہ بات کہی جائگی کہ ہمنے پیسہ دیا لیکن آپ خرچ نہیں کرپائے مجھے اس بات کا تجربہ ہے کہ اگر ۹ کروڑ خرچ کرنے ہیں تو کم از کم ۲۵ کروڑ کا کام ہاتھ میں لیں اور رقم بر وقت Release ہو ابتک نہ ہی کام شروع ہوئے نہ ہی رقم Release ہوئی اگر برسات میں رقم Release ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکے گا اور مارچ ختم پر رقم lapse ہو جائگی اور لوگوں میں جو Discontent ہے وہ جوں کہ توں برقرار رہیگی-

میں سمجھتا ہوں کہ سنٹر گورنمینٹ اور Oposition leaders کا فرض ہے کہ وہ سب بیٹھکر اس مسلہ پر غور کریں اور اس کا حل نکالیں ایک دوسرے پر تہمت لگانے یا ذمہ داری عائد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اگر اس کا حل فوری نہ نکالا گیا تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑیگا-

نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤگے اے ہندوستاں والو

تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں]

श्री निहाल सिंह (चन्दौली) : सभापति महोदय, मैं इस मांग का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि दो ढ़ाई साल के अन्दर गृह मन्त्रालय ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। लगातार खराबियों पर खराबियां बढ़ती गई हैं। दो साल के अन्दर विद्यार्थियों की हड़ताल इतनी उच्चतम सीमा पर हुई कि सरकार ने विश्व-विद्यालयों की स्वायत्तता को नष्ट करके वहां पर पुलिस और पी० ए० सी० का अखाड़ा बना दिया। शिक्षकों, गुरुजनों की हड़ताल अपनी रोजी रोटी के लिए इतनी तेज बढ़ी कि दो वर्ष के अन्दर गुरुजन यूनिवर्सिटीज़ में न जाकर जेलों की हवा खाने लगे।

इसके साथ-साथ आश्चर्य की बात है कि हिन्दुस्तान इतना पिछड़ा हुआ देश है जहां पर इन्जीनियर्स के द्वारा तरक्की करने के लिए इतने भू-भाग खाली हैं, उन्नति के करने इतने जरिए हैं, फिर भी इस देश के इन्जीनियर्स इस सर-कार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको तरक्की करने का कोई स्थान नहीं रह गया है, इन्जीनियर्स बेकार होने लगे हैं। इसी के साथ साथ पुलिस के द्वारा भी अपनी रोजी रोटी के लिए प्रदर्शन होने लगे। पुलिस इसलिए प्रदर्शन करती हैं कि उसको भरपेट खाना नहीं मिलता है। भ्रष्टाचार का नाम बहुत लिया जाता है लेकिन भ्रष्टाचार सरकार की तरफ से कराया जाता है। सरकार का रवैया ही ऐसा है जिसके कारण भ्रष्टाचार में इतनी बढ़ोत्तरी हो रही है। जब पुलिस का नौजवान जाड़े की रात्रि में पहरा देता है और उसके बाद जब घर आकर देखता है कि उसके बच्चे खाने के बिना बिलबिला रहे हैं, जाड़े के मौसम में उसके बच्चों के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है

[श्री निहाल सिंह]

तो फिर दीवाल पर लिखी हुई लाइन को, कि घूस लेना पाप है, वह सहन नहीं कर सकता है और घूस लेने के लिए बाध्य हो जाता है। ज्यों-ज्यों इस देश में पुलिस की संख्या बढ़ती गई है त्यों-त्यों इस देश में अपराधों की संख्या बढ़ती गई है। पुलिस की संख्या .....

15 57 hrs.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए]

अपराधों को रोक नहीं सकती है। पुलिस की दशा सुधारने से भ्रष्टाचार मिट सकता है और घूस-खोरी मिट सकती है लेकिन सरकार का ध्यान कभी भी उनकी दशा सुधारने की तरफ नहीं गया बल्कि उनकी बढ़ोत्तरी की तरफ ही गया है। सरकार तो यही चाहती थी कि एक ऐसी पलटन तैयार हो जाये जोकि वक्त बे वक्त सरकार को काम देती रहे लेकिन नतीजा उलटा ही होता रहा। गृह मन्त्री का घर घेरा जाता रहा, पुलिस के प्रदर्शन होते रहे। दो ढ़ाई वर्षों का नतीजा यही रहा।

इसी के साथ-साथ साम्प्रदायिकता का इतना उभाड़ हुआ कि जिसकी कहानी कही नहीं जा सकती है। अभी तक तो हिन्दू मुसलमानों के बीच में ही साम्प्रदायिकता का उभाड़ होता था लेकिन इस चुनाव के दर्मियान हमने देखा कि ऊंची जाति और छोटी जाति के दो वर्ग तैयार हो गये। छोटी जातियां सोचती थीं कि हम संख्या बल में अधिक हैं, हम सरकार पर हावी हों और ऊंची जातियां सोचती थीं कि बुद्धी बल तो हमारे पास है, हम उस पर कब्जा करें। अब ये दो वर्ग खुलकर इस देश में सामने आये हैं। छोटी जाति और बड़ी जाति में कितना संघर्ष हुआ है, इस सम्बन्ध में मैं जहां से जीत कर आया हूं चन्दौली से, जहां से कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष लड़े थे, वहां का मैंने जिक्र भी किया था कि जिन-जिन पोलिंग स्टेशन्स पर हरिजनों को वोट देने नहीं दिया गया, उन्हीं पोलिंग स्टेशन्स पर सबसे अधिक वोट पोल हुए हैं। यह पुलिस की करामात और कांग्रेस अध्यक्ष की करामात थी कि सरकारी नौकरों को मिला जुला कर वोट दिलाये गये और मूवेबिल वोट दिलाये गये, जो एक ही वोट कई स्थानों पर वोट देता था और सरकारी तन्त्र उन से मिला हुआ था। कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो निर्दोष था। निगुरा पोलिंग स्टेशन पर पुलिस ने एक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एजेन्ट को जबरदस्ती पटक दिया और पुलिस के एस० एम० पी० ने उस के नीचे से एक जाली पिस्तौल उठाया और कहा कि यह पिस्तौल इस के हाथ में था, और उस को जेल भेज दिया। इस तरीके से वहां का चुनाव जीता गया है। कारण क्या था? कारण यह था कि वहां जो दूसरा कैंडीडेट था वह हरिजन था और उस का दूसरा नम्बर था। अगर स्वतन्त्र वोट कराया गया होता तो शायद जिस तरह से 1967 के चुनाव में कमलापति जी हारे थे उसी तरह से इस चुनाव में भी हार गये होते। भ्रष्टाचार का यह सब से बड़ा नमूना इस दो वर्ष की सरकार में आया है। गोलियों का तांता इतना तेज चला है कि जिस की गणना नहीं की जा सकती है।

16 hrs.

गवर्नर स्वतन्त्र तो थे ही अब वह स्वच्छन्द भी हो गये। जो भी सरकार अल्पमत में हो, जहां अल्पमत के लोग हैं उन्हीं के पक्ष के नेता को नियुक्त करना और एक ऐसी व्यवस्था बना देना ताकि सरकार चलती रहे इस तरीके का रवैया केन्द्र के इशारे पर चला है। और जहां बहुमत का नेता हो, उस नेता की और उस सरकार की बातों को न मानना और स्वच्छन्द दृष्टि से कार्य करना यही गवर्नरों का काम

हो गया। गवर्नर स्वच्छन्द हो गये हैं, ऐसा मालूम होता है कि गवर्नर अपनी स्वतन्त्रता से नहीं बल्कि किसी केन्द्रीय इशारे पर चल रहे हैं। जब तक केन्द्र का गवर्नरों के साथ और प्रान्तों के साथ इस तरीके का रिश्ता लगा रहेगा तब तक केन्द्र और प्रान्त का रिश्ता ठीक से नहीं निभ सकेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि आज जो केन्द्रीय सरकार कर रही है यह रवैया ठीक नहीं है।

सभापति जी, इस देश में अन्ध विश्वास बढ़ा है। नरबलि की घटनायें इतनी तेज हुई हैं कि लोग यह सोचने लगे हैं कि जो हजारों वर्ष पूर्व कहानियों में सुना जाता था उसी तरीके से नर बलि की घटनायें इस देश में चली हैं। अन्ध विश्वास बढ़ा है। मनुष्य का जीवन कबूतर की तरह हो गया है। इतना ही नहीं एक अमानवीय कार्य भी प्रारम्भ हुआ है। माता के साथ बेटे का यौन सम्बन्ध पुलिस थाने में बैठा कर के और जबरदस्ती माता के ऊपर बेटे को लिटा कर के इस तरह से यौन सम्बन्ध कराया गया है जिस से प्रकृति भी लज्जित हो गई है। यह रवैया आज तक सरकार का रहा है।

सेनाओं का निर्माण इतनी तेजी से बढ़ा है जैसे शंकर को एक बार व्यामोह हो गया था और उन्हों ने भस्मासुर को तलवार दे दी और उस ने अपना प्रथम परीक्षण शंकर पर ही किया था तो शंकर को बचाने के लिए विष्णु भगवान को एक सुन्दरी का रूप धारण कर के आना पड़ा। उसी प्रकार से गृह मन्त्री महोदय ने जो सेनाओं को आशीर्वाद दे दिया है बम्बई में, उस की हालत यह रही है कि अभी तक तो गृह मन्त्री गृह को जलाते थे लेकिन उस सेना ने बम्बई की अट्टालिकाओं को जलाना प्रारम्भ कर दिया है। यदि उस ने अन्तिम परीक्षण गृह मन्त्री पर शुरू कर दिया तो आप बतलाइये कि कौन सी सुन्दरी आयेगी अपना रूप धारण कर के जो गृह मन्त्री को बचायेगी ?

इसी तरह से कर्मचारियों की हड़ताल इतनी तेजी से चली है कि ऐसा लगता था कि कुछ दिन तक इस देश में कोई सरकार ही नहीं रह गयी है, और सरकार विहीन देश हो गया हैं। इस तरह से देश की हालत एकदम खराब हो गई है। साथ ही साथ मन्त्रियों की सेना बढ़ती गई है। मन्त्रियों की सेना कम कर के खर्च घटाया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दिनों दिन मन्त्रियों की सेना बढ़ती जा रही है, और देशी नरेशों की थैलियों को कम कर के भी खर्चा घटाया जा सकता था वह भी काम नहीं किया गया है। इसलिए मैं गृह मन्त्रालय की मांग का विरोध करता हूं।

श्री सीता राम केसरी (कटिहार) : मान्यवर, गृह मंत्रालय की मांग का समर्थन करते हुए मैं भी कुछ अपने सुझाव पेश करना चाहता हूँ। सर्व प्रथम भाषा के सम्बन्ध में जो सेठ गोविन्ददास जी ने कहा और हमारे एक जनसंघ के माननीय शालवाले जी ने जो तर्क दिये हैं उन के उत्तर में ये बातें आप के सामने मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि अंग्रेजी को हटाने के लिए विरोध नहीं है। अंग्रेजों को हटाने में सारे देश में एकता थी और अंग्रेजी भी हटाने में एकता थी। यह ठीक है कि जिस समय अंग्रेज यहां थे हमारे देश में अंग्रेजों को हटाने के लिए एक मत था देश एक मत था और अंग्रेज गये उस समय भाषा का जहां तक प्रश्न है और जो गांधीजी का नाम लेते हैं, लोगों को मैं तो नहीं समझता भाषा का नाम लेकर गांधी जी का नाम लेने की क्या आवश्यकता थी। और जहां तक मुझे याद है अगर कांग्रेस के इतिहास के पन्नों को उलटें तो देखेंगे गांधी जी ने हिन्दी की जगह पर हिन्दुस्तानी चलाने की एक योजना बनाई थी। मगर वह नहीं चली।

दूसरी बात यह है कि आज अंग्रेजी हटाने के लिए मेरे ख्याल में इस देश में वह एकता नहीं है जो अंग्रेजों को हटाने के लिए

[श्री सीताराम केसरी]

इस देश में एकता थी। इसलिए अब देश की एकता कैसे बरकरार हो उस को मद्देनजर रखते हुए हमें भाषा के सम्बन्ध में आन्दोलन चलाना चाहिए या विरोध करना चाहिए।

डी० एम० के० के मित्र ने ठीक ही कहा कि यदि आप भाषा को ले कर आन्दोलन करेंगे तो दक्षिण में, विशेष कर मद्रास, आन्ध्र या मैसूर, जहां पर भी भाषा को ले कर आन्दोलन है, वह आन्दोलन ज्यादा दिन तक नहीं ठहरता यदि हम लोगों ने हिन्दी के सम्बन्ध में उत्तर भारत में आंदोलन नहीं चलाया होता। जैसा मुझे पता है वहां पर सिनेमा जो हिन्दी में होते हैं उसे देखने में वह ज्यादा लोग दिलचस्पी लेते हैं, और हिन्दी का प्रचार जिस ढंग से हो रहा था उस में एक अवरोध आ गया है और अब वह एक राजनैतिक हथकंडा बन गया है। भाषा और उसके आधार पर लोग देखते हैं कि कितनी दूरी तक हम जनता को अपने स्वार्थ अनुसार बना सकते हैं, या ऐक्सप्लायट कर सकते हैं। राष्ट्रीय सरकार ने भाषा के सम्बन्ध में जो नीति अपनायी है उन का मैं समर्थन करता हूं और अपने दोस्तों से कहता हूं कि भाषा को ले कर के जो आज मुल्क में बहुत सारी समस्यायें उठ खड़ी हुई हैं, जो विघटनकारी प्रवृत्तियां पैदा हुई हैं, देश को जो बिखराव की तरफ जा रहा है, देश की अखण्डता पर जो आघात हो रहा है, उन कारणों में भाषा भी एक मुख्य कारण बनती जा रही है। विघटनकारी इसी प्रकार से महाराष्ट्र में शिव सेना है दक्षिण भारत में गोपाल सेना, केराला में लाल सेना इत्यादि जो प्रान्तों में क्षेत्रीय विचारधारा को फैलाती जा रही है। देश को बिखेरती हुई जा रही है उस में अभी तक रुकाव नहीं आया है। इसलिए मैं गृह मन्त्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आज देश में, विशेषकर दो सालों से जो प्रवृत्ति पैदा हो रही है क्षेत्रीय आधार पर प्रदेशों की मांग यह देश की अखण्डता के लिए एक चुनौती है, खतरा है, इस प्रवृत्ति का हमें मनोवैज्ञानिक आधार पर हल निकालना चाहिए और ये जो आंदोलन विभिन्न प्रकार के हो रहे हैं इन को रोकें। और कोइ ऐसी योजना बनायें जिस से जो बिखराव की प्रवृत्ति है, राष्ट्रीय भावना का अभाव है उस में रुकावट हो। नहीं तो मुझे सन्देह है कि देश की अखण्डता, लोकतन्त्र की अखण्डता खतरे में पड़ जायेगी।

दूसरे दिन मैं अखबार पढ़ रहा था कि किस प्रकार देश की अखण्डता के विरोधी सीमाओं पर काम कर रहे हैं। मैंने पढ़ा कि नागालैंड से ले कर लद्दाख तक हिमालय की तराई में हिन्दुस्तान की अखडता पर आघात करने के लिए एक भयंकर योजना बन रही है। दुश्मन देश के लोग इसके सक्रिय हैं उस ओर मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्रालय का ध्यान जाय। हांलाकि उस मे डिफेंस डिपार्टमेंट का ध्यान जाना ही चाहिए क्योंकि उस का काम है। परन्तु जहां तक आप की सीमा सुरक्षा का सवाल है, सीमा सुरक्षा से पुलिस का सम्बन्ध है। जैसे कि नागालैंड और मीजोलैंड में, तो पुलिस का ध्यान जाना चाहिए। यद्यपि आप ने असम का पुनर्गठन किया, एक अच्छी चीज हैं, क्षेत्रीय जो विचार हैं उस को आप ने एक सान्त्वना के रूप में दिया है मगर समूचे देश को मद्देनजर रखते हुए और राष्ट्रीय दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि इस प्रकार की प्रवृत्ति पर अगर रोक नहीं लगाई जायगी, अंकुश नहीं लगाया जायगा तो देश की अखण्डता खतरे में पड़ेगी।

होम मिनिस्टरी ने अपनी बजट मांगों में आदिमजातियों के सुधार और कल्याणार्थ विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया है। जो धनराशि इस के लिए इस मन्त्रालय ने सन् 67–68 के दौरान रक्खी थी वही रकम सन् 68–69 के लिए भी दी है। उसे आप ने बढ़ाया नहीं है। इस के विपरीत हम देखते हैं कि पुलिस के लिए

और गृह मन्त्रालय के लिए आप ने पहले की अपेक्षा काफी रकम बढ़ाई है। मेरा ख्याल है कि पुलिस में जो एक भावना पैदा होनी चाहिए थी जैसी कि यू० के० की पुलिस में है कि देश के तमाम नागरिक को अपने मित्र व बन्धु समझते हैं। यह भावना अपनी पुलिस के अन्दर पैदा नहीं की है। पुलिस में जो कार्यक्षमता आनी चाहिए वह उन में अभी नहीं आई है। मन्त्रालय में एफिशिऐन्सी का अभाव है जिस के कि कारण से वह अराजकता और एनार्की को रोकने में असफल रहा है। आज चारों तरफ जो राज्यों के साथ एक सामजस्य नहीं पैदा हो रहा है, एक तारतम्य नहीं पैदा हो रहा है उस के पीछे भी मैं समझता हूं कि नौकरशाही की इनएफिशिएन्सी का ज्यादा हाथ है।

मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि गवर्नर सैन्ट्रल गवर्नमेंट से आदेश ले कर चलते हैं। मैं समझता हूं कि मेरे वह दोस्त अपना इस तरीके का प्रचार करके जो सारी वह खुद गलतियां राज्यों में करते हैं और जो उन की कमजोरियां रहती हैं यह कह कर केन्द्रीय सरकार पर दोष मढ़ना चाहते हैं। यह बात कह कर गवर्नर सैन्ट्रल गवर्नमेंट से आदेश लेकर चलते हैं वह केन्द्रीय सरकार पर सारा लांछन लाना चाहते हैं और यह आरोप लगाना चाहते है कि गवर्नर के द्वारा आप अमुक प्रदेश की गैर कांग्रेसी सरकार को गिरा रहे हैं जब कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं कि जब महामाया की सरकार बनी थी उस समय कांग्रेस की वहां पर साफ मेजारिटी थी और वहां भी महेश प्रसाद सिंह ने 162 आदमियों के नाम लिए थे मगर उस समय वहां के गवर्नर ने कांग्रेस के पक्ष में समर्थन न देकर भी महामाया प्रसाद की सरकार के निर्माण कराने में सहयोग दिया था। हम कांग्रेस वाले हैं और चूंकि कांग्रेस सत्ता में है इसलिए हम शिकायत नहीं करते हैं। लेकिन यह विरोधी दल वालों की एक टैकनिक होती है, प्रचार करने के लिए, और यह उन की साजिश होती है जिसको कि आप को समझना चाहिए और उस का मुकाबला करने के लिए आपके पास कोई माकूल योजना होनी चाहिए ताकि जो इस तरह का गलत और भ्रामक प्रचार करते हैं वह उस का नाजायज फायदा न उठा सकें।

अब यह दुर्गापुरा स्टील प्लांट में घटी घटना को ही ले लीजिए। यह ठीक है कि ला ऐन्ड आर्डर राज्य का विषय है और सी० आर० पी० को साधारण तौर पर सीधे वहां पर दखल नहीं देना चाहिए था लेकिन वह जो उन्होंने वहां दखल दिया तो उसके विशेष कारण और विशेष परिस्थितियां भी हो सकती हैं जिसके लिए कि वह बाध्य हो गए थे। लेकिन मेरे उधर के मित्रों ने जनता में यह प्रचार किया कि केन्द्र के लोग और केन्द्रीय सरकार ने इस तरीके से अपनी इस सी० आर० पी० के द्वारा जनता की भावना पर आघात किया है तो मेरा कहना है कि इस तरह के प्रचार का भी आप को मुकाबला करने के लिए कारगर योजना बनानी चाहिए।

इस के अलावा एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि विरोधी दल वालों के द्वारा जो सरकारी कर्मचारियों में एक सरकार के प्रति असन्तोष फैलाया जाता है, विभिन्न दल वाले उन में प्रवेश कर सरकार के प्रति और इस लोकतन्त्र के प्रति जो लाएल्टी है उस को वह तोड़ रहे हैं, उस पर जो आघात कर रहे हैं तो इस ओर भी सरकार को गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि एक मनोवैज्ञानिक ढंग पर जो उन की डिमाण्ड्स है, जो भी उन की जायज मांगें सरकार के पास आई हुई हैं उन की पूर्ति करके सरकारी कर्मचारियों में सरकार के प्रति जो एक असन्तोष की भावना पैदा की जा रही है उस का अन्त कीजिए।

[श्री सीताराम केसरी]

सरकारी कर्मचारियों द्वारा 19 सितम्बर, 1968 को की गई स्ट्राइक आखिर किस बात का संकेत थी ? दरअसल वह आप की सत्ता को उलटने का संकेत था, लोकतांत्रिक सरकार को उलटने का एक संकेत था। गृह मन्त्रालय का ध्यान मैं उस ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि आप यह मत सोचियेगा कि एक सामाजिक आधार पर एक मांग के आधार पर वह एक आन्दोलन था। दरअसल वह उन लोगों की एक ताकत की आजमाईश थी। यह उन का एक अन्दरूनी फैसला था कि सरकार को परोलाइज़ कर दो। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि सरकारी कर्मचारियों की जो नीड बेस्ट वैजेज़ की डिमांड थी जो कि मेरी समझ में एक परिवार के भरण-पोषण के लिए आवश्यक होती है वह मांग यदि आप पूरी कर देंगे तो मैं समझता हूं कि वह असन्तोष का कारण ही नहीं रहेगा। जब वह असन्तोष रूपी बीज ही नहीं रह जायेगा तब उधर के मेरे मित्र कैसे उनको इन्स्टीगेट कर सकते हैं अथवा बहका सकते है।

हमारे देश में साम्प्रदायिक भावना के आधार पर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी आप ने मुल्क में देखा कि इधर कुछ दिनों से विशेष कर हमारे देश मे जो एक साम्प्रदायिक भावना को उभारा जाता है और उसके आधार पर उस में भी आप पायेंगे कि एक विघटन करने की प्रवृत्ति और आप पर आघात करने की प्रवृत्ति किस तरीके से पैदा की जाती है। हमारे जो अल्पसंख्यक भाई है उनके दिमाग में यह बैठाया जाता है कि बहुसंख्यक जाति वाले तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते हैं, वह आतताई हैं और तुम्हारी जो मांग है उस की वह पूर्ति नहीं करते हैं। इस तरह की जो एक भावना अल्पसंख्यक लोगों में भर गई हैं उस का भी उन्मूलन कीजिए। उन के दिमाग से यह बात निकालिए। सद्भावना का प्रचार किजीये नहीं तो मैं आप से कहता हूं कि जिस तरीके से केरल में साम्प्रदायिक आधार पर दो जिलों का निर्माण हुआ एक बार पुनः इस देश की अखडता खतरे में पड़ जाएगी। इस देश में यह मांग हो सकती है कि आप साम्प्रदायिक आधार पर एक अलग प्रान्त का निर्माण करें। उस के लिए एक वार्निंग है और इस लिए मैं आप से कहूंगा कि इस ओर आप का ध्यान जाना चाहिए और जो अल्पसंख्यक लोगों की जायज मांग है नौकरी में असेम्बली में, पार्लियामेंट में उन की मांगों की पूर्ति की जाय। उन को आप प्रतिनिधित्व दीजिए तभी आप का यह लोकतन्त्र व जनतन्त्र जिन्दा रह सकता है नहीं तो मैं तभी आप से कहता हूं कि यह आपका जनतन्त्र खतरे में पड़ जायेगा।

जहां तक आदिम जातियों के सुधार की बात है उसके बारे में कहना यह है कि आदिम जातियों के लिए अपनी डिमांड में आप ने उतनी ही रकम दी है जितनी कि सन् 67–68 में दी थी। इसलिए मैं कहूँगा कि आदिम जातियों के सुधार के लिए, उन के मकान अच्छे हों, उन के बच्चों की पढ़ाई का पूरा इन्तजाम हो, उन की गरीबी का स्तर घटे और वह एक अच्छे और खुशहाल जीवन की ओर प्रगति कर सकें मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आदिवासी जातियों के लिए, हरिजनों के लिए जो आप के यहां प्राविज़न है उस में खास तौर से आदिम जातियों की प्रगति के हेतु आप ज्यादा रकम बढ़ाइये वरना आप याद रखिये कि जो हरिजन या गिरिजन हैं और जिनके कि संरक्षण का भार आप के मन्त्रालय के अन्तर्गत आता हैं उस पर आप ने उचित ध्यान नहीं दिया, नागालैंड से लेकर लद्दाख तक जो हमारी सीमा हैं और वहां के जो गिरिजन और आदिवासी हैं, अगर उन की जायज मांग की, उन के रहन-सहन की पूर्ति के लिए, उन के भोजन, पढ़ाई और शिक्षा आदि के हेतु अगर आप उचित प्रबन्ध नहीं कर सकेंगे तो मैं आप को चेतावनी

देना चाहता हूँ कि सीमा पर एक गम्भीर खतरा पैदा होगा तो उस का भी आप मुकाबला नहीं कर सकेंगे ।

गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत जो द्वीप है जैसे कि अण्डेमान द्वीप है तो उस के लिए मैं गृह मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि चूंकि वह आजादी की लड़ाई में राजनैतिक लोगों का एक ऐसाइलम था इस लिए उसका सुन्दर नाम रखिए और इलाके का बढ़िया प्रबन्ध कीजिये । उस इलाके की बहुत थोड़ी बढ़ोतरी की गई है । मैं चाहता हूँ कि उस इलाके की तरक्की के लिए अधिक से अधिक प्रयास किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव) : सभापति महोदय, मुझे इस मौके पर वह कहावत याद आ रही है कि चिराग तले अंधेरा । सब से पहले तो मैं होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो पुलिस कमीशन ने रिपोर्ट की थी उस पर हरियाणा और पंजाब जैसी छोटी स्टेटों में तो अमल किया गया लेकिन यह अमल नहीं करते है । मुझे यकीन है कि इस की तरफ उन का ध्यान जरूर जायगा ।

यह बात सच है कि दिल्ली पुलिस ने यूनियन बनाने का हक लेने के वास्ते जद्दोजहद की थी । उस पर कुछ न कुछ गुस्सा आया सरकार को और काफी ले दे हुई, काफी उन को सजाएं भी मिली बाद में लेकिन मुझे मालूम यह पड़ता है कि अभी भी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने गुस्सा ठंडा नहीं किया है । उन्हें अब अपना गुस्सा ठंडा करना चाहिए ।

दूसरी एक छोटी सी बात जिस पर मैं चाहता हूँ कि वह गौर करें वह यह है कि यहां दिल्ली पुलिस के कुछ हिस्से हमारी पार्लियामैंट में भी खिदमत करते हैं । जो ओवर टाइम मिलता है वह उन्हें नहीं मिलता । मैं समझता हूँ कि इस से यकीनन अन्याय होता है । जब घर में ही अन्याय हो तब बाहर कैसे तवक्को की जाये ?

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : एम पीज को भी ओवर-टाइम मिलना चाहिये । वह भी आठ आठ घण्टे यहां बैठते हैं ।

श्री अब्दुल गनी डार : आप में और उन में फर्क है । आप इस वक्त जनता के सेवादार के रंग में है और वह और रंग में है । हमारे लिये और रास्ते खुले हुए हैं । अगर हमारे एम पी भाई सेशन्स कोर्ट में भी जायेंगे तो लोग उन को हजारों रुपये फीस खुशी खुशी देंगे । मगर उन बेचारों के लिए कोई और रास्ता खुला हुआ नहीं है ।

मैं जबान के बारे में यह अर्ज करूंगा कि यह बात सच है कि वह देश देश नहीं जिसमें कोई जबान नहीं । आखिर देश की कोई न कोई जबान तो होती ही है । जब यह मसला पहले पेश हुआ था तब कहते हैं कि वहां एक वोट से हिन्दी पास हो गई और फैसला हो गया । बापू ने कहा था कि हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी । लेकिन कोई बापू की सुनता नहीं । कल मैं ने हाउस में भी कहा था कि ब्राह्मण एक हिन्दू है और दूसरा मुसलमान है तो वह दो कौम तो नहीं है । मैं भी ब्राह्मण हूँ और शुक्ल भी ब्राह्मण हैं, लेकिन दोनों एक कौम हैं । हमारे बाप दादे हिन्दू थे, लेकिन गांधीजी की कुर्बानी हुई थी । गांधी जी ने कहा था कि मैजारिटी जो है, अक्सरियत जो है उस की जबान मुश्तरका जबान है, और वह हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी ही हो सकती है । जब कोई भाई हिन्दी के हक में बड़े जोर से बोलते हैं तो मैं यकीनन उनकी बात की तारीफ करता हूँ क्योंकि उन को हक हासिल है उसका । वह देश देश नहीं जिस की कोई जबान न हो । लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि केल्टिक की जगह अंग्रेजी को आते आते 700 बरस लग गये । श्री चव्हाण बड़े बाहिम्मत हैं, वह बड़े बाप के बेटे हैं और कांग्रेस सरकार में बड़ा असर रखते हैं । वह अगर लगा सकें, या श्री बाजपेयी उन की जगह बैठ जाये और वह मोर्चा लगा सकें

[श्री अब्दुल गनी डार]

और तीन दिन में हिन्दी को लागू कर दें सारे देश में तो मैं समझता हूँ कि ऐसा चमत्कार न भगवान राम ने किया होगा न किसी ऋषि मुनि ने भी किया होगा और न किसी पैगम्बर ने किया होगा। शायद भगवान ने भी नहीं किया होगा। कहते हैं कि भगवान ने भी दुनिया बनाते बनाते सात दिन लगा दिये। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग हिन्दी को चाहते हैं उन को एक बात नहीं भूलनी चाहिये कि साउथ में हिन्दी आते आते आयेगी, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। इस वक्त भी साउथ में उर्दू के अखबार ज्यादा निकलते है, यानी फारसी रस्मुल-खत में ज्यादा निकलते है बमुकाबले देवनागरी रस्मुल खत के। यही हाल बाकी स्टेट्स में भी है। पंजाब में पंजाबी सरकार की जबान है, हरियाणा में हिन्दी जबान है, लेकिन जो अखबार निकलते है रोजाना वह अंग्रेजी के बाद सब से ज्यादा उर्दू में निकलते हैं।

होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जब तुम कहते हो कि उर्दू के साथ अन्याय किया जाता है तब उस का असर होता है और सारी दुनिया में यह बात फैलती है। मुसलमानों की एक बड़ी कमजोरी यह है कि उनका जितना भी मजहबी लिट्रेचर है वह तमाम उर्दू जबान में है। उनको धीरे धीरे देवनागरी में बदला जायेगा। हम लोग इस बात के हामी हैं कि उस को हिन्दी रस्मुल-खत में आहिस्ता आहिस्ता लिखा जाये। लेकिन यह काम एक दिन में तो नहीं हो सकता। जैसा में ने कहा, अगर श्री चव्हाण एक दिन में हिन्दी को लागू कर दें तो वह एक ऐसा चमत्कार होगा जैसा भगवान राम ने भी नहीं किया है। अगर मैं भी चाहूं कि ऐसा चमत्कार कर दूं कि मुसलमानों का तमाम लिट्रेचर एक दिन में हिन्दी में कर दूं, तो यह नामुमकिन है। जैसा मैंने तामिलनाडु के बारे में कहा था, अंडमन के बारे में भी और सारे हिन्दुस्तान के बारे में दुनिया वाले शिकायत करते हैं। हाल में ही मैं हज को गया था। वहां से मैंने रिपोर्ट भेजी है कि वहां पर गलतफहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को दीन से बेबहरा करने के लिए जान बूझ कर उर्दू के साथ अन्याय किया जाता है, उन को डिस्करेज किया जाता है।

एक माननीय सदस्य : उर्दू हमारी जबान है।

श्री अब्दुल गनी डार : यकीनन उर्दू आप की जबान है। जैसा मैंने कल अर्ज किया था कि यहां 7 करोड़ मुसलमान हैं या 5 करोड़ मुसलमान हैं, इस से मुझे बहस नहीं। अदद के बारे में मेरा कोई झगड़ा नहीं है क्योंकि सेन्सस जो होता है उस के मुताबिक 1961 में तकरीबन 5 करोड़ की उन की तादाद थी। लेकिन अगर सब को कत्ल कर दिया जाये तो यह मुझे कबूल है मगर हम अपने देश को छोड़ कर चले जायें, यह मुझे कबूल नहीं है क्योंकि हमने इस देश के लिये बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इस देश को बनाने के लिये .....

एक माननीय सदस्य : कत्ल कौन करता है ?

श्री अब्दुल गनी डार : बूटा सिंह जी, आप तो खुद मदद करने गये थे मेरठ में, आप ने मदद की कलकत्ते में, आप ने मदद की कई जगह गुरुद्वारों में, अपने मकानों में। मैं इस बहस में नहीं पड़ता। मैं होम मिनिस्टर साहब की रिपोर्ट को सामने रखता हूं, और किसी चीज से मुझे बहस नहीं है। वह फरमाते हैं कि 1966 में 133 कम्यूनल झगड़े हुए, 1967 में 209 हुए और 1968 में 331 हुए। इस के माने क्या यह हुये कि यहां फसादात रुक नहीं सकते ? अगर रुक नहीं सकते तो इस का कोई न कोई प्रबन्ध करना ही होगा क्योंकि कभी भी आप कोई बात एक दिन के लिए कर सकते

हैं, हमेशा के लिए करना चाहें तो यह नामुमकिन है। मैंने श्री राजगोपालाचार्य को लिखा, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि वहां तो श्री चव्हाण की हुकूमत नहीं है, न कांग्रेस वालों की हैं। वहां पर 1 या सवा फीसदी मुसलमान हैं। कटक में तकरीबन 24 फीसदी मुसलमान हैं जो बीड़ी बनाते हैं। उन के ऊपर कुछ हल्ला हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन उस के बाद उनका बायकाट कर दिया जाये तो एक फीसदी मुसलमान कहां जायेंगे, उन के लिये समाज में कहां जगह रह जाती है। कहते हैं कि एक बड़ा बम फटा था। यकीनन फटा होगा क्योंकि तीन लोग मर गये, पांच जख्मी हो गये। मैंने प्राइवेट तौर पर इस के बारे में बातें की। मैं कहना चाहता हूँ कि वहां की हालत सुधरनी चाहिये क्योंकि उड़ीसा में जन संघ नहीं है। हमारे होम मिनिस्टर ने जो और नाम दिये हैं कि किन स्टेटों में झगड़े हुए है, उन में असम का नाम है, मैसूर का नाम है, उस में उड़ीसा का नाम हैं, उस में आन्ध्र महाराष्ट्र का नाम भी है। बहरहाल इस बात को मैं छोड़ता हूँ। यह वह जगह है जहां पर जन संघ का कोई जोर नहीं, कोई उन को रिप्रेजेन्टेशन नहीं, उन का कोई आर्गेनाइजेशन नहीं। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं कि जन संघ वाले अमृतसर से उठे या मध्य प्रदेश से उठे, उत्तर प्रदेश से उठे, और वहां जाकर हल्ला गुल्ला करे। इसे मेरा दिमाग मानता नहीं, क्योंकि अब भी मैं अपनी सरकार को ऐसा सरकार नहीं मानता जैसे कि बहादुरशाह की थी जो कि लाल किले के अन्दर रह जाये और शाहंशाह हिन्द कहलाये।

आप को सोचना चाहिये कि यह सब क्यों होता है। कहते हैं कि चूंकि अच्छा सलूक नहीं करते थे इसलिए नई स्टेट फलां जगह बन गई। कल यकीनन बारी आयेगी उत्तर प्रदेश की। उस में लोग कहेंगे कि पहाड़ी इलाका जो है उन के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ, जो मशरिक के रहने वाले हैं वह कहेंगे कि आगरा डिवीजन और मेरठ डिवीजन बहुत अच्छे हैं, उन के साथ अच्छा सलूक है, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं होता। इस तरह से कब तक आप मुल्क के टुकड़े करते चले जायेंगे। मैं इस बात पर बधाई नहीं दे सकता। जहां श्री चव्हाण में बाकी खूबियां हैं और उन की मैं जितनी भी तारीफ करूं, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि डिसिप्लन में कई बातें अच्छी आती हैं, लेकिन इस बात को अच्छा नहीं कहा जा सकता, यह अलग बात है।

अभी मेरे भाई श्री शाल वाले ने एक बात कही। इस का जवाब तो होम मिनिस्टर ही देंगे, मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं जानता नहीं अपनी बहन के बारे में। ब्राह्मणों की आबादी छः परसेंट होगी। लेकिन काश्मीर के सैक्रेटेरिएट में या सैंट्रल गवर्नमैंट में, पार्लिमैंट में या और दूसरे जो सरकारी दफ्तर है वहां आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जो 94 परसेंट हैं वे तो नौकरियों में 6 परसेंट है और जो 6 परसेंट हैं वे नौकरियों में 94 परसेंट हैं। इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये।

करप्शन का भी बहुत जिक्र होता है। मैंने डाकुमैंट्स पेश किये है कि किस तरह से बैंकों के जरिये बेईमानी होती है। जब मैं इसके बारे में होम मिनिस्टर को लिखता हूं तो वह कह देते है कि इसकी इबतदाई जिम्मेदारी तो फाइनेंस मिनिस्टरी पर है। वह कहेंगी तो मुकदमा चलेगा। यह चीज मैंने 1955 में आपके नोटिस में लाई थी और आज 1969 है। डालमियां ग्रुप, शान्ति प्रसाद जैन ग्रुप है, साहू जैन ग्रुप के मामले थे और विवियन बोस की रिपोर्ट भी उनके बारे में आई थी। मैंने भी दो डाकुमैंट्स छपवाये थे, आई ओपनर नम्बर 1 और आइ ओपनर नम्बर 2 लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैंने 28 अगस्त को श्रीमती इन्दिरा गांधी को लिखा था। मैंने इसको डेढ़ बरस तक सीने में छिपाये रखा। इसकी वजह यह थी कि मैं चीप पापुलैरिटी का हामी नहीं। मैं नहीं चाहता कि किसी को ब्लैकमेल किया जाए।

[श्री अब्दुल गनी डार]

मैंने चैकों का नम्बर दिया था और बताया था कि किस पार्टी ने जारी किये, किस कांग्रेस के नेता के नाम जारी किये और किस ब्रांच से उस कांग्रेस के नेता ने चैकों को वसूल किया। मेरी बहन ने लिखा कि मैं भी इस बारे में कंसर्न्ड हूं और मैं चाहती हूं कि किसी तरह से इस कुरप्शन को कम किया जाए। मैं हैरान हूं कि वही तारीख फिर दोहराई गई। मेरे पास चैकों के नम्बर हैं, किस पार्टी ने जारी किये उसके नाम है, जिस पार्टी ने वसूल किए, उसके नाम हैं। तीस जनवरी को जिस दिन बापू को शहीद किया गया था उस दिन वे चैक जारी हुए और कांग्रेसी नेताओं ने वसूल किये।

हमारे होम मिनिस्टर बहुत दूर अंदेश हैं। क्या वे छोटी छोटी बातों को रोक नहीं सकते हैं। अगर नहीं रोक सकते तो क्या नतीजा होने वाला है? आप जरा पाकिस्तान की तरफ देखें वहां क्या हुआ है। अयूब ने अपने जमाने में पाकिस्तान की बडी खिदमत की या ताकत दिखाई। लेकिन वह भी आखिर को मजबूर हो गया। आप भी क्या अपनी ताकत एक सिपाही के खिलाफ दिखायेंगे जो कि दो रुपये रिश्वत लेता हैं और पकडा जाता है और अखबारों में उसकी चर्चा होनी शुरू हो जाती है? लेकिन जब एक वजीर घर में बैठा हुआ अब्दुल गनी को तीस लाख रुपया दे दे या अब्दुल गनी से नौ लाख ले ले तो क्या वह कुरप्शन नहीं है? आप देखें कि पावर लूम्ज को खरीदने का हुक्म दिया गया था। पुरानी पावर लूम्ज जो थी जिन को रद्द करके नये सिर से बदला गया था, उनके लिए हुकम दिया गया कि एस. टी. सी. उनको खरीदे। लेकिन कानपुर की जो चार सौ थी उनके बारे में हुकम दिया गया कि वे प्राइवेट पार्टी की हैं उनको न लिया जाए। इस वास्ते कि उनको अब्दुल गनी ने पहले मैनेज कर लिया था, तीन सौ पावर लूम्ज ले ली उसने, उनको दस दस हजार में बेच दिया और दस लाख एक ही सौदे में पैदा कर लिया तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। इस तरह की मैं दसियों मिसालें दे सकता हूं। कामर्स मिनिस्टरी में इस तरह से करोड़ों रुपये का जोडतोड़ हुआ है। क्या इस तरह से काम चलेगा?

मैं चाहता हूं कि देश को बनाया जाए। जुबान का मामला हल हो, कम्युनल झगड़े बन्द हों, कुरप्शन खत्म हो। पाकिस्तान का असर आप देख रहें हैं। मुझे डर है मुझ जैसे अन्धे जो हैं ये तो कत्ल हो जायेंगे लेकिन ये बच जायेंगे। इनके आगे पीछे, दायें बायें, रिवाल्वर लिये पुलिस रहती है। कुरप्शन जो बढ़ रही है इस को आप चैक करें। मैं कह चुका हूं कि मैं चीप पौपुलैरिटी का हामी नहीं हूं। मेरे पास फैक्ट्स एण्ड फिगर्ज हैं। तारीखें हैं, नाम मैं दे सकता हूं। मैंने श्रीमती गांधी को दिये भी हैं। मैं डेढ़ बरस तक सीने में इसको छिपाये रखा है। अब मैं तंग आ गया हूं आप कोई काम नहीं करते हैं। क्या साहू जैन ग्रुप इतना मजबूत ग्रुप हो गया है कि उसने जनरल असगर को भी मात दे दी है, क्या अयूब से भी वह मजबूत है कि आपका उस पर हाथ ही नहीं पड़ता है। क्या इसलिए आप उस पर हाथ नहीं डालते कि वह आपको लाखों रुपये देता है इलैक्शन लड़ने के लिए? आप देखें कि सी बी गुप्त के लिए शराब के जो कारखाने हैं उन्होंने ढोल खोल कर रख दिये थे और कहा था कि बोतलों में देने की कोई जरूरत नहीं है, इन ढोलों में से शराब पिलाओ। मोहन कूरी ने लाखों रुपये खर्च किये और आगे पता नहीं कितना खर्च करने जा रही हैं।

मैं आपकी खिदमत में आखिर में यही कहना चाहता हूं कि एक एक मुसलमान इस वक्त कहता है :—

किस तरह से सताते हैं ये बुत हमें निजाम
हम ऐसे हैं कि जैसे किसी का खुदा न हो।

मैं कहूंगा कि मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिये ।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y B CHAVAN) : I would like to say, Sir, that the hon Member is making wild allegations against a person of the status of the Chief Minister of U P without any proof and I do not think such allegations should be made These are very mischievous and irresponsible allegations

श्री ग्रब्दुल गनी डार : मैंने होम मिनिस्टर को भी लिखा था । उस में से ही मैंने यह सब कहा है । मैंने यह खत बहन इन्दिरा को भी लिखा था । मैंने नाम किसी के नहीं लिये हैं । लेकिन में जरूर कहता हूं कि डालमिया जैन ग्रुप है ग्रौर पंजाब नैशनल बैंक है जिन्होंने लाखों रुपये के चैंक दिये हैं ग्रौर लाखों रुपये के चैंक आपने वसूल किये हैं । जिस ब्रांच ने दिये ग्रौर जिस लीडर ने वसूल किये उसके नाम ग्रौर एड्रेस मैं दे सकता हूं । मैं इनको मेज पर रख सकता हूं । मैं चाहता हूं कि ग्राप मुझे ऐसा करने की इजाज़त दें ।

[شری عبدالغنی ڈار (گڑگاؤں) سبھاپتی مہودے-مجھے اس موقعہ پر وہ کہاوت یاد آرہی ہے کہ چراغ تلے اندھیرا-سب سے پہلے تو میں ہوم منسٹر صاحب سے گذارش کرنا چاہونگا کہ جو پولس کمیشن نے رپورٹ کی تھی اس پر ہریانا اور پنجاب جیسی چھوٹی اسٹیٹوں میں تو عمل کیا گیا لیکن یہ عمل نہیں کرتے ہیں-مجھے یقین ہے کہ اس طرف ان کا دھیان ضرور جائیگا-

یہ بات سچ ہے کہ دلی پولس نے یونین بنانے کا حق لینے کے واسطے جدوجہد کی تھی-اس پر کچھ نہ کچھ غصہ آیا سرکار کو اور کافی لے دے ہوئی کافی ان کو سزائیں بھی ملیں بعد میں لیکن مجھے معلوم یہ پڑتا ہے کہ ابھی بھی ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے غصہ ٹھنڈا نہیں کیا ہے-انہیں اب اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہئیے-

دوسری آپ ایک چھوٹی سی بات جس پر میں چاہتا ہوں کہ وہ غور کریں وہ یہ ہے کہ یہاں دلی پولس کے کچھ حصے ہماری پارلیامینٹ میں بھی خدمت کرتے ہیں-جو اور ٹائم ملتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یقیناً انیائے ہوتا ہے-جب گھر میں ہی انیائے ہو تب باہر کیسے توقع کی جائے-

شری رنویرسنگھ (روہتک) ایمپلائز کو بھی اور ٹائم ملنا چاہئیے-وہ بھی آٹھ آٹھ گھنٹے یہاں بیٹھتے ہیں-

شری عبدالغنی ڈار-آپ میں اور ان میں فرق ہے-آپ اس وقت جنتا کے سیوادار کے رنگ میں ہیں اور وہ اور رنگ میں ہیں-ہمارے لئے اور راستے کھلے ہوئے ہیں-اگر ہمارے ایمپلائی بھائی سیشنس کورٹ میں بھی جائینگے تو لوگ ان کو ہزاروں روپیے فیس خوشی خوشی دے دیں گے-مگر ان بیچاروں کے لئے کوئی اور راستہ کھلا ہوا نہیں ہے-

میں یہاں کے بارے میں عرض کروں گا کہ یہ بات سچ ہے کہ وہ دیش دیش نہیں جس کی کوئی زبان نہیں-آخر دیش کی کوئی نہ کوئی زبان تو ہوتی ہی ہے-جب یہ مسئلہ پیش ہوا تھا

(شری عبدالغنی ڈار)

تب کہتے ہیں وہاں ایک ووٹ سے ہندی پاس ہوگئی اور فیصلہ ہوگیا- باپو نے کہا تھا کہ ہندی اتھوا ہندوستانی لیکن کوئی باپو کی سنتا نہیں-کل میں نے ہاؤس میں بھی کہا تھا کہ براہمن ایک ہندو ہے اور دوسرا مسلمان ہے تو وہ دو قوم تو نہیں ہیں-میں بھی براہمن ہوں اور شری شکل بھی براہمن ہیں-لیکن دونوں ایک قوم ہیں-ہمارے باپ دادے ہندو تھے-لیکن گاندھی جی کی قربانی ہوئی تھی-گاندھی جی نے کہا تھا کہ مجارٹی جو ہے- اکثریت جو ہے اس کی زبان مشترکہ زبان ہے- اور وہ ہندی اتھوا ہندوستانی ہی ہو سکتی ہے-جب کوئی بھائی ہندی کے حق میں بڑے زور سے بولتے ہیں تو میں یقینا ان کی تعریف کرتا ہوں کیونکہ ان کو حق حاصل ہے اس کا-وہ دیش دیش نہیں جس کی کوئی زبان نہ ہو-لیکن اس بات سے انکار نہیں کہا جا سکتا کہ کینٹک کی جگہ انگریزی کو آتے آتے ۷۰۰ برس لگ گئے- شری چوہان بڑے باہمت ہیں-وہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور کانگریس سرکار میں بڑا اثر رکھتے ہیں-وہ اگر مورچا لگا سکیں-یا شری واجپئی ان کی جگہ بیٹھ جائیں اور وہ مورچا لگا سکیں اور تین دن میں ہندی کو لاگو کر دیے سارے دیش میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا چمتکار نہ بھگوان رام نے کیا ہوگا نہ کسی رشی منی نے کیا ہوگا اور نہ کسی پیغمبر نے کیا ہوگا-شائد بھگوان نے بھی نہیں کیا ہوگا-کہتے ہیں کہ بھگوان نے بھی دنیا بناتے بناتے سات دن لگا دئے-میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہندی کو چاہتے ہیں ان کو ایک بات نہیں بھولنی چاہئے کہ ساؤتھ میں ہندی آتے آتے آئی گئی-یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے-اس وقت بھی ساؤتھ میں اردو کے اخبار زیادہ نکلتے ہیں-یعنی فارسی رسم الخط میں زیادہ نکلتے ہیں بمقابلے دیوناگری رسم الخط کے- یہی حال باقی اسٹیٹس میں بھی ہے-پنجاب میں پنجابی سرکار کی زبان ہے-ہریانہ میں ہندی زبان ہے لیکن جو اخبار نکلتے ہیں روزانہ وہ انگریزی کے بعد سب سے زیادہ اردو میں نکلتے ہیں-

ہوم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو کہ اردو کے ساتھ انیائے کیا جاتا ہے تب اس کا اثر ہوتا ہے اور ساری دنیا میں یہ بات پھیلتی ہے- مسلمانوں کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان کا جتنا بھی مذہبی لٹریچر ہے وہ تمام کا تمام اردو زبان میں ہے- اس کو دھیرے دھیرے دیوناگری میں بدلا جائے گا-ہم لوگ اس بات کے حامی ہیں کہ اس کو ہندی رسم الخط میں آہستہ آہستہ لکھا جائے-لیکن یہ کام ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا-جیسا میں نے کہا- اگر شری چوہان ایک دن میں ہندی کو لاگو کردیں تو وہ ایک ایسا چمتکار ہوگا جیسا بھگوان رام نے بھی نہیں کیا ہے-اگر میں بھی چاہوں کہ ایسا چمتکار کر دوں کہ مسلمانوں کا

تمام لٹریچر ایک دن میں ہندی میں کر دوں۔تو یہ ناممکن ہے۔جیسا میں نے تاملناڈ کے بارے میں کہا تھا۔انڈمن کے بارے میں بھی اور سارے ہندوستان کے بارے میں دنیا والے شکایت کرتے ہیں۔

حال میں ہی میں حج کو گیا تھا۔ وہاں سے میں نے رپورٹ بھیجی ہے کہ وہاں پر غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو دین سے بے بہرہ کرنے کے لئے جان بوجھ کر اردو کے ساتھ انیائے کیا جاتا ہے۔ان کو ڈسکوریج کیا جاتا ہے۔

ایک مانیہ سدسیہ۔اردو ہماری زبان ہے۔

شری عبدالغنی ڈار۔یقیناً اردو آپ کی زبان ہے۔جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہاں ۷ کروڑ مسلمان ہیں یا ۵ کروڑ مسلمان ہیں۔اس سے مجھے بحث نہیں۔عدد کے بارے میں میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے کیونکہ سینسس جو ہوتا ہے اس کے مطابق ۱۹۶۱ میں تقریباً ۵ کروڑ کی ان کی تعداد تھی۔ لیکن اگر سب کے سب کو قتل کر دیا جائے تو یہ مجھے قبول ہے کیونکہ ہم نے اس دیش کے لئے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔اس دیش کو بنانے کے لئے...

ایک مانیہ سدسیہ۔قتل کون کرتا ہے۔

شری عبدالغنی ڈار۔بوٹا سنگھ جی۔ آپ تو خود مدد کرتے گئے تھے میرٹھ میں آپ نے مدد کی کلکتے میں آپ نے مدد کی کئی جگہ گرودواروں میں— اپنے مکانوں میں۔میں اس بحث میں نہیں پڑتا۔میں ہوم منسٹر صاحب کی رپورٹ کو سامنے رکھتا ہوں۔اور کسی چیز سے مجھے بحث نہیں ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ ۱۹۶۶ میں ۱۳۳ کمیونل جھگڑے ہوئے۔۱۹۶۷ میں ۲۰۹ ہوئے اور ۱۹۶۸ میں ۳۳۱ ہوئے۔اس کے معنی کیا یہ ہوئے کہ یہاں فسادات رک نہیں سکتے۔اگر رک نہیں سکتے تو اس کا کوئی نہ کوئی پربندھ کرنا ہی ہوگا۔ کیونکہ کبھی بھی آپ کوئی بات ایک دن کے لئے کر سکتے ہیں۔ہمیشہ کے لئے کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔میں نے شری راجگوپال آچاریہ کو لکھا۔لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہاں تو شری چوہان کی حکومت نہیں ہے۔ نہ کانگریس والوں کی ہے۔وہاں پر آیا سوا فی صدی مسلمان ہیں۔کٹک میں تقریباً ۲۹ فی صدی مسلمان ہیں جو بیڑی بناتے ہیں۔ان کے اوپر کچھ حملہ ہوا۔میں مانتا ہوں۔لیکن اس کے بعد ان کا بائکاٹ کر دیا جائے تو ایک فیصدی مسلمان کہاں جائیں گے۔ان کے لئے سماج میں کہاں جگہ رہ جاتی ہے۔کہتے ہیں کہ ایک بڑا بم پھٹا تھا۔یقیناً پھٹا ہوگا کیونکہ تین لوگ مر گئے پانچ زخمی ہوگئے۔میں نے پرائیویٹ طور پر اس کے بارے میں بات کیں۔میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں کی حالت سدھرنی چاہئے کیونکہ اڑیسا میں جن سنگھ نہیں ہے۔ ہمارے ہوم منسٹر نے جو اور نام دیئے ہیں کہ کن اسٹیٹوں میں جھگڑے ہوئے ہیں۔ان میں اسر کا نام ہے۔میسور کا

آتی هیں۔لیکن اس بات کو اچھا نہیں کہا جا سکتا۔یہ الگ بات هے۔

ابھی میرے بھائی شری شالوالے نے ایک بات کہی۔اس کا جواب تو هوم منسٹر هی دیں گے۔میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں جانتا نہیں اپنی بہن کے بارے میں۔براهمنوں کی آبادی ٦ پرسینٹ هوگی - لیکن کشمیر کے سیکریٹیریٹ میں یا سینٹرل گورنمنٹ میں پالیمینٹ میں یا اور دوسرے جو سرکاری دفتر هیں وهاں آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو ٩۴ پرسینٹ هیں وہ تو نوکریوں میں ٦ پرسینٹ هیں اور جو ٦ پرشینٹ هیں وہ نوکریوں میں ٩۴ پرسینٹ هیں۔اس طرف آپ کا دهیان جانا چاهئے۔

کرپشن کا بھی بہت ذکر هوتا هے۔میں نے ڈاکومنٹس پیش کئے هیں کہ کس طرح سے بنکوں کے ذریعے بے ایمانی هوتی هے۔جب میں اس کے بارے میں هوم منسٹر کو لکھتا هوں تو وہ کہہ دیتے هیں کہ اس کی ابتدائی ذمہ داری تو فائننس منسٹری پر هے۔وہ کہتے هیں تو مقدمہ چلے گا۔یہ چیز میں نے ١٩۵۵ میں آپ کے نوٹس میں لائی تھی اور آج ١٩٦٩ هے۔ڈالمیا گروپ هے۔شانتی پرشاد جین گروپ هے ساهو جین گروپ کے معاملے تھے اور ویوین بوس کی رپورٹ ان کے بارے میں آئی تھی۔میں نے بھی دو ڈاکومنٹس چھپوائے تھے آئی اوپیر نمبر ١ اور آئی اوپیر نمبر ٢۔لیکن ابھی تک کچھ نہیں هوا هے۔میں نے ٢٨ اگست کو شریمتی اندرا گاندھی کو لکھا تھا ۔

(شری عبدالغنی ڈار)

نام هے۔اس میں اڑیسا کا نام هے۔اس میں آندھرا، مهاراشٹر کا نام بھی هے۔بهرحال اس بات کو میں چھوڑتا هوں۔یہ وہ جگہیں هیں جہاں پر جن سنگھ کا کوئی زور نہیں۔کوئی ان کا ریپریزینٹیشن نہیں۔ان کا کوئی آرگنائزیشن نہیں۔میں یہ ماننے کے لئے تیار نہیں کہ جن سنگھ والے امرتسر سے اٹھیں یا مدھیہ پردیش سے اٹھیں۔اترپردیش سے اٹھیں اور وهاں جاکر هلا گلا کریں۔ایسے میرا دماغ مانتا نہیں کیونکہ اب بھی میں اپنی سرکار کو ایسی سرکار نہیں مانتا جیسے کہ بهادر شاہ کی تھی جو کہ لال قلعے کے اندر وہ جائیں اور شاهنشاہ هند کہلائیں۔

آپ کو سوچنا چاهئے کہ یہ سب کیوں هوتا هے۔کہتے هیں کہ چونکہ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے اس لئے نئی اسٹیٹ فلاں جگہ بن گئی۔کل پھیلن باری آئے گی اترپردیش کی۔اس میں لوگ کہیں گے کہ پہاڑی علاقہ جو هے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں هوا۔جو مشرق کے رهنے والے هیں وہ کہیں گے کہ آگرہ ڈویژن اور میرٹھ ڈویژن بہت اچھے هیں۔ان کے ساتھ اچھا سلوک هے۔همارے ساتھ اچھا سلوک نہیں هوتا۔اس طرح سے کب تک آپ ملک کے ٹکڑے کرتے چلے جائیں گے۔میں اس بات پر بدھائی نہیں دے سکتا۔جہاں شری چوهان میں باقی خوبیاں هیں اور ان کی میں جتنی بھی تعریف کروں۔کوئی بڑی بات نہیں هے کیونکہ ڈسپلن میں کئی باتیں اچھی

ایک وزیر گھر میں بیٹھا ہوا عبدالغنی کو بیس لاکھ روپیہ دے دے یا عبدالغنی سے نو لاکھ لے لے تو کیا وہ کرپشن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاور لومز کو خریدنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پرانی پاور لومز جو تھیں جن کو رد کرکے نئے سرے سے بدلا گیا تھا ان کے لئے حکم دیا گیا کہ ایس۔ٹی۔سی۔ ان کو خریدے لیکن کالپور کی جو چار سو تھیں انکے بارے میں حکم دیا گیا کہ وہ پرائیوٹ پارٹی کی ہیں انکو نہ لیا جائے اس واسطے کہ انکو عبدالغنی نے پہلے مینیج کر لیا تھا۔ تین سو پاور لوز لے لیں۔ اس نے انکو دس دس ہزار میں بیچ دیا اور دس لاکھ ایک ہی سودے میں پیدا کر لیا۔ تو اسکو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کی میں دسیوں مثالیں دے سکتا ہوں۔ کامرس منسٹری میں اس طرح سے کروڑوں روپے کا جوڑ توڑ ہوا ہے۔ کیا اس طرح سے کام چلے گا۔

میں چاہتا ہوں کہ دیش کو بتایا جائے زبان کا معاملہ حل ہو۔ کمیونل جھگڑے بدھوں کرپشن ختم ہو۔ پاکستان کا حشر آپ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے مجھ جیسے اندھے جو ہیں یہ تو قتل ہو جائیں گے لیکن یہ بچ جائیں گے ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں۔ ریوالور لئے پولس رہتی ہے کرپشن جو بڑھ رہی ہے۔ اس کو آپ چیک کریں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں چیپ لیڈرشپ کا حامی نہیں ہوں۔ میرے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں۔ تاریخیں ہیں۔ نام میں دے سکتا ہوں۔ میں نے شریمتی گاندھی کو دئے بھی ہیں۔ میں نے ڈیڑھ برس تک،

میں نے اس کو ڈیڑھ برس تک سینے میں چھپائے رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں چیپ پاپولرٹی کا حامی نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بلیک میل کیا جائے۔ میں نے چیکوں کا نمبر دیا تھا اور بتایا تھا کہ کس پارٹی نے جاری کئے۔ کس کانگریس کے نیتا کے نام جاری کئے اور کس برانچ سے اس کانگریس کے نیتا نے ان چیکوں کو وصول کیا۔ میری بہن نے لکھا کہ میں بھی اس بارے میں کنسرنڈ ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ کس طرح سے اس کرپشن کو کم کیا جائے۔ میں حیران ہوں کہ وہی تاریخ پھر دوہرائی گئی۔ میرے پاس چیکوں کے نمبر ہیں۔ کس پارٹی نے جاری کئے اس کے نام ہیں۔ جس پارٹی نے وصول کئے اس کے نام ہیں۔ ۳۰ جنوری کو جس دن باپو کو شہید کیا گیا تھا اس دن یہ چیک جاری ہوئے اور کانگریسی نیتاؤں نے وصول کئے—

ہمارے ہوم منسٹر بہت دوراندیش ہیں۔ کیا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو روک نہیں سکتے ہیں۔ اگر نہیں روک سکتے ہیں تو کیا نتیجہ ہونے والا ہے۔ آپ ذرا پاکستان کی طرف دیکھیں۔ وہاں کیا ہوا ہے۔ ایوب نے اپنے زمانے میں پاکستان کی بڑی خدمت کی یا طاقت دکھائی۔ لیکن وہ بھی آخر کو مجبور ہو گیا۔ آپ بھی کیا اپنی طاقت ایک سپاہی کے خلاف دکھائیں گے جو کہ دو روپے رشوت لیتا ہے اور پکڑا جاتا ہے اور اخباروں میں اس کی چرچہ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب

(شری عبدالغنی ڈار)

سینے میں اس کو چھپائے رکھا ہے۔اب میں تنگ آگیا ہوں۔آپ کوئی کام نہیں کر سکے ہیں۔کیا سا ہو جین گروپ اتنا مضبوط گروپ ہو گیا ہے کہ اس نے جنرل اصغر کو مات دے دی۔کیا ایوب سے بھی وہ مضبوط ہے کہ آپ کا اس پر ہاتھ ہی نہیں پڑتا ہے۔کیا اس لئے آپ اس پر ہاتھ نہیں ڈالتے کہ وہ آپ کو لاکھوں روپے دیتا ہے الیکشن لڑنے کے لئے۔آپ دیکھیں کہ سی۔بی گپت کے لئے شراب کے کارخانے ہیں انہوں نے ڈھول کھول کر رکھ دئے تھے اور کہا تھا کہ بوتلوں میں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ان ڈھولوں میں سے شراب پلاؤ۔ہوں بروریز نے لاکھوں روپے خرچ کئے اور آگے پتا نہیں کتنا خرچ کرنے جا رہے ہیں۔میں آپ کی خدمت میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک۔ ایک مسلمان اس وقت کہتا ہے کس طرح سے ستائے ہیں یہ بہت میں نظام ہم ایسے ہیں کہ جیتے کسی کا خدا نہ ہو میں کہونگا کہ مسلمانوں کو بدنام کرانے کی کوشش نہیں ہونی چاہئے۔

Shri Y. B. Chavan : I would like to say, Sir that the hon. Member ismaking wild allegations against a person of the status of the Chief Minister of U· P. without auy proof and I do not think such allegations should be made. These are very mischievous and irresponsible allegations.

شری عبدالغنی ڈار۔میں نے ہوم منسٹر کو بھی لکھا تھا اس میں سے ہی میں نے یہ سب کچھ کہا ہے۔میں نے یہ خط یہاں اندرا کو بھی لکھا تھا۔میں نے نام کسی کے نہیں لئے ہیں۔لیکن میں ضرور کہتا ہوں کہ ڈالما جین گروپ نے اور پنجاب نیشنل بینک نے جنہوں نے لاکھوں روپے کے چیک دئے ہیں اور لاکھوں روپے کے چیک آپ نے وصول کئے ہیں۔جس برانچ نے دئے اور جس لیڈر نے وصول کئے ان کے نام اور اڈریس میں دے سکتا ہوں۔میں اس کو میز پر رکھ سکتا ہوں۔میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایسا کرنے کی اجازت دیں۔]

श्री कुशोक बाकुला (लद्दाख) : सभापति महोदय, गृह मन्त्रालय की मांगों पर जो बहस में भाग लेने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इन मांगों का मैं समर्थन करता हूं। पुलिस संगठन को मजबूत करना आज के हालात में बहुत आवश्यक है। उसकी संख्या भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसका कारण यह है कि जो हिंसा की घटनायें हो रही हैं, तोड़फोड़ की कारंवाइयां हो रही हैं, उनको रोकने के लिए और उन पर काबू पाने के लिए पुलिस को मजबूत करना आवश्यक है। बाहर से और अन्दर से जो कई बार खतरा पैदा हो जाता है उसका मुकाबला करने के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस संगठन को मजबूत किया जाए।

मैं गृह मंत्रालय की मांगों पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन मजबर होकर मुझे बोलना पड़ रहा है। मैंने दो दिन पहले लद्दाख में जो बड़ी घटनायें घटी हैं उनके बारे में कालिंग एटेंशन नोटिस दिया था। अध्यक्ष ने कहा था मुझसे कि गृह मंत्रालय की मांगें आ रही है और उस पर मैं बोल सकता हूं। इसलिए मुझे आज बोलना पड़ रहा है।

लद्दाख कितना बड़ा है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर का कुल क्षेत्र 53,664 मील है और उस में से लद्दाख का 37,753 मील है। यह इतना बड़ा क्षेत्र है, जिसकी सीमायें पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से मिलती हैं। इतना होते हुए भी लद्दाख की तरक्की के लिये कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। मैं यह भी जानता हूं कि हमारे लिये सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट 90 प्रतिशत ग्रान्ट देती है, लेकिन उस को लद्दाख के लिये खर्च नहीं किया जाता। मैं इस की तफसील के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं जब गृह मन्त्री जी से मिलूंगा तब उन को इसके बारे में बताऊंगा।

दूसरे--मैंने बार बार इस सदन में कहा है कि लद्दाख के लोगों को शेडयूल्ड कास्ट या शेडयूल्ड ट्राइब या बेकवर्ड क्लासेज में शामिल किया जाय। मुझे कहा गया है कि कुछ कानून ऐसे है, जिनको जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया है, वे कानून लागू हैं या नहीं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं यह चाहता हूं कि हमारे लोगों को बेकवर्ड शेडयूल्ड कास्ट या शेडयूल्ड ट्राइब में शामिल किया जाय। हमारा क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से बहुत पीछे है, ये लोग बहुत निर्धन हैं, इन के विकास के लिये जब तक इनको इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया जायगा, तब तक इन का विकास नहीं हो सकेगा।

आप जानते हैं कि हमारा लद्दाख बौद्धों का मुल्क है, लेकिन वहां पर कुछ समय से बौद्ध धर्म को खतरा पैदा हो गया है। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं कहा है लेकिन आज मुझे वहां से जो तार मिला है, उस को मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। इस तार का मूल अंग्रेजी में है, लेकिन मैं इस के हिन्दी अनुवाद को आप की इजाजत से पढ़ना चाहता हूं—

'हाल में अब्दुल कयूम और मोहम्मद बाकिर ने साबू ग्राम स्थित तारचोक में बौद्ध धार्मिक ध्वजों को उतार फेंका और अनेक लोगों के सामने गाली-गलौच की। लद्दाख के बौद्ध" धर्मावलम्बियों की भावनाओं को इस से गहरी ठेस पहुंची है। स्थानीय शासन अपराधियों को विरुद्ध कार्यवाही करने में असफल रहा। बड़ी संख्या में स्त्री-पुरुष और महामान्य अस कुशोक लोगदान, कुशोक खानपो, कुशोक स्तकना, फियांग के प्रधान लामा, थिकसे और स्तकना मठों के लामा और लद्दाख बुद्ध एसोसियेशन के अध्यक्ष ने प्रदर्शन किया। बौद्धों के प्रति किए गए इस गम्भीर अपराध की निन्दा की तथा उन्होंने अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। लेह में कल और आज हड़ताल रही। स्थिति निरन्तर बिगड़ती जा रही है। युगों से चली आ रही परम्परायें और परस्पर अच्छे सम्बन्धों को खतरा पैदा हो गया है। अपराधियों को दण्ड देने पर ही स्थानीय जनता को सन्तोष होगा। लद्दाख के बौद्धों की यह मान्यता हो चली है कि धर्मनिरपेक्ष भारत में उनका पावन धर्म सुरक्षित नहीं है। यदि एक सप्ताह में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो स्थिति और बिगड़ कर नियन्त्रण के बाहर हो जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व स्थानीय शासन और सरकार पर होगा।

"अध्यक्ष, लद्दाख बुद्ध एसोसियेशन"

यह तार 25 मार्च का है। इस की कापी में होम मिनिस्टर साहब को दे रहा हूं इस तरह की घटनायें वहां पर हो रही हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। वहां पर पुलिस, कलेक्टर सब मौजूद हैं, पता नहीं कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है।

सभापति महोदय, इस किस्म की घटनायें वहां पर पहले भी हुई है। कारगिल में लद्दाख के बौद्ध अपना पूजा स्थान और धर्मशाला

[श्री कुशोक बाकुला]

बनाना चाहते थे, लेकिन उनको बनाने नहीं दिया गया। इस पर काफी झगड़ा होने वाला था। जहां बौद्ध मठ हैं, वहां मस्जिदें भी होती हैं और उस पर कोई एतराज नहीं होता है और न एतराज कर सकते हैं। लद्दाख के मुसलमान प्राचीन काल से बौद्धों के साथ रहते आ रहे हैं, लेकिन अब वह स्थिति बिगड़ने लगी है उस समय मैं मंत्रीमंडल में था, मैंने उस झगड़े को रोकने की कोशिश की और समझाने का प्रयत्न किया कि बौद्धों का भी धर्म वहां रहना चाहिये और मुसलमानों का धर्म भी रहना चाहिये और मुसलमानों का धर्म भी रहना चाहिये, और दोनों धर्मों की रक्षा होनी चाहिये। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसमें अनेक धर्म हैं, सब धर्मों की रक्षा होती है, फिर लद्दाख में बौद्ध धर्म की रक्षा क्यों नहीं हो पा रही है, यह बड़ा गम्भीर विषय है।

दूसरी बार एक एश्तिहार लगाया था जिस में यह कहा था कि गया लद्दाख से बौद्ध धर्म खत्म किया जायेगा, पाकिस्तान के झण्डे लगाये जायेंगे। उस समय भी वहां बड़ा विरोध हुआ, जलूस निकाले गये, मैं उस समय भी वहां मौजूद था, लेकिन मैंने उन को निकलने नहीं दिया। राज्य सरकार ने हम से कहा कि हम एक्शन लेंगे, एक कमेटी बनायेंगे जिसमें वहां की मुसलमान एसोशियेशन और बुद्धिस्ट एसोशियेशन के लोगों को रखा जायेगा और वे लोग ऐसी बातों को रोकेंगे, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ नहीं हुआ।

तीसरी बार अब यह घटना घट रही है। मैं गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चीफ मिनिस्टर से इसके बारे में फौरन बातचीत करें। अपराधियों के खिलाफ पूरा एक्शन लिया जाना चाहिये, वरना लद्दाख में बौद्ध धर्म को खतरा पैदा हो जायेगा। आप जानते हैं कि तिब्बत के बाद हम लद्दाख को दूसरा तिब्बत समझते हैं, इस समय वह बौद्धों का बहुत बड़ा केन्द्र है, बुद्ध धर्म की महायान और हीनयान शाखाओं का एक बहुत बड़ा केन्द्र हम उसको समझते हैं। अगर वहां से हमारे धर्म को खत्म करने की कोशिश की गई तो इस की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर होगी। उस की सरहदें चीन और पाकिस्तान से मिलती थीं, इस वजह से उस क्षेत्र के लिए बाहरी खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन अन्दर कोई खतरा नहीं था, जो अब पैदा हो गया है। इसलिये जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, उनको सख्त से सख्त कानूनी सजा दी जानी चाहिये।

सभापति महोदय, इस समय जम्मू-काश्मीर मन्त्री मंडल में लद्दाख का कोई मन्त्री नहीं है। मैं 10-12 साल तक वहां के मन्त्री मंडल का सदस्य था, लेकिन जब से इधर आया हूं, तब से उस क्षेत्र का कोई मन्त्री नहीं है। इस के न होने से वहां पर गड़बड़ हो रही है और यह गड़बड़ इसी तरह से होती जायेगी। जितना हो सकता है, हम लोग इस गड़बड़ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितना रोक सकेंगे। वहां की जनता कहती है कि हमारा लद्दाख गरीब है, इसलिये उसको सैन्ट्रल गवर्नमेंट के अन्दर लेना चाहिये। लेकिन मैं इस को नहीं मानता हूं और मैंने उनसे यही कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। पिछले साल मैं ने 14 अगस्त को एक मेमोरेण्डम पेश किया था, जिसमें अनुरोध किया था कि लद्दाख को नेफा पैटर्न पर बनाया जाय। उस समय लोगों ने हम से कहा कि तुम लद्दाख को जम्मू-काश्मीर से काट कर सैन्ट्रल में ले जाना चाहते हो। मेरा यह मतलब नहीं था, वह जम्मू-काश्मीर में ही रहे, लेकिन जैसे नेफा में सैंट्रल गवर्नमेंट इन्तजाम करती है, उस तरह की व्यवस्था हो। बाद में प्रधान मन्त्री जी और गृह मन्त्री जी से इस सबंध में बातचीत हुई, हमारे मुख्य मन्त्री सादिक साहब से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी

ऐसा कहने का समय नहीं है, आप इस ख्याल को छोड दो। लेकिन इन घटनाओं को देखते हुए मैं समझता हूं कि वह समय आ गया है। मैंने 1949 में स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरु जी से भी कहा था कि इस को डाइरैक्टली सेंटर में ले लें। हमारे जम्मू-काश्मीर में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए इसको काश्मीर के साथ नहीं रख—हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं था, हमारी मांग का उद्देश्य केवल यही था कि लद्दाख बहुत बैकवर्ड है, उसकी तरक्की नहीं हो पाई है, केन्द्र के अधीन आने से उसको तरक्की का मौका मिलेगा। उस समय हम को यही कहा गया कि कुछ कानूनी दिक्कतें हैं, इस लिये इस समय इसको नहीं लेंगे। हमारा उद्देश्य यही था कि लद्दाख मजबूत हो और उसके साथ भारत भी मजबूत हो। तिब्बत को हाथ से छोड़ने में जो खतरा पैदा हो गया है, वह लद्दाख में नहीं है, लद्दाख में कम्यूनिस्टों की हवा भी नहीं है, चीन की हवा भी नहीं है, लेकिन अगर उसकी तरक्की का ख्याल नहीं रखा गया तो वहां भी स्थिति खराब हो सकती है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को कहे कि इस तरह की घटनाओं से वहां की हालत खराब हो सकती है, इसलिये वह जल्द से जल्द इन्तजाम करे।

लद्दाख में बिजली भी नहीं है, वहां पर 90 किलोवाट के दो डिजल इन्जिन थे, जिसमें से एक खराब है, एक इन्जिन चलता है, जिससे जनता को बिजली नहीं मिल पाती। कारगिल में मुसलमानों की संख्या बहुत है, उनकी तरक्की करना भी बहुत जरूरी है। वहां पर बिजली पैदा करना कठिन भी नहीं है क्योंकि वहां पर पानी बहुत है, दरियायें बहुत हैं। लेकिन अफसोस है कि अभी तक आपने वहां पर बिजली पैदा करने का कोई काम नहीं किया है। अगर आगे भी आप वहां पर कुछ नहीं करते हैं तो उससे खतरा पैदा होगा। लद्दाख से कोई भी नुमाइन्दा काश्मीर के मन्त्रीमंडल में नहीं लिया गया है। इस वक्त मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मुख्य मन्त्री, श्री सादिक ने कहा है कि बजट सेशन खत्म होने पर वे हमारा नुमाइन्दा लेंगे। अगर वे ले लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो फिर गडबड़ शुरू होगी और इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। क्योंकि जैसा आप कहेंगे वैसा ही राज्य सरकार करेगी। उसको चलाने वाले तो आप ही हैं। लद्दाख के लिए बहुत जरूरी है। कि वहां पर तरक्की हो। उसके लिए पैसा भी मिलना चाहिये।

16.51 hrs.

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा पीठासीन हुईं]

पिछले साल वहां पर एक डिप्टी मिनिस्टर गई थीं और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि वहां पर आकाशवाणी का केन्द्र खोला जायेगा। लेकिन अफसोस है कि अभी तक वहां पर कुछ भी नहीं किया गया है। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी मन्त्री मंडल में थी, उस वक्त उन्होंने भी यही कहा था और पिछले साल एक डिप्टी मिनिस्टर ने भी जाकर कहा लेकिन अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। वहां पर सबसे बड़ी आवश्यकता बिजली की है। बहुत से ससद सदस्यों ने वहां पर जा कर देखा है कि बिजली पैदा करने के कितने साधन मौजूद हैं। आपने कह दिया कि वहां पर इतनी बड़ी-बड़ी सब्जी पैदा की गई लेकिन उससे क्या होता है।

लद्दाख के सम्बन्ध में हमने गजेन्द्रगदकर कमीशन के सामने अपनी मांगें रखी थीं। उन्होंने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि लद्दाख को पैसा कम मिला है और वहां पर तरक्की नहीं हुई है। उन्होंने यह भी सजेस्ट किया है कि लद्दाख से फुलफ्लेज्ड मिनिस्टर होना चाहिए, वहां पर डिग्री कालेज होना चाहिये और एक पावरफुल डेवलपमेन्ट कौंसिल की स्थापना होनी चाहिये। और भी दूसरी उनकी सिफारिशें हैं।

[श्री कुशोक बाकुला]

आपको मुकम्मिल तौर पर उन सारी सिफारिशों पर कार्यवाही करनी चाहिये । नहीं करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा । इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं ।

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : Madam Chairman, what a pleasure to address the House when you are in the Chair !

The first point which strikes anybody who speaks on these demands is the position of law and order in this country. Much has already been said and I do not want to repeat it. All that I want is that the Home Minister and the Home Ministry should take a greater interest in these things in the sense that they should not wait until information comes or follow the ordinary routine and protocol. But they should themselves be always vigilant to know what is happening in this country and what is to be done in consultation with the local governments. Unless that is done, if they continue the present habit of merely waiting for somebody to report, until a Member of Parliament raises it in the House, the things will not go all right.

There are several reasons why these disturbances are going on. The Home Minister has been giving the reasons. To give reasons is one thing but to act is another thing. We want the Home Minister and the Home Ministry to act more quickly and more expeditiously than they have done so far.

Perhaps, it is not right to say what I myself told him about a particular State as long back as January 23. But nothing was done until January 29. And things went worse and shootings had to take place. It is only now that the Prime Minister is taking some active interest--we see in the papers--and it is only now that the Home Minister is taking active interest. But why should there be so much delay ? My complaint is not that the Home Minister is not acting. But they must act more expeditiously and quickly, particularly in these days, when the things have to be brought under control as quickly as possible because we have got to consolidate our independence. The Government cannot simply sit and think, "Let the report come and see what happens in Nagaland, what happens in Mizo Hills, what happens in Telengana or somewhere else". It is not like that. The situation is more critical now and, therefore, my request to him is that he should take the initiative. Many of the troubles of the Centre-State relationship are coming up, if I may say so, without wounding the feelings of the officers of the Centre or the Ministers of the Centre, because there is a feeling here that we are superiors and that those who are in the State Governments or who are manning the State administrations are subordinates. This kind of feeling must go.

Take, for example, the matter of engineers. The engineers here do not pass higher examination than the engineers who pass and work in our States. They send their proposals here. An enormous amount of time is taken for scrutiny, ticking off with blue pencil and that pencil because that is manufactured in this country and they must use it. Many times, the Planning Commission, the Central Secretariat here, C. W. P. C. ask the State engineers to come and explain proposals. Why should they do so ? Or, take the Finance Department. There also, in the States, it is the I. A. S. officers that are meaning the administration. There also, they have got the Accountant, General. The proposals are sent after being scrutinised by the Finance Department. It may be with regard to loans or something. But the scrutiny takes place here once again and the papers are sent back often for explanations. The reason is, here they feel that they are a superior Government and that the Government in the States are mere colonial governments subject to tutelage; the same thing that was happening in the British days. Madam Chairman, we are sitting in this House with the legacy of British mind. That is the mistake. We should have built a new Parliament House. Perhaps, we would have had a new approach I want, therefore, the Home Minister who is very active-minded gentleman and who has got a lot of imagination, to start

a new chapter in this kind of thing. There must be generated an active living feeling that the Centre at the States are joint partners in a common adventure, the adventure of making India more prosperous and making people more happy and more contened.

With regard to corruption that is going on, two things are primarily responsible for it. This morning, the Lokpal Bill has come. As has already been said, the Lokpal Bill will not be very much of an improvement on the Vigilance Commissioner unless the Government itself removes all the points where corruption is growing. Corruption and nepotism, the twin, brothers, grow on two things, descretionary power and delays.

17 hrs.

The Government takes discretionary powers in every bit of legislation. The second is the scope they give for causing delay. The discretionary powers should be reduced to the minimum. Everybody must be certain about what is going to happen, and it should not depend merely on discretion. For instance, take the age of retirement. They have fixed at 55 years, but if the Government like they can extend an officer's term to 58 years. In States also it is like this. Some proposal was published in the newspapers--I do not know whether it is right or not--to reduce it to 50 years, but at the discretion of the Minister it could be extended further. This particular fact may be right or wrong, but it should not be left to the officers to speculate as to what would happen on a particular date. If they have to retire, they will have to retire. Then there will be certainty and they will not go round the houses of Members of Parliament or around the coridors of the houses of Ministers. On account of this, they lose their indepence in advance. Therefore, I suggest that the discretionary powers in every field wherever they exist now must be reduced to the very minimum. I do not say that all discretion must be taken away. There is a place for discretion, for instance, when there is a question of coming to a particular decision on a quasi-judicial matter. But on other matters there should not be any discretion left.

While talking about Governors and their powers, I would like to say that I have given notioe of a Bill, if the Home Minister agrees, to drop the articles in the Constitution asking the President and the Governors compulsorily to give Addressed to Parliament and Assemblies. No Address of a President or a Governor ever gave any extra light either to the Members of Parliament or to the public. Then what is the purpose in that ? It only adds to the national cost. In fact, the Budget itself provides the occasion when everything can be said. We know what happened in West Bengal recently. And what is likely to happen almost in every State hereafter will be greater friction without giving us any benefit. Therefore, I would ask the hon. Home Minister to consider dropping of those articles from the Constitution. On the other hand, I find that there has been a strong move--because they are prejudiced against the West-Bengal Government--to give more powers to Governors. I specially caution the Home Minister never to accede to that request. If you give more powers to Governors, then what will happen is that there will be two Governments and we will be reverting back to the diarchy of the olden days. Therefore, I want the Home Minister to give thought to this and never to consider giving more powers to Governors. We can imagine what will happen when there is a strong-headed Governor, particularly a gentleman from the ICS cadre. I know, when I was in the Congress, we took objection when an ICS man was appointed as Governor of Orissa; there was an uproar against it. But now it has become an ordinary thing. If you draft a man from the ICS cadre for Governorship what will really happen is that he will introduce diarchy when you give him more powers. Therefore, never think about that.

On the question of language, something has been side. Mr. Kandappan has really voiced what is being felt in non-Hindi-speaking areas. I do not want the senior members here to raise again the whole controversy which we thought came to rest in 1967 wnen the Official Language Amend-

[Shri Tenneti Viswanatham]

ment Bill was passed. We all agreed to that and the Bill was passed and things are going on alright. Therefore, I would request all my frinds not to raise further controversies. But I would say this particular thing. You have a Commissioner for Linguistic Minorities. You have given him a very small status and that status must be raised to that of a Minister of State. Now, I think, he is given the status of a joint Secretary. In fact, if I may say so, it was in one of my private conversations with late Pandit Nehru that the idea of a Commissioner for Linguistic Minorities was developed–some of us sat together; it was a private conversation and then there was the Fazal Ali Commission. . .

SHRI Y. B. CHAVAN : What gave you the idea that the Commissioner for Linguistic Minorities is given the status of a joint Secretary ?

SHRI TENNETI VISWANATHAM : What is his status ?

SHRI Y. B. CHAVAN : His status depends upon the work. It is an office recognised by an Act of Parliament.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : I may tell you why I am saying this, I happened once to reside in the same guest house in which Linguistic Minorities Commissioner stayed. He was an ex-Judge of a High Court. He said that he has got to wait at the doors of the State Ministers. Why is it that such an important person, one of the highest officers appointed under the Constitution, is not given the proper status, I asked. Then he said, 'I am given the status of a Joint Secretary'. That is all. What happens now ? When he is given the status of a Joint Secretary Ministers do not take him with the respect due, his reports are not very much minded. Then also with regard to the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, what I would suggest is that his status also should be raised.

Now there is another thing. We have been told that the Planning Commission has been trying to identify all the undeveloped areas in the country. It is good. Instead of leaving it to the States and the vagaries of group politics it is much better that the Central Government itself identify all the undeveloped areas and have some special Commissioner of the same status as other Commissioners to pay special attention to the development of all the undeveloped areas. Just now we have heard a silent gentleman who rarely talks, the hon Member from Ladakh. Now what he has said, we all heard. Only if time is given that will be repeated from the various areas of the country. Therefore, I suggest that a Special Commissioner should be appointed. A Special Commissioner may be appointed to pay special attention to all these undeveloped areas throughout the country.

Now only one point remains. That is the language of Hindi. I do not like to raise any controversy. They say 'one people, one language'. What was the language in those days? We used to call 'Hindustan Hamara'. Then Hindi came. But the Constitution uses the word 'India that is Bharat'. Therefore our official language should be Bharati, that is to say, Sanskrit. I ask the hon Minister, "Will you work for it ?" and conclude.

श्री वीरभद्र सिंह (महासू) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आप ने मुझे गृह-मंत्रालय की मांगों पर बोलने का मौका दिया। गृह मंत्रालय हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है और इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं, और आज देश में जो स्थिति पैदा हो रही है उस को देखते हुए इस मंत्रालय की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गयी है। 1967 के आम चुनाव के बाद हमारे देश के राजनीतिक चित्र में एक खास परिवर्तन हुआ है और जिस की वजह से राज्यों और केन्द्र के बीच में तनाव बढ़ा है। और आज यह मांग की जा रही है कि राज्यों और केन्द्र के बीच के मामलों में उन के आपसी रिश्ते के बारे में फिर से विचार किया जाये और राज्यों को और ज्यादा अधिकार दिये जायें। यह भी मांग की जा रही है कि संविधान के अन्तर्गत जो साधनों

का बटवारा राज्य और केन्द्र के बीच में होना है उसके बारे में फिर से विचार किया जाये। तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में लोकतंत्र के लिये और देश की एकता के लिये यह बहुत जरूरी है कि राज्यों और केन्द्र के बीच में किसी प्रकार का तनाव न हो उनके बीच में अच्छे रिश्ते हों, उन के बीच में परस्पर सहयोग हो और अपने बीच में वह ठीक तरह से काम कर सकें। इसलिये मैं समझता हूं कि जितने भी यह तनाव के कारण हैं हमें कोशिश करनी चाहिये कि हम उन कारणों को शीघ्रातिशीघ्र दूर करें। मगर इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम कोई भी ऐसा कदम न उठायें जिसकी वजह से केन्द्र कमजोर हो जाता है।

जहां मैं इस बात के हक में हूं कि राज्यों और केन्द्र के बीच जो तनाव है उसको जितना भी मुमकिन हो सके कम करने की कोशिश की जाये वहां मैं इस बात को भी चाहूंगा कि कोई भी ऐसा कदम न उठाया जाये जिससे कि केन्द्र कमजोर हो जाये। मैं समझता हूं कि एक सुदृढ़ और शक्तिशाली केन्द्र ही भारत की अखडता एकता को कायम रख सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय इस ओर ध्यान दे। अब समय आ गया है कि संविधान की धारा 263 में जिस इंटरस्टेट कौंसिल का प्राविजन किया गया है उस कौंसिल को बनाया जाये ताकि इस केन्द्र और राज्यों के रिश्ते के बारे में विचार कर सकें। जो भी झगड़े की बातें केन्द्र और राज्यों के बीच में हैं, जो भी तनाव की बातें हैं उन पर वह विचार कर सके और दूसरे भी जो राज्यों के अपने बीच में झगड़े हैं चाहे पानी का झगड़ा हो, चाहे सरहद के बारे में झगड़ा हो उन सब के ऊपर भी यह कौंसिल विचार कर सकती है। इस बारे में पहले भी कई दफा सदन के दोनों ओर से मांग की गई है कि उस कौंसिल का गठन किया जाये उसका निर्माण किया जाये। मैं समझता हूं कि समय आ गया है, जबकि इस बारे में बड़े गौर से और बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा, ताकि आगे चलकर राज्यों और केन्द्र के बीच में जो तनाव है और जो कि मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में और भी उभरेंगे, वह तनाव कम हो सकें।

17·12 hrs

[श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए]

गृह मंत्रालय का और बातों के साथ साथ जो केन्द्र प्रशासित क्षेत्र हैं उन के साथ उस का सीधा सम्बन्ध है। मैं आज हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य की मांग के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। आप को मालूम है कि हिमाचलप्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को लगभग 30 पहाड़ी रियासतों को मिला कर हुआ था और शुरू से ही हिमाचलप्रदेश की जनता को अपने राजनैतिक भविष्य के बारे में कोई भी संदेह नहीं था। उस वक्त के उपप्रधान मंत्री और मिनिस्टर आफ स्टेट्स स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल ने हिमाचलप्रदेश की जनता को आश्वासन दिया था कि आगे चल कर हिमाचल प्रदेश को दूसरे राज्यों की तरह एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जायेगा। इस सिलसिले में सरदार वल्लभभाई पटेल ने डा० पट्टाभि सीतारमैय्या को जो एक मात्र लिखा था। सरदार पटेल ने 10 मार्च, 1948 को डा० पट्टाभि, सीतारमैय्या को पत्र लिखा था उस में से मैं कुछ अंश पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"The ultimate objective is to enable this area to attain the position of an autonomous province of India. This objective would be attained in two stages. The area will, in the first instance be administered by an Administrator, probaly an officers of the Chief Commissioner's status assisted by an Advisory Council consiting of Rulers and representatives of the people appointed in such a manner and with such functions as the Central Government may decide. Subsequently subjects to the decision of the Constituent Assembly it is proposed that the

[श्री वीरभद्र सिंह]

administration should be put in charge of a Lieutenant-Governor assisted by an Advisory Council, representing the Princes and a Legislature in the Province. In the final stage, after this area is sufficiently developed in its resources and administration, it is proposed that its constitution should be similar to that of any other province."

यह स्पष्ट आश्वासन स्वर्गीय सरदार पटेल ने हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया था कि तीसरी स्टेज पर पहुंचने के बाद हिमाचल प्रदेश को दूसरे राज्यों की तरह एक पूर्ण राज्य बनाया जायगा। मैं आज गृह मन्त्रालय से और खास कर अपने गृह मन्त्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं कि स्वर्गीय सरदार पटेल ने हिमाचल प्रदेश की जनता को जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन को वह पूरा करें। जितनी भी शर्तें उन्होंने लगाई थी, हिमाचल प्रदेश ने उन शर्तों को आज पूरा कर दिया है।

श्रीमान्, जब भी हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य का सवाल आता है तो आम तौर पर तीन बातें सामने रक्खी जाती है। एक रकबा दूसरी आबादी और तीसरी फाइनेंशियल वाएबिल्टी की। अब जहां तक रकबे का सवाल है मैं बतलाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश आज रकबे में पंजाब हरियाणा और केरल राज्यों से बड़ा है। हिमाचल प्रदेश का रकबा 22000 वर्गमील है जोकि इन तीनों राज्यों से बड़ा है। मैं नागालैंड की बात ही नहीं करता वह तो एक जिले के बराबर है। जहां तक आबादी का सवाल है आज हिमाचल प्रदेश की आबादी 30 लाख के लगभग है जोकि जम्मू और काश्मीर की आबादी के बराबर ही है। जहां तक यह रकबे और आबादी की दलीलें है मैं समझता हूं कि यह दलीलें आज काम नहीं करतीं। मैं समझता हूं कि गृह मंत्रालय भी इस बात को मानता और समझता है कि आज इन दो दलीलों में कोई भी वजन नहीं है। पिछले दिनों में जब यह मामला राज्य सभा में उठा था उस समय माननीय विद्या चरण शुक्ल जी ने अपने भाषण में इस बात को माना था कि जहां तक आबादी और रकबे का सवाल है यह अब कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। अब सिर्फ प्रश्न यह है कि एकोनामिक वाएबिल्टी की शर्त पूरी होती है या नहीं! एकोनामिक वाएबिल्टी की शर्त अगर पूरी होती है, तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बना लेंगे। सिद्धान्त: भारत सरकार ने इस बात को मान लिया है कि अगर यह शर्त पूरी हो जाये तो हम हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनायेंगे। श्री शुक्ल ने 9 अगस्त, सन् 1968 को राज्य सभा में जो भाषण दिया था उस में से कुछ अंश मैं यहां पर कोट करना चाहूंगा :

> We have full sumpathy for the demand (that is the demand for statehood) We do not want to hold back statehood for Himachal Pradesh for a day longer than necessary. As a matter of fact, it is our firm policy to help Himachal Pradesh with financial resources as quickly as possible and once the financial resources become equal to their requirements and they obtain the condition of financial viability we would not hesitate to give it Statehood.

इस से सीधा मतलब यह है कि जहां तक सिद्धान्त का सवाल है भारत सरकार ने इस बात को मान लिया है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाया जायेगा। सवाल सिर्फ फाइनेंशियल वाएबिल्टी का है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा यह दावा है कि फाइनेंशियल वाएबिल्टी के लिये जो भी शर्तें हैं आज हम उन को पूरा करते हैं। हिमाचल प्रदेश आज उसी मापदंड से फाइनेंशियली वाएबुल है जिस से कि दूसरे राज्य हैं। वैसे तो क्या आज कोई भी ऐसा राज्य है जिसको आप कह सकते हैं कि वह सही मायनों में फाइनेंशियली वाएबुल है?

कोई भी ऐसा राज्य देश में नहीं है जो कि अपनी ही आमदनी से अपने प्रदेश का खर्चा चला रहा है। हिन्दुस्तान के सारे राज्य चाहे वह मद्रास हो, यू० पी० हो, अथवा मध्यप्रदेश हो जम्मू कश्मीर और असम की तो मैं बात ही नहीं करता, उन को तो 70–80 फीसदी तक सैंट्रल ग्रान्ट मिलती है, लेकिन मैं और दूसरे बड़े बड़े राज्यों की बात करता हूं, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो कि दावा कर सके कि वह अपने पांव पर खड़ा है वह अपनी ही आय-दानी से अपना खर्चा चला सकता है। इस माने में अगर फाइनेंशियल वाएबिल्टी को बहुत ज्यादा खींचा जाये तो फिर हमारा देश भी फाइनैंशियली वाएबिल नहीं है। हम बड़ी-बड़ी अन्तर्राष्ट्रिय सस्थानों–,वर्ल्ड बैंक और रूस अमरीका आदि देशों से कर्जा लेकर अपनी विकास योजनाओं को चला रहे है, इसलिए मैं समझता हूं कि फाइनेंशियल वाएबिल्टी की बात को ज्यादा खीचना एक उचित बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश भी उतना ही फाइनेंशियली वाएबुल है जितने कि दूसरे राज्य हैं और हम यह चाहते है कि एक पूर्ण राज्य बनाने के बाद आप हम को उसी स्तर पर और उन्हीं शर्तों पर कर्जा और अनुदान आदि दीजिये जैसे कि आप दूसरे राज्यों को देते है। यही हमारी आप से दरख्वास्त है।

श्रीमान् जहाँ तक पूर्ण राज्य की मांग है यह कोई एक व्यक्ति विशेष की मांग नही है, एक राजनैतिक दल की मांग नहीं है बल्कि यह हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की मांग है, सारी राजनैतिक पार्टियों की मांग है। इस वास्ते मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब हिमाचल प्रदेश में विधान सभा नही थी जब वहां पर क्षेत्रीय परिषद् थी उस वक्त भी वहां पर टैरिटोरियल कौंसिल ने इस बारे में सर्वसम्मति से रेजोल्युशन पास किया था। उसके बाद हिमाचलप्रदेश विधानसभा ने भी सर्वसम्मति से इस विषय में रेजोल्युशन पास किया है जिसमें केन्द्रीय सरकार से और इस माननीय सदन् मे मांग की गई है कि हिमाचल प्रदेश की जनता की इस मांग को जल्द से जल्द स्वीकार करें।

श्रीमान, एक प्रश्न हमेशा उठाया जाता है कि अगर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाया जाय तो दूसरे केन्द्र प्रशासित प्रदेशों का क्या होगा ?

मणिपुर में क्या होगा, त्रिपुरा में क्या होगा, गोआ में क्या होगा, इत्यादि। इस बारे में सब से सहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आप हिमाचल प्रदेश को दूसरे केन्द्र प्रशासित प्रदेशों के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। उनके समकक्ष नहीं रख सकते। क्योंकि शुरु से ही भारत सरकार ने यह माना है कि जहां तक हिमाचल प्रदेश और विंध्य प्रदेश का सवाल है वह दूसरी यूनियन टेरिटरीज से अलग है।

जिस दूसरी बात की तरफ में इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह कि जितने केन्द्र प्रशासित राज्य हैं उनका निर्माण भिन्न भिन्न राजनैतिक तथा एतिहासिक कारणों से हुआ था। अलग अलग कारण थे और उनके भविष्य का फैसला करने के लिये उनको एक ही थैली में नहीं डाला जा सकता। उन का समाधान अलग अलग तरीकों से करना होगा। मणिपुर की जनता क्या चाहती है, गोआ की जनता क्या चाहती है, दूसरे केन्द्र प्रशासित राज्यों की जनता क्या चाहती है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। उन की मांगों के बारे में सरकार को सोचना चाहिये, लेकिन जहां तक हमारी जनता का सवाल है, वह पूरी आशा लगाये हुए हैं, और भारत सरकार की शीघ्रातिशीघ्र उन की मांगों को पूरा कर के पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिये।

अन्त में मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि जहां पूर्ण राज्य की हम मांग करते हैं वहां पर

[श्री वीरभद्र सिंह]

हम भारत सरकार के और गृह मंत्री जी के आभारी भी है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की तरक्की के लिये, उसको आगे ले जाने के लिये, बहुत मदद की है, बड़ी उदारता से मदद की है। मगर साथ साथ हम समझते हैं कि हम बीस साल तक नाबालिग रहे। हिन्दुस्तान के कानून के अनुसार भी 18 साल के बाद नाबालिग बालिग बन जाता है। हम भी अब बालिग हो गये हैं। हम चाहते हैं कि अपने घर के इन्तजाम अब हम खुद चलायें। इस की वजह यह नहीं है कि हमें भारत सरकार पर विश्वास नहीं है या उन के ऊपर हम को कोई नाराजगी है। बल्कि हम चाहते है कि हम को बालिगाना हक मिले और अपना काम हम खुद चलायें।

इन शब्दों के साथ में मत्र लय की मांगों का समर्थन करता हूं

श्री केवार पास्वान (रोसेरा) : सभापति महोदय, में सदन का बहुत आभारी है कि मुझे बोलने का मौका मिला, लेकिन में श्री चव्हाण का भी आभारी हूं जिन्होंने गरीबों पर सहानुभूति नहीं दिखलाई। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान मे 50 प्रतिशत बेईमानी और भ्रष्टाचार पुलिस के द्वारा होता है। जो गरीब दूसरों के खेत में काम करने के लिये नही जाते हैं उन को वह रात दिन तग करती है। धनिकों का पक्ष लेकर पुलिस चौबिसों घटे दफा 109 या दूसरी दफाओं मे उन को तग करने के लिये तैयार है, जिस का मैं उदाहरण दे रहा हूं। बिहार में दरभगा जिले में एक थाना बहेड़ी है जिसके अन्तंगत नडोगा गांव है वहां एक जमींदार गांव के एक हरिजन को जबर्दस्ती 379 में फंसा कर ले गया और पुलिस ने उस को जेल में रख दिया। इसी तरह से बिहार के बहेड़ी थाना में हाबी भौआर गांव है, वहां के एक हरिजन को जबर्दस्ती फसा कर रख दिया। इस तरह से 50 फीसदी बेईमानी पुलिस कर रही है। इस के लिये हमारे श्री चव्हाण कुछ नहीं कर रहे हैं।

मेरा कहना यह है कि जितने सांपद-सदस्य हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, अगर वह पुलिस द्वारा बेईमानी या डकैती की रिपोर्ट करते हैं तो उन की जांच कौन करता है ? वही इन्स्पेक्टर और दरोगा। मगर जहां दही होना है वहां बिलाई भडारी नहीं हो सकती। संसद-सदस्य के लिखने पर इन्स्पेक्टर या दरोगा एन्क्वायरी करें यह बात मेरी समझ में नहीं आती। चव्हाण साहब को इस के लिये दूसरा इन्तजाम सोचना चाहिये। अगर किसी मुकदमे में पुलिस चार्जशीट दे और कोई संसद-सदस्य या कोई विधायक उस के बारे में कोई लिखा पढ़ी करता है तो उस मुकदमे में भ्रष्टाचार निरोध समिति द्वारा जांच कराई जाये।

आज हमारे देश में भाषा का बड़ा भारी झगड़ा चल रहा है। एक आदमी कहता है कि यह भाषा चलनी चाहिये। दूसरा आदमी कहता है कि यह भाषा चलनी चाहिये। मैं उन सबका विरोध करता हूं क्योंकि इस देश की भाषा हिन्दी है। सारे देश की मातृ-भाषा हिन्दी है। अगर कोई और भाषाओं का सवाल उठता है तो इस से देश खण्ड खण्ड हो जायगा। इस से देश की अखण्डता बढ़ेगी नही। आज सारे देश में हिन्दी भाषा ही रखनी चाहिये। अगर यह न माना जाय तो देश के सब प्रान्तों की अपनी अपनी भाषा को मान्यता दी जाये तो बिहार में दो करोड़ निवासियों की भाषा मैथिली को अवश्य मान्यता मिलनी चाहिये।

आज देश में जो सब से बडी बेईमानी हो रही है वह यह कि जो गरीब तबके के आदमी हैं उन को खाना ठीक से नहीं मिलता है। चौकीदार की तन्खवाह तो है 17 रुपये और उस के अफसर की तन्खवाह है 1750 रु०। जिस रूप में यह बात चल रही है आखिर कब तक उसी तरह से चलती जायेगी ? मैं चाहता हूं

कि आप को वेतनों में इस प्रकार से सुधार करना चाहिये कि किसी को भी 17 रु० नहीं मिलने चाहियें। आज तो 17 रु० में 17 सेर चावल भी नहीं मिलता है। वह रात दिन पहरा देता है, गश्ती लगाता है। इतने कम रुपयों में उस का काम कैसा चलेगा ? श्री चव्हाण को इस पर सोचना चाहिये।

इस के बाद मैं जिस को हिन्दुस्तान में ब्लाक कहते हैं उस के बारे में कहना चाहता हूं। वहां बी० डी० ओ० इतना अत्याचार कर रहे हैं। हम लोग लिखते लिखते थक गये। बिहार में राष्ट्रपति शासन हो गया था। बिहार में नित्यानन्द कानूनगो थे उन्हें नित्यानन्द न कहा जाय, उन्हें अनित्यानन्द कहा जाय। इतनी** उन्होंने की। बिहार की सरकारें उन्होंने कई बार तोड़ दी केन्द्रीय सरकार की इजाजत से। बीच में सरकार बनी उस को तोड़ दिया। इस लिये उन्हें अनित्यानन्द कहा जाय।

सभापति महोदय : आप को और जो कुछ कहना हो वह कहें लेकिन गवर्नर के बारे में कुछ न कहें।

श्री केदार पास्वान : वहां पर पहले गवर्नर का शासन था इस लिये क्यों नहीं कहेंगे ?

सभापति महोदय : आप कह सकते हैं, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये।

श्री केदार पास्वान : आज आप देखिये कि इस देश में गरीबी की क्या हालत है। आज पुलिस को चोरी करनी पड़ती है। पुलिस की तनख्वाह आज 150 रु० है, लेकिन उस के बड़े अफसर की तन्ख्वाह बहुत ज्यादा है। आज देश में वेतनक्रम इस तरह से होना चाहिये कि 100 रु० से कम नहीं और 1,000 रु० से ज्यादा नहीं। आज हमारे देश में....

SHRI Y. B. CHAVAN : Sir, I think that remark about the Governor was uncalled for.

AN HON. MEMBER : Uncharitable.

SHRI Y. B. CHAVAN : He was making a very drastic allegation against the Governor who should not be discssed on the floor of the House. I request you to think about expunging those remarks.

SHRI MANUBHAI PATEL (Dabhoi) : He said**

It is unparliamentary and so it should be removed from the records.

SHRI Y. B. CHAVAN : He is a highly respected person in public life. He was a Member of this hon. House. He was a Minister here and he was Governor of another State. I think to make such lighthearted remarks about a respected person is not very good.

MR. CHAIRMAN : That word may be expunged from the records.

श्री केदार पास्वान : सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि आज इस देश में किसी आदमी के पास 2,000–4,000 बीघे जमीन है और किसी के पास थोड़ी भी जमीन नहीं है। इसलिये हमारी उपज बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि जमीन का सामान बटवारा कर दिया जाये। जैसे पहले एक आदमी के पास 40 बीघे से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिये ऐसा कानून पास किया गया था, उस को ही लागू कर दिया जाये। आज किसी के पास 500 बीघे है, किसी के पास 1,000 बीघे और किसी के पास 2,000 बीघे है, और नौकरी भी उसी के आदमी को मिलती है। इसलिये देश में बेकारी बढ़ रही है कि जमीन भी उसी आदमी के पास है और नौकरी भी उसी के आदमी के पास है। आज यह नियम कर दिया जाना चाहिये कि जिस आदमी के पास पांच एकड़ से ज्यादा जमीन

****Expunged as ordered by the Chair.**

[श्री केदार पास्वान]

होगी उस आदमी को सरकारी नौकरी चाहिये। इसी तरह से हमारे यहा बेकारी दूर हो सकती है।

महात्मा गांधी ने कहा था कि हम सब को रोजी रोटी देंगे और सब के घर में दीप जलायेंगे। लेकिन आज दीप जलने के बदले किसी के घर में भगजोगनी भी नहीं जलती। किसी को आज खाने को अनाज नहीं मिल रहा है और किसी के घर में अनाज सड़ता है। आज इस के लिये हमारे खाद्य मंत्री कोई इन्तजाम नहीं कर सके है।

DR. P. MANDAL (Vishnupur) : Sir, I thank you for giving me time to speak on the Home Ministry's demands. In my speech on the budget, I have spoken about cutting the expenditure on the departments. So, I request the Home Minister to curtail extravagant expenditure on administration. Thereby the additional taxation of Rs 150 crores will be minimised and there will be no deficit of Rs. 250 crores.

Police administration is there to help the people and give protection, but nowadays the police are only used for threatening. The police should be trained to help the public and make themselves friends by their cordial behaviour. If theft and burglary take place in rural areas, the people do not bring it to the notice of the police, because they know that they will get no help from the police. Rather they will be tortured and forced to supply foods etc. Border police are much-more corrupt. In the checkposts, corrupt practice is going on rampantly. The purpose for which the border police and other police are posted in checkposts is not served. Most of them are running behind corrupt practices. So, I request the Home Minister to look into this matter seriously. There is a proverb in Bengali.

"ये सरिशा दिये भुत ताड़ान हच्छे सेई सरिशार भितर भुत ढुके छे।"

Ghost is driven away by mustard, but ghost is within the mustard. So, nothing appreciable is coming out by the above arrangement, because the police is not serving national interest.

State-Centre relations should be cordial. There is a hue and cry in the press daily that the relation is not cordial. The States want more power. Proper thought should be given to this issue in the near future, so that non-Congress governments do not think that they are treated step-motherly. It is an urgent need of the day.

I come to welfare of backward classes. The weaker sections and scheduled castes and scheduled tribes are harassed too much nowadays. Several examples of torture have been discussed on the floor of the House. Yet, these tortures are coming in repetition. Proper attention should be given to this matter, so that such things may not happen in the near future and thereby the weaker sectinos feel secure and safe. *Satabdi* celebrations of the Father of the Nation are coming. He had devoted his whole life for the removal of torture of these weaker sections who have been down-trodden But no such programme has been taken up to solve even the acute problems. Water-supply and minimum land for housing are not yet available to these classes. Untouchability is still prevailing even in the birth place of Mahatma Gandhi, ie. Porbander in Gujarat. From the papers we come to know that Government is trying to do so many things for the welfare of these backward classes, but the Government is not interested in their implementation.

In Government service the percentage of reservation in paper or in advertisements is all right. But, in actual recruitment, they are served with letter of regret that they are technically unfit. This is the misfortune of the backward classes.

Recently there was a circular from the Home Ministry to all the Ministries that there will be reservation in class II and class I post for Scheduled Tribes and Castes on promotion. But several cases have come to notice where this circular is not strictly followed or adhered to. I have myself brought

several cases to the notice of the Social welfare Ministry for necessary action. It is specifically mentioned in the circular that if members of the Scheduled Castes or Tribes are not promoted in those reserved vacancies the reason for the same has to be reported to the Home Ministry. May I know whether the Home Minister has ever received any such papers from other Ministries ? There are several cases where members belonging to the Scheduled Castes and Tribes have been denied promotion even in reserved vacancies. If the Home Minister so desires, I am prepared to supply him the relevant papers for taking necessary action. If he does not show any interest in the implementation of this circular then the only conclusion will be that it is only an eye-wash on paper. So, I would request the Home Minister to post one Scheduled Caste or Tribe member in the UPSC, selection committees of the various Ministries for promotion, State Public Service Commissions and Railway Service Commissions to look after the interest of the backward classes; otherwise, these circulars will remain only on paper.

Then, there should be reservation for scheduled caste and scheduled tribe members in the various corporations, public sector undertakings, private industries, import and export business, transport etc. Otherwise, their economic condition cannot be improved.

Then, giving *khas* land to landless labour will not solve their problems. In addition to land, they should also be given monetary help so that the owner of the gift land may purchase bullocks and meet the expenditure for one harvesting season. Otherwise, the scheme will be a total failure. Because, the labourers earn their livelihood by daily labour. If they work in their own fields, from where will they get money for buying food until the harvesting season. So ? both land and monetary help have to be given, and that too as a grant and not as a loan. Then alone will the scheme be a success. So, I would request the Government to consider carefully the loopholes and defects in the scheme.

Then I come to the question of stipends to members of the backward classes. Pre-matric stipend is not given to all students beloging to the Scheduled Castes and Tribes in West Bengal. Then, even to those to whom it is given it is not given in time; it is very much delayed. The amount of post-matric stipend should be increased. I have received a letter from the Principal of Ramananda College, Bishnupur that he has not yet received stipends for the students even thought ten months have passed. As a result, the boys are not able to pay their dues to the college hostel and the Principal is in great difficulties. I would earnestly request the Minister to expedite the payment so that such difficulties may not arise in future. When there is an arrangement for advance payment of stipend to medical and technical students, I do not know why that facility may not be extended to arts and science students also. This advance money will be ajdusted in final payment this arrangement was there when disbursement was done from the Centre, but after giving the power of disbursement to the States, such difficulty is arising in West Bengal at least. I know it from the inception of the transfer. So, please do the needful so that the difficulty of students and the Principal may go immediately.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभापति जी, मैं अपने कुछ उन मित्रों से सर्वथा सहमत हूं, जिन्होंने कहा है कि भाषा के प्रश्न को लेकर देश में इस प्रकार के वातावरण का निर्माण नहीं करना चाहिए जिससे देश की एकता पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़े । परन्तु साथ ही साथ में यह बात भी गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश में जिस समय संविधान में राजभाषा का प्रश्न आया था और सर्वसम्मति से हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था उसी दिन से यदि अपेक्षित प्रयत्न प्रारम्भ से किये गये होते तो यह प्रश्न इतना न उलझाता । इस समय स्थिति इस प्रकार की है कि देश में सात राज्य ऐसे हैं जिन्होंने उसी भाषा के माध्यम से अपने प्रांत का काम करना शुरू किया है जिसको संविधान में राज भाषा माना गया है । लगभग चार-

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

पांच राज्य ऐसे हैं, जिनमें पंजाब, कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा शामिल है, जिन्होंने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है-अपनी प्रांतीय भाषाओं में अपने प्रांत का काम करते हुए। तो इस दृष्टि से जब इतने बड़े क्षेत्र ने राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार कर कर लिया है तो फिर गृह मन्त्रालय का निश्चित रूप से यह दायित्व हो जाता है कि उस के विकास के लिये अपेक्षित रूप से प्रयास प्रारम्भ करे। अभी गृह मन्त्रालय से जो प्रतिवेदन हमें मिला है, इसमें लिखा है कि अब तक लगभग 2 लाख 19 हजार कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मैं अगर भूल नहीं करता हूं तो ये 2 लाख 19 हजार कर्मचारी वे हैं जो हिन्दी भाषी राज्यों के निवासी नहीं है। केन्द्रीय सरकार की नौकरी में 24 लाख के लगभग कर्मचारी हैं, इन में से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निकाल दे तो इन की संख्या लगभग आधी-12 लाख के लगभग रह जाती है। दो लाख 19 हजार कर्मचारी वे हैं, जिनको विधिवत आपने हिन्दी का प्रशिक्षण दिया है और इन से लगभग दुगने वे हैं जो प्रारम्भ से ही हिन्दी जानते हैं। जब केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में आधे कर्मचारी वे हैं जो हिन्दी की परीक्षायें पास कर चुके हैं, जिनको हिन्दी का प्रशिक्षण देने पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है तो इस अनुपात से आधा काम राजभाषा में प्रारम्भ होना चाहिये था, लेकिन इस प्रतिवेदन को देखने से इस के सम्बन्ध में कोई जानकारी हम को नहीं मिली।

एक और सुझाव मैंने कुछ दिन पहले गृह मन्त्रालय को दिया था और कई बार इस सदन में उसकी चर्चा भी हुई है। जब आप हिन्दी को इस देश की प्रमुख राजभाषा के रूप में स्वीकार कर चुके है तो इस में आपको क्या आपत्ति है कि संसद में जितने अधिनियम या विधेयक आयें वह मूलपाठ के रूप में दोनों भाषाओं में आयें। गृह मन्त्री जी ने इस विषय में अपने मन्त्रालय के द्वारा कुछ अनुसंधान भी कराया था कि क्या दुनिया के किसी देश में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जहां अधिनियम या विधेयक दो भाषाओं में आते हैं सभापति जी ! कनाडा में इस प्रकार की स्थिति है, वहां दो भाषाओं में आ. हैं। जब वहां दो भाषाओं मे मूलपाठ आते हैं, तो उसी प्रकार की स्थिति हमें इस संसद में भी स्वीकार कर लेना चाहिये। जिस समय राजभाषा के रूप में सारे देश में हिन्दी चल पड़े, उस समय केवल हिन्दी में ही आयें। परन्तु जिस समय तक ऐसी स्थिति नहीं है, उस समय तक दोनों भाषाओं में प्राधिकृत पाठ के रूप में आयें, केवल अनुवाद के रूप में न आयें। इस समय राजभाषा विधायी आयोग के अन्तर्गत तमाम पुराने कानूनों का हिन्दी अनुवाद हो रहा है। लेकिन जो इस समय नये कानून पास हो रहे हैं वह अंग्रेजी में पास हो रहे हैं। उन का फिर से हिन्दी अनुवाद करके सरकारी गजट में प्रकाशित करना पड़ेगा, मैं चाहता हूं कि इस विपरीत परम्परा को प्रारम्भ न कर के, यदि अभी से ही उन का प्राधिकृत पाठ हिन्दी में भी आ जाय तो अधिक अच्छा होगा।

अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि हिन्दी का वह स्वरूप होना चाहिये, जिसे हिन्दुस्तानी कहते हैं। दक्षिण भारत के हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि हिन्दी का वह स्वरूप होना चाहिये जो संस्कृत के अधिक निकट है। दक्षिण के लोग उस हिन्दी को स्वीकार करते हैं जो संस्कृत के निकट है। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा हैदराबाद का उस हिन्दी को स्वीकार करता है जो उर्दू और फारसी के अधिक निकट है। मैं चाहता हूं कि भाषा के स्वरूप पर किसी प्रकार की खेंचतान नहीं होनी चाहिये। भाषा अपने स्वरूप को मंजते-मंजते अपने आप निर्धारित कर लेती

है। मैं तो उस हिन्दी को भी हिन्दी कहने के लिये तैयार हूं जिसमें कोई आदमी कहे–मैं संडे–मॉर्निंग को स्टार्ट हो रहा हूं। कम से कम मैं और हो रहा हूं तो उस में हिन्दी के हैं। आगे चल कर वह धीरे धीरे अपना स्वरूप स्वयं बना लेगी। मैं हिन्दी का इस प्रकार का कट्टर और कठमुल्ला समर्थक नहीं हूं जो हिन्दी के साथ उस के शब्दों और उस के स्वरूप के सम्बन्ध में कोई खेंचतान प्रारम्भ से ही करना चाहते हैं। शब्दों के साथ ज्यादा छेड़छाड़ न की जाय। भाषा को अपना स्वरूप स्वयं बनाने का अवसर दिया जाय।

दूसरी बात मैं कश्मीर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में गृह मंत्री जी को जानकारी है कि अभी कश्मीर की जो वर्तमान सरकार है, उस की दुर्बल नीति का लाभ उठा कर फिर कुछ घुसपैठिये काश्मीर राज्य के अन्दर आने प्रारम्भ हो गये हैं। यह जानकारी भी आपको है कि काश्मीर राज्य में कुछ इस प्रकार के कर्मचारी हैं जो पाकिस्तानी तत्वों का समय-समय पर समर्थन करते रहते हैं। उदाहरण के लिये श्रीनगर जेल से कुछ पाकिस्तानी कैदी भाग गये। हमारी सी० आइ० डी० श्रीनगर के आसपास चक्कर काटती रही। लेकिन वह सीधे पाकिस्तान चले गये और वहां जा कर उन्होंने समाचार दिया कि हम तो यहां पर आ गये हैं, क्यों तुम श्रीनगर के आसपास परेशान हो रहे हो।

शेख अब्दुल्ला ने नई विष-वमन की नीति अख्तियार की है और फिर से विषाक्तता लाने का प्रयास प्रारम्भ किया है। मैं चाहता हूं कि इस के लिये काश्मीर समस्या का कोई स्थायी समाधान होना चाहिये। मेरी अपनी दृष्टि में काश्मीर का स्थायी समाधान यह है कि काश्मीर को एक पृथक टुकड़े के रूप में न रखा जाय। मैं भारत सरकार की उस नीति का कट्टर विरोधी हूं कि चन्द लाख लोगों के अलग अलग प्रांत बना कर खड़े किये जायें और इस तरह से देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाय। विशेष कर सीमावर्ती राज्यों में, सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ लाख लोगों के प्रांत बनाने की प्रवृत्ति को मजबूती के साथ रोकना चाहिये। इस के लिये मेरा अपना सुझाव यह है जैसा अभी हमारे एक मित्र हिमाचल प्रदेश को बड़े व्यवस्थित शब्दों में एक स्वतन्त्र राज्य बनाने की कल्पना कर रहे थे, वह क्षमा करें, मेरा अपना विचार तो है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर और पंजाब-तीनों को मिलाकर एक मजबूत इकाई के रूप में सीमावर्ती सुदृढ़ राज्य का निर्माण किया जाय। यह बात दूसरी है कि जैसे महाराष्ट्र विधान सभा का अधिवेशन कभी बम्बई में होता है तो कभी नागपुर में होता है, उसी तरह से इन का अधिवेशन भी कभी शिमला में हो जाया करे, कभी श्रीनगर में हो जाया करे। इस से चण्डीगढ़ की समस्या का भी हल हो जायगा। हरियाणा वाले भी चण्डीगढ़ के लिये लड़ रहे हैं, उनको चण्डीगढ़ दे दीजिये। इधर उन को यह शिमला और श्रीनगर मिल जायगा। दोनों ही पहाड़ी स्थान हैं और ठण्डे प्रदेश हैं। इस लिये एक सीमावर्ती मजबूत राज्य की स्थापना वहां पर होनी चाहिये।

एक बात मैं केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। केन्द्र और राज्यों के सबध में विशेष रूप से–सभापति जी–मुझे कहने की आवश्यकता यों पड़ी कि मध्यावधि निर्वाचनों ने देश के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया है? अनुमान यह था कि पिछली संविद सरकारों का लाभ उठा कर इन राज्यों में फिर से कांग्रेस अपना स्थान बना लेगी। उत्तर प्रदेश में जैसे तैसे जोड़ तोड़कर कांग्रेस ने सत्ता अपने हाथ में ले ली है, नहीं कहा जा सकता, कब तक वह चल सकेगे? लेकिन बाकी राज्यों में परिणाम ज्यों का त्यों रहा। उन में अभी भी भिन्न भिन्न दलों की सरकारें बनी हैं। कभी राज्यपाल को लेकर, कभी रिजर्व पुलिस

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

को लेकर, कभी रेडियो को लेकर उनमें भी झगड़े शुरू हो गये हैं। अभी तो प्रारम्भ ही है, आगे चल कर इस की परिणति कहां होगी, कहा नही जा सकता ? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप जो जनतन्त्र में आस्था रखनेवाले दल है समय रहते उन का सम्मेलन बुलाइये और इन परिवर्तित परिस्थियों में देश के जनतंत्र की रक्षा कैसे करनी है, इस विषय में कुछ मजबूत निर्णय लें।

मुझे बडी प्रसन्नता हुई–भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष–श्री कामराज ने मद्रास के प्रांतीय कांग्रेस के अधिवेशन का उदघाटन करते हुए इस प्रकार का सुझाव दिया है कि बजाय इस के कि 1972 के बाद जब केन्द्र में कांग्रेस का बहुत बहुमत नहीं होगा, तब इस पर विचार हो, अभी समय रहते इस पर विचार किया जाय। 1970 में राज्य सभा में भी कांग्रेस का बहुमत समाप्त होने वाला है। उस के बाद यहां से विधेयक पास हो कर वहां जाया करेंगे और फिर वहां से यहां वापस आयेंगे। क्या आप रोज–रोज जवाइन्ट सैशन बुलाया करेंगे। आज मौका है कि आप इस समस्या पर विचार करें और इस का निदान ढूढें ताकि हमारे जनतन्त्र के लिये इस प्रकार कोई गंभीर समस्या पैदा न हो।

एक बात शांति और व्यवस्था के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं और विशेष रुप से अपने प्रदेश–उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। प्रधान मन्त्री जी को मैंने एक पत्र लिखा है, जिसकी प्रतिलिपि मैंने गृह मन्त्री जी को भी भेजी है। उस पत्र में मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने सत्ता सम्भालते ही किस तरह से राजनीतिक बदले लेने प्रारम्भ कर दिये हैं। वहां की विधान सभा के सदस्य इस प्रकार के पत्र लिख रहे हैं। पटियाली एटा जिले का एक निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से श्री तिरुमल सिंह ने मुझे पत्र लिखा है कि मेरे मारने के लिये, कत्ल करने के लिये कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। मेरे सहयोगियों पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह मेरठ जिले के जिस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं–आपको जानकर आश्चर्य होगा–300 व्यक्तियों के खिलाफ़ वहां पर रिपोर्टें दर्ज हैं। उन 300 व्यक्तियों मे एक हमारे संसद के सदस्य श्री रघुवीर सिंह शास्त्री की धर्मपत्नी का का नाम है। उन का अपराध यह था कि वह बेचारी निर्वाचन के दिन अपना मत देने के लिये अपने गांव चली गई और सायंकाल अपने पति के साथ लौट कर चली आई। इस प्रवृत्ति से क्या राज्य में शान्ति और व्यवस्था कायम रह सकेगी। मैं इस बात का भी समर्थन नहीं करता कि मुजफ्फरनगर में जिस कांग्रेसी प्रत्याशी की हत्या हुई थी-उस को अच्छा कहूं। यह मेर स्वभाव के विपरीत है। लेकिन तथ्यों की तह में जाना चाहिये।

मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश में जितनी इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं–अभी गोरखपुर के अन्दर भारतीय क्रांति दल के दो कार्यकर्ताओं की हत्या एलेक्शन के बाद में हुई है। उसके सम्बन्ध में आप एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण की नियुक्ति करें जो कि इन सारी घटनाओं की तह में जा सके। राजनीतिक बदले की भावना से यदि इस प्रकार की प्रवृत्तियां प्रारम्भ हो गई और जनता ने शांति और व्यवस्था का अधिकार अपने हाथों में ही ले लिया तो मेरा अनुमान है कि प्रांतीय सरकार को भी कठिनाई पड़ेगी और केन्द्रीय सरकार को भी कठिनाई पड़ेगी। आज इस बात को मिल कर सोचने की बड़ी आवश्यकता है।

एक बात मैं राज्यों के पारस्परिक झगडों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार की कुछ ऐसी नीति बनती चली जा रही है कि इस प्रकार के विषयों को टालो, टालो,

टालो, शायद अपने आप भूल जायेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि वे और अधिक उग्र रूप में सामने आयेंगे। आज आप जो मैसूर-महाराष्ट्र का विवाद है उसको देख लीजिए, कृष्णा-गोदावरी विवाद को देख लीजिए, नर्मदा के विवाद को देख लीजिए या चंडीगढ़ विवाद को देख लीजिए। ऐसे सारे प्रश्नों को आप टालना चाहते हैं और यह समझते हैं कि लोग उनको भूल जायेंगे या उनके मस्तिष्कों की उग्रता समाप्त हो जायेगी। परन्तु मैं समझता हूं आप उनके मस्तिष्क की उग्रता को और प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसलिए वीरता के साथ, बहादुरी के साथ आप इन प्रश्नों का समाधान कीजिए, उनका कोई न कोई हल ढूंढिये।

श्री स० मो० बनर्जी : एक विवाद और है-चन्द्रशेखर और मोरारजी का झगड़ा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : वह उनका घरेलू झगड़ा है।

तो इन तमाम बातों को लेकर उनका समाधान कीजिए। इस प्रकार से इन समस्याओं को टालने की जो प्रवृत्ति है वह कोई समझदारी की बात नहीं है। उनका कोई न कोई हल आपको अवश्य ढूंढना चाहिए।

स्वतंत्र पार्टी के एक हमारे मित्र श्री लोबो प्रभू जिन्होंने गृह मन्त्रालय की अनुदानों पर चर्चा प्रारम्भ की थी, उन्होंने एक बात कही जिससे मुझे थोड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि इस देश में बहु-संख्यकों को अल्प-संख्यकों पर अविश्वास करने की आदत सी होती जा रही है। मैं नहीं समझता उन्होंने यह बात किस आधार पर कही ? उन लोगों पर तो निश्चित रूप से अविश्वास है जो रहते तो यहां हैं, खाते-पीते तो यहां हैं, हवाओं में यहां की सांस लेते हैं लेकिन हित की कल्पना करांची की करते हैं या पीकिंग की करते हैं। उन लोगों पर निश्चित रूप से अविश्वास है। भारत में अराष्ट्रीय कार्य करनेवाले कुछ विदेशी क्रिश्चियन मिशनरीज, जिनमें पादरी फेरर हों या कोई और हों, उनकी आलोचना तो होती है परन्तु क्या कभी आपने देखा कि भारत के अल्पसंख्यक पारसियों की भारत के किसी कोने में आलोचना हुई हो ? कारण यह है कि उन्होंने इस देश के राष्ट्रीय जीवन में अपने को इतना आत्मसात कर लिया है कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई पैदा ही नहीं होती। आलोचना तो केवल उनकी होती है जो कि यहां पर हमारी राष्ट्रीयता को धर्म प्रचार की आड़ में चुनौती देते हैं। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 1968 के अन्त में हमारे देश में 6,393 विदेशी इसाई प्रचारक हैं। गांधी जी ने लिखा था कि जो विदेशों से मिशनरी यहां पर आकर काम करते हैं उनकी सेवा उसी प्रकार की है जैसे मछली पकड़ने वाला कांटे के अगले हिस्से में आटा लगाकर तालाब में डालता है। उस में उसका उद्देश्य मछली का पेट भरना नहीं होता है बल्कि उसके पीछे उसका उद्देश्य कुछ और ही होता है। तो इस प्रकार से जो लोग धर्म परिवर्तन की आड़ में राष्ट्रीयता में भी परिवर्तन करना चाहते हैं, मेरा कहना है कि उन व्यक्तियों को यहां से हटाना चाहिए। विदेशी धर्म प्रचारकों के स्थान पर, जबकि भारत में ही इसाइयों की इतनी संख्या है, उन्हीं में से आप उन धर्म प्रचारकों की पूर्ति क्यों नहीं करते हैं ? विदेशी प्रचारकों में ही ऐसे कौन से लाल लगे हैं कि उन्हीं को बुलाकर आप प्रचार करना चाहते हैं।

अन्त में दो एक बातें विशेष रूप से और कहना चाहता हूं। एक बात कहूंगा मद्यनिषेध के सम्बन्ध में। यह गांधी शताब्दी का वर्ष है। इस वर्ष में सन 64 की टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट पर आपने निर्णय लेना है। मेरा कहना है कि या तो आप हिम्मत से कह दीजिए कि गांधी जी ने जो हमको तीन काम दिये थे, खादी का, मद्यनिषेध का और हिन्दी की प्रगति

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

का, उनके आदर्शों से हम हट रहे हैं। ताकि देश जान तो ले कि आप कहां खड़े हुए हैं। एक ओर तो आप गांधीजी का नाम लेते हैं और दूसरी ओर गांधीजी के आदर्शों की हत्या कर रहे हैं। याद रखिए, 1969 के इस वर्ष में जोकि गांधी शताब्दी का वर्ष है, यदि आपने मद्यनिषेध के सम्बन्ध में किसी प्रकार से अपनी निश्चित नीति की घोषणा नहीं की, जिसको सविधान में भी आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं। उसके लिये भले ही आप गांधीजी की जय के नारे लगाते रहें परन्तु निश्चित रूप से देश यही कहेगा कि आप गांधीजी का नाम तो लेते हैं लेकिन गांधीजी के कामों से बहुत दूर जा चुके हैं। इसलिए इन समस्याओं पर आपको विचार करना चाहिए।

अन्त में एक बात और कहकर समाप्त करूंगा। मेरे पास लगभग 14 केसेज इस प्रकार के हैं जिनमें सघ लोक सेवा आयोग ने अवैध रूप से नियुक्तियां की हैं। उन केसेज को मैं निजी रूप से गृह मन्त्री के पास भेजूंगा। मेरा कहना यह है कि संघ लोक सेवा आयोग की निष्पक्ष निर्णय की प्रवृत्ति होनी चाहिए। उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। उसकी पवित्रता बराबर बनी रहे, इस दिशा में भी आपको प्रयत्नशील रहना चाहिए।

SHRIMATI ILA PALCHOUDHARI (Krishnagar): I thank you Sir, for giving me time to participate in this discussion.

The Home Ministry's demands for grants are being discussed today in a shaow. What is happening in West Bengal today and viciates the atmosphere there, I do not suppose, reaches Delhi,

I am very happy that the Ministry has increased the grants under the Central Reserve Police, under the Border Security Forces and also under the Central Industrial Security Force which has been newly created. I congratulate the Home Minister. This was entirely necessary. What is happening to the people in West Bengal can be realised when I say that when the students go and break up the B. Sc. examination, the Police stand by. When squatters go and occupy the banks of the canals of the irrigation works, the Police simply stand by. When people are threatened to leave their houses within twenty four hours or be killed, the Police stand by. "We are very sorry", they say, "but we can do nothing." What is the attitude of the Government over there ? We say that the State-Centre relations should be cordial. How can it be cordial when things like this are said at public meetings ? I will quote one or two choice bits for the knowledge of the House. In public meeting, Shri Jyoti Basu has said the other day that "the movement in Pakistan is welcome and the people of Bengal should join hands with them." Secondly the joint convener of the United Front Shri Sudhin Kumar said "We have conquered Bengal, we will soon conquer Delhi." Thirdly, Shri Narain Das of the SSP said, "Our next move would be to overthrow the present Central Government in Delhi."

SHRI GEORGE FERNANDES : What is wrong with that ? (*Interruptions*).

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : When these "sort of things are said, it is time that all forces that lead to peace for the people should be strengthend. My submisson is that the police force must be under independent control, and not under political control. They must protect; and maintain, law and order. The Central Reserve Police should on no account be withdrawn from West Bengal.

I have brought to the notice of the Chief Minister of West Bengal 35 cases of murders and arson having taken place and all the answer that I have got from him is "I am asking the appropriate authorities to examine these cases". That is all ! (*Intrruptions*) When it is an acute case of people getting killed, the "appropriate authority" should have examined them and taken some decision by this time.

SHRI S. M. JOSHI (Poona) : All these cases occurred when you were in power.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHARI : No, after you and the U. F. Government came to Power. I have cited 35 cases of murder and arson, there are many more.

AN HON MEMBER : It should open your eyes.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHRUI : Yes it is true, it should open their eyes. While the Government are looking into it, many more people are getting Killed !

One point I would like to bring to the notice of the Home Minister. (*Interruption*). You have your own time. You can contradict me later if you can, but I will give you the facts. I would just like to bring to the notice of the Minister that I come from a border area. What is happening in Pakistan and what is the attitude of the Government there ? The borders must really be secure and I would request that the Border Security Forces may be strengthened still further without any delay. Sir, already Pakistan flags are being distributed in the border areas, though some of these have, I am glad to say, been burnt, and not accepted ! When you make the Border Security Forces stronger.which you must do, please look to the border roads because the Border Security Forces in Nadia have told me that should anything happen, some of the border roads are so impassable that they cannot be used effectively if there is even a slight shower of rain. Both Pakistan and China have all weather roads to the borders of India. We need all-weather roads wherever we have our border with China and Pakistan.

Secondly I wish to bring to the notice of the Minister a vital problem. There are minority communities in my area living on the borders. They are honest and loyal citizens of India. They have asked for India citizenship. It has gone through vicissitudes because citizenship has some technical difficultes. There may be some difficulties–I do not know. However, they should feel secure, they should feel secure to live in India and there should not be any harassment and if they ask for citizenship, that should be granted without any delay. I would appeal to the hon. Minister that when I bring specific cases, I hope he will kindly look into them, and see that citizenships asked for are given we want the minority Community, the Muslims, to feel secure, with every right as Indian citizens safe guarded for them, Then, Sir, I want to say that the U. F. Government has made a very funny suggestion, the other day. The subject of corruption is being talked about so much from the opposition benches.

18 hrs.

But what have the UF Government in West Bengal said about it ? About Anti-corruption tribunal, it is stated that there was a controversy over the matter and at the UF sitting held on Sutarday they said that they wanted to take a lot of time to consider the setting up of such an anti-corruption tribunal. In contrast to that, what has our Government done in the Centre ? The Central Bureau of Investigations, I must say, must be congratulated. Because. Sir, they have gone into cases of corruption. Upto date they have got 50 Government servants, including 2 gazetted officers and 57 private persons, convicted and Rs. 1,24,302 has been levied as fines. On top of that, there are departmental punishments, in 238 cases, There were 297 public servants including 49 gazetted officers who were punished, as they deserved. That shows the attitude of the congress Government and of the U. F. Government. The U. F. Government would wish to take a lot of time to consider the matter of eradicating corruption, while the Congress Government at the centre has taken action.

Next, I would like to bring to the Home Minister's notice the accumulation of cases in the courts. It is really a hard thing for the public. Government have given some statistics in answer to my question and certain information has been furnished on the Floor of the House I would like to bring to the Minister's notice that there are 3,56,831 cases pending in the courts and in the Calcutta High Court 61,541 cases are pending. This is a very great hardship if cases are not disposed of quickly. Mr, Justic J. C. Shah, the Judge of the Supreme Court of India has made a remark that the whole judicial system would break down unless the

[Shrimati Ila Palchoudhrui]

cases are disposed of quickly. I hope the hon Home Minister will find some way of doing it. A good number of the cases are incometax cases and I would like to bring to the notice of the House that income-tax arrears as on 1st April 1968 stood at Rs. 374.52 crores and this includes, Rs.79 61 crores as arrears out of demand made during 1967-68. If all these arrears are collected most of our fiancial difficulties would be over. Justice should be dispensed quickly. Sir, justice delayed is justice denied.

AN HON. MEMBER : As it is in U. F. Government in Bengal.

SHRIMHTI ILA PALCHUDHURI Yes I agree with that. Next I would like to make a point regarding the freedom fighters who have given their lives for the country. Now, they get a certain pension. These pensions are very paltry sums. I think most of them get Rs. 30 or even less. We have our freedom fighters who have been disabled, some of them are blind; some of them are living in utter poverty. They have given their all for India, I know of a number of persons whose pensions are going to end in June or July, If the Government Servant1969. gets a pension for life, should not a freedom-fighter get his pension as long as he lives ? I hope this will be done.

And, lastly, Sir, about the cellular jail in the Andamans. This has remained in the memory of the people for a long time. I would appeal to the Home Minister that the cellular jail in the Andamans should be treated as a national monument because there, the future generations could go and get new inspiration. For the love of India, men have been sent there who have given their lives. The cell of Vir Savarkar is preserved there. The cell where Beren Ghose, the great revolutionery of Bengal lived is also there. There are variours freedom-fighters from Bengal and India, who have suffered sentences in the cellular jail. Their names should be written in letters of gold on stone and not on a black-board with white paint, as has been done.

Let this be declared as a national monument, Let the Home Minister himself take this matter up because many people have given their lives and served their sentences in that Cellular Jail and therefore let that not be demolished, but on the other hand let in remain as a beacon of fire to inspire others, Our leaders have suffered for India, for these who did, They consider death as the carrying on of the torch of freedom, those who were sent to that jail, have given the fire of their heart there, I hope the Cellular jail will be named as a national monument and will be preserved and not demolished, Hospitals, Sir, can be bulit anywhere else. I heard that the Cellular Jail in going to be made into a hospital. I strongly oppose this idea. Let it remain as a monument with the names of the people who served their sentences there and served India in the process, a place of pride and a place of pilgrimage for all Indians, I warmly support the grants.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : सभापति महोदय, आज मैं एक ऐसे आन्दोलन की ओर संकेत करना चाहती हूं जो आंध्र प्रदेश में चल रहा है, परन्तु उस की गूंज भारत के कोने कोने में पहुंच रही है, और भारत की एकता को चुनौती दे रही है ।

इस आन्दोलन का आज का स्वरूप भी कुछ ऐसा विलक्षण है कि सरकार तथा जनता को इस पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये । जैसा हम सब जानते हैं, तेलंगाना एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है और उस की उन्नति के लिये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । यह आवश्यकता मुद्दत से रही है और आगे भी मुद्दत तक रहने वाली है ।

राजनीतिक तथा आर्थिक विकास क्रम में मौलिक अन्तर यही है कि राजनीतिक परिवर्तन एकाएक हो सकते हैं, जो देश आज परतन्त्र है, कुछ ही दिनों में स्वतन्त्र हो सकता है, यदि इस के लिये अनुकूल परिस्थिति एकाएक उत्पन्न हो जाये तो सरकारें देखते देखते बनती हैं और समाप्त भी हो जाती हैं । नेताओं का उत्थान और पतन, साम्राज्यों का निर्माण

और पतन, साम्राज्यों का निर्माण और विघटन—ऐसी कई घटनायें बड़ी क्षिप्र गति से घट सकती हैं और घट रही हैं। परन्तु आर्थिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आते हैं वे बहुधा दीर्घ-कालीन ही हुआ करते हैं। दशक ही नहीं शताब्दियों के बीतने पर भी किसी समय जनता की आंखों को चकाचौंध करने वाला आर्थिक विकास एकाएक नहीं हो सकता। आर्थिक प्रगति किसी भी देश मे क्रमिक ही हो सकती है। ऐसा होना अनिवार्य है।

तेलंगाना प्रान्त का इतिहास सामन्तशाही शोषण का रहा है। आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से यह प्रान्त सदियों से पिछड़ा हुआ रहता आया है। निजामशाही में जो भी प्रगति हुई वह इतनी थोड़ी और अपर्याप्त रही कि जन-साधारण ने किसी विशेष लाभ का अनुभव ही नहीं किया। निजामशाही के अन्त होने के उपरान्त सन्धिकाल की समस्याओं की इतनी भरमार रही कि जनता की सरकार को जमकर आर्थिक प्रगति के कार्यक्रमों को तेजी और लगन से आगे बढ़ाने का अवसर ही नहीं मिला। इतने में भाषावार राज्यों की रचना की मांग आई और तदनुसार विशाल आन्ध्रप्रदेश बना और तेलुगू बोलने वाली चार करोड़ जनता जो कई राज्यों बिखरी हुई थी, उस का अधिकांश एक राज्य शासन में आ गया। समूचे आन्ध्रप्रदेश की उन्नति और विकास का इतिहास प्रारम्भ हुआ।

आन्ध्र प्रदेश के बनते समय आन्ध्र और तेलंगाना प्रान्तों की आर्थिक तथा अन्य बातों में असमानता के बारे में काफी सोच विचार किया गया था और उसी के परिणामस्वरूप एक समझौता बना जो जेन्टुलमैन्स ऐग्रीमेंट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समझौते में तेलंगाना प्रान्त को कुछ विशेष सुविधायें दी गई थीं और आन्ध्र प्रदेश सरकार को उन्हें कार्यान्वित करने का आदेश दिया गया था। इस समझौते को एक मुख्य बात यह थी कि तेलंगाना प्रान्त की नान-गजेटिड मुलाजमतों पर उसी प्रान्त के निवासियों की नियुक्ति की जायेगी। साथ ही उस में यह भी था कि तेलंगाना प्रान्त से सरकार की जो आय होगी, वह सारी उसी प्रान्त पर खर्च की जायेगी। इसके साथ साथ तेलंगाना के लिये उस प्रान्त मे चुने गये विधायकों की एक प्रान्तीय समिति भी बनाने का सुझाव हुआ और आगे चल कर ऐसी प्रान्तीय समिति बनी भी थी।

इस समझौते के आधार पर यह आशा की गई थी कि दोनों प्रान्तों की प्रगति और आपसी मेलजोल बढ़ता जायेगा और भावनात्मक एकता दृढ़ होगी।

आंध्र प्रदेश उन इने गिने राज्यों में से एक है जहां शान्ति और स्थिरता का कई वर्षों से दौर दौरा रहा है। राज्य अमन और प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। राज्य के सभी प्रान्तों के बीच भावनात्मक एकता मजबूत होती गई और राज्य के सारे लोग बड़ी हद तक आपस में घुल मिल कर रह रहे थे। परन्तु आज बारह बरस के बाद दुर्दैव से हम आंध्र प्रदेश का कुछ और ही चित्र पाते हैं। अचानक प्रान्तीयता की भावना उमड़ पड़ी है और कई जगहों पर हिंसात्मक वारदातें हुई हैं। जो घाव हरा हुआ है उसके कारणों की छानबीन करना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा नहीं किया गया तो भय इस बात का है कि आंध्र प्रदेश के दोनों प्रान्तों का वैमनस्य बढ़ता ही जायेगा और समूचे राज्य की प्रगति में कई प्रकार के विघ्न आ पड़ेंगे।

मैं अभी कह चुकी हूं कि 1956 में किये गये समझौते की एक शर्त यह थी कि तेलंगाना प्रान्त की नान-गजेटिड मुलाजमतें उसी प्रान्त को दी जानी चाहियें। आज दस बारह साल के बाद यह पाया गया कि एक हद तक इस शर्त का उल्लंघन हुआ है और कोई दो तीन हजार तेलंगाना प्रान्त की मुलाजमतों पर आंध्र प्रान्त के लोगों की नियुक्ति हुई है। सारे

[श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा]

प्रान्त की दृष्टि से यह संख्या बहुत अधिक तो नहीं कही जा सकती तथापि समझौते की खिलाफवर्जी की दृष्टि से काफी गम्भीर है।

इसके अलावा आज देश भर में और विशेष कर आंध्र प्रदेश में उद्योगों के अभाव में जो बेरोजगारी फैली है उस पृष्ठभूमि में यह समस्या अत्यन्त असन्तोषजनक हो गई है जो मेरी राय में बड़ी हद तक स्वाभाविक है।

अब मैं समझौते की दूसरी शर्त पर आती हूं। वह यह थी कि तेलंगाना प्रान्त में जो राजस्व वसूल होगा उसे वहीं खर्च किया जायेगा। दुर्भाग्य से इस शर्त का भी उल्लंघन होता आया है जो अवश्य शोचनीय है। प्रान्त प्रान्त के बीच जो आर्थिक असन्तुलन है उसे निकाल देने के लिये पिछड़े हुये प्रान्तों पर विशेष ध्यान देना चाहिये, यह बात सभी को मान्य है। परन्तु प्रत्यक्ष में ऐसा बहुत कम हुआ करता है। कई कारणों और दबावों के परिणामस्वरूप जिस प्रान्त में प्रगति पहले ही हो चुकी होती है उसी प्रान्त में आगे भी अधिक सुगमता से प्रगति हो जाती है। जो प्रान्त पहले से पिछड़ा हुआ होता है वह साधारणतया पिछड़ा हुआ ही रह जाता है। यदि इस परिणाम को रोकना हो तो राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक तीनों स्तरों पर अटल निर्णय लेने होंगे और ईमानदारी से उन्हें कार्यान्वित करना होगा। अनुभव बताता है कि यह कोई आसान काम नहीं है। तथापि आज की स्थिति में यही प्रयत्न करना अनिवार्य है। कोई और विकल्प हमारे सामने नहीं है।

तेलंगाना प्रान्त से जो राजस्व प्राप्त होता रहा, उस का कुछ भाग अन्य प्रान्तों में खर्च किया गया और उस हद तक तेलंगाना की प्रगति कम हो गई, यह बात अब स्पष्ट हो गई है। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि पिछले बारह बरस में तेलंगाना प्रान्त में जो कुछ प्रगति हुई है वह कोई कम नहीं है। लेकिन इस के बावजूद भी यह प्रान्त आज तक पिछड़ा हुआ है और इसी लिये यहां के लोग सोचते हैं कि कम से कम इस प्रान्त में वसूल होने वाली आय यहां खर्च की जाती तो प्रगति अधिक होती। उन का ऐसा सोचना भी स्वाभाविक है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि तेलंगाना प्रान्त का राजस्व जितना आज तक खर्च नहीं हुआ है, उसे चौथी पंचवर्षीय योजना काल में खर्च किया जायगा। यह निर्णय उचित है। परन्तु निर्णयमात्र से जनता का सन्तोष नहीं होगा। इस के लिये एक ऐसा कार्यक्रम बनना चाहिये जिस के अनुसार प्रत्येक वर्ष में इस बात पर कड़ी नजर रखी जायगी कि तेलंगाना प्रान्त की प्रगति के लिये जो रकम रखी जाती है, वह अवश्य इसी प्रान्त में खर्च हो और उसी वर्ष में हो। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है और मैं आशा करती हूं कि वह व्यवस्था सफल होगी।

सभापति महोदय, यह जो समझौता हुआ है, इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। यह समझौता शर्तिया नहीं था और न ही वह सर्वकालीन था। एक पिछड़े हुये प्रान्त की प्रगति को शीघ्रतर करने का ही इस समझौते का उद्देश्य था। तेलंगाना में जो असन्तोष पैदा हुआ है, उन त्रुटियों को सुधारने की तुरन्त चेष्टा की जाय और उसे राजनीतिक नारेबाजी से अलग रखा जाय। दरअसल इस मामले में राजनीतिक नारों की कोई गुंजायश ही नहीं है। यह एक आर्थिक समस्या है, पिछड़ेपन की समस्या है, रोजगार की समस्या है, विकास की समस्या है। इस का राज्य रचना या पुनर्रचना से कोई सम्बन्ध नहीं है और ऐसा सम्बन्ध करने की चेष्टा व्यर्थ है, अर्थहीन है। अलगाव की प्रवृत्ति आज देश में यत्र-तत्र बढ़ रही है, इस का हम सब को भान है। इस लिये यह प्रश्न अकेला तेलंगाना का नहीं है, इस बात का भी

हमें पूरा पूरा भान होना चाहिये । यह प्रश्न है सारे भारत का, भारत की एकता का । भारत में 16 या 17 राज्य हों या 50 या 60 राज्य बना कर भी और अधिक की मांग सदा के लिये बनी रहेगी तथा प्रान्तीयता और उपप्रान्तीयता का विष देश को छिन्न-भिन्न कर देगा । स्पष्ट है कि कोई भी देश का हितचिन्तक इन खतरनाक प्रवृत्तियों को सहन नहीं करेगा । मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि इन प्रवृत्तियों को उभरने न दें और उन समस्याओं को हल करने की चेष्टा करें जिन के कारण ये प्रवृत्तियां पैदा होती हैं ।

देश भर में कई ऐसे प्रान्त और इलाके हैं जो और इलाकों से बहुत पिछड़े हुये हैं । कोई भी राज्य ऐसे इलाकों से खाली नहीं है और न ही रह सकता है । राज्यों की रचना चाहे जैसे की जाय, परन्तु यह स्थिति बनी रहेगी । इस लिये पिछड़े इलाकों के भी अलग राज्य नहीं बन सकते और न विकास प्राप्त इलाकों के ही बन सकते हैं । ऐसी मांग एक दम फिजूल है, हानिकर है । होना यह चाहिये कि योजना कमीशन ऐसे पिछड़े हुये इलाकों की स्थिति की पूरी छानबीन करे और उन के पर्याप्त और समयबद्ध विकास के लिये विशेष योजना बना कर राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित कराये । इस योजना के लिये पैसा अलग रखा जाना चाहिये और उस का किसी और काम में उपयोग करने की पाबन्दी होनी चाहिये ।

इस प्रकार की विशेष योजना 10–12 वर्ष पहले की जाती तो आज देश में जो आर्थिक विषमता बढ़ती हुई मात्रा में पाई जाती है, उस की रोकथाम हो जाती, पर ऐसा नहीं किया गया । मैं मानती हूँ कि अब इस मामले में विलम्ब नहीं होना चाहिये ।

आन्ध्र प्रदेश उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम कर रहा है । इस दृष्टि से आन्ध्र प्रदेश का अपना विशेष महत्व है । भारत के भावनात्मक एकीकरण में आन्ध्र प्रदेश सदैव प्रयत्नशील है और रहेगा । इस एकीकरण को आगे बढ़ाने के सब प्रयास करने होंगे । मेरा विश्वास है कि हाल में जो अवांछनीय वातावरण आन्ध्र प्रदेश में उत्पन्न हुआ है, उस से तुरन्त ही मुक्ति मिलेगी और राज्य की प्रगति यथा सम्भव शीघ्रतिशीघ्र आगे बढ़ेगी ।

धन्यवाद ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमैन महोदय, सबसे पहले मैं होम मिनिस्टर साहब का न सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूं बल्कि उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ । आसाम के इतने बिगड़े हुये मसले को उन्होंने इतनी खुश अस्लूबी से, इतने शानदार तरीके से, सारी पार्टीज को साथ लेकर जिस तरह से उन्होंने सुलझाया, पहले तो इस बात पर मैं होम मिनिस्टर साहब की तारीफ करता हूं । दूसरी बात यह कि जो नागालैंड का बिगड़ा हुआ मसला था जोकि बीस साल से बस में नहीं आता था, न मिलिट्री के बस में, न लोकल गवर्नमेंट के बस में, न पार्टीज के बस में, वहां पर जो तब्दीली आई है, वहां की पापुलेशन और वहां के अनासिर का अमन की तरफ जो रुझान हुआ है उसके लिये जहां सारी सरकार जिम्मेदार है इतना अच्छा माहौल लाने के लिये उसमें ज्यादा जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की है । इस बात के लिये भी मैं होम मिनिस्टर साहब को मुबारिकबाद देता हूं ।

तीसरी बात यह कि कश्मीर के मसले पर शेख अब्दुल्ला साहब जो अकड़े फिरते थे, बात ही नहीं करते थे, इनसान को इनसान नहीं समझते थे, उनका जो दिमाग सही हुआ है और वहां पर पहले के मुकाबले में जो अमन का माहौल कायम हुआ है और साथ ही साथ वहां पर जो विदेशी अनासर और कुछ वहीं की फिरकापरस्त ताकतें काम करती थीं उसके मुताल्लिक जो हालात सुधरे, उसमें ज्यादा हिस्सा होम मिनिस्ट्री का ही है । इसके लिये भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूं ।

[श्री रणधीर सिंह]

इससे भी जरूरी एक बात और है। इस देश की 9 स्टेट्स में इस गवर्नमेंट और कांग्रेस की मुखालिफत थी, उनमें से चार पांच स्टेट्स में निहायत पुर-अमन हालात में एलेक्शन्स हुये हैं, चाहे एलेक्शन कमीशन की मार्फत या गवर्नमेंट की मार्फत, वहां पर फ्री ऐन्ड फेयर एलेक्शन्स कराये गये है। मेरे भाई कोई भी बात कहें लेकिन अब इनके पास कोई जबाव नहीं है। इसके लिये भी मैं होम मिनिस्टर साहब को मुबारिकबाद देता हूं।

इससे भी बड़ी एक मुबारिकबाद और है। इस देश का जो उलझा हुआ जबान का मसला था जोकि पंडित जी के जमाने में भी सुलझाने में नहीं आता था, लैंग्वेज बिल जोकि बहुत कन्ट्रोवर्शल बिल था, लेकिन हमारे होम मिनिस्टर ने जिस तरह से तमाम पार्टीज को साथ लेकर, इस देश के सबसे बड़े जबान के मसले पर जो कुछ थोड़ा बहुत किया है-हालांकि कुछ थोड़े बहुत झगड़े हुये हों, कुछ नारे बुलन्द हुये हों, कुछ जगह आग भी लगी हो, रेलें भी जलाई गई हों- इसके लिए भी मैं होम मिनिस्ट्री को मुबारिकबाद देता हूं।

इससे भी ज्यादा जरूरी बात एक और है। सेन्टर और स्टेट्स की जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुकात है, हमारे भाई कुछ भी कहें वेस्ट बंगाल के हमारे यूनाइटेड फ्रन्ट के भाई कुछ भी कहें या केरल वाले भाई कुछ भी कहते फिरें लेकिन जिस जब्त के साथ, जिस काबिलियत के साथ, जिस शराफत के साथ और जिस अक्लमन्दी के साथ सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने उन के साथ व्यवहार किया है, उन को फ्री ऐक्सेस दी है और जिस तरीके से हिन्दुस्तान में सेन्टर और स्टेट रिलेशनशिप के बारे में होम मिनिटर साहब ने रोल अदा किया है वह सराहनीय है।

इस से भी ज्यादा जरूरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट कमिशनर की जो रिपोर्ट आयी है अनुसूचित और जनजातियों के बारे में और उस के लिये पार्लियामेंट के मैम्बर्स की जो एक वाच डौग कमेटी बनी है, उस के लिये भी मैं मंत्री महादय को बधाई देता हूं। और चाहूंगा कि जो गरीब तबके के लोगों और हरिजनों की 1948 से ले कर आज तक बाहर और अन्दर की सर्विसेज में जो कमी हैं, जो उन का डिजायर्ड रिप्रेजेन्टेशन नहीं है, वह कमी दूर की जाय, उन की शिकायतें दूर की जायें। और जो कमेटी मुकर्रर की है होम मिनिस्टर साहब ने उस के लिये भी मैं उन को मुबारकबाद देता हूं।

मुबारकबाद तो दे ली, अब में कुछ बात भी कहना चाहूंगा। एक बात तो यह कहना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब बड़े नरम दिल हैं, सूझ बूझ के मालिक हैं, दिल्ली पुलिस में हरियाणे के नौजवानों के, करीब हजार, बारह सौ जवानों के केसेज अभी भी पैंडिंग हैं। जब आप डिफेंस मिनिस्टर थे आप के हुक्म पर इस इलाके के लोग जान देते थे, और आज भी देते हैं, हम चीन और पाकिस्तान का मुंह लम्बा बना देंगे आपके हुक्म पर, इन लोगों के हजारों की तादाद में केसेज चल रहे हैं। मैं समझता हूं मेरी बात का असर जरूर होगा, आप की मजबूरियां हैं, लेकिन मैं बारबार प्लीड करूंगा कि उन केसेज पर आप फिर से गौर करें, हमदर्दाना गौर करें और हजारों कुनबे जो बेरोजगारी का शिकार होते जा रहे हैं उन की तरफ ख्याल करें।

दूसरी बात यह कहना चाहता है, पिछली दफा भी कहा था, मेरे पास अब भी शिकायत आयी है, मुझे मालूम है कि आप की हमदर्दी है, और आप नहीं चाहते कि किसी के साथ बेइन्साफी हों, क्या वजह हैं कि रोहतक और हरियाणा के जोपुलिस में लड़के भरती किये जाते हैं, हजार, बारह सौ जो भी भरती किये जाते हैं, ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा के पांच, सात या

दस लड़के ही लिये जाते हैं? और मैं चाहूँगा कि आप उन अफसरान की गर्दन पकड़ें जो जय जवान और जय किसान इलाके के लड़कों को नहीं ले रहे हैं। जो बेहतरीन जवान आप को मिल रहे हैं, जो पाकिस्तान और चीन के मुकाबले में सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिये तैयार हैं उन को यहां दिल्ली पुलिस में नहीं लिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि यहां की पुलिस में सब जगह के लड़के आयें, बेस्टर्न यू० पी० के भी आयें, लेकिन इस राजधानी की हिफाजत के लिये, यहां की सेवा करने के लिये, आप की सेवा करने के लिये उन लड़कों को क्यों सर्विसेज से डिसाइव किया जाय ? मैं चाहूंगा कि आप इस की तरफ भी देखें।

MR. CHAIRMAN : I would like to know whether the hon. Member would like to conclude his speech in another one or two minutes, because at 6.30 we have to take up the half-an-hour discussion.

SHRI RANDHIR SINGH : Sir, I will conclude on the next day.

MR. CHAIRMAN : The hon.Member may continue his speech on the next day.

18.29 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Income-tax Appellate Tribunal for Mysore

SHRI BENI SHANKER SHARMA (Banka) : Mr. Chairman, Sir, in raising this half-an-hour discussion my only object is to draw the attention of the House to the policies governing the setting up of new benches of the Income-tax Appellate Tribunal that which is one of the most important institutions in the Tax administrative set-up of our country.

Sir, at the outset I would like to state that I have no grudge against the setting up of a new bench at Mysore or, in fact, in any other State. But it is not a piece of decoration which should be attached to every State. These Tribunal Benches are meant for some type of work and they should be established and set up in places where there is sufficient work for them.

In reply to a question of mine, No. 2509 dated 28-11-68 the hon. Law Minister had stated that there were 14,749 appeals pending in West Bengal, while the pendency at Bombay was 10,488 and in Mysore it was only 819. On 1-9-69 in reply to my supplementary to Starred Question No. 392 when I had enquired of the hon. Minister what was the reason for setting up a Bench at Mysore where the pendency was only 819, he stated in reply :

> "....that a Bench of the Income-tax Appellate Tribunal was opened in Bangalore in order to help assessees in Mysore State so that they need not go to Bombay or Madras in order to have their cases tried. . .Bombay and Calcutta are the Centres where there are the largest number of income-tax cases, but there is no use of adding to the number of Benches in those places because there is no proportionate increase in disposal of work for want of departmental officers and for want of advocates who will be called in one Bench and who will then ask for adjournment in the other Benches."

Sir, I really fail to understand the argument of the hon. Minister. In the present situation of educated unemployment, it is rather, sheer foolishness to talk of lack of officers. It is equally ludicrous to talk about advocates wanting adjournment for their engagements before other Benches. In my humble submission, Sir the opening of new Benches where there is much backlog of pendency will not only celar up the pendency but will give employment to more officers and lawyers. Why the hon. Minister should grudge the appointment of new officers, or engagement of new lawyers, passes my comprehension.

It is not only necessary that justice should be done, but it is equally necessary

[Shri Beni Shanker Sharma]

that it should be done, quickly and expeditiously. As my hon. sister Shrimati Ilapal Choudhuri has just now said, justice delayed is justice denied". In those places where the pendency is the highest, it takes a long time for disposal of cases. I am told that in Calcutta alone if an appeal is filed today, it takes about 42 months for it to come up for hearing. Therefore, I really do not understand why a bench was established in Mysore when the number of pending cases there was only 819 and not in Calcutta or Bombay where there was enough backlog.

I am told that this Mysore Bench shall have to go on tour to places like Calcutta or Bombay to help them in clearing up the arrears as for as possible. If the Bench which is started in Mysore has to go to Calcutta or Bombay, besides the in convenience and hardship to all those who have to move from one place to another, there is the question of expenditure, which has to be incurred in the movement of such courts with all their parapharuobia of departmental representatives and other members of the staff.

Sir, the direct taxes, *i. e.*, taxes on income, wealth, gift and state duty are the main sources of revenue to the Government of India. The assessees under these taxes, though negligible in number, being 27,08,000 and odd, contribute as much as Rs. 660 crores: that is, 0 5 per cent of the total population of the country is countributing approximately one-fifth of its total revenue. But I can say without any fear of contradiction that it is these persons who are the most despised, most hated, most harassed and ill-treated. Of late, a fashion has grown with our legislators even to denounce the assesees and assessors, both, who are the main props of our revenue structure as a set of thieves and scoundrels. Sir, if you want to have milk from a cow, you must learn to treat it gently, lovingly and sympathetically.

But what is the position at present ? It is considered to be a sin and crime to be on the register of the Income-tax Department through in the earliaer days it was considered as a sign of prestige, prosperity and respect. Nobody now-a-days would like to be an income-tax assessee if he could avoid it howsoever he may wish, from his heart of hearts to contribute his share of taxes to the country's exchequer, as the whole process is so insulting and and harassing.

On account of constant interference from the high ups, starting from Members of Parliament down to the lower division clerk of the Auditor-General, the Income-tax Department has become a sort of a night-mare to all concerned and its administrations degenrated beyond imagination. No officer likes to take any responsibility which is cast upon him by law, with the result that in cases where generally the income of an ass ssee would be between Rs. 10,000 and Rs 20,000 or so, the assessmen t is as high as Rs. 2 lakhs, Rs. 3 lakhs or even Rs. 5 lakhs on the slightest suspicion. Therefore the important of the appellatce tribunals.

Sir, I had the proud privilege of arguing the first appeal in the eastern zone at Calcutta and I have been associated with this important branch of justice for the last so many years and I have no hesitation in saying that it has lived up to the people's expectation But of late there has been a growing tendency in the law Ministry to interfere with its working. I am told that the Secretary of the Ministry has been issuing directions to the Tribunal members or its President to achieve a certain number of disposals or to deal with the stay petetions in a particular way. I wonder if he or the Law Minister could issue the same type of directives to High Court Judges.

So far as the tribunal is concerned, it is a judicial body and no interference is called for in its discharge of duties. It would be sheer criminal, I should say, if anybody interferes with its jurisdiction or gives any directive to it. The whole idea of its being an independent judiciary will be lost. In fact, as I stated the other day in Calcutta, these tribunals were a sort of oasis in the arid desert of income-tax administration. It is here that the much

harassed and much troubled assessees run for redress and relief and it is here that they get some consolation.

Sir, In reply to another question of mine, Unstarred Question No. 2508 during the last session, the hon. Finance Minister had stated that about 76 per cent of the appeals by the assessees were successful. Therefore you see, Sir, how indiscriminately and carelessly the assessments are made at the initial stages. I may further tell you that the Income-tax Department has also gone in appeal to High Courts and the Supreme Court and in most of the cases the decisions of the tribunals were upheld. Therefore you find, Sir, that the income-tax appellate tribunals occupy a very important position in the scheme of our tax administration.

In this context, it is no wonder that due to the indiscriminate and Tughlaki attitude of the assessing authorities, more assessees flock to the tribunals for redress and it is very necessary that these tribunals were allowed to work independently and without any let or hindrance from any quarter.

Sir, as regards the constitution of these benches, when the idea was conceived, it was decided to draft its members from the profession, that is, from the bar and accountancy. But of alate there has been a growing tendency in the Law Ministry to recruit members from the services, *i.e.* from the Finance Ministry or the Law Ministry. I may tell you that if this tendency continues, it will go against the very spirit of this institution. It is, therefore, necessary that competent members from the bar and accountancy were coaxed and cajoled to join this august institution.

Sir, I am told that so far as the emoluments are concerned, they are not sufficient to attract the best talents in the country. I would suggest that, besides improving the conditions as regards remuneration and other amenities avenues should be open for the members to be promoted to act as High Court judges.

About the conditions of service, of the Assistant Registrar and the clerical staff, I may say that they are the most ill-paid and most neglected. In the Income-Tax Department, a clerk or an inspector could rise upto the highest rung of the ladder. I have seen Inspectors coming upto the post of Commissioners. But so as the Tribunal is concerned, their fate is sealed and they are made to work in the same place for years together where they cease to have any interest. Therefore, I would suggest that in the tribunals also, the members of the staff, should have incentive in the shape of promotions in suitable and deserving cases.

Further, this will serve another very good purpose. On the floor of the House, there has been talk of arrears and arrears for a long time. I have seen how the hon. Deputy Prime Minister has been hackled at times on the inability of his officers to collect arrears of outstanding taxes. But I would submit it that a least 50 percent of the taxes imposed are under appeal are not realisable. The same cannot be called arrears unless and until the appeals are finally decided by the highest fact finding body, namely, the income-tax tribunal. Therefore, if you increase the number of tribunals in places where it is most needed, you will not only be simply rendering justice to the agrieved, quickly but you will also be helping the Finance Minister in reducing his arrears. I would therefore submit that more Benches should be opend in Calcutta, Bombay and such other places where the pendancy is highest. In the present set up of disbelief and suspicion, and consequent Tuglaki assessment many more cases are going up in appeal of the tribunals.

With these words, Sir, I would recommend to the hon. Law Minister to consider my suggestions, Further, I would submit that as within the short space of half-an-hour discussion it is not possible to give all the facts about the working conditions of the employees and/other things, it is, necessary that a commission be appointed consisting of those members of Parliament and the Ministers who have some experience in the working of the income-tax department so that they could devise the ways and means to improve the working of the

[Shri Beni Shanker Sharma]

tribunals, so that this august institution is able to fullfil the expectations with which it was started.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI M. YUNUS SALEEM) : Mr. Chairman, Sir, we have at present 19 Benches of Income-Tax Tribunals located in different cities of the country, namely, four Benches are functioning at Bombay, four at Calcutta, three at Delhi, two at Madras and one each at Allahbad, Hyderabad, Patna, Cochin, Ahmedabad and Bangalore. The function of the tribunal is to hear appeals against the decisions of the Assistant Appellate Income-Tax Commissioner and, as you are aware, these Income-Tax Tribunals are the final authority on the question of facts. Many appeals are filed by the assessees who are aggrieved by the decisions of the Appellate Assistant Commissioner. . . .

SHRI BENI SHANKER SHARMA : The department also goes in appeal against the A. A. C's orders.

SHRI M. YUNUS SALEEM : The functional jurisdiction of the Tribunal covers all direct taxes, namely, income-tax, estate duty, wealth tax, expenditure tax, gift tax and the rules made under the relevant Acts of those taxes, with the result that several thousand appeals are filed by the assessees in different benches of these Tribunals. Very recently the Ministry of Finance has taken certain policy decisions to liquidate the arrears of assessments of income-tax, particularly in respect of cases disposed of in assessment year 1967-68 and 1968-69, and with that purpose, the Department of Revenue has also increased the staff, increased the number of Income-tax Officers, Assistant Commissioners and appellate Assistant Commissioners. The net result of this policy of Government is that the disposal has increased. Because the number of officers has been increased, the assessment and the disposal of the appeals have become speedier; the speed of assessment and disposal of appeals has become faster,.....

SHRI BENI SHANKER SHARMA: You should appoint more Tribunals in those places....

SHRI M. YUNUS SALEEM : I am coming to that.

SHRI NARENDRA KUMAR SALVE (Betul) : I hope the Minister is aware of the fact that the increase in disposal of cases is in respect of this year. This has nothing to do with appeals....

MR. CHAIRMAN : Please listen to him first. You will get your chance to put a question.

SHRI NARENDRA KUMAR SALVE : He was speaking about increase in disposal. He may not be aware of the fact that that is in respect of this year, The appeals have yet to come to the Tribunal.

SHRI M. YUNUS SALEEM : That is not the question.

As I was submitting, this increase in the strength of officers in the Department of Revenue throws a heavier burden on the work of appeals coming before the income-tax appellate tribunals, resulting in heavy influx of appeals. In order to see that these appeals which are instituted before the income-tax tribunals are disposed of quickly, certain measures have been adopted. As Mr. Sharma has rightly said, justice should not be delayed. The assessee and also the Revenue Department should not be kept in suspense for a very long time because a pendency of their appeals before the income-tax appellate tribunal may not always be final because reference lie to the High Court and sometimes appeals go to the Supreme Court. Therefore, certain measures have been adopted to obtain quick disposal of these appeals. The Ministry has, in order to enhance the rate of disposal, have adopted some measures. Firstly, Members duly exercise their power singly to dispose of appeals in cases not exceeding the amount of Rs. 25,000 . As you are aware, according to the previous

rules. these appeals were heard by a Bench of the Member of the Income-Tax Appellate Tribunal. Therefore, in order to get quicker disposal of these appeals, power have been given to a single member of the Tribunal to sit singly and dispose of the cases upto a jurisdiction of Rs. 25,000 .

SHRI BENI SHANKER SHARMA : I may tell you that this power was also there even in earlier years.

SHRI M. YUNUS SALEEM : Please let me conclude. Now we are considering enhancing the jurisdiction upto Rs. 50,000. I did not say that there was no power. I say the pecuniary jurisdiction of this disposal is being enhanced so that more cases, between Rs. 25,000 and Rs. 50'000 which were heard by a Bench, would now be heard by a Single Judge and a single Member of the Tribunal. That means that at a time more appeals would be disposed of.

Second measure is to fix a target disposal of 150 cases per Bench per month. The present rate is 120 cases per month. We are trying to fix up a target so that the members of the Tribunal may realise that at least they have got to dispose of 150 cases per month. This figure has been fixed after having discussed with all the persons concerned so that the qualitative aspect and the disposal of cases may not also suffer. There may be quicker disposal and the quality also may be maintained. Just as I have submitted that it being a last court of appeal over the question of facts, the quality of the cases has also got to be taken into consideration. As a matter of policy directions have been issued that the Tribunals should be very careful and rather strict in granting adjournments to the parties on fictitious grounds because it is a question of common experience that sometimes lawyers, Chartered Accountants or the parties themselves appear and for adjournment and if conveniently they get the adjournment, the life of the appeal pending before the Income Tax Tribunal is automatically prolonged.

The third measure in that they are advised to dictate the orders then and there only in small cases in open court so that the moment they hear the appeal, order may be pronounced and judgment may not be reserved for weeks together. At least they are expected to sit five hours every day-from Monday to Friday for hearing of cases. These are all the measures which are being adopted to expedite the disposal of the appeals.

Sir, in this context, when it was discovered that the tendency is towards increasing of the appeals, as a member of policy, it was decided that each State should have at least one Income Tax appellate tribunal because, if there is no tribunal in a particular State, then the result would be that the appeal arising out of the orders of the Income-Tax authorities on the assessees of that particular State would be instituted in the adjacent State. For example, my friend, hon. Shri Sharma just now mentioned that the pendency of the appeal was very poor in the State of Mysore. In spite of that a new Tribunal has been established there. But he did not consider that the appeals pertaining to the State of Mysore were being instituted in Maharashtra and they were being filed before the Bombay High court.

The number of pendency of the appeals before the Bombay benches was increasing. Therefore, by establishing such tribunals in each state the arrears which have increased in big cities like Bombay and Calcutta would be controlled and would be shifted to those States were newly constituted appellate tribunals have been established.

MR. CHAIRMAN : I hope you have concluded. . .

SHRI M. YUNUS SALEEM : I will take at least 5 or 10 minutes more.

MR. CHAIRMAN : This is Half-an-hour Discussion. . .

SHRI M. YUNUS SALEEM : Mr. Chairman, you are aware, how many points were raised,

MR. CHAIRMAN : It can't be helped. You have to be very brief and answer to the point. We cannot proceed beyond half-

[Mr Chairman]

an-hour generally. We can take at the most five minutes more. Other Members have to put questions. Then you will have to answer again.

SHRI M. YUNUS SALEEM : I am concluding within five minutes.

MR. CHARMAN : Then let the other Members put the questions

SHRI M. YUNUS SALEEM : I will submit 2 or 3 sentences and than conclude.

I was submitting that every possible effort is being made to see that the appeals instituted before these tribunals are quickly disposed of And, the convenience of the assessees and the disposal of the appeals is the main point which is receiving serious consideration of the Government.

So far as the other points raised by hon. Members are concerned they are not very relevant So far as the question regarding service condition is concerned. I may inform the hon Member that this has now become more or less a practice that the Members of the Tribunal are being elevated to the Bench. The President of the Income-tax Tribunal is selected as a judge of the high court, The previous President of the Tribunal has become a judge of the high court; and similarly several members of the tribunal are being elevated to the Bench on the basis of their integrity and on the basis of their efficiency and knowledge of law. Therefore they are receiving encouragement provided the quality of their work is found satisfactory And, regarding the other personnal of the tribunal. their service conditions are the same as in other departments of the Central Government and there is no grivance the part of any Bench whatsoever which has been received by the Ministry that they are dis-satisfied in any way or the other.

Therefore, Sir, I submit, and I conclude with this submission, that so far as the anxiety of the hon. Members to get quick disposal of the appeals is concerned, this is in the mind of the Ministry and every possible effort is being made to see that the pendency of the appeals before the Income-tax tribunal is reduced as much as possible.

SHRI NARENDRA KUMAR SALVE : Sir, I whole-heartedly associated myself with the sentiments expressed by Mr. Sharma. The Income-tax Appellate Tribunal is an extrembly important institution sitting in judgment as the final appeal court so far as questions of facts are concerned. They have functioned magnificently and they have done their job so well that they have earned for themselves the reputation for high sence of duty and their profound knowledge about the practice and the law of taxation. These institutions have to be saved from any political influence. They are under the Law Ministry. It is of the utmost importance to see that nothing should be done by this Ministry which might carry with it the seeds and germs of politics. In view of this, may I know from the Minister, whether the Minister will assure this House that where a President is being promoted out of turn the Ministry will not do so without consulting the Chief Minister of Maharashtra ? The President sits in Bombay. The Law Minister nominates the President. And if they select person not in conformity with seniority that carries with it very serious disconted and polltics in the tribunal. Secondly, as regards disposal of appeals, about mode and manner, will the Minister assure the House that the Law Ministry shall not sit in judgment over the the Tribunal ? And finally, in Maharashtra they have four benches sitting in Bombay itself, they are saturated in Bombay. Will the hon. Minister agree to shift one Bench to Nagpur so that the people of Vidarbha, Marathawada and/South and East Madhya Pradesh can be catered ? I am not asking for increasing the Benches, but out of four one can be shifted to Nagpur.

19 hrs.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : I personally feel that the proceedings before the Income-tax Tribunals are not strictly judicial, but they are quasi-judicial. Will

the Hon. Minister consider or examine the viability of placing these tribunals directly or indirectly under the High Court or Supreme Court so that they could be free from Executive pressure ? What I feel is like Revenue Officers ond other executive officers such as Magistrates, Assistant Collectors in different branches of Law, they are not free from executive pressure. What I feel is that right from the top till the lowest in the hierarchy, much of pressure this way or that way is being exercised on these gentlemen, without any reflection on them. The ends of justice will be amply served if they are directly put under the highest judiciary, namely, High Court or Supreme Court.

Secondly, what I feel is–this is without any motive of casting reflection on them–that is Ministerial staff such as Inspectors and people down below have not got a good reputation. I say nothing about the Tribunals or Presiding Officers. In order to remove mal-practices will the Hon. Minister the question of increasing their emoluments so that the evil of mal-practices and corruption could be nipped in the bud ? My third point is. . .

MR. CHAIRMAN : That is enough, I think.

SHRI RANDHIR SINGH : This is about disposal of cases. A very prolonged procedure has got to be followed and as a result generally the litigant public and Government also suffer. What concrete proposals are in the mind of the Ministry so that this prolonged procedure could be cut short and it could be summarised so that speedy justice is done ?

श्री शिवचंद्र झा (मधुबनी): अभी तक मैसूर के लोगों को बम्बई जाना पड़ता था, महाराष्ट्र जाना पड़ता था तो स्पीडी जस्टिस के लिए मैसूर में बेंगलौर में एपैलेट ट्रिब्युनल बनाया गया तो मै जानना चाहता हूँ कि जो आपने बेंगलौर में एक दूसरा एपैलेट ट्रिब्युनल बनाया है उसके बारे में मैसूर और मद्रास के लोगों का क्या रिएक्शन है ?

यह टैक्स इवेजन के बारे में जो बातें चल रही हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक मैसूर का सम्बन्ध है तो मैसूर स्टेट में जो टोटल इनकमटैक्स इवेजन है वह आल इंडिया के हिसाब से कितना है और उसकी क्या फीगर ? एक अन्य सवाल यह है कि कितने टैक्स इवेजन के केसेज अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं ?

पटना के बारे में आपने कुछ कहा था लेकिन मैंने ठीक से सुना नहीं । मैं जानना चाहता हूँ कि पटना में आप एपैलेट ट्रिब्युनल बनाने जा रहे हैं या नहीं ?

आखिरी सवाल यह है कि इनकमटैक्स का यह सारा झमेला इनकम की डिस्पैरिटी की वजह से है तो मैं कानून मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा कि वह इनकम पर सीलिंग लगाने के लिए क्या कोई एक विधेयक लायेंगे ताकि यह झमेला कम हो और यह केसेज कम हो ?

MR CHAIRMAN : That is a different matter. That cannot be dealt with here.

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : मन्त्री महोदय ने बतलाया है कि कलकत्ते में इस वक्त 14,000 केसेज हैं, बम्बई में 10 हजार हैं । यही दो शहर हैं जहां चार चार अपेलेट ट्राईब्यूनल्स इस समय बैठती हैं । मैं इस मांग का पूरा समर्थन करता हूं कि विदर्भ और उस इलाके के लिए नागपुर में बम्बई की बेंच जाये । यह बात बड़ी अच्छी होगी । लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जब यह असलियत है कि तीन चार वर्षों तक यह मुकदमे तय नहीं हो पाते हैं और बम्बई और कलकत्ते में वर्षों तक हजारों की तादाद में मुकदमे चलते रहते हैं । तो क्या इन सूबों का विकेन्द्रीकरण करके आप वहां ट्राइब्यूनल बढ़ाने के लिए तत्काल कोई उपाय करेंगे जिससे सारे मुकदमे बहुत जल्दी तय हो जायें ?

मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब मन्त्री महोदय ने कहा कि वह इस प्रयास में लगे हुए

[श्री जार्ज फरनेंडीज]

है कि हर एक सूबे में एक एक ट्राइब्यूनल हो जाय, तो जिन प्रदेशों में ट्राइब्यूनल नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और असम वहां ट्राइब्यूनल का निर्माण करने के लिए सरकार कोई कदम उठायेगी ?

SHRI M. YUNUS SALEEM : Shri Salve asked regarding the procedure adopted for selection of the President of the Tribunal. At the time of his appointment, the seniority of the member of the Tribunal along with his performance as a member and his integrity and ability are always taken into account. I assure hon. members that in making selection, there are no political or executive considerations. It is simply on the basis of merit.

The hon. member is aware that for the selection of members of the tribunal, a committee has been constituted presided over by a Judge of the Supreme Court. Mr. Justice Shah is now the Chairman of the committee. This is in order to ensure that the selection may be only on the basis of merit.

As for the establishment of a Bench at Nagpur, the suggestion will be considered and if it is found that it would facilitate assessees, it would certainly receive sympathetic consideration.

Shri Randhir Singh also expressed apprehension whether in appointments political and executive considerations found a place. I assure him also on this score, that it is not so.

MR. CHAIRMAN : It need not be repeated.

SARI RANDHIR SINGH : Why not put them under the High Court and Supreme Court ?

MR. CHAIRMAN : It is a half:hour decision.

SHRI M. YUNUS SALEEM : So far as the appellate jurisdiction of the High Courts and Supreme Court is concerned, they are under the Act....

SHRI RANDHIR SINGH : I asked about control and supervision of the High Court, not under the Law Ministry.

SHRI M. YUNUS SALEEM : that is not possible and that is not under consideration.

One hon. member asked about the reaction of those districts of Mysore State adjacent to Maharashtra State to the newly-established bench in Mysore State. We have received no complaints from any of these districts that they are unhappy about it; our information is that they are happy that this facility has been provided for them to go in appeal in their own State.

There is no other important point raised ?

SHRI RANDHIR SINGH : I asked about delay in procedure and emoluments.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि बम्बई और कलकत्ते ऐसे स्थान हैं जहां हिन्दुस्तान का करीब करीब सारा असेसमेंट होता है और चार ट्राइब्यूनल से वहां काम नहीं चल रहा है।

बम्बई और कलकत्ते में आपने कहा है कि तीन तीन और चार चार बरस से मुकदमे चल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन दो सूबों में आप ट्रिब्यूनल बढ़ाने के तत्काल उपाय करेंगे।

SHRI M. YUNUS SALEEM : The same question was put by Mr. Sharma, when the question of establishing this Bench at Bengalore was under consideratiod, and in reply to his question, the Law Minister has given that reply and we stand by that reply even now, namely, that there is no use in adding to the number of Benches in this

place because there is no proportionate increase in the dispesal of work for want of departmenal officers and for want of advocates who may be called in one Bench and ask for an adjournment in other cases What actually happens is this. By increasing the number of Benches, quick disposal is not achieved because a very limited number of advocates and chartered accountants appear in the Benches. Therefore, if they are arguing a case and ase busy in one Bench, they simply send a slip to the other Bench. (*Interruption*)

MR. CHAIRMAN : Anyway you have given the reply. There is no question of argument.

19.12 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March, 28, 1969/ Chaitra 7, 1891 (Saka).